सत्यमेव जयते

रक्षा मंत्रालय

भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

सत्यमेव जयते

रक्षा मंत्रालय

भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

सत्यमेव जयते

रक्षा मंत्रालय
भारत सरकार

विषय सूची

	पृष्ठ संख्या
रक्षा मंत्रालय के विभाग और संगठन	1
रक्षा विभाग	5
राष्ट्रीय समारोह	7
राष्ट्रीय कैडेट कोर	17
सीमा सड़क संगठन	27
भारतीय तटरक्षक	35
सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएं	41
सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण	48
रक्षा विभाग के अन्य संगठन	55
रक्षा वित्त	80
विभिन्न देशों के साथ रक्षा सहयोग	86
महत्वपूर्ण पहल	102
रक्षा उत्पादन विभाग	103
सैन्य कार्य विभाग	125
भारतीय सेना	129
भारतीय नौसेना	159
भारतीय वायु सेना	191
मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ	213
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन	221
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग	255
महिला सशक्तिकरण और कल्याण	265

रक्षा मंत्रालय के विभाग और संगठन

रक्षा मंत्रालय

स्वतंत्रता के बाद, रक्षा मंत्रालय एक कैबिनेट मंत्री के प्रभार में बनाया गया था और प्रत्येक सेना को उसके स्वयं के कमांडर–इन–चीफ के अधीन रखा गया था। वर्ष 1955 में, कमांडर्स–इन–चीफ के नाम बदलकर सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष और वायुसेनाध्यक्ष कर दिए गए। नवंबर 1962 में, रक्षा उपकरणों के अनुसंधान, विकास और उत्पादन से संबंधित मामलों से निपटने के लिए रक्षा उत्पादन विभाग की स्थापना की गई थी।

नवंबर, 1965 में, रक्षा आवश्यकताओं के आयात प्रतिस्थापन के लिए योजनाओं के नियोजन और निष्पादन के लिए रक्षा आपूर्ति विभाग बनाया गया था। बाद में रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग बनाने के लिए इन दोनों विभागों का विलय कर दिया गया था। वर्ष 2004 में, रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग का नाम बदलकर रक्षा उत्पादन विभाग कर दिया गया।

वर्ष 1980 में, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग बनाया गया था। वर्ष 2004 में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग का गठन किया गया था । वर्ष 2019 में, संसाधनों के इष्टतम उपयोग और तीनों सेनाओं के बीच संयुक्तता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सैन्य कार्य विभाग नामक एक नया विभाग बनाया गया था।

भारत के रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रमुख होते हैं जो भारत की रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा की देखभाल करते हैं। इसके अतिरिक्त रक्षा मंत्री, रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान के अध्यक्ष के रूप में और रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान एवं राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करते हैं। रक्षा मंत्री की सहायता रक्षा राज्य मंत्री द्वारा की जाती है। रक्षा सचिव, रक्षा विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं और इसके साथ ही मंत्रालय में पांच विभागों की गतिविधियों के समन्वय हेतु जिम्मेदार होते हैं।

मंत्रालय के विभाग

(i) **रक्षा सचिव की अध्यक्षता में रक्षा विभाग (डीओडी)** रक्षा बजट, स्थापना संबंधी मामलों, रक्षा नीति, संसद से संबंधित मामलों, विदेशों के साथ रक्षा सहयोग और सभी रक्षा संबंधी गतिविधियों के समन्वय से संबंधित कार्य करता है।

रक्षा विभाग के संबद्ध कार्यालय/अंतर सेवा संगठन

(ii) **रक्षा उत्पादन विभाग** के प्रमुख, सचिव होते हैं और यह विभाग रक्षा हेतु अपेक्षित हथियारों/प्रणालियों/प्लेटफार्मों/उपकरणों को प्रदान करने हेतु एक व्यापक उत्पादन अवसंरचना विकसित करने में शामिल है। वर्षों से, इस विभाग ने डीपीएसयू के जरिए विभिन्न रक्षा उपकरणों के लिए व्यापक उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं और साथ ही निजी उद्योग को भी सुकर बनाया है।

रक्षा उत्पादन विभाग	
डीपीएसयू	अन्य संगठन
• हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)	• गुणता आश्वासन महनिदेशालय (डीजीक्यूए)
• भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	• वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीएक्यूए)
• भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल)	• मानकीकरण निदेशालय (डीओएस)
• भारत डायनमिक्स लिमिटेड (बीडीएल)	• योजना एवं समन्वय निदेशालय (पीएंड सी निदेशालय)
• गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)	• रक्षा प्रदर्शनी संगठन (डीईओ)

डीपीएसयू	अन्य संगठन
• गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) • हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल) • मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) • मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी) • म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) • आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (एवीएनएल) • एडवान्स्ड वेपन्स एण्ड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूईआईएल) • ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड (टीसीएल) • यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल) • इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल) • ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल)	• आयुध निदेशालय (समन्वय एवं सेवाएं)

रक्षा उत्पादन विभाग के संगठन

(III) **सैन्य कार्य विभाग (डीएमए)** की अध्यक्षता इसके सचिव के तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द्वारा की जाती है, जो सेवाओं हेतु अधिप्राप्ति, प्रशिक्षण और स्टाफिंग में संयुक्तता को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यों को देखते हैं। संसाधनों के इष्टतम उपयोग और स्वदेशी उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सैन्य कमानों के पुनर्गठन को सुविधाप्रद बनाना भी इस विभाग का अधिदेश है।

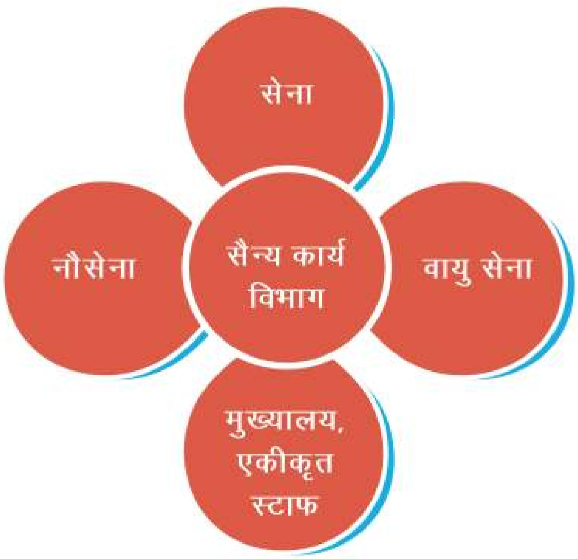

(iv) **रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग (डीडीआरएंडडी)** को अध्यक्ष, सचिव डीडीआरएंडडी और चेयरमैन, डीआरडीओ होते हैं और ये भूमि, वायु, समुद्र, अतंरिक्ष और साइबर के क्षेत्रों की रक्षा और सुरक्षा में नवीनतम सेंसर, हथियार प्रणाली, प्लेटफार्म्स और संबंधित उपस्कर के सभी डिजाइन और विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। डीआरडीओ की 36 प्रयोगशालाएं/इकाइयां हैं।

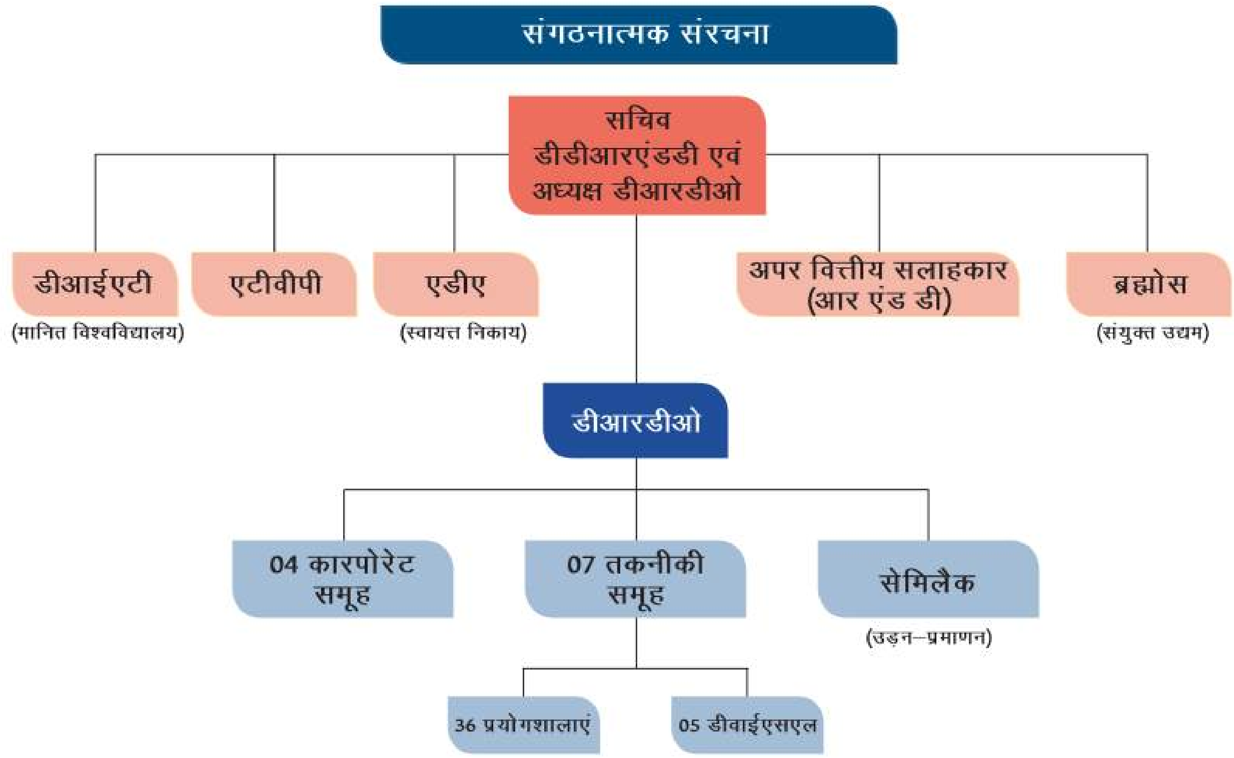

(v) **भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (डीईएसडब्ल्यू)** के अध्यक्ष, प्रमुख सचिव होते हैं और यह विभाग भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास, कल्याण और पेंशन संबंधी सभी मामलों को देखता है।

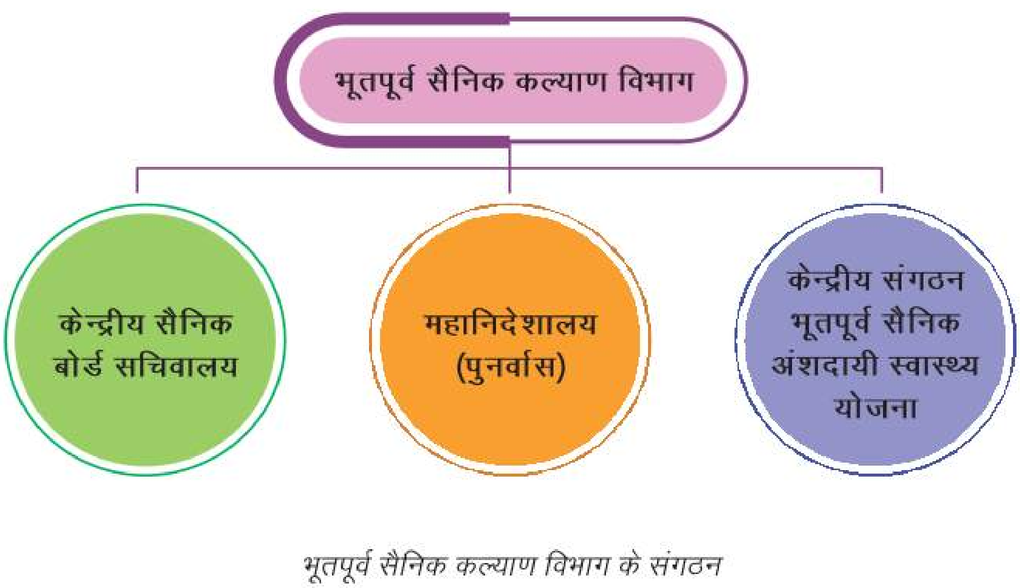

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के संगठन

* * * * *

रक्षा विभाग

सत्यमेव जयते

रक्षा मंत्रालय

भारत सरकार

राष्ट्रीय समारोह

स्वतंत्रता दिवस समारोह – 2024

- स्वतंत्रता दिवस का जश्न माननीय प्रधानमंत्री के लाल किले पर पहुंचने के साथ शुरू हुआ। तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। इसके बाद, प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके साथ सेना बैंड द्वारा राष्ट्रगान बजाया गया। इस अवसर पर स्वदेशी तोपों से इक्कीस तोपों की सलामी दी गई। प्रधानमंत्री द्वारा देश को संबोधन के बाद, एनसीसी कैडेटों और एनसीसी स्वयं सेवकों द्वारा राष्ट्रगान गाने और गुब्बारे छोड़ने के साथ समारोह सम्पन्न हुआ।

- स्वतंत्रता दिवस–2024 की पूर्व संध्या पर, निम्नलिखित वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गईः–

पुरस्कार का नाम	पुरस्कारों की कुल संख्या (मरणोपरांत मामलों सहित)	मरणोपरांत मामले
कीर्ति चक्र	04	03
शौर्य चक्र	18	04
सेना पदक (जी) (बार सहित सेना मेडल)	64	02
नौसेना पदक (जी)	11	–
वायु सेना पदक (जी)	06	–
कुल	**109**	**09**

- लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह, 2024 सम्पन्न होने के बाद, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की।

ज्ञानपथ पर मेरा भारत प्रतीक–चिह्न (लोगो)

ज्ञानपथ पर मेरा भारत प्रतीक–चिह्न (लोगो) बनाया गया। लगभग 2000 एनसीसी कैडेट और 500 एनएसएस स्वयंसेवक मेरा भारत फॉर्मेशन में बैठे।

स्वतंत्रता दिवस, 2024 में विशेष अतिथि

स्वतंत्रता दिवस समारोह, 2024 का साक्षी बनने के लिए सरकार के विशेष अतिथियों के रूप में निम्नलिखित श्रेणियों/स्कीमों/पहलों आदि से लगभग 6000 अतिथियों को आमंत्रित किया गया था:–

ड्रोन दीदी	बाल कल्याण समिति से आए अतिथि
लखपति दीदी	एमपीएसआरएलएम के स्वयं सहायता समूह की दीदियां
बीआरओ के कर्मचारी	एनएसटीएफडीएस द्वारा निधियन–प्राप्त आदिवासी उद्यमी
आशा/एएनएम कार्यकर्ता	आदिवासी कारीगर/वन धन विकास सदस्य
सखी केंद्र से आए अतिथि	जिला बाल संरक्षण इकाइयों से आए अतिथि
आंगनवाड़ी की महिला कार्यकर्ता	मेरी माटी मेरा देश के तहत एनएसएस के स्वयंसेवक
प्रधान मंत्री श्री योजना के छात्र	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के छात्र
प्रेरणा स्कूलों के छात्र	अटल इनोवेशन मिशन के इनोवेटर्स/छात्र
निर्वाचित महिला प्रतिनिधि	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थी
किसान उत्पादक संगठन	संकल्प से आए अतिथिः महिला सशक्तिकरण का केन्द्र
पेरिस ओलंपिक, 2024 के खिलाड़ी	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अतिथि	अलग– अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले (खान मंत्रालय से)
मेरा भारत योजना के लाभार्थी	एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम (एबीपी) के हर ब्लॉक से एक अतिथि
प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से पारंपरिक पोशाक में 75 युगल	ग्राम पंचायत जिसे सेचुरेशन और प्राथमिकता क्षेत्र स्कीम प्राप्त हुई है।

आम जनता के लिए बैठने की व्यवस्था

स्वतंत्रता दिवस समारोह में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, आम लोगों के लिए 10000 सीटों का इंतज़ाम किया गया था, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पारंपरिक कपड़ों में आए अतिथि और अलग–अलग क्विज़/प्रतियोगिताओं के विजेता शामिल थे।

ऑनलाइन क्विज़ प्रतियोगिताएँ/प्रतिस्पर्धाएं

- जनता की भागीदारी को बढ़ाने और उत्सव का माहौल बनाने के लिए, 20–31 जुलाई, 2024 के बीच MyGov पोर्टल और आकाशवाणी के साथ मिलकर रक्षा उत्पादन में ''आत्मनिर्भर भारत''; भारतीय स्वतंत्रता संग्राम; भारत की सैन्य ताकत; राष्ट्रीय प्रतीक और परंपराएं जैसे विषयों पर ऑनलाइन क्विज़ प्रतियोगिता की एक सीरीज़ आयोजित की गई।
- इसके अलावा, 12–30 जुलाई, 2024 के बीच ये प्रतिस्पर्धाएं भी आयोजित की गई:–
  - o 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता
  - o 'मिशन लाइफ' थीम पर पेंटिंग प्रतियोगिता
  - o देशभक्ति पोशाक प्रतियोगिता
  - o 'विकसित भारत' थीम पर वीडियो स्टोरी प्रतियोगिता
  - o देशभक्ति गीत प्रतियोगिता
- सभी प्रतिस्पर्धाओं/क्विज़ के विजेताओं को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह, 2024 देखने के लिए बुलाया गया था।

रक्षा अलंकरण समारोह

रक्षा अलंकरण समारोह, 2024 राष्ट्रपति भवन में दो चरण में अर्थात् पहली बार 05 जुलाई, 2024 को और दूसरी बार 19 जुलाई, 2024 को राष्ट्रपति सचिवालय के साथ मिलकर आयोजित की गई थी। इस अवसर पर, माननीय राष्ट्रपति द्वारा शौर्य तथा विशिष्ट सेवा पुरस्कार दिए गए। माननीय प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति से समारोह की गरिमा बढ़ाई।

कारगिल विजय दिवस

- कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह के स्मरणार्थ भारतीय सेना द्वारा **26 जुलाई, 2024** को लद्दाख के कारगिल युद्ध स्मारक में रजत जयंती महोत्सव मनाया गया। माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी उपस्थिति से इस समारोह की गरिमा बढ़ाई।

- नई दिल्ली के इंडिया गेट पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक पुष्पांजलि कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। माननीय रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव और सशस्त्र सेना के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस मौके पर पुष्पांजलि अर्पित की।

विजय दिवस

- विजय दिवस **16 दिसंबर, 2024** को मनाया गया। इस अवसर पर, माननीय रक्षा मंत्री ने इंडिया गेट पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। माननीय रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा सचिव ने भी अपनी उपस्थिति से समारोह की गरिमा बढ़ाई और पुष्पांजलि अर्पित की।

गणतंत्र दिवस परेड, 2025

- माननीय प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी, 2025 की सुबह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। हमारे देश की अखंडता की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन रखा गया।
- रिपब्लिक ऑफ़ इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, महामहिम श्री प्रबोवो सुबियान्टो, गणतंत्र दिवस परेड, 2025 के मुख्य अतिथि थे। इंडोनेशिया की मिलिट्री एकेडमी के मिलिट्री बैंड के साथ इंडोनेशियन नेशनल आर्म्ड फोर्सेज़ की मार्चिंग टुकड़ी ने भी गणतंत्र दिवस परेड, 2025 में हिस्सा लिया।

- कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति के अंगरक्षकों ने राष्ट्र की सलामी दी, जिसके बाद सेनाओं के बैंड ने राष्ट्रगान बजाया और 21 तोपों की सलामी दी गई।
- गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत हेलीकॉप्टरों से पुष्पवृष्टि के साथ हुई, जिन पर राष्ट्रीय ध्वज और सेनाओं के ध्वज थे। परेड का नेतृत्व जीसीओ दिल्ली क्षेत्र ने किया और इसमें निम्नलिखित घटक शामिल थे:—
  - देश के अलग—अलग हिस्सों के 300 सांस्कृतिक कलाकारों द्वारा वाद्ययंत्रों के साथ परेड का आगाज़ किया गया।
  - हेलीकॉप्टर से पुष्पवृष्टि
  - इंडोनेशिया (मुख्य अतिथि का देश), तीनों सेनाओं, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, एनसीसी, एनएसएस आदि के मार्चिंग दस्ते और बैंड।
  - घुड़सवार सेना दस्ता
  - मशीनीकृत दस्ता
  - पूर्व सैनिकों की झांकी, नौसेना की झांकी, डीएमए की झांकी, डीआरडीओ की झांकी, भारतीय तटरक्षक बल की झांकी और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की 26 झांकियां।
  - लगभग 5000 कलाकारों के समूह द्वारा कर्तव्य पथ के पूरे हिस्से पर 'जयति जय ममः भारतम्' के नाम से शानदार सांस्कृतिक प्रदर्शन।
  - मोटर साइकिल डिस्प्ले, फ्लाई पास्ट और रबर के गुब्बारे छोड़ना।

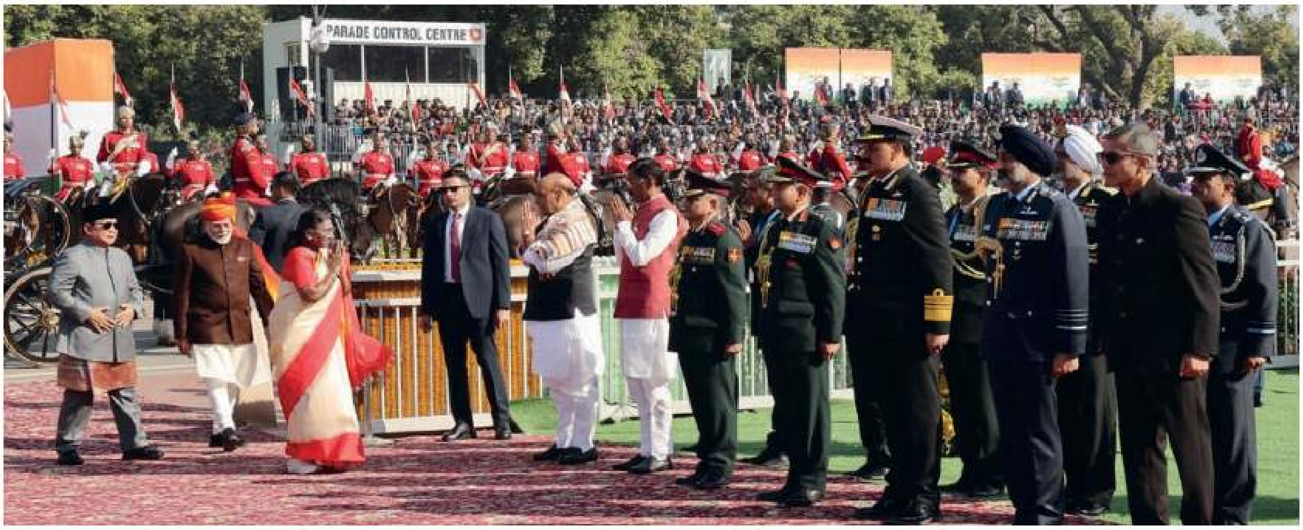

गणतंत्र दिवस समारोह 2025 की कुछ झलकियां

- गणतंत्र दिवस 2025 पर निम्नलिखित वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कारों की घोषणा की गई:–

पुरस्कार का नाम	पुरस्कारों की कुल संख्या (मरणोपरांत मामलों सहित)	मरणोपरांत मामले
वीरता पुरस्कार		
कीर्ति चक्र	02	01
शौर्य चक्र	14	03
सेना पदक/नौसेना पदक/वायु सेना पदक (शौर्य) (बार सहित)	77	08
विशिष्ट पुरस्कार		
परम विशिष्ट सेवा पदक	30	–
उत्तम युद्ध सेवा पदक	05	–
अति विशिष्ट सेवा पदक	57	–
युद्ध सेवा पदक	10	–
सेना पदक/नौसेना/वायु सेना पदक (कर्तव्य के प्रति समर्पण भावना)	67	–
विशिष्ट सेवा पदक (बार सहित)	136	–
कुलः	**398**	**12**

बीटिंग रिट्रीट समारोह, 2025

- 'बीटिंग रिट्रीट' सदियों पुरानी सैन्य परंपरा है जिसका अनुपालन करते हुए सैनिक सूर्यास्त के समय युद्ध से लौटते हैं। बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम, गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली में एकत्र हुए सैनिकों के प्रस्थान का द्योतक है। यह समारोह 29 जनवरी, 2025 को विजय चौक पर आयोजित किया गया, जिसके साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह सम्पन्न हो गया।

- समारोह में तीनों सेनाओं के बैंड के साथ केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के बैंड भी शामिल थे। सभी शामिल बैंड ने सिर्फ़ भारतीय धुनें बजाईं। समारोह के अंत में राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट हाउस और इंडिया गेट को रोशन किया गया।

गणतंत्र दिवस समारोह–2025 के दौरान की जाने वाली अन्य गतिविधियाँ

राष्ट्रपर्व पोर्टल– लोगों को गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के अलग–अलग कार्यक्रमों की जानकारी आसानी से मिल सके और वे टिकट बुक कर सकें, और उनको बैठने और पार्किंग की जगह की जानकारी मिल सके, इन प्रयोजनों के लिए एक वृह्त मोबाइल एप (एप्पल प्लें और एम.सेवा पर) और "राष्ट्रपर्व पोर्टल" बनाया गया है जो गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट समारोह से जुड़े सभी कार्यक्रमों की जानकारी के लिए एक फोकस पॉइंट का काम करेगा।

मार्चिंग संघटक– कुल 18 (17+1) मार्चिंग टुकड़ियों (सेना से 09, सीएपीएफ से 05, एनसीसी से 02, एनएसएस से 01 और इंडोनेशिया से 01) और कुल 15(14+1) बैंड (07 सेना, 05 सीएपीएफ, 01 तटरक्षक, 01 एनसीसी और 01 इंडोनेशिया) ने गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में भाग लिया।

सांस्कृतिक प्रदर्शन– संस्कृति मंत्रालय ने संगीत नाटक अकादमी के ज़रिए, 'जयति जय ममः भारतम्' शीर्षक पर 5000 कलाकारों के साथ कर्त्तव्य पथ पर सभी सीटिंग एरिया में 10 मिनट के सांस्कृतिक प्रदर्शन का आयोजन किया।

जनभागीदारी के लिए विशेष गतिविधियां

विशेष अतिथि– हाल के वर्षों में, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, अलग–अलग सरकारी स्कीम, पहल, प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों के लाभार्थियों, उपलब्धियां प्राप्त करने वालों, विजेताओं और कर्मचारियों को विशेष अतिथियों के रूप में इस कार्यक्रम में बुलाया जाता है। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के लिए, 36 श्रेणियों में लगभग 10,000 विशेष अतिथियों (जिनमें पति/पत्नी/माता–पिता/अध्यापक इत्यादि शामिल हैं) को बुलाया गया था। परेड देखने के अलावा लोकल साइट विज़िट और कॉल ऑन फंक्शन्स का भी इंतज़ाम किया गया था। इसके अलावा, हर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दिल्ली के 50 युगल को पारंपरिक पोशाक पहनकर परेड देखने के लिए बुलाया गया था। ऐसे लगभग 2000 अतिथियों ने परेड देखी। इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय द्वारा MyGov और आकाशवाणी के साथ मिलकर आयोजित की गई अलग–अलग ऑनलाइन प्रतिस्पर्धाओं के लगभग 2000 (1000x2) विजेताओं को परेड देखने के लिए बुलाया गया था।

मेट्रो सेवाएं– रक्षा मंत्रालय ने 26 जनवरी, 2025 को यह सुनिश्चित किया कि प्रातः 04:00 बजे से मेट्रो सेवा शुरु हो जाए। यह गणतंत्र दिवस परेड के किसी भी तरह के आमंत्रण कार्ड/टिकट धारकों के लिए निःशुल्क था। सभी मेट्रो स्टेशनों पर दिल्ली मेट्रो की पार्किंग की जगहें भी खोल दी गई थीं।

वीर गाथा 4.0– प्रोजेक्ट वीर गाथा का चौथा संस्करण गणतंत्र दिवस समारोह–2025 के हिस्से के तौर पर आयोजित किया गया था ताकि बच्चों को सशस्त्र सेना के बहादुरी भरे कामों और कुर्बानियों के बारे में प्रेरित और जागरुक किया जा सके। यह कार्यक्रम रक्षा मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर 16 सितंबर से 31 अक्तूबर, 2024 के बीच आयोजित किया था। अखिल भारतीय स्तर पर लगभग 1.76 करोड़ छात्रों ने हिस्सा लिया है और कुल 100 छात्र, वीर गाथा 4.0 के विजेता घोषित किए गए है। उन्हें कर्त्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए भी आमंत्रित किया गया था।

भारत पर्व– 'जन भागीदारी' थीम को दिखाते हुए, पर्यटन मंत्रालय द्वारा 'भारत पर्व' का आयोजन 26–31 जनवरी, 2025 तक दिल्ली के लाल किले में किया गया। इसमें सभी झांकियों के साथ–साथ गणतंत्र दिवस परेड की झांकियां, सैन्य बैंड (स्थिर) की प्रस्तुतियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फूड कोर्ट जो संपूर्ण भारत में प्रचलित भोजन परोस रहे थे और क्राफ्ट्स बाजार लगाए गए थे।

प्रधानमंत्री के घर पर कार्यक्रम– 24 जनवरी, 2025 को 1600 बजे से 1645 बजे (45 मिनट) तक प्रधानमंत्री के घर पर कार्यक्रम के दौरान माननीय प्रधानमंत्री के साथ झांकी कलाकारों, एनसीसी कैडेट्स, आदिवासी कलाकारों, एनएसएस स्वयं सेवकों की बैठक आयोजित की गई थी।

स्कूल बैंड प्रतियोगिता– अखिल भारतीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित की गई थी। रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की मिली–जुली पहल में, भारतीय सेना के रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर्स (आरटीसी) ने स्कूल बैंड टीमों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा दी। इस कार्यक्रम में कुल 697 स्कूल बैंड्स (लगभग 12,857 विद्यार्थी) ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता का समापन मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ। उद्घाटन और पुरस्कार वितरण क्रमशः 24 और 25 जनवरी, 2025 को रक्षा सचिव और सचिव, शिक्षा मंत्रालय और रक्षा राज्य मंत्री और राज्य मंत्री (स्कूली शिक्षा) ने मिलकर किया। जीतने वाली टीमों में से एक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, पटमदा, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड की बालिकाओं के बैंड ने राष्ट्रपति के मंच के सामने बैंड परफॉर्मेंस दी, जबकि दो अन्य जीतने वाली टीमों ने विजय चौक पर बैंड परफॉर्मेंस दी।

संविधान का 75वां वर्ष– भारत के संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, निम्न गतिविधियां आयोजित की गईः–

(क) दो झांकियों में भारतीय संविधान के लागू होने के 75 वर्ष दिखाए गए।

(ख) कर्तव्य पथ के उत्तर और दक्षिण की ओर ब्लीचर के पीछे व्यू कटर लगाए गए, जिन पर भारतीय संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने के आधिकारिक प्रतीक–चिह्न लगे थे।

(ग) भारतीय संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने के आधिकारिक प्रतीक–चिह्न वाले बैनर, रबर के गुब्बारों के साथ रिलीज़ किए गए।

(घ) रोस्ट्रम पर फूलों की सजावट भारतीय संविधान के लागू होने के 75 वर्ष के आधिकारिक प्रतीक–चिह्न के साथ की गई थी।

My Gov और आकाशवाणी पर आयोजित विभिन्न गतिविधियां – गणतंत्र दिवस समारोह–2025 और भारतीय संविधान के लागू होने के 75वें साल के मौके पर, निम्नलिखित प्रतिस्पर्धाएं/प्रतियोगिताएं/गतिविधियां आयोजित की गई:–

(क) निमंत्रण कार्ड डिजाइन प्रतियोगिता

(ख) '' स्वर्णिम भारत : विरासत और विकास ''थीम पर एक झांकी डिजाइन करने की प्रतियोगिता

(ग) '' भारतीय गणराज्य की अजेय यात्रा : अतीत, वर्तमान, भविष्य'' विषय पर निबंध प्रतियोगिता

(घ) '' रचनात्मक भारत '' विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता

(ङ) ऑनलाइन क्विज़ प्रतियोगिताओं की श्रृंखला

- i. भारत के युद्ध नायक
- ii. भारतीय संविधान के 75 वर्ष
- iii. भारत की सांस्कृतिक विरासत और परंपराएँ

(च) आकाशवाणी पर बीटीआर ट्यून पर क्विज़ प्रतियोगिता

(छ) उत्तम झांकी और उत्तम मार्चिंग टुकड़ी पर मतदान।

शहीद दिवस समारोह, 2025

दिनांक 30.01.2025 को, राष्ट्रपति ने राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और दूसरे गणमान्य लोगों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद भारत की आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर करने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन रखा गया।

गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के लिए नई पहल

गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के दौरान नई पहल के तहत, ये कदम उठाए गए:–

क्लोक रूम– कर्तव्य पथ पर अलग–अलग जगहों पर स्थापित इन क्लोक रूम्स की, गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में आए लोगों ने बहुत तारीफ़ की और इनका उपयोग किया ।

दिव्यांगजन अनुकूल एन्क्लोज़र्स– (सभी एन्क्लोज़र्स) को दिव्यांगजनों /व्हीलचेयर का उपयोग करने वालों के लिए रैंप के निकट स्थापित किया गया।

व्हीलचेयर सपोर्ट– पहली बार, दिव्यांगजनों की मदद के लिए एनसीसी के स्वयं सेवकों के साथ व्हीलचेयर भी दिए गए।

स्वयंसेवकों द्वारा सहायता– मेरा भारत के स्वयं सेवक और एनसीसी कैडेटों को, सभी उपस्थितजनों को उनके अपने एन्क्लोज़र तक पहुँचने में मदद करने के लिए तैनात किया गया था।

सूचना प्रसार– गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए "राष्ट्रपर्व पोर्टल" लॉन्च किया गया।

राष्ट्रीय कैडेट कोर

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की स्थापना एनसीसी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत हुई थी। एनसीसी देश के युवाओं को प्रतिबद्धता, समर्पण, स्व–अनुशासन और नैतिक मूल्यों की भावना के साथ सर्वांगीण विकास के अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है ताकि वे भविष्य के जिम्मेदार नागरिक बन सके। ''एकता और अनुशासन'' एनसीसी का आदर्श वाक्य है ।

इनकी स्वीकृत संख्या 20 लाख है, (तीन लाख अतिरिक्त संख्या तीन नामांकन वर्षों में जोड़ी जाएगी) और एनसीसी इकाइयों की कुल संख्या 831 है।

एनसीसी देश के अधिकांश शैक्षिक संस्थानों में है। बालिका कैडेटों का प्रतिशत, कुल नामांकन का 39 प्रतिशत है। कुल **21329** संस्थान हैं जिनमें **13165** स्कूल, **1949** इंटर कॉलेज और **6215** महाविद्यालय शामिल हैं ।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उत्तम निदेशालय बैनर प्रदान करते हुए

31 दिसम्बर, 2024 की स्थिति के अनुसार नामांकित कैडेटों के स्कंध–वार वितरण की संख्या

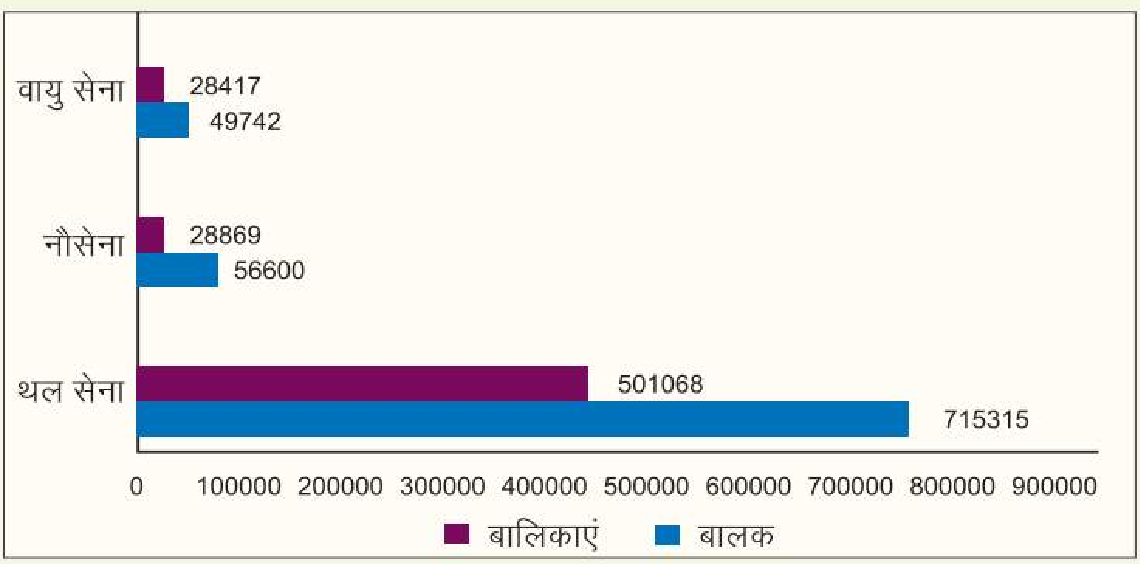

शिविर और प्रशिक्षण

एनसीसी का केआरए प्रशिक्षण का उद्देश्य ' कैडेटों को हमारे देश के संभावित नेता और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए सशक्त बनाना है ' । संस्थागत प्रशिक्षण और शिविर प्रशिक्षण एनसीसी पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है ।

संस्थागत प्रशिक्षण

एएनओ और पीआई स्टाफ सामान्य विषयों और सेवा–विषयों दोनों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं ताकि राष्ट्र की निःस्वार्थ सेवा एवं समाज के उपयोगी सदस्य के रूप में सशक्त बनाने के लिए मानव–संसाधन के रूप में संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं को तैयार किया जा सके।

शिविर प्रशिक्षण

कैडेटों को शिविर जीवन के रोमांच से अवगत कराया जाता है, जहाँ वे संस्थागत प्रशिक्षण में प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग करते हैं। जूनियर डिवीजन/जूनियर विंग (जेडी/जेडब्ल्यू) कैडेटों के लिए, उनके नामांकन की अवधि के दौरान, कम से कम एक शिविर में भाग लेना और सीनियर डिवीजन/सीनियर विंग(एसडी/एसडब्ल्यू) कैडेटों के लिए, कम से कम दो शिविरों में भाग लेना अनिवार्य है ।

वार्षिक प्रशिक्षण शिविर (एटीसी)– इस वर्ष, अब तक सभी एनसीसी राज्य निदेशालयों में 1225 एटीसी/सीएटीसी आयोजित किए गए हैं, जिनमें लगभग छह लाख कैडेटों ने भाग लिया है ।

केंद्रीय स्तर पर आयोजित शिविर (सीओसी)– संचालित सीओसी और उनमें प्रतिभागिता संबंधी आंकड़े निम्न प्रकार से हैं:–

केन्द्रीय स्तर पर आयोजित शिविरों के प्रकार

प्रमाणपत्र परीक्षाएं– प्रशिक्षण वर्ष 2024–25 में लगभग छह लाख बीस हजार कैडेट एनसीसी की 'ए', 'बी' और 'सी' प्रमाणपत्र परीक्षाओं में शामिल हुए ।

गणतंत्र दिवस शिविर

वार्षिक एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में 30 दिनों की अवधि के लिए दिल्ली कैंट के करिअप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाता है, जो पीएम रैली के साथ समाप्त होता है । इस वर्ष शिविर के दौरान कैडेटों ने कई प्रशिक्षण और समारोह संबंधी प्रतियोगिताओं में भाग लिया । इसके अलावा, युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम (वाईईपी) के एक भाग के रूप में 24 मित्र देशों के कैडेटों/युवाओं ने भी गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लिया।

गणतंत्र दिवस समारोह– 2024 के दौरान कैडेटों से बात–चीत करते हुए माननीय रक्षा मंत्री

गणतंत्र दिवस समारोह– 2024 के दौरान कैडेटों से बात–चीत करते हुए माननीय रक्षा राज्य मंत्री

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और एसएसबी प्रशिक्षण– 2024–25

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण : एनसीसी दो प्रमुख प्रशिक्षण अकादमी चलाता है जो सहायक राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी (पुरूष और महिला), महिला कैडेट अनुदेशक और स्थायी अनुदेशक स्टाफ की कमीशनिंग और रिफ्रेशर ट्रेनिंग में विशेषज्ञता प्राप्त है। 2024–25 में कुल 3,479 सहायक कैडेट कोर अधिकारियों और 606 महिला कैडेट अनुदेशकों ने इन अकादमी में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया। इसके अलावा, हाल में तैनात अधिकारियों और स्थायी अनुदेशक स्टाफ (जेसीओ/एनसीओ) के लिए राज्य निदेशालय स्तर पर हर तिमाही में एक अभिविन्यास कैडर का आयोजन किया गया, जिससे नियमित अपडेट्स और निरंतर व्यावसायिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।

एसएसबी कोचिंग : भविष्य के नेताओं को तैयार करने के लिए प्रति निदेशालय 30 कैडेट के हिसाब से 510 एसडी/एसडब्ल्यू कैडेटों के लिए एसएसबी कोचिंग आयोजित की गई। उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षण वर्ष 2024–25 में, एनसीसी विशेष प्रवेश (सेना) की 100% रिक्तियां, यानी, 110 रिक्तियां एनसीसी कैडेटों द्वारा भरी गई। इसके अलावा 10,642 कैडेट अग्निवीर के रूप में सशस्त्र सेनाओं में शामिल हुए।

साहसिक और खेल गतिविधियां

साहसिक गतिविधियां : साहसिक गतिविधियों का उद्देश्य कैडेटों में साहस, समन्वेषी कौतुहल की भावना जागृत करना, ऊर्जस्विता, सहन–शक्ति, आत्मविश्वास और एकता की भावना का विकास करना है। साहसिक गतिविधियां कैडेटों के नेतृत्व–कौशल को बेहतर बनाने और उनकी स्वभावगत विशेषताओं को बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है। संभावित कैडेटों को ऐसे अभियानों में भाग लेने के अवसर दिए जाते हैं जिनमें ज्यादा सुविज्ञता और निपुणता की जरूरत होती है।

02x माउंट कांग यात्से ।। (लेह) और माउंट अबी गामिन पर्वतारोहण अभियानः (58 कैडेट)

58x पर्वतारोहण पाठ्यक्रम (591 कैडेट)

37x अखिल भारतीय ट्रेकिंग अभियान (18,870 कैडेट)

16x व्हाइट वाटर राफ्टिंग (458 कैडेट)

02x पैरा बेसिक कोर्स (101 कैडेट)

रॉक क्लाइंबिंग ट्रेकिंग कैंप (1,362 कैडेट)

समुद्री सॉर्टी (102 कैडेट)

रेगिस्तान सफारी (100 कैडेट)

नौकायन अभियान मेन्यू (1,200 किलोमीटर)

अखिल भारतीय नौकायन रेगेटा (102 कैडेट)

साहसिक गतिविधियों के प्रकार

माउंट कांग यात्से जाने वाली पर्वतारोहण टीम

विशेष नौकायान अभियान

एनसीसी के 76वें साल के अवसर पर, लीक से हटकर एक यादगार नौकायान अभियान शुरू किया गया। अपने इतिहास में पहली बार, 500 से ज्यादा कैडेटों ने पवित्र गंगा और हुगली नदियों में एक प्रेरणा दायक यात्रा शुरू की, जिसमें तीन राज्यों–उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच से होकर 1200 कि.मी. का बड़ा रास्ता तय किया गया। 21 अक्तूबर, 2024 को कानपुर से शुरू हुआ यह एनसीसी अभियान, जिसकी थीम 'भारतीय नदियाँ– संस्कृतियों की जननी' है, भारत की नदियों को उसकी सांस्कृतिक और समुद्री विरासत के मर्म के रूप में प्रतिष्ठित करता है।

तरंगिणी

यह अभियान दो महीनों में छह चरणों से गुजरा और कोलकाता में सम्पन्न हुआ। पूरी यात्रा के दौरान, कैडेटों ने पानी में नेविगेशन किया और स्थानीय समुदायों से जुड़े। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत नदी के किनारों की सफाई करके पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को बढ़ावा दिया, साथ ही देश का गौरव बढ़ाया और भारत की समुद्री विरासत को उजागर किया। इसी तरह, अभियान में तटीय भागों की यात्रा के दौरान, 180 एनसीसी कैडेट 30 नवंबर 2024 को आईएनएसवी तरंगिणी पर सवार होकर मुंबई से विशाखापत्तनम गए, जिस दौरान वे गोवा, न्यू मैंगलौर, कोच्चि और चेन्नई से गुज़रे।

खेल गतिविधियां

सभी एनसीसी निदेशालयों के एनसीसी कैडेटों ने राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेल गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। बड़ी/प्रमुख खेल गतिविधियां, जिसमें एनसीसी कैडटों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया/प्रदर्शन किया, निम्न प्रकार से है:–

अंतर निदेशालय खेल शूटिंग चैंपियनशिप (आईडीएसएससी) 2024– इस चैंपियनशिप का उद्देश्य एनसीसी कैडेटों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना और अखिल भारतीय जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए एनसीसी शूटिंग टीम को चुनना है। आईडीएसएससी 2024, 02 से 15 जुलाई 2024 तक आयोजित की गई थी। सभी 17 निदेशालय (@अधिकतम 20 कैडेट्स/निदेशालय) के 295 कैडेटों ने चैंपियनशिप में भाग लिया। टूर्नामेंट, एनसीसी निदेशालय कर्नाटक और गोवा ने जीता।

प्री मावलंकर कोचिंग कैंप और 33वीं अखिल भारतीय जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप (एआईजीवीएमएससी)– 33वीं एआईजीवीएमएससी (भारत के राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के तत्वावधान) में कोचिंग और प्रतिभागिता 03 नवंबर 24 से केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरू हुई। कैडेट्स ने चैंपियनशिप में 12 स्वर्ण, 08 रजत और 06 कांस्य पदक जीते।

शूटिंग चैंपियनशिप 2024 के सभी विजेता कैडेट

जवाहर लाल नेहरू (जेएलएन) हॉकी टूर्नामेंट– जेएलएनएच टूर्नामेंट 2024, 15 अक्तूबर से 06 नवंबर 24 तक हुआ था। इसमें जूनियर बॉयज कैटेगरी (रेड और ब्लू) और जूनियर गर्ल्स कैटेगरी में एनसीसी टीमों ने हिस्सा लिया। जूनियर गर्ल्स टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल में रनर–अप रही। खास बात यह है कि टीम की कैप्टन को टूर्नामेंट का सर्वोत्तम खिलाड़ी चुना गया, जिससे टीम की असाधारण प्रतिभा और स्पोर्ट्समैनशिप का पता चलता है। प्रतिस्पर्धा से पहले डीजीएनसीसी टीमों को जाने–माने प्रशिक्षकों से खास कोचिंग दी गई थी।

सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट– एनसीसी टीमों ने सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में तीन श्रेणियों अर्थात् जूनियर गर्ल्स, सब जूनियर बॉयज और जूनियर बॉयज में हिस्सा लिया। इन टीमों ने अपने कौशल और स्पोर्ट्समैनशिप को प्रदर्शित किया।

घुड़सवारी प्रतियोगिता– आर एंड वी एनसीसी कैडेटों ने आर्मी घुड़सवारी चैंपियनशिप और रीजनल हॉर्स शो में भाग लिया और 02 स्वर्ण, 06 रजत और 13 कांस्य पदक जीते।

युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम (वाईईपी)

आउटगोइंग वाईईपी– वाईईपी का संचालन अप्रैल – मार्च (शैक्षणिक वर्ष) में होता है। कुल 16 अधिकारियों और 98 कैडेटों ने यूके, कजाकिस्तान, वियतनाम, सिंगापुर, भूटान, मालदीव, नेपाल, किर्गिज रिपब्लिक, मालदीव और नेपाल का दौरा किया।

वाईईपी के एनसीसी कैडेटों ने सिंगापुर में फोर्ट कैनिंग का दौरा किया

सामाजिक सेवा और सामुदायिक विकास (एसएससीडी) कार्यक्रम

राष्ट्र–निर्माण एनसीसी प्रशिक्षण का आधार है, जो नागरिक कर्त्तव्य, जिम्मेदारी और राष्ट्रीय गौरव के मूल्यों को सिखाने पर ध्यान केन्द्रित करता है। अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हुए, एनसीसी कैडेटों ने विभिन्न समाज सेवा और विकास गतिविधियों में हिस्सा लिया, जैसा कि आगामी पैराग्राफों में बताया गया है। एसएससीडी गतिविधियाँ अब एनसीसी कैडेटों के लिए संशोधित पाठ्यक्रम में भी शामिल हैं।

इस साल के एसएससीडी कार्य योजना के हिस्से के तौर पर, निम्नलिखित दिशानिर्देश भी दिए गए हैं:–

- प्रत्येक कैडेट को 100 घंटों का श्रमदान करना होगा।
- प्रत्येक एनसीसी इकाई को दो निकटतम गावों/झुग्गी बस्तियों को अपनाना होगा और सरकारी/अर्द्ध सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर वहां संयुक्त रूप से गतिविधियां संचालित करनी होंगी।
- कैडेटों को ऐसे कार्य/ऐसी गतिविधियां नहीं करनी होगी जिनमें उनकी सुरक्षा को खतरा हो।
- सभी गतिविधियां, जब भी संभव हो, प्राधिकारियों, स्थानीय प्रशासन/गैर–सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय करके संचालित करनी होगी।

एसएससीडी कार्य योजना के लिए दिशा–निर्देश

न केवल कैडेट्स बल्कि माहौल को भी अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये गतिविधियां की गई है:–

स्वतंत्रता दिवस / 'हर घर तिरंगा' अभियान– इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को 13–15 अगस्त 2024 तक स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना था। पूरे भारत में कुल 2,72,397 एनसीसी कैडेट्स ने अभियान के दौरान पूरे देश में अपनी अटूट प्रतिबद्धता और जोश दिखाया। इसके अलावा, दिल्ली निदेशालय के 2,000 कैडेट्स ने लाल किले पर हुए समारोह में हिस्सा लिया, जिससे राष्ट्रीय विरासत के प्रति उनके समर्पण और गौरव का पता चलता है।

विश्व पर्यावरण दिवस– 05 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, एनसीसी कैडेट्स ने पूरे भारत में **भूमि पुनरुद्धार, पलायन और सूखे से बचाव** थीम पर अलग–अलग गतिविधियों में हिस्सा लिया। बढ़ते पलायन, टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज और सेव एनवायरनमेंट, मिशन लाइफ, सूखे से बचाव की तकनीकों, भूमि पुनरुद्धार तंत्र और गो ग्रीन, ब्रीद क्लीन पर 1500 जगहों पर जागरुकता अभियान आयोजित किए गए, जिनमें 6,50,000 कैडेट्स शामिल हुए।

अतंर्राष्ट्रीय योग दिवस– 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व–संध्या पर एनसीसी ने अखिल भारत में **वसुधैव कुटुम्बकम हेतु योग** थीम पर अपनी इकाइयों में योग से जुड़े कई कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित कीं। इस कार्यक्रम में योग सत्र, प्रदर्शन, समग्र स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए योग के लाभ से संबंधित जागरूकता अभियान शामिल थे, जो 5535 स्थानों में आयोजित किए गए और इनमें 7,80,226 कैडेट शामिल हुए।

योग दिवस

रजत जयंती महोत्सव कारगिल विजय दिवस पर 26 जुलाई 2024 को कारगिल युद्ध के 25 साल पूरे होने पर युद्ध नायकों के साथ फिल्म स्क्रीनिंग, पुष्पांजलि, प्रेरक व्याख्यान और प्रतियोगिताओं के माध्यम से जश्न मनाया गया।

स्वच्छ भारत दिवस 02 अक्तूबर को 'स्वभाव स्वच्छता—संस्कार स्वच्छता' टैगलाइन के साथ मनाया गया। गतिविधियों में 'एक पेड़ माँ के नाम' के तहत पेड़ लगाना, फूड स्ट्रीट सेंसिटाइजेशन और अपशिष्ट नवाचार कार्यक्रम शामिल थे। 4,19,600 कैडेट्स ने 2,341 स्वच्छता स्थानों को चिह्नित किया और सफाई प्रबंधन, बिजली, बैंकिंग, गैस, स्वास्थ्य और बीमा जैसी सरकारी योजनाओं पर जागरुकता कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

एकता दिवस में 47 कैडेट्स ने केवड़िया, गुजरात में ड्रिल टुकड़ियों में हिस्सा लिया, जिसमें 'इस देश की मिट्टी में कुछ खास है' और 'राष्ट्र प्रथम' विषय संबंधी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए।

एक पेड़ माँ के नाम पहल में 5.5 लाख कैडेट्स ने पूरे देश में 9,38,714 से ज्यादा पेड़ लगाए। इंदौर, मध्य प्रदेश ने एक दिन में 1,00,000 से ज्यादा पेड़ लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।

दांडी पद यात्रा गांधीजी के नमक मार्च की याद में 10—24 दिसंबर 2024 तक अहमदाबाद से दांडी तक तय की गई जिसमें 40 कैडेट्स (20 लड़के, 20 लड़कियां) शामिल हुए, जिसका उद्घाटन गुजरात के गवर्नर ने किया।

1857— प्रथम स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता के पहले युद्ध की स्मृति में साइकिलिंग अभियान के दौरान मेरठ से नई दिल्ली तक की यात्रा तय की गई।

वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, गृह मंत्रालय की पहल के तहत प्रशिक्षण वर्ष 2025—26 के लिए 662 गांवों में लागू किया जा रहा है, जिसमें 15 गांवों में पायलट कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

मेरी लाइफ मिशन ने 'प्रकृति रक्षति रक्षिता' आदर्श—वाक्य के साथ पर्यावरण अभियानों में 8 लाख कैडेट्स शामिल हुए, जिसमें प्लास्टिक—मुक्त भारत को बढ़ावा देने के लिए माउंट कांग यात्से पर पर्वतारोहण अभियान भी शामिल था।

रक्तदान अभियान में 40,000 यूनिट ब्लड इकट्ठा हुआ, जो सेवा और सहयोग की परंपरा को दर्शाता है।

पुनीत सागर अभियान में विशेष पर्यावरण दिवसों पर विशेष अभियान चलाकर समुद्र के किनारों की सफाई की गई। 5.6 लाख कैडेट्स ने 501 टन प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया, 304 टन कचरे का पुनःचक्रण किया, और समुद्री संरक्षण के लिए मत्स्य संपदा योजना में सहयोग करते हुए 6.9 करोड़ लोगों को प्रभावित किया।

महत्वपूर्ण पहल

तीन लाख एनसीसी संवर्धन योजना— एनसीसी का विस्तार करने और युवाओं की उम्मीदों को पूरा करने की चल रही कोशिशों के तहत, सरकार ने 'तीन लाख कैडेट संवर्धन योजना' को मंजूरी दी है, **जिससे एनसीसी की संख्या 20 लाख कैडेट तक बढ़ जाएगी** और यह दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी बल बन जाएगा। एनसीसी संवर्धन योजना लगातार आगे बढ़ रही है, जिसमें एक प्रारंभिक परियोजना के तहत 30,000 कैडेट्स को भर्ती किया गया है और इस साल 345 भूतपूर्व—सैनिकों की भर्ती—प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। इसके अलावा, जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में तीन सेना एनसीसी यूनिट्स और एक एयर विंग भी ऑपरेशनल कर दिया गया है। शेष 2.7 लाख कैडेट्स की भर्ती और 1,943 भूतपूर्व—सैनिकों की हायरिंग 01 अप्रैल 2025 से शुरू होगी।

इसरो में एनसीसी कैडेटस

समकालीन प्रशिक्षण को अपनाना– एनसीसी, अमृत पीढ़ी को कौशल युक्त कर रही है ताकि विकसित भारत @2047 का विजन पूरा हो सके। साइबर जागरुकता, आपदा प्रबंधन और ड्रोन प्रशिक्षण जैसे समकालीन विषयों को शामिल किया गया है, साथ ही आधुनिक युग की चुनौतियों से निपटने के लिए सिम्युलेटर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। डीआरडीओ, आईएसआरओ और एनपीसीआईएल जैसे संगठनों के साथ मिलकर काम करने से कैडेट्स को उन्नत अनुसंधान एवं तकनीक के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कैडेट्स की क्षमताओं को उद्योग की जरूरतों के हिसाब से ढालने के लिए स्किल मंथन, आइडिया और इनोवेशन कैंप और कौशल कैंप जैसी पहल की जा रही हैं।

आइडिया / इनोवेशन और स्टार्ट अप–वर्तमान प्रशिक्षण वर्ष में एनसीसी कैडेट्स को आइडिया/इनोवेशन और स्टार्टअप के बारे में जानकारी देने पर जोर दिया गया। कैडेट्स को जोड़ने के लिए पूरे भारत में आइडिया/इनोवेशन प्रतियोगिताएं करवाई गई, ताकि उन्हें लीक से हटकर सोचने, अपनी अवधारणाएं विकसित करने और एनसीसी के राष्ट्र–निर्माण के मिशन में अर्थपूर्ण योगदान देने का अवसर मिले।

कौशल प्रशिक्षण– ऑल इंडिया ट्राईसर्विस कॉम्पिटिशन कैंप के दौरान स्किल मंथन वर्कशॉप, जिसमें सभी एनसीसी के राज्य निदेशालयों के 3,000 चुने हुए कैडेट्स शामिल हुए। इसके अलावा, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर स्किल कौंसिल द्वारा प्रदत्त **डिजिटल 101 कोर्स** पर उज्जैन, (मध्यप्रदेश) में एवं हाइड्रोकार्बन्स सेक्टर स्किल कौंसिल द्वारा प्रदत्त **न्यू एवेन्यूज़ ऑन एनर्जी ट्रांज़िशन** विषय पर लॉ गार्डन (गुजरात) में ईबीएसबी स्किल (कौशल कैंप्स) आयोजित किए गए। इस कौशल प्रशिक्षण ने एन सी सी कैडेटों को एनसीवीटी द्वारा अनुमोदित सरकारी मान्यता प्राप्त करना और 5,000 कैडेटों को एनएसक्यूएफ प्रमाणन प्राप्त करना सुविधाजनक बना दिया है।

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के साथ समझौता ज्ञापन– एनपीसीआईएल की कोशिशों के प्रति कैडेट्स को जागरूक करने की दिशा में एक कदम के तौर पर, एनसीसी और एनपीसीआईएल के बीच 21 मार्च 2024 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल से अलग–अलग स्तरों पर एनसीसी कैडेट्स के मध्य नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के बारे में जागरूकता फैलेगी।

पात्र कैडेट्स को पोशाक भत्ते का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर– एनसीसी ने डिजिटल भुगतान को आसान बनाने के लिए ऐसी प्रौद्योगिकी को अपनाया है, जिससे पूरे भारत में कैडेट्स तक कुशल और पारदर्शी पहुंच सुनिश्चित हो सके। डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए सरकार के प्रयासों के अनुरूप, एनसीसी ने यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, 07 लाख से ज्यादा पात्र कैडेट्स को 298 करोड़ रुपये डिजिटल तरीके से दिए हैं। यह पहल न केवल प्रक्रिया को आसान बनाती है बल्कि समय पर ट्रांसफर भी सुनिश्चित करती है, जिससे आधुनिकीकरण के प्रति एनसीसी की प्रतिबद्धता और अधिक सुदृढ़ होती है।

एडीजी/डीडीजी सम्मेलन– एनसीसी, केन्द्र और राज्य सरकारों, दोनों के संयुक्त अधिकार क्षेत्र में काम करता है। निर्बाध एकीकरण का लगातार कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, 04–05 जून 2024 को दिल्ली में एक वार्षिक सम्मेलन **'वार्षिक एनसीसी नीति संवाद शिविर'** का आयोजन किया गया था। इसमें सभी 17 एनसीसी राज्य निदेशालयों के अपर महानिदेशक (एडीजी) और उप महानिदेशक (डीडीजी) शामिल हुए। इस सम्मेलन में विस्तार–योजना के खास पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं और संबंधित राज्यों से जरूरी अनुमोदन मिलने की स्थिति का आकलन किया गया।

विशेष जेएसआर और ए/डी सम्मेलन– राज्यों के साथ विस्तार योजना के तौर–तरीकों को और आसान बनाने के लिए, **माननीय रक्षा राज्य मंत्री, श्री संजय सेठ की अध्यक्षता** में 23 सितंबर, 2024 को दिल्ली छावनी के मानेकशॉ केन्द्र में एक विशेष संयुक्त राज्य प्रतिनिधियों (जेएसआर) और अपर निदेशक/उप–निदेशक (ए/डी) का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में नौ राज्यों के मंत्री, अलग–अलग राज्यों के वरिष्ठ प्रतिनिधि, रक्षा मंत्रालय के अधिकारी, तीनों सेनाओं के सदस्य और सभी राज्यों के एडीजी और डीडीजी शामिल हुए। एनसीसी के होने वाले विस्तार से जुड़े अलग–अलग पहलुओं पर राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हुई और राज्यों की तरफ से सकारात्मक प्रतिबद्धताएं सामने आईं।

एनसीसी एलुमनाई संगठन (एनसीसीएए) की कार्यकारी समिति की प्रारंभिक बैठक— एनसीसीएए, जिसे माननीय प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर 21 को 'यूथ पावरः ए विजन ऑफ न्यू इंडिया' के अपने विजन के हिस्से के तौर पर लॉन्च किया था, तेजी से राष्ट्र—निर्माण के लिए एक जीवंत प्लेटफॉर्म बन गया है। विशिष्ट नेता, चर्चित हस्तियां और पेशेवरों समेत 2.7 लाख से ज्यादा भूतपूर्व कैडेट्स इससे जुड़ चुके हैं। डीजीएनसीसी की अध्यक्षता में हुई अपनी कार्यकारी समिति की प्रारंभिक बैठक में, संगठन ने एनसीसी प्रशिक्षण मानदंडों को बढ़ाने, कौशल विकास को बढ़ावा देने और स्वच्छ भारत अभियान जैसी सामाजिक पहलों में शामिल होने के अपने मिशन के बारे में बताया। इसका उद्देश्य जरूरतमंद भूतपूर्व कैडेटों की सहायता करना और एनसीसी से जुड़े कार्यक्रमों में अर्थपूर्ण हिस्सेदारी को सुविधाजनक बनाना भी है, जिससे एक मजबूत और अधिक समावेशी भारत के निर्माण में इसकी भूमिका और प्रबल होगी।

एनसीसी के 76 वर्ष— एनसीसी के 76 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाते हुए, संगठन को माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सेना प्रमुखों और रक्षा सचिव से बधाई संदेश मिले, जिन्होंने कैडेट्स के जोश और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की तारीफ की। पूरे भारत में कैडेट्स ने निःस्वार्थ सेवा की मिसाल पेश करते हुए देश भर में रक्तदान अभियान चलाया। रक्षा सचिव ने भी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर फूल चढ़ाकर सशस्त्र सेना के बलिदानों को श्रद्धांजलि दी। इस जश्न में एनसीसी के अनुशासन, देशभक्ति और एकता के मूल सिद्धांतों की झलक देखने को मिली।

प्रेसीडेंट एट होम फंक्शन

* * * * *

सीमा सड़क संगठन

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) एक आधुनिक एवं देश–विदेश का निर्माण संगठन है जो भारतीय सशस्त्र बलों की सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रति समर्पित है। यह संगठन निम्नलिखित मंत्रालयों के लिए अवसंरचनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है:–

(क) रक्षा मंत्रालय

(ख) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(ग) गृह मंत्रालय

(घ) विदेश मंत्रालय

(ड़) ग्रामीण विकास मंत्रालय

(च) उत्तर–पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

(छ) डिपॉजिट वर्क्स के तौर पर पीएसयू/अन्य एजेंसियां

संगठनात्मक संरचना

वर्तमान संरचना के अनुसार, बीआरओ की 17 परियोजनाओं की अध्यक्षता ब्रिगेडियर/मुख्य अभियंता (सिविल) रैंक के एक अधिकारी द्वारा की जा रही है। प्रत्येक परियोजना में दो/तीन सीमा सड़क कार्य बल (बीआरटीएफ) शामिल होते हैं जिनकी अध्यक्षता कर्नल/अधीक्षक अभियंता (सिविल) रैंक के एक अधिकारी द्वारा की जाती है। प्रत्येक बीआरटीएफ में दो/तीन सड़क निर्माण कंपनियां (आरसीसी)/पुल निर्माण कंपनियां (बीसीसी) शामिल होती हैं। आरसीसी/बीसीसी की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट कर्नल/मेजर/कार्यकारी अभियंता (सिविल) रैंक के एक अधिकारी द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त आरसीसी/बीसीसी में कई प्लाटून शामिल होती हैं जिनकी अध्यक्षता कैप्टन/सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल)/सहायक अभियंता (सिविल) रैंक के एक अधिकारी द्वारा की जाती है।

गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए रक्षा मंत्रालय (बीआर) के अधीन गुवाहाटी, दीमापुर और जम्मू में 3 क्षेत्रीय तकनीकी जांचकर्ता कार्यरत हैं।

वर्तमान में, बीआरओ का पुणे में एक प्रशिक्षण केन्द्र, जीआरईएफ स्कूल और केन्द्र व शिलांग में एक अनुसंधान एवं विकास अधिष्ठान है।

महानिदेशक सीमा सड़क

महानिदेशक, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। महानिदेशक सीमा सड़क निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है:–

(क) बीआरओ को सौंपी गई परियोजनाओं संबंधी योजना बनाना और उनका क्रियान्वयन करना तथा सभी तकनीकी मामलों का समन्वय करना।

(ख) परियोजनाओं के निर्माण में अपनाई गई डिजाइन विशिष्टताओं की तकनीकी सुदृढ़ता।

(ग) आवधिक बजट अनुमान तैयार व प्रस्तुत करना तथा सरकार से निधि प्राप्त करना।

(घ) बीआरओ के कार्य–बल, मानव शक्ति इत्यादि का प्रशासन, योजना एवं नियंत्रण।

अपर महानिदेशक सीमा सड़क

डीजीबीआर को उनके दायित्वों का निर्वहन करने में अपर महानिदेशक सीमा सड़क मदद करते हैं। मुख्यालय डीजीबीआर में मौजूद एडीजीबीआर (मुख्यालय), संगठनात्मक नीति, योजना और निर्देशों को समन्वित करता है, निर्दिष्ट संचालनात्मक शाखाओं की देखरेख करता है, और डीजीबीआर के निर्देशानुसार सभी सेक्टरों में प्रमुख अभियंताओं और परियोजनाओं हेतु मार्गदर्शन करता है। एडीजीबीआर (उत्तर पश्चिम) और एडीजीबीआर (पूर्व) अपने–अपने सेक्टर में प्रोजेक्ट की आयोजना, निष्पादन और निगरानी का काम देखते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि अनुमोदित डिज़ाइन, विशिष्टताओं और समय–सीमा का पालन हो। वे प्रमुख अभियंताओं के साथ–साथ लोकल आर्मी और सिविल अथॉरिटी के साथ समन्वय स्थापित करते हैं ताकि काम आसानी से हो सके, साथ ही सभी सौंपी गई परियोजनाओं की तकनीकी विश्वसनीयता, गुणवत्ता और समयबद्ध रूप से उन्हें पूरा करना सुनिश्चित करते हैं, और अपने क्षेत्रों के हितधारकों के साथ घनिष्ठता बनाए रखते हैं।

मुख्य अभियंता

सीमा सड़क महानिदेशक निर्दिष्ट क्षेत्रों में कार्यरत मुख्य अभियंताओं के माध्यम से सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) पर नियंत्रण रखते हैं। मुख्य अभियंता निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैंः–

(क) परियोजनाओं की विस्तृत योजना बनाना और अपनी वित्तीय शक्ति के तहत अनुमानों को मंजूरी प्रदान करना, यह सुनिश्चित करना कि स्वीकृत परियोजना अनुमान समय–समय पर निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार हों और डिज़ाइन ठोस व किफायती हों।

(ख) तकनीकी स्वीकृतियों के अनुसार स्वीकृत परियोजनाओं का उचित व शीघ्र निष्पादन करना तथा आवधिक निरीक्षण करना। वह यह सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी है कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना विनियमों, अनुमोदित विशिष्टताओं या उच्च प्राधिकारी के आदेशों से किसी भी प्रकार का विचलन न हो।

(ग) मानव संसाधन और उपस्करों में संसाधनों का किफायती उपयोग।

(घ) सरकार के सर्वोत्तम हित में उपलब्ध कराए गए धन का उपयोग करना।

(ङ) मुख्य अभियंता अपने नियंत्रण में आने वाली अधीनस्थ इकाइयों को उचित तकनीकी और प्रशासनिक निर्देश जारी कर सकता है। वह लोकल आर्मी और सिविल प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखेगा।

टास्क फोर्स कमांडर

मुख्य अभियंताओं के अधीन विभिन्न प्रकार की यूनिटों से बनी टास्क फोर्स तैनात की जाती है। इन टास्क फोर्स के कमांडरों को सौंपे गए कार्यों और रख–रखाव सेवाओं के निष्पादन के अलावा, नियमों और विनियमों का उचित पालन करने, आबंटित निधियों का कुशल और मितव्ययी प्रबंधन करने और विभिन्न प्रक्रियाओं में निर्धारित दस्तावेजों और अभिलेखों का उचित व अद्यतित रखरखाव सुनिश्चित करने का दायित्व भी होता है।

समारोह, शैक्षणिक उपलब्धियाँ और साहसिक गतिविधियां

बीआरओ, छः से भी अधिक दशकों से राष्ट्र को असाधारण सेवा प्रदान करता रहा है। पूर्व में टस्कर (अब वर्तक) और पश्चिम में बीकन जैसी दो परियोजनाओं से एक छोटी–सी शुरूआत करने के बाद, बीआरओ देशभर में फैली 17 परियोजनाओं सहित एक जीवंत संगठन बन गया है। समय के साथ, संगठन ने स्थायी कंक्रीट और स्टील पुल, आवासीय परियोजनाएं, बॉर्डर फेंसिंग, एयरफील्ड और सुरंग निर्माण जैसे विविध कार्य निष्पादित किए हैं और यह अपनी गति, गुणवत्ता और लागत प्रभावशीलता के लिए जाना जाता है। बीआरओ ने भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान और तज़ाकिस्तान में निर्माण कार्यों को निष्पादित करके मैत्रीपूर्ण संबंधों को और अधिक मजबूत किया है। आज की तारीख में, बीआरओ की मौजूदगी 11 राज्यों और तीन केन्द्र शासित प्रदेशों (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित) और भूटान में है।

रिकॉर्ड बजट व्यय

पिछले कुछ वर्षों में बीआरओ के बजट में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, वित्त वर्ष 2024–25 में ₹16,690 करोड़ का रिकॉर्ड खर्च हुआ और अगले वित्त वर्ष में ₹18,700 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, जो संगठन की संवर्धित क्षमता और जरूरी आधारभूत अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को बहुत तेजी से पूरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

आधारभूत अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का पूरा होना

12 अक्तूबर 2024 को, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने ₹2,243 करोड़ की 75 बीआरओ अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को वर्चुअली समर्पित किया। इनमें 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फैली 22 सड़कें, 51 पुल और दो विविध कार्य शामिल थे, जिनमें जम्मू व कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और दूसरे सीमावर्ती राज्यों में बड़ी परियोजनाएं शामिल थीं, जिससे इन रणनीतिक क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और सक्रियात्मक तैयारी को काफी बढ़ावा मिला।

माननीय रक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह 75 आधारभूत अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए एवं उन्हें राष्ट्र को समर्पित करते हुए

75 परियोजनाओं में से, सिक्किम में कुपुक–शेराथांग सड़क एक जरूरी लिंक है। यह रणनीतिक मार्ग जवाहर लाल नेहरू मार्ग, को जुलुक एक्सिस से जोड़ता है, जो कार्मिकों और मशीनरी के सुगम आवागमन हेतु एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। यह सड़क इस ऊंचाई वाले इलाके में बिना रुकावट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है।

एक अन्य उल्लेखनीय उपलब्धि अंडमान और निकोबार द्वीप–समूह में उत्तर–दक्षिण सड़क है, जो भारत के सबसे दक्षिणी सिरे इंदिरा पॉइंट से जुड़ती है। ये परियोजनाएं न सिर्फ विकास की दृष्टि से मील का पत्थर हैं, बल्कि भारत के सीमावर्ती और द्वीप–समूह क्षेत्रों की रणनीतिक अहमियत को भी दर्शाती हैं।

कुपुप–शेरथांग सड़क– सिक्किम

उत्तर–दक्षिण सड़क– अंडमान और निकोबार द्वीप–समूह

सड़कें

पिछले कुछ सालों में, बीआरओ ने देश के कुछ सबसे दुर्गम और दूर दराज के इलाकों में 63,000 कि.मी से ज़्यादा सड़कें बनाई हैं जिससे इन दुर्गम सीमावर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी काफी बेहतर हुई है। इन सड़कों ने न सिर्फ परिवहन को आसान बनाया है बल्कि रिवर्स माइग्रेशन के ज़रिए इलाके तक पहुंच और एकीकरण को भी सुदृढ़ किया है। दूरदराज और मुश्किल जगहों को जोड़ने वाली रणनीतिक अहमियत वाली सड़कें, जैसे– संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में तांगत्से लुकुंग–सड़क, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर खरबर–देवसर सड़क जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में प्रशिक्षण गतिविधि में मदद करती है एवं आदि कैलाश यात्रा को आसान बनाने के लिए गुंजी–कुट्टी–जोलिंगकोंग सड़क खास तौर पर उल्लेखनीय हैं।

बीआरओ ने द्रास–उम्बा ला–सांकू सड़क पर ऊंचाई पर कम तापमान में बिटुमिनस मिक्स बिछाकर रेजुपेव प्रौद्योगिकी के सफल परीक्षण भी किए। इस प्रौद्योगिकी के सफल क्रियान्वयन ने सड़क बनाने की भावी परियोजनाओं के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया है जिससे ऐसे ही ऊंचाई वाले इलाकों में ज्यादा स्थायित्व और लचीलापन प्राप्त होगा।

द्रास–उम्बा ला–सांकू सड़क पर रेजुपेव

राजस्थान में खरबरा–देवसर सड़क

तांगत्से– लुकुंग सड़क पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील तक कनेक्टिविटी को काफी बेहतर बनाती है। रिफ्लेक्टिव मार्किंग, क्रैश बैरियर्स, गार्डरेल, एलईडी लाइटिंग और चौड़े ट्रक ले– बाय जैसी आधुनिक सुरक्षा विशेषताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के हिसाब से बनी इस सड़क ने यात्रा का समय 60 मिनट से घटाकर सिर्फ 35 मिनट कर दिया है। यह सड़क पर्यटन को बढ़ावा देती है, लोकल बाजारों, स्वास्थ्य केन्द्रों और शिक्षा तक स्थानीय पहुंच को बेहतर बनाती है और इसका रणनीतिक महत्व है।

लद्दाख में तांगत्से–लुकुंग सड़क

गुंजी–कुट्टी–जोलिंगकोंग सड़क

दिसंबर 2024 में पूरी हुई यह 36 कि.मी की गुंजी–कुट्टी–जोलिंगकोंग सड़क, धर्मा और व्यास घाटियों के बीच आवाजाही को बेहतर बनाती है, जिससे ज़रूरी लैटरल कनेक्टिविटी मिलती है। वर्ष 2018 में सामना की गई ज़्यादा ऊंचाई वाली चुनौतियों और बर्फीले तूफान वाले इलाकों के बावजूद, सतर्कतापूर्ण योजना बनाने और संसाधनों का सही इस्तेमाल करके कनेक्टिविटी हासिल की गई, जिससे अब आदि कैलाश यात्रा आसान हो गई है।

पुल

आज तक, बीआरओ ने देश के कुछ सबसे दुर्गम और दूर–दराज के इलाकों में 1,056 प्रमुख स्थानीय पुल बनाए हैं, जिनकी कुल लंबाई 72,825 मीटर है। इन पुलों ने कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया है, जिससे इन इलाकों का सामाजिक–आर्थिक विकास आसान हुआ है। इस साल बने कुल 51 पुलों में से, लॉन्गतलाई–डिल्टलांग–परवा रोड पर नेंगपुइलुई नदी पर बना 125 मी. डबल स्पैन स्टील सुपरस्ट्रक्चर नेंगपुइलुई पुल और तीस्ता नदी पर बना 300 फुट का बेली सस्पेंशन पुल इंद्राणी उल्लेखनीय हैं। नेंगपुइलुई पुल 70आर लोड क्लासिफिकेशन के साथ ज़रूरी कनेक्टिविटी देता है, जिससे भारी गाड़ियों और उपस्करों का आना–जाना आसान हो जाता है। सिक्किम में इंद्राणी पुल का औपचारिक उद्घाटन सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) ने 12 अगस्त 2024 को किया था, जो सिंगथम (पूर्वी सिक्किम) और नामची के बीच सीधा कनेक्शन देता है, जिससे स्थानीय समुदायों को काफी राहत और बेहतर कनेक्टिविटी मिलती है।

सिक्किम में इंद्राणी पुल

मिजोरम में नेंगपुइलुई पुल

सुरंगे

बीआरओ ने पहले ही छह सुरंगे बना ली हैं जिससे दूर–दराज और रणनीतिक इलाकों में साल भर कनेक्टिविटी काफी बेहतर हुई है। इंजीनियरिंग के इन अजूबों से न सिर्फ आनेजाने का समय कम हुआ बल्कि ज़रूरी रास्तों पर ऑपरेशनल कुशलता भी बढ़ी है। इनसे उन इलाकों तक पहुंच मजबूत हुई है जो पहले सर्दियों में कट ऑफ रहते थे जिससे पूरे साल लोगों और सामान का आवागमन आसान हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री ने 26 जुलाई 2024 को द्रास से शिंखुन ला सुरंग परियोजना का पहला वर्चुअल विस्फोट किया। 4.10 कि.मी. लंबी शिंखुन ला सुरंग परियोजना बहुत रणनीतिक और सामाजिक–आर्थिक महत्व रखती है। पूरा होने पर, यह 15800 फुट पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। यह लद्दाख को हर मौसम में ज़रूरी कनेक्टिविटी देगी, जिससे लद्दाख तक पहुंचने के लिए एक भरोसेमंद तीसरा एक्सिस बनेगा।

शिंखुन ला में माननीय प्रधानमंत्री

भीमबेर गली सुरंग का प्रारंभिक विस्फोट द्वारा उद्घाटन के तौर पर पहला विस्फोट

इसके अलावा, अखनूर–पुंछ सड़क पर तीन निर्माणाधीन सुरंगें सुंगल, नौशेरा और कंडी में महत्वपूर्ण ब्रेकथ्रू प्राप्त किया गया है, कंडी और नौशेरा सुरंग का काम पूरा होने के आखिरी चरण में है। भीमबेर गली सुरंग पर भी काम शुरू हो गया है, जिसका पहला विस्फोट 03 मार्च 2025 को किया गया था। कुल मिलाकर 4.85 कि.मी. लंबी ये सुरंगें आगे के इलाकों में तैनात सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों को काफी फायदा पहुंचाएंगी, क्योंकि इनसे यात्रा की दूरी और समय कम होगा, और मुश्किल पहाड़ी इलाकों से भी बचा जा सकेगा।

एयरफील्ड

अब तक बीआरओ ने देश में 21 एयरफील्ड बनाए/ठीक किए हैं। बीआरओ, पूर्वी लद्दाख में 13,710 फुट की ऊंचाई पर मुध–न्योमा में एक एयरफील्ड बना रहा है। 2.743कि.मी लंबा रनवे परियोजना पूरा होने के आखिरी चरण में है। मुध–न्योमा एयरफील्ड से एयर मोबिलिटी बढ़ेगी और सशस्त्र बलों की त्वरित तैनाती होगी जो अलग–अलग एयर ऑपरेशन्स के लिए एक फॉर्वर्ड स्टेजिंग एरिया के तौर पर काम करेगा।

मुध–न्योमा एयरफील्ड

एचएडीआर ऑपरेशन

कनेक्टिविटी बढ़ाने के अतिरिक्त, बीआरओ आपदा राहत कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, विशेषतया प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में। चाहे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी पुलों का निर्माण हो या बर्फ से ढकी सड़कों को साफ करना हो, हमारी टीमों ने निरंतर लचीलेपन और समर्पण का परिचय दिया है।

30 मार्च 2025 को, बीआरओ के लोगों ने पूर्वी लद्दाख में चांगला एक्सिस पर बर्फीले तूफान और स्खलन की वजह से 17,500 फुट पर फंसे 100 से ज़्यादा आम लोगों और 50 वाहनों को तेज़ी से बचाया।

पूर्वी लद्दाख में चांगला एक्सिस पर बचाव अभियान

उत्तरी सिक्किम (मई–जून 2024) में अचानक आई बाढ़ के दौरान, लाचेन इलाके में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसमें छह पुल और 15 कि.मी. ज़रूरी सड़कें बह गईं, जिससे स्थानीय लोग और पर्यटक उस क्षेत्र में फंस गए। बीआरओ ने नुकसान का अंदाज़ा लगाने, 800 से ज़्यादा पर्यटकों को बचाने और लॉजिस्टिक मदद जैसे ज़रूरी काम किए। कनेक्टिविटी ठीक करने के लिए गंगटोक–चुंगथांग सड़क पर मरम्मत कार्य पूरा किया गया, जिसमें अल्टरनेट अलाइनमेंट कंस्ट्रक्शन (90–90.780कि.मी.), वेंटेड कॉज़वे, सॉसेज रिटेनिंग स्ट्रक्चर और चुंगथांग में 190 फुट का बेली पुल शामिल है।

सम्मान, पुरस्कार और विविध

एएसएसओसीएचएएम अचीवर्स पुरस्कार– बीआरओ को 17 दिसंबर 2024 को रणनीतिक महत्वपूर्ण परियोजना श्रेणी में सेला सुरंग परियोजना के लिए एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स (एएसएसओसीएचएएम) अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया है।

सेला सुरंग परियोजना के लिए बीआरओ को एसोचैम अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया

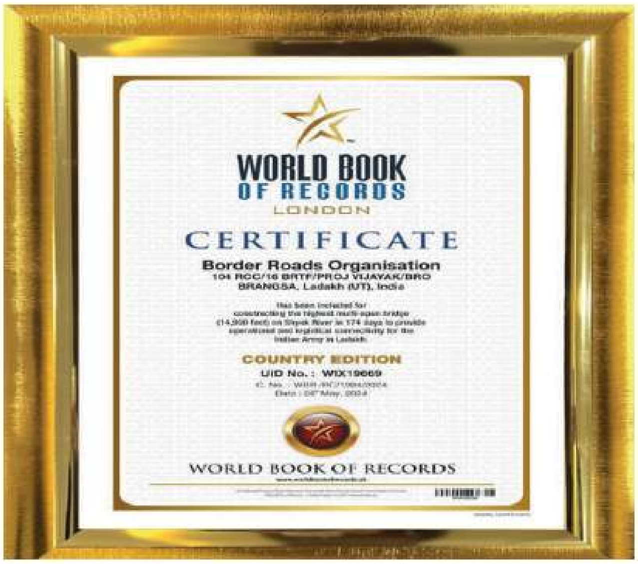

वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन ने ब्रांग्सा पुल को दुनिया के सबसे ऊंचे मल्टी–स्पैन पुल के तौर पर मान्यता प्रदान की है।

श्रेष्ठता का प्रमाणपत्र– 24 फरवरी 2025 को माननीय सड़क परिवहन व राजमार्ग और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा ने सेला सुरंग परियोजना के लिए बीआरओ को 'सड़कों और राजमार्गों में इंपैक्ट श्रेणी' के लिए बिल्ड इंडिया इंफ्रा पुरस्कार दिया।

वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन– 08 मई 2024 को, श्योक नदी पर बने ब्रांगसा पुल को वर्ल्ड बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स, लंदन ने दुनिया के सबसे ऊंचे मल्टी–स्पैन पुल के तौर पर मान्यता प्रदान की थी। बीआरओ ने इसे सिर्फ़ 174 दिनों में 14,900 फुट की ऊंचाई पर बनाया है, जो लद्दाख में ज़रूरी रणनीतिक कनेक्टिविटी देता है।

अकादमिक गतिविधियाँ

प्रशासनिक/तकनीकी पाठ्यक्रमः बीआरओ के लगभग 1260 कार्मिकों ने वर्ष 2024–25 के दौरान अनेक सिविल/सरकारी संस्थानों, बीआरओ स्कूल एवं केंद्र और राजमार्ग अभियांत्रिकी संकाय में विभिन्न प्रशासनिक, तकनीकी और प्रबंधन पाठ्यक्रमों में भाग लिया।

एएससीआई, हैदराबाद में भूमि अधिग्रहण संबंधी पाठ्यक्रमः 27 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई), हैदराबाद में लैंड एक्विजीशन एवॉयडिंग कॉस्टली मिस्टेक्स से बचने पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 43 बीआरओ अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिसने आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं में अतिव्यय का कारण बनने वाली गलतियों से बचाव के लिए प्रभावशाली भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और रणनीति संबंधी उनकी समझ को बढ़ाया।

निष्कर्ष

बीआरओ द्वारा की गई पहल और कार्यों की गुणवत्ता इसकी सुदृढ़ संगठनात्मक प्रकृति और समर्पित कार्य संस्कृति को दर्शाती है। बीआरओ उत्कृष्ट काम करने, तकनीकी ज़रूरतों को पूरा करने और अपने आदर्श वाक्य **''श्रमेण सर्वं साध्यम्''** पर कायम है। सीमाओं पर उभरती नई और अलग–अलग चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार, बीआरओ लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है ताकि सबको साथ लेकर चलने वाले क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया जा सके, और रणनीतिक आधारभूत अवसंरचनात्मक विकास के लिए देश की **पसंदीदा एजेंसी** के तौर पर अपनी स्थिति पुख्ता करने हेतु तत्पर है।

*****

भारतीय तटरक्षक

वर्ष 1977 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय नौसेना के 2 जहाजों और 05 नौकाओं एक्स–कस्टम्स की बेड़ा नफरी के साथ 'तटरक्षक बल' की स्थापना को मंजूरी दी। परिणामस्वरूप भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) को औपचारिक रूप से संसद द्वारा पारित तटरक्षक अधिनियम, 1978 द्वारा 18 अगस्त, 1978 को संघ के एक सशस्त्र बल के रूप में स्थापित किया गया था। भारतीय तटरक्षक बल, रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

तटरक्षक संगठन का नेतृत्व भारतीय तटरक्षक महानिदेशक (डीजीआईसीजी) करते हैं जो नई दिल्ली में स्थित तटरक्षक मुख्यालय (सीजीएचक्यू) से अपनी समग्र कमान और अधीक्षण का प्रयोग करते हैं। प्रभावी कमान और नियंत्रण के लिए, भारत के समुद्री क्षेत्रों को गांधीनगर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और श्रीविजयपुरम में एक क्षेत्रीय मुख्यालय के साथ पांच तटरक्षक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

इन क्षेत्रों को आगे 16 तटरक्षक जिलों में विभाजित किया गया है, जो मुख्य भूमि पर 9 तटीय राज्यों और 2 संघ राज्यक्षेत्रों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में 2 संघ राज्यक्षेत्रों से जुड़े समुद्र तट और समुद्री क्षेत्रों को कवर करते हैं। इसके अलावा, तटरक्षक जिला मुख्यालय के अधीन 42 तटरक्षक स्टेशन काम कर रहे हैं। तटरक्षक के हवाई प्रचालन के लिए 11 तटरक्षक एयर स्टेशन और एयर एन्क्लेव उत्तरदायी हैं।

कर्तव्य एवं कार्य

तटरक्षक अधिनियम, 1978 में व्यापक रूप से उल्लिखित तटरक्षक बल के कर्तव्य एवं कार्य भारत के समुद्री क्षेत्रों में भारत के समुद्री और अन्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। भारतीय तटरक्षक बल को भू भागीय समुद्रों में तटीय सुरक्षा, प्रवर्तन, गहरे समुद्र में मत्स्यन पर नज़र और निगरानी, समुद्री खोज और बचाव, समुद्री तेल रिसाव से निपटने संबंधी उपाय जैसे अतिरिक्त उत्तरदायित्व भी सौपे गए हैं। यह तटीय और समुद्री सीमाओं के लिए प्रमुख आसूचना खुफिया एजेंसी भी है।

संक्रिया संबंधी विशेष तथ्य (वर्ष 2009 से)

- प्रभावी समन्वित गश्त सुनिश्चित करने और मानक प्रचालन कार्यविधि के प्रमाणन के लिए भारतीय नौसेना और समुद्री पुलिस के साथ 288 तटीय सुरक्षा अभ्यास किए गए।
- हितधारकों के साथ समन्वय से 593 तटीय सुरक्षा अभियान चलाए गए।
- मछुआरों के पहचान पत्र सहित मछली पकड़ने वाली नौकाओं के दस्तावेजों की जांच के लिए 472 सजग अभियान सम्पन्न किए गए (प्रत्येक क्षेत्र में मासिक विशेष अभियान)।
- 3,59,466 बोर्डिंग अभियान चलाए गए (वर्ष 2024 में 27,520 अभियानों सहित);
- सुरक्षा और बचाव के मुद्दों पर मछुआरों को संवेदनशील बनाने के लिए आईसीजी द्वारा 15,326 समुदायिक भागीदारी कार्यक्रम (वर्ष 2024 में 2,085 कार्यक्रम सहित) आयोजित किए गए।
- संयुक्त तटीय गश्त (जेसीपी) कार्यक्रमः अगस्त, 2020 में शुरू की गई जेसीपी पहल ने तटीय पुलिस के साथ वर्ष 2024 में 1,283 यात्रा की। समग्र कार्यक्रम के आंकड़ों में 3,645 समुद्री यात्रा, 2,579 प्रशिक्षण सत्र और स्थापना के बाद से 8,666 कर्मी भर्ती करना शामिल हैं।

महत्वपूर्ण लक्ष्य एवं उपलब्धियां

सागर द्वीप, पश्चिम बंगाल के बाहर यात्री बेड़ा स्वास्थ्य साथी का तट पर आगमन : 16 जनवरी 2024 को, आई. सी. जी. एयर कुशन व्हीकल (एसीवी) एच–182, एच–186 और एच–188 को सागर द्वीप और हल्दिया से लॉन्च किया गया था, ताकि पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप के उत्तर–पूर्व में 12 एनएम की स्थिति में लगभग 400 तीर्थयात्रियों के साथ बेड़े एमवी स्वास्थ्य साथी को तट पर आगमन हेतु सहायता प्रदान की जा सके।

केरल के वायनाड में लैंड स्लाइड के दौरान राहत और बचाव कार्य : 30 जुलाई, 2024 को आईसीजी ने केरल के वायनाड जिले के मेप्पडी गांव में भारी भूस्खलन के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए **'ऑपरेशन सहायता 02/24'** शुरू किया। आई. सी. जी. एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मेक–III और आपदा राहत दलों (डीआरटी) ने फंसे हुए व्यक्तियों की तलाश करने और बचाकर वापस लाने/शवों की बरामदगी में सहायता की। इसके अतिरिक्त, आईसीजी टीमों ने प्रभावित क्षेत्रों में जीवन रक्षक उपकरण, राहत भंडार/सामग्री, दवाएं और ताजा पानी भी वितरित किया।

क्षेत्रीय समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र (आरएमपीआरसी) का उद्घाटन : आरएमपीआरसी का उद्घाटन 18 अगस्त, 2024 को चेन्नई में माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया था। इस केंद्र की परिकल्पना पीआर प्रशिक्षण, डेटा के भंडार और प्रदूषण प्रतिक्रिया से संबंधित मामले के अध्ययन और समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (एमआरसीसी) के समान संपर्क के नोडल बिंदु के संदर्भ में एक "उत्कृष्टता का केंद्र" बनने के तौर पर की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस–2024 : भारत सरकार के प्रयासों से **'स्वच्छ भारत अभियान'** और **'स्वच्छता ही सेवा'** के माध्यम से बड़े पैमाने पर स्वच्छता और साफ–सफाई अभियान के लिए माननीय प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप, भारतीय तटरक्षक बल ने 21 सितंबर, 2024 को सभी तटीय राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस–2024 (आईसीसी–2024) का आयोजन किया। आई.सी.सी.–2024 राष्ट्रव्यापी अभियान में कुल **27,563 स्वयंसेवकों** ने भाग लिया और **61,248 किलोग्राम** प्लास्टिक और कचरा एकत्र किया।

तटरक्षक कमांडरों का सम्मेलन : तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली में 41वां भारतीय तटरक्षक कमांडरों का सम्मेलन 24 सितंबर, 2024 और 26 सितंबर, 2024 के बीच आयोजित किया गया था। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सम्मेलन का उद्‌घाटन किया। सम्मेलन में रणनीतिक उद्देश्यों, सक्रियात्मक तैयारी और उभरती समुद्री चुनौतियों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

समुद्री खोज और बचाव उपलब्धियाँ : आईसीजी ने वर्ष 2024 में 199 अभियानों के दौरान 169 लोगों की जान बचाई। आपात स्थिति में मछुआरों और नाविकों को समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करके 29 चिकित्सा निकासियां की गई। इसके अतिरिक्त, नियमित समुद्री खोज और बचाव कार्यशाला (वर्ष 2024 में 15) और मछुआरों के साथ सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें खोज और बचाव (एसएआर) और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला गया।

खोज और बचाव अभ्यास (एसएआरईएक्स)–24 : 29 नवंबर, 2024 को एसएआरईएक्स–24 के अधीन समुद्री अभ्यास कोच्चि में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में समुद्र में एक सामूहिक बचाव अभियान शामिल था। एसएआरईएक्स वैश्विक समुद्री सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों के साथ भारत की साझेदारी को उजागर करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

श्रीलंका तटरक्षक बल को कलपुर्जों का हस्तांतरण : 9 करोड़ 26 लाख रुपये मूल्य के 891 अतिरिक्त कलपुर्जे पूर्व–विक्रम श्रेणी अपतटीय पोत जून, 2024 को श्रीलंका सरकार को **'निःशुल्क आधार'** पर हस्तांतरित किए गए हैं।

समुद्री निगरानी की दिशा में वर्धित उड़ान प्रयास : भारतीय तटरक्षक बल ने हवाई दल, हवाई परिसंपत्तियाँ और अन्य संसाधनों के इष्टतम नियोजन के अलावा नए अत्याधुनिक विमानों को शामिल करके हवाई समुद्री निगरानी पर अधिक ध्यान देने के साथ अपने उड़ान प्रयासों को बढ़ाया है। वर्ष 2024 के दौरान, भारतीय तटरक्षक विमानों द्वारा कुल **27271 घंटे** की उड़ान की गई है।

सीजीएई पुडुच्चेरी को चालू करना : कोस्ट गार्ड एयर एन्क्लेव (सीजीएई) पुडुच्चेरी का उद्‌घाटन 18 अगस्त, 2024 को माननीय रक्षा मंत्री द्वारा किया गया। 848 स्क्वाड्रन (सीजी) को 30 दिसंबर, 2024 से चेन्नई से पुडुच्चेरी हस्तांतरण कर दिया गया है।

अप्रचलन प्रबंधन : अप्रचलन को दूर करने और उड़ान सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, अन्य पूंजीगत अधिप्राप्ति प्रक्रिया (ओसीपीपी) अधीन परिशोधन के द्वारा नवीनतम अत्याधुनिक प्रणालियों/उपस्कर के साथ प्रणालियों/उपकरणों को उन्नत किया जा रहा है। आईसीजी डोर्नियर पर कुल 13 प्रणालियों और आईसीजी चेतक पर 05 प्रणालियों का उन्नयन चल रहा है।

प्रमुख नीतिगत निर्णय

पूर्व अग्निवीरों का समावेशन : भारत सरकार की दूरदर्शी अग्निपथ योजना के अनुरूप, भारतीय तटरक्षक बल वर्ष 2027 से अपने रैंकों में अग्निवीरों को शामिल करने की तत्परतापूर्वक तैयारी कर रहा है। यह हमारी सेना के लिए एक नए युग की शुरूआत करेगा, क्योंकि हम युवा, गतिशील, बहुआयामी प्रतिभा को उमंग और उत्साह के साथ अपना रहे हैं। आईसीजी, सावधानीपूर्वक नियोजित प्रशिक्षण मॉड्यूल और सशक्त कैरियर संवर्धन ढांचे के द्वारा हमारे कार्यबल में अग्निवीरों का निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारतीय निजी उद्योग की ज्यादा सहभागिता : उद्योग का ध्यान आकर्षित करने के लिए सृजन प्रतिरक्षा पोर्टल पर कुल 264 आयातित पुर्जों को अपलोड किया गया है। अधिकांश पुर्जे स्वामित्व प्रकृति के हैं जिनका वर्तमान में आयात किया जा रहा है। आईसीजी ने एफओईएम के साथ कार्य किया है और सक्षम भारतीय उद्योगों की सहभागिता के साथ मेक–इन–इंडिया के तहत पुर्जों/पुर्जों के स्थानीयकरण/स्वदेशीकरण के लिए प्रोत्साहित किया है। एफओईएमएस द्वारा स्थानीयकरण की योजना पर ध्यानपूर्वक विचार–विमर्श और नियमित पुनर्विलोकन के साथ, एफओईएमएस स्वदेशीकरण के साथ संयुक्त रूप से 101 कलपुर्जों के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है।

आईसीजी वर्ष 2024 में, एनएमआरएल के द्वारा एफपीवी (कामेवा वाटरजेट) पर उपयोग किए जाने वाले परिवर्तनीय एनोड के स्वदेशीकरण में सफल रहा है। वर्तमान में आयात किए जा रहे आरओ पादप झिल्ली का स्वदेशीकरण भी डीएमएसआरडीई/डीआरडीओ के साथ सहभागिता में प्राप्त किया गया है और प्रोटोटाइप परीक्षण संतोषजनक रहा है। डीआरडीओ द्वारा टीओटी प्रदान किए जाने के बाद पूर्ण पैमाने पर स्वदेशी उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा, एसीवी स्कर्ट घटकों (विशेष रबर) और एक्स–बैंड रडार (ठोस अवस्था) के स्वदेशीकरण प्रस्ताव क्रमशः जीआईएल, कानपुर (डीपीएसयू) और एलआरडीई, बैंगलूरू के साथ संयुक्त रूप से तकनीकी विनिर्देशों को अंतिम रूप देने के उन्नत चरण में हैं।

एचएलएम और द्विपक्षीय बैठकें

वर्तमान में आईसीजी के 09 देशों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)/सहयोग ज्ञापन (एमओसी) है और इन समझौता ज्ञापनों/एमओसी के दायरे में सालाना उच्च स्तरीय बैठकें और द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की जाती हैं। उक्त अवधि के लिए एचएलएम और द्विपक्षीय बैठकों का ब्योरा इस प्रकार हैः–

आईसीजी–जापान तटरक्षक (जेसीजी) द्विपक्षीय बैठक : जेसीजी की ओर से चार सदस्यीय जापान तटरक्षक प्रतिनिधि मंडल ने 10 जनवरी, 2024 को सीजीएचक्यू, नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया (जहां भारतीय तटरक्षक बल और जापान तटरक्षक बल के बीच सहयोग ज्ञापन (एमओसी) के प्रावधानों के अनुसार समुद्री सुरक्षा और संरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की गई)।

5वीं आईसीजी–वियतनाम तटरक्षक (वीसीजी) उच्च–स्तरीय बैठकें (एचएलएम) : छह सदस्यी वीसीजी प्रतिनिधिमंडल ने 20 फरवरी, 2024 को 5वीं आईसीजी–वीसीजी उच्च स्तरीय बैठक के लिए तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली का दौरा किया। बैठक के दौरान, दोनों पक्ष समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार आपसी सहयोग को सशक्त करने पर सहमत हुए और नियमित उच्च–स्तरीय बैठकों और जहाज यात्राओं की निरंतरता को बढ़ावा देकर सहकारी भागीदारी को प्रोत्साहन देने पर भी सहमत हुए।

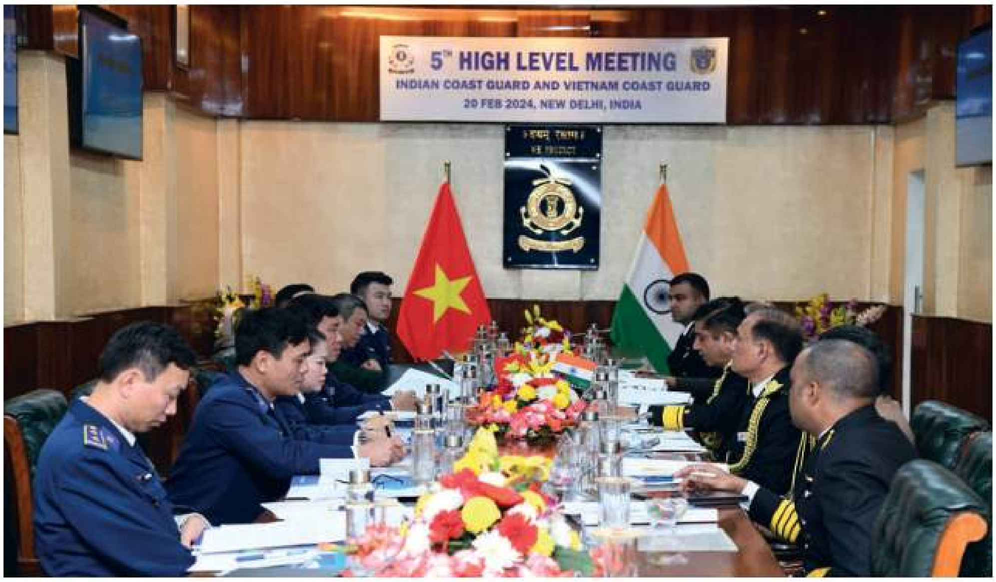

5वीं आईसीजी–आरओपीसीजी एचएलएम : चार सदस्यी रॉयल ओमान पुलिस तटरक्षक प्रतिनिधि मंडल (आरओपीसीजी) ने अप्रैल, 2024 से भारत का दौरा किया और समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के तहत 5वें आईसीजी–आरओपीसीजी एचएलएम में भाग लिया। यात्रा के दौरान, आरओपीसीजी के प्रतिनिधिमंडल ने 25 अप्रैल, 2024 को नई दिल्ली में भारतीय प्रतिरक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) जैसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल), मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) और लार्सन एंड टर्बो (एलएंडटी) शिपबिल्डिंग के साथ बातचीत की, जिसमें 'आत्मनिर्भर भारत' के अधीन भारत के प्रतिरक्षा उद्योग क्षमताओं पर प्रकाश डाला गया।

12वीं आईसीजी–कोरिया तटरक्षक (केसीजी) एचएलएम : आईसीजी–केसीजी 12वीं उच्च स्तरीय बैठक, (एचएलएम) 4 सितंबर, 2024 को 20वें एचएसीजीएएम के अवसर पर दक्षिण कोरिया के इंचियोन में आयोजित की गई।

7वां आईसीजी–एसएलसीजी एचएलएम : समझौता ज्ञापन के प्रावधान के अनुसार आईसीजी–एस एलसीजीएचएलएम का 7वां संस्करण नवंबर, 2024 से कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित किया गया था।

आईसीजी–पीसीजी द्वीपक्षीय बैठक : फ़िलिपींस तटरक्षक बल के चार सदस्यी उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 08–12 नवंबर, 2024 तक भारत का दौरा किया और एमओयू के प्रावधान के अधीन आईसीजी–पीसीजी द्विपक्षीय बैठक, में भाग लिया।

संयुक्त द्विपक्षीय/बहुपक्षीय अभ्यास/समारोह

सहयोग कैजिन अभ्यास : जापान तटरक्षक जहाज याशिमा ने 10–14 जनवरी 2024 तक भारत का दौरा किया और 12 जनवरी, 2024 को चेन्नई में आईसीजी–जेसीजी के बीच एक संयुक्त अभ्यास "सहयोग कैजिन" में भाग लिया।

अभ्यास सी डिफेंडर–2024 : यूएससीजी कटर बर्थोल्फ ने आईसीजी के साथ, वृत्तिक चर्चा हेतु मार्च 07–10,2024 तक श्रीविजयपुरम में एक पोर्ट कॉल किया।

11वां खोज और बचाव अभ्यास (एसएआरईएक्स) : आईसीजी ने 27–30 नवंबर, 2024 कोच्चि, केरल में 28 एफएफसी और दो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (बिम्सटेक और आईओआरए) के 38 पर्यवेक्षकों की सहभागिता के साथ 11वें एसएआरईएक्स का आयोजन किया।

अभ्यास सहयोग हॉप टेक–24 : वियतनाम तटरक्षक जहाज सीएसबी 8005 ने 16–20 दिसंबर 2024 से कोच्चि का दौरा किया। पहले दो दिनों के लिए एमपीआर और एम–एसएआर पर व्याख्यान/प्रशिक्षण, जहाजों पर निर्देशित यात्रा, खेल जुड़ाव और समुदाय सहायता गतिविधियों सहित व्यावसायिक बातचीत की गई।

सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएं

सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएं (एएफएमएस) रक्षा कार्मिकों और उनके आश्रितों को समर्पित, भरोसेमंद और व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करती हैं। फील्ड में तैनात अर्द्ध सैन्य संगठनों और देश के अशांत व सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यरत केन्द्रीय पुलिस/खुफिया संगठनों और जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स (जीआरईएफ) यूनिटों के कार्मिकों को भी चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को भी देश के अंदर चिकित्सा संबंधी सेवा प्रदान की जाती है। प्राकृतिक आपदाओं, विपत्तियों के समय तथा सक्रियात्मक क्षेत्रों में यह नागरिक आबादी को भी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती हैं।

एएफएमएस में सेना, नौसेना और वायु सेना की चिकित्सीय सेवाएं शामिल हैं जो महानिदेशक, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएं (डीजीएएफएमएस) के अधीन कार्यरत हैं। डीजीएएफएमएस सशस्त्र बलों से संबंधित समग्र चिकित्सा नीतिगत मामलों के लिए प्रत्यक्ष तौर पर रक्षा मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी हैं। सेना, नौसेना और वायु सेना के चिकित्सा सेवा प्रमुख, डीजीएएफएमएस द्वारा दिए गए सामान्य नीतिगत निर्देशों के अनुसार संबंधित सेना प्रमुखों के अधीन इन सेवाओं के कामकाज के लिए उत्तरदायी हैं और वे अपनी संबंधित सेनाओं के चिकित्सा सलाहकार हैं। इसके अलावा, डीजीएएफएमएस, अस्पताल सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस), राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (एनएएमएस), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और भारत व विदेश में स्थित रक्षा सेवाओं के बाहर अन्य निकायों और शोध संस्थानों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में एएमसी (एनटी) सहित सेना चिकित्सा कोर (एएमसी), सेना दंत चिकित्सा कोर (एडी कोर) तथा सैन्य नर्सिंग सेवा (एमएनएस) शामिल हैं।

सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज (एएफएमसी), पुणे

रेडियोलॉजी विभाग में एक डिजिटल मैमोग्राफी केंद्र का उद्घाटन: रेडियोलॉजी विभाग में एक डिजिटल मैमोग्राफी केंद्र का उद्घाटन सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन, एवीएसएम, वीएसएम, डीजीएएफएमएस द्वारा 8 नवंबर, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस पर किया गया, जो नैदानिक इमेजिंग क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है। यह केंद्र अत्याधुनिक डिजिटल मैमोग्राफी मशीन से सुसज्जित है।

नए विभाग

स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन (एचटीए) संसाधन केंद्रः एएफएमसी, पुणे में एचटीए संसाधन केंद्र का उद्‌घाटन किया गया है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारत में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन (एचटीएआईएन) के तकनीकी भागीदार के रूप में, यह केंद्र स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों की उपयुक्तता और लागत–प्रभावशीलता का मूल्यांकन करेगा और सुविचारित स्वास्थ्य नीति निर्णयों में सहायता करेगा।

जीनोम सीक्वेंसिंग प्रयोगशालाः एएफएमसी में नई जीनोम सीक्वेंसिंग प्रयोगशाला का उद्‌घाटन 27 जून, 2024 को हुआ। नई प्रयोगशाला में अत्याधुनिक नेक्स्ट जेनरेशन सीक्वेंसिंग (एनजीएस) सुविधाओं में परिष्कृत "नेक्स्टसेक 2000" और "मिनिसेक" विश्लेषक शामिल हैं। आनुवंशिक रोगों, ऑन्कोलॉजी, प्रत्यारोपण चिकित्सा और प्रजनन चिकित्सा सहित कई स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में एन जी एस तकनीक का व्यापक उपयोग हुआ है।

नवाचार और एकीकृत स्टार्टअप

रोबोट समर्थित संपूर्ण घुटना प्रतिस्थापनः ऑर्थोपेडिक्स विभाग ने 12 जून, 2024 को सफलतापूर्वक रोबोट–समर्थित संपूर्ण घुटना प्रतिस्थापन किया। रोबोट समर्थित टीकेआर ऑर्थोपेडिक सर्जरी में एक महत्वपूर्ण उन्नति को दर्शाता है और रोबोटिक्स की सटीकता को कुशल सर्जनों की विशेषज्ञता के साथ मिलाकर घुटने के जोड़ के प्रतिस्थापन के लिए देखभाल के मानक को पुनर्परिभाषित करता है।

पैथोलॉजी लैब में निदान के लिए एआई मॉडलः लेफ्टिनेंट कर्नल परीक्षित सान्याल ने स्पूटम स्मीयर से ट्यूबरकुलोसिस बेसिली की जांच, मलेरिया पैरासाइट स्क्रीनिंग, साइटोलॉजी स्क्रीनिंग मॉड्यूल, हायर डाइमेंशनल फ्लो साइटोमेट्री एनालाइज़र और साइटोजेनेटिक्स एनालिसिस के लिए फोटोमाइक्रोग्राफी उपकरण के लिए एआई मॉडल विकसित किए हैं।

उपलब्धियां

यूनिट प्रशस्ति–पत्रः चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने 18 मार्च, 2024 को वर्ष 2022–23 के लिए सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज, पुणे को यूनिट प्रशस्ति–पत्र प्रदान किया।

कृत्रिम अंग केंद्र (एएलसी), पुणे

पैरालंपिक और पैरा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले दिव्यांग सैनिकों के लिए अत्याधुनिक कृत्रिम अंग प्रदान करना: एएलसी दिव्यांग सैनिकों के लिए अत्याधुनिक खेल कृत्रिम अंग उपकरण प्रदान करने में अग्रणी है। पिछले 10 वर्षों में 80 सेवारत कार्मिकों को खेल कृत्रिम अंग और उनके पुर्जे प्रदान किए गए हैं। इन सैनिकों ने पैरालंपिक खेलों सहित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लिया है और विभिन्न पदक जीते हैं और भारतीय ध्वज को गौरवान्वित किया है। ये खेल कृत्रिम अंग सेना खेल विकास कोष (एएसडीएफ) से प्रदान किए जाते हैं, जो विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए आवंटित गिया गया है। पेरिस में 2024 के पैरा ओलंपिक में, एएलसी द्वारा सुसज्जित सैनिकों और उनके आश्रितों ने 3 खेल प्रतिस्पर्धाओं में 3 पदक जीते।

इनोवेशन फीनिक्स: हायर एक्टिविटी लेवल डायनेमिक फुट: "फीनिक्स फुट" एक उन्नत कृत्रिम पैर है जो एम्प्यूटी को टखने की बेहतर गतिशीलता प्रदान करता है, जिसे लेफ्टिनेंट कर्नल जीपी रेड्डी (प्रोस्थेटिक सर्जन, एएलसी), श्री गुरविंदर ख्एएलसी रोगी एच/लेफ्टिनेंट गुरबचन (सेवानिवृत्त) के पुत्र, और एएलसी टीम द्वारा विकसित किया गया है। इसे 5 दिसंबर, 2024 को दिल्ली कैंट स्थित मानेकशॉ सेंटर में आयोजित वार्षिक नवाचार प्रतियोगिता "इनो–योद्धा 2024–25" और "विचार एवं नवाचार संगोष्ठी" में प्रदर्शित किया गया और इसे गणमान्य व्यक्तियों से अत्यधिक प्रशंसा प्राप्त हुई। श्री गुरविंदर को "सीओएएस प्रशस्ति पत्र" से सम्मानित किया गया।

कृत्रिम अंग फिटमेंट शिविर म्यांमार: सात सदस्यीय भारतीय टीम ने म्यांमार के यंगून स्थित रक्षा सेवा पुनर्वास अस्पताल में दो सप्ताह का कृत्रिम अंग शिविर आयोजित किया, जिसका उद्देश्य 50 एम्प्यूटीज को के2/के3 स्तर के कृत्रिम अंग प्रदान करना था। सीमित स्थानीय बुनियादी ढांचे के बावजूद, 10 दिनों में 50 कृत्रिम अंग तैयार किए गए। पैरालिंपियनों के साथ बातचीत में के4 खेल कृत्रिम अंगों की आवश्यकता के बारे में पता चला।

प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम

विदेशी अधिकारियों और पैरामेडिक्स को प्रशिक्षण: हमारा देश विदेशी मित्र देशों के सैन्य कार्मिकों को सहायता प्रदान कर रहा है और उन्हें सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (एएफएमएस) संस्थानों में विभिन्न चिकित्सा पाठ्यक्रमों, जैसे पीजी, यूजी और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के लिए चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। प्रशिक्षण वर्ष 2024–25 के लिए, एफएफसी को 13 पीजी (एमडी/एमएस/एमडीएस), 05 एमबीबीएस, 71 पैरामेडिक और 24 ऑब्जर्वरशिप सीटें आवंटित की गई हैं।

एनडीएमए के साथ संयुक्त एचएडीआर अभ्यास: मुख्यालय आईडीएस (चिकित्सा) एनडीएमए के साथ समन्वय कर एचएडीआर के लिए एनडीआरएफ/एसडीआरएफ/यूटीडीआरएफ के साथ संयुक्त अभ्यास आयोजित करता है। विभिन्न चिकित्सा प्रतिष्ठानों के चिकित्सा अधिकारी एनडीएमए द्वारा आयोजित संयुक्त एचएडीआर अभ्यासों का हिस्सा रहे हैं।

खरीद

चिकित्सा सेवा वितरण को और बेहतर बनाने के लिए, एएफएमएस ने सैन्य अस्पतालों और प्रशिक्षण केंद्रों में तैनाती के लिए निम्नलिखित चिकित्सा उपकरण खरीदे हैं:–

क्र. सं.	मद	उद्देश्य/स्थान
क	01 x 512 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन	सेना अस्पताल (आर एंड आर) के लिए
ख	01 x हाइपरबेरिक चैम्बर (छह की क्षमता)	आईएनएचएस अश्विनी पर गहरे समुद्र में गोताखोरी से होने वाली चोटों के प्रबंधन के लिए
ग	01 x लेसिक लेज़र प्रणाली	सेना अस्पताल (आर एंड आर) में कॉर्नियल सर्जरी में सहायता के लिए
घ	प्रशिक्षण संवर्धन के लिए सिम्युलेटर	
	i. 01 x कैटरैक्ट विट्रियो–रेटिनल सर्जिकल सिम्युलेटर ii. 01 x आर्थोस्कोपिक सिम्युलेटर iii. 01 x हाई फाइडेलिटि बर्थिंग सिम्युलेटर	कमान अस्पताल (वायु सेना), बेंगलुरू में रेटिना की सर्जरी के लिए एएफएमएस पुणे में आर्थोस्कोपिक सर्जरी के लिए एएफएमएस पुणे में ऑब्सटेट्रिक्स तथा गाइनेकॉलोजी के लिए
ड.	मोबाइल ब्लड ट्रांस्पोर्टेशन वैन (14)	–20 से +20 डिग्री पर ब्लड और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के परिवहन के लिए।
च	वातानुकूलित ब्लड कलनेक्शन वैन	ब्लड यूनिट्स के संग्रहण और प्रोसेसिंग यूनिट तक परिवहन के लिए।
छ	इजेक्शन प्रोसीजर सिम्युलेटर (ईपीएस)	चोट लगने का जोखिम कम करने के लिए एयरक्राफ्ट इजेक्शन प्रोसीजर में वायुकर्मीदल के सुरक्षित और यथार्थवादी प्रशिक्षण के लिए 1 एयरो मेडिकल ट्रेनिंग सेन्टर (एएमटीसी), हिंडन में।

रक्षा सहयोग

वार्षिक रक्षा सहयोग योजना (डीसीपी): भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच 2023–24 के लिए वार्षिक डीसीपी के एक भाग के रूप में, भारतीय सशस्त्र बलों की दो सदस्यीय चिकित्सा टीम, जिसमें कर्नल गौरव मित्तल, वरिष्ठ सलाहकार (ऑर्थोपेडिक्स) और कर्नल सुबीर डे, 302 फील्ड अस्पताल कमान अधिकारी शामिल थे, ने 8 जनवरी से 22 जनवरी, 2024 तक ताशकंद, उज़्बेकिस्तान का दौरा किया। इस यात्रा का उद्देश्य ताशकंद के केंद्रीय क्लिनिकल सैन्य अस्पताल में मास्टर कक्षाएं और संयुक्त सर्जिकल ऑपरेशन आयोजित करना था।

संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर यूनिट प्रशस्ति पत्र: आईएफएच स्तर–III, एमओएनयूएससीओ (डीआर कांगो) को 31 जनवरी, 2024 को फोर्स कमांडर यूनिट प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है।

एएफएमएस में स्वचालन/डिजिटलीकरण

ई–औषधि का संचालनः दवाओं और उपभोज्य सामग्रियों की आपूर्ति श्रृंखला और माल–सूची प्रबंधन प्रणालियों में सुधार के लिए, सीडैक, नोएडा के सहयोग से एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन ई–औषधि विकसित किया गया है। यह एप्लिकेशन इंटरनेट आधारित है और एएफएमएस की सभी चिकित्सा इकाइयाँ वर्तमान में मेडिकल स्टोर्स में उपभोज्य सामग्रियों की खरीद और मांग के लिए इन मॉड्यूल का उपयोग कर रही हैं। सी–डैक नोएडा अपने टियर–III डेटा सेंटर के माध्यम से डेटा सेंटर की सेवा भी प्रदान कर रहा है।

ई–उपकरण का संचालनः ई–उपकरण गैर–व्यय योग्य मेडिकल स्टोर्स के लिए एक ऑनलाइन इन्वेंट्री प्रबंधन एप्लिकेशन है। यह एप्लिकेशन सबसे परिधीय इकाई से लेकर सबसे बड़े तृतीयक देखभाल अस्पताल तक चिकित्सा उपकरणों की इंडेंटिंग और इन्वेंट्री प्रबंधन की सुविधा प्रदान करती है। यह एप्लिकेशन जून 2024 से चालू हो गई है।

नि–क्षय पोर्टलः क्षय रोग मुक्त भारत के विज़न को साकार करने के भारत सरकार के उद्देश्य को साझा करते हुए, भारतीय सेना के सैन्य अस्पतालों ने नि–क्षय पोर्टल को शामिल किया है, जो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन के अंतर्गत क्षय रोग नियंत्रण के लिए एक वेब–आधारित रोगी प्रबंधन प्रणाली है।यह पोर्टल स्वास्थ्य कर्मियों को परीक्षण, उपचार और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए क्षय रोग के मामलों को पंजीकृत करने में मदद करता है।

सेहत (एसईएचएटी) के लिए ईसीएचएस मॉड्यूलः जुलाई 2024 से सेहत (एसईएचएटी) का एक ईसीएचएस मॉड्यूल शुरू किया गया है। इस मॉड्यूल को केंद्रीय संगठन ईसीएचएस द्वारा विकसित किया गया है और इसे मुख्यालय आईडीएस (मेडिकल) द्वारा सेहत (एसईएचएटी) एप्लिकेशन के साथ होस्ट किया गया है। इस सुविधा की सहायता से, ईसीएचएस सदस्य अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में जाए बिना ऑनलाइन टेली–परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। इस सेवा का लाभ वेबसाइट पर जाकर या एंड्रॉइड और ऐप्पल स्टोर पर उपलब्ध मोबाइल ऐप का उपयोग करके उठाया जा सकता है।

एएफएमएस में आधुनिकीकरण/बुनियादी ढांचा

कमान अस्पताल (उत्तरी कमान) का उद्घाटनः कमान अस्पताल (उत्तरी कमान) जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में स्थित 650 बिस्तरों वाला एक मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल है। नए अत्याधुनिक बहुमंजिला अस्पताल भवन का निर्माण 273.42 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। इसका उद्घाटन अप्रैल 2024 में सीओएएस द्वारा किया गया था।

एचएडीआर ऑपरेशन 2024

बाढ़ राहत कार्यों के लिए सिविल प्राधिकरण को सहायता 2024: वर्ष 2024 के दौरान विभिन्न राज्यों में बाढ़ जैसी स्थितियों और भूस्खलन के मामलों में, प्रभावित आबादी को आवश्यक चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए बाढ़ राहत कार्यों के लिए सिविल प्राधिकरण को सहायता के तहत चिकित्सा दल तैनात किए गए थे। जुलाई के अंत और अगस्त 2024 के बीच महाराष्ट्र, केरल, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विभिन्न सैन्य अस्पतालों और फील्ड अस्पतालों से कुल 11 चिकित्सा टुकड़ियाँ सक्रिय की गईं। इन टीमों ने सांगली, वायनाड, झाकरी, द्वारका, वडोदरा, मांडवी और नलिया हवाई अड्डे सहित प्रभावित जिलों में काम किया और अपनी तैनाती के दौरान कुल 1,699 मरीजों का इलाज किया। राहत गतिविधियों की कुछ झलकियाँ नीचे दी गईं हैं:–

सहयोग हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल (भीष्म): भीष्म एक आधुनिक आपदा प्रबंधन क्यूब है जिसे माननीय प्रधानमंत्री की आरोग्य मैत्री पहल के तहत स्थापित एक अंतर–मंत्रालयी कार्य–बल द्वारा विकसित किया गया है। इस क्यूब को भारतीय वायुसेना के चिकित्सा विशेषज्ञों और भारत के प्रमुख पैकेजिंग विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया है। इस क्यूब में मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्ट अप इंडिया जैसी प्रमुख पहल शामिल हैं। अत्यधिक गतिशील, बहुमुखी और तेजी से परिनियोजित होने वाला यह क्यूब, जिसका पैरा–ड्रॉप परीक्षण किया जा चुका है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अगस्त 2024 में अपनी यूक्रेन यात्रा के दौरान वहाँ की जनता को उपहार में दिया गया था। भीष्म क्यूब को हाल ही में विशाखापत्तनम में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास एक्स–टाइगर ट्रायम्फ के दौरान भी परिनियोजित किया गया था।

आगरा में एयर ड्रॉप

विशाखापत्तनम में परिनियोजन और विदेशी प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत

भारतीय वायु सेना में आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली (ईएमआरएस): भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू की गई ईएमआरएस, तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए एक केंद्रीकृत हेल्पलाइन (155226) प्रदान करती है। सीएचएएफ, बेंगलुरु से संचालित यह हेल्पलाइन भारतीय वायुसेना कर्मियों और उनके परिवारों को संपर्क विवरण पर समय बर्बाद किए बिना तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। 21 मई, 2024 से, ईएमआरआई हैदराबाद की एक प्रशिक्षित टीम तत्काल मार्गदर्शन प्रदान कर रही है और आस–पास की वायुसेना स्वास्थ्य सेवाओं के साथ समन्वय कर रही है ताकि एम्बुलेंस तुरंत पहुंच सके और समय के दौरान तत्काल महत्वपूर्ण देखभाल सुनिश्चित की जा सके।

एचएडीआरके लिए रैपिड एक्शन मेडिकल टीम (आरएएमटी) की तैनातीः भारतीय वायु सेना के आरएएमटी को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों के दौरान चिकित्सा संबंधी आकस्मिकताओं से निपटने के लिए तैनात किया गया है, जैसे कि अभ्यास–तरंगशक्ति–2024, जो भारतीय वायुसेना द्वारा अगस्त 2024 और सितंबर 2024 में सुलूर और जोधपुर में आयोजित पहला बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास है, अभ्यास वायुशक्ति 2024 और अभ्यास गगन शक्ति–2024 आदि।

आर्मड फोर्सेज ट्रांस्फ्यूजन सेन्टर

पिछले एक दशक में, एएफटीसी रक्त केंद्र ने एक परिवर्तनकारी यात्रा की है और अपने कार्यभार के कुशल प्रबंधन के लिए प्रसिद्धि पाकर उत्कृष्टता के एक प्रतीक के रूप में विकसित हुआ है। एएफटीसी ने तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखा है तथा अपनी क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए अत्याधुनिक उपकरण अपनाए हैं। विशेष रूप से, एएफटीसी के पास जमे हुए आरबीसी भंडारण के लिए देश की एकमात्र लाइसेंस प्राप्त सुविधा है। यह अग्रणी उद्यम लाल रक्त कोशिकाओं की शेल्फ लाइफ को मात्र 35 से 42 दिनों से 5 साल तक बढ़ाकर ब्लड ट्रास्फ्यूजन में क्रांति लाता है, जिससे रक्त की उपलब्धता बढ़ जाती है और बर्बादी कम होती है। यह फ्रोजन आरबीसी सुविधा दुर्लभ समूह आरबीसी के दीर्घकालिक परिरक्षण को संभव बनाती है और आपात स्थिति के दौरान स्टॉक इन्वेंट्री बनाने में भी मदद कर सकती है।

*****

सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण

भारत सरकार भारतीय सशस्त्र बलों को सुरक्षा चुनौतियों के संपूर्ण परिदृश्य का सामना करने के लिए बिना किसी देरी के, विशिष्ट तकनीकी उपकरण और प्लेटफार्मों से सुसज्जित करने के लिए प्रतिबद्ध है। चूँकि ऑपरेशन अधिक से अधिक नेट–केंद्रित होते जा रहे हैं, इसलिए समय की माँग है कि हम अपनी सेनाओं को अगली पीढ़ी के युद्धों को लड़ने के लिए तैयार करें। इस दृष्टि से, उन्नत तकनीकों की क्षमता का उचित उपयोग करने और सशस्त्र बलों को भविष्य के लिए तैयार रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रमुख नीतिगत पहल

रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीएपी) 2020, उद्योग के विकास और सुरक्षा आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, रक्षा खरीद में सुधार और उसे सुव्यवस्थित करने के लिए 30.09.2020 को शुरू की गई थी। इस नीति का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 'मेक इन इंडिया' पहल और 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' में सहायता करना है। डीएपी 2020 के प्रमुख पहलू:

स्वदेशी खरीद को प्राथमिकता: अधिप्राप्ति में सर्वोच्च प्राथमिकता खरीद (भारतीय–आईडीडीएम) को दी जाती है। सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने के लिए एक नई श्रेणी, यानी 'खरीद (वैश्विक भारत में निर्माण करें)' शुरू की गई है। मेक–I (सरकार द्वारा वित्तपोषित) और मेक–II (उद्योग द्वारा वित्तपोषित) परियोजनाएँ, निजी संस्थाओं सहित विकास एजेंसियों के सहयोग से, विशिष्ट तकनीकी मदों के प्रोटोटाइप विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई हैं। आयात प्रतिस्थापन के माध्यम से आत्मनिर्भरता बढ़ाने के उद्देश्य से मेक–III प्रक्रिया (मुख्य रूप से टीओटी के मार्फत) के जरिए आयातित पुर्जों का स्वदेशीकरण शुरू किया गया है।

स्वदेशी सामग्री (आईसी) में वृद्धि: भारत में निर्मित सामग्री, घटकों और सॉफ्टवेयर सहित सभी खरीद श्रेणियों के लिए बढ़ी हुई न्यूनतम 50% आईसी आवश्यक है।

विदेशी सोर्सिंग: खरीद मूल्य के निरपेक्ष विदेशी सोर्सिंग की अनुमति रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) से पूर्व अनुमोदन के साथ केवल असाधारण मामलों में ही दी जाती है।

रक्षा वस्तुओं का स्वदेशीकरण: सैन्य कार्य विभाग (डीएमए) ने 5 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची अधिसूचित की हैं, जिनमें 509 मदों के रूप में हथियार या प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं जिनका स्वदेशीकरण निर्दिष्ट समय–सीमाओं के आधार पर किया जाना है। इनमें से लगभग 50% (मदों) का स्वदेशीकरण पहले ही हो चुका है।

एमएसएमई और स्टार्ट–अप को प्रोत्साहित करना: एक मज़बूत रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एमएसएमई और स्टार्ट–अप को प्रोत्साहित किया जाता है। 300 करोड़ रुपये तक के खरीद मामलों में वित्तीय मानदंडों की आवश्यकता के बिना एमएसएमई/स्टार्ट–अप पर विचार किया जाता है।

डीआरडीओ द्वारा प्रौद्योगिकी विकास कोष (टीडीएफ): यह रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए एमएसएमई, स्टार्ट–अप और शैक्षणिक संस्थानों सहित उद्योगों को अनुदान सहायता प्रदान करता है।

एमएसएमई और स्टार्ट–अप के लिए छूट: आईडीईएक्स/टीडीएफ नीतियाँ एमएसएमई और स्टार्ट–अप को सहायता प्रदान करने के लिए निष्पादन गारंटी, वारंटी खंड, भुगतान अनुसूचियों आदि के संबंध में छूट प्रदान करती हैं।

डीएसी/डीपीबी द्वारा दी गई आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन)

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, माननीय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने भारतीय सशस्त्र बलों के 20 पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए एओएन प्रदान किया, जिनकी राशि 1.71 लाख करोड़ रुपये (लगभग) है, जिनमें से 19 प्रस्ताव स्वदेशी स्रोतों से खरीद के लिए हैं। इनके अलावा, रक्षा खरीद बोर्ड (डीपीबी) ने भारतीय सशस्त्र बलों के 04

पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए एओएन प्रदान किया, जिनकी राशि 1457.19 करोड़ रुपये (लगभग) है। जिन प्रमुख प्रस्तावों के लिए एओएन प्रदान किए गए हैं, वे हैं:

टी–90 टैंक के लिए आईएनवीएआर (3 यूबीके 20) मिसाइल: टी–90 टैंक मैकेनाइज्ड फोर्सिज का मुख्य आधार हैं। टी–90 टैंकों को अभियानों और मिशनों के दौरान, दिन और रात दोनों समय, लंबी दूरी पर दुश्मन के टैंकों को हराना होता है। आईएनवीएआर मिसाइल एक लेज़र गाइडेड सेकेंड जेनरेशन प्लस मिसाइल है जो 5000 मीटर तक अत्यधिक सटीक निशाना लगाती है, जिससे टी–90 टैंकों को स्टैंड–ऑफ एंगेजमेंट में बड़ा लाभ मिलता है। वर्तमान में, यह एकमात्र टैंक गोला–बारूद है जो समकालीन पीएलए और पाक एएफवी के फ्रंटल 60° कवच को नष्ट करने में सक्षम है।

पी–17बी फ्रिगेट: प्रोजेक्ट 17बी, नीलगिरि श्रेणी के फ्रिगेट की निरंतरता और विकास का प्रतिनिधित्व करेगा, जो वर्तमान में प्रोजेक्ट 17ए के रूप में निर्माणाधीन हैं। नए फ्रिगेट में उन्नत क्षमताएँ होंगी, जिनमें स्वदेशी हथियार, अग्नि नियंत्रण प्रणालियां और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां शामिल हैं।

न्यू वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट (एनडब्ल्यूजेएफएसी): एनडब्ल्यूजेएफएसी पोत कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों (एलआईएमओ), निगरानी, गश्त, खोज और बचाव (एसएआर)कार्यों को करने में सक्षम हैं। इसके अलावा, ये पोत विशेष रूप से हमारे द्वीपीय क्षेत्रों में और उनके आसपास, समुद्री डकैती विरोधी अभियानों में प्रभावी भूमिका निभाएंगे। भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के अनुरूप, एनडब्ल्यूजेएफएसी पोतों का डिज़ाइन और निर्माण भारतीय शिपयार्डों द्वारा स्वदेशी रूप से किया जाएगा।

फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट–स्वदेशी (एफआईसी–I): एफआईसी–I पोत तटीय रक्षा के लिए कई भूमिकाएँ निभाने में सक्षम हैं, जिसमें भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों और पनडुब्बियों का अनुरक्षण भी शामिल है। भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के अनुरूप, एफआईसी–I का डिज़ाइन और निर्माण भारतीय शिपयार्डों द्वारा स्वदेशी रूप से किया जाएगा। इन पोतों के स्वदेशी निर्माण से भारतीय जहाज निर्माण उद्योग की निर्यात क्षमता को भी बढ़ावा मिलेगा।

पक्षी पहचान और निगरानी रडार: पक्षी पहचान और निगरानी रडार (बीडीएमआर) की आवश्यकता सभी प्रकार के पक्षियों का पता लगाने के लिए होती है, जिससे पक्षियों के टकराने की घटनाओं को रोकने के लिए संबंधित एजेंसियों को वास्तविक समय पर जानकारी मिल जाती है। पक्षी का टकराना वायुयान सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। बीडीएमआर वायुयान की सुरक्षा को बढ़ाकर भारतीय वायुसेना की समग्र परिचालनात्मक प्रभावशीलता को बढ़ावा देगा। खरीद के अंतर्गत कुल 25 (आईएएफ के लिए 23 और नौसेना के लिए 02) प्रणालियाँ मांगी गई हैं।

इंटरसेप्टर बोट्स (आईबी): इंटरसेप्टर बोट्स (आईबी) उच्च गति वाले सतही प्लेटफॉर्म हैं जो दिन/रात, विशेष रूप से उथले पानी में इंटरसेप्शन के लिए तटीय गश्त और निगरानी करने में सक्षम हैं। ये कानून प्रवर्तन कर्तव्यों, खतरों/आतंकवाद–विरोधी/तस्करी–विरोधी/एलआईएमओ परिदृश्यों से सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण, मादक पदार्थों की तस्करी–विरोधी निगरानी और अवरोधन सहित समुद्री–वायु यूनिटों के साथ समन्वित संचालन करने में सक्षम हैं।

अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत (एनजीओपीवी): एनजीओपीवी भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख सतही प्लेटफॉर्म हैं जो डेक से हेलीकॉप्टर संचालित करने और समुद्र में उन्नत क्षमता और स्थायित्व के साथ लंबी दूरी के ऑपरेशन करने में सक्षम हैं। इन्हें भारत के समुद्री क्षेत्रों और द्वीपीय क्षेत्रों में गश्त और पुलिसिंग के लिए नियोजित किया गया है, जिसमें भारतीय खोज और बचाव क्षेत्र में अवरोधन अभियान और खोज एवं बचाव शामिल हैं।

डोर्नियर विमान (डीओ–228): डोर्नियर 228 विमान बहुमुखी प्लेटफॉर्म हैं जो व्यापक रेंज के ऑपरेशन कर सकते हैं। 8 अतिरिक्त डोर्नियर विमानों की खरीद के लिए एओएन को मंजूरी दी गई ताकि निगरानी कवरेज क्षेत्र को बढ़ाया जा सके और साथ ही विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में प्रशिक्षण, अप्रत्याशित/विशेष ऑपरेशन जैसे समुद्री डकैती विरोधी, प्रदूषण प्रतिक्रिया आदि के लिए हवाई ऑपरेशनों की व्यवस्था की जा सके। इसके अतिरिक्त, नवंबर 2024 में एचएएल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें कॉकपिट इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोपायलट, नेविगेशन सिस्टम, इंटरकॉम, सॉलिड स्टेट फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (एसएसएफडीआर)/कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (सीवीआर), एसईएल–सीएएल और रेडियो अल्टीमीटर शामिल हैं।

उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर (एएलएच एमके–III): स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर भारतीय डिज़ाइन, विकास और विनिर्माण क्षमताओं का प्रमाण है। तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंतरिक जल क्षेत्रों में तटीय सुरक्षा और निगरानी को और मज़बूत करने के लिए 6 एएलएचएमके–III के लिए एओएन प्रदान किया गया।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान हस्ताक्षरित अनुबंध

एमक्यू–9बी एचएएलई आरपीएएस: एमक्यू–9बी एचएएलई आरपीएएस का अनुबंध 15 अक्टूबर 2024 को 8593.15 करोड़ रुपये की लागत से संपन्न हुआ। ये ड्रोन बल प्रवर्धक के रूप में काम करेंगे, जिससे भारतीय सशस्त्र बलों को विविध और चुनौतीपूर्ण परिचालन परिवेशों में बेहतर स्थितिजन्य जागरूकता और सटीकता के साथ काम करने में मदद मिलेगी। इस अधिग्रहण से भारत में रखरखाव, मरम्मत और संचालन सुविधाएँ भी आएंगी,जिससे **'आत्मनिर्भरता'** को बढ़ावा मिलेगा भारत सरकार की **'मेक इन इंडिया'** पहल के साथ संरेखित होने वाले भारतीय उद्योग के लिए ऑफसेट भी शामिल होंगे।

155 मिमी/52 कैल एसपी (ट्रैक्ड) के–9 वज्र–टी गन सिस्टम: 155 मिमी/52 कैल एसपी (ट्रैक्ड) के–9 वज्र–टी गन सिस्टम का अनुबंध 20 दिसंबर 2024 को 7628.70 करोड़ रुपये की लागत से संपन्न हुआ। मैकनाइज्ड फार्मेशनों से संबद्ध फायरपावर रिसोर्सेज को निर्णय लेने के समय पर युद्ध क्षमता के इष्टतम उपयोग को सक्षम करने के लिए उपयुक्त

गतिशीलता की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता पश्चिमी सीमाओं के साथ रेगिस्तानी/अर्ध–रेगिस्तानी इलाकों और उत्तरी सीमाओं के साथ उच्च तुंगता वाले मैदानों/पठारी इलाकों में अधिक हो जाती है, जहाँ ट्रैक वाली मैकेनाइज्ड सेनाएँ खींची जाने वाली और पहिएदार गन सिस्टम की तुलना में अधिक गहराई तक बहुत तेज़ी से संचलन कर सकती हैं। के–9 वज्र टी गन सिस्टम मैकनाइज्ड फार्मेशनों की पहुँच और फायरपावर को काफी हद तक बढ़ाएगा।

मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एमआरएसएएम): एमआरएसएएम का अनुबंध 16 जनवरी 2025 को 2959.63 करोड़ रुपये की लागत से संपन्न हुआ। अनुबंध के तहत, मिसाइल और संबंधित उपकरणों का निर्माण और आपूर्ति मेसर्स बीडीएल द्वारा की जाएगी, जिसमें 50% से अधिक सामग्री स्वदेशी होगी। इन मिसाइलों का अधिग्रहण भारत सरकार की **'मेक इन इंडिया'** पहल पर जोर देते हुए भारत की समुद्री रक्षा को मजबूत करता है।

एरिया डिनायल म्यूनिशन (एडीएम) टाइप–1: 214 मिमी पिनाका का अनुबंध 06 फरवरी 2025 को 4474.33 करोड़ रुपये की लागत से संपन्न हुआ। डीआरडीओ (एआरडीई) द्वारा डिज़ाइन और विकसित की गई 214 मिमी पिनाका एमएलआरएस, सभी मौसम में काम करने वाली रॉकेट प्रणाली है जिसकी मारक क्षमता 37.5 किमी है। एडीएम टाइप–1 दोहरे उद्देश्य वाली उन्नत पारंपरिक युद्ध सामग्री (डीपीआईसीएम) रॉकेट एम्यूनिशन में दोहरे उद्देश्य वाले सब म्यूनिशन शामिल हैं जो टैंकों और बख्तरबंद कार्मिक वाहकों के साथ–साथ बी–श्रेणी के वाहनों और खाई में तैनात सैनिकों को भी निष्क्रिय करने में सक्षम हैं। एरिया डिनायल म्यूनिशन टाइप–1 के शामिल होने से भारतीय सेना की रॉकेट प्रणालियों की मारक क्षमता और विध्वंसक शक्ति में वृद्धि होगी।

अश्विनी रडार: 12 मार्च 2025 को हस्ताक्षरित अनुबंध के तहत 2906.57 करोड़ रुपये मूल्य के कुल 18 अश्विनी रडार खरीदे जा रहे हैं। इन प्रणालियों की डिलीवरी मई 2027 से शुरू होगी। अश्विनी का उपयोग हवाई वस्तुओं के संबंध में पूर्व चेतावनी देने और निर्णय लेने के लिए कमान और नियंत्रण केंद्रों को सेंसर सूचना भेजने हेतु संचार प्रणालियां उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। तत्पश्चात् ये निर्णय घुसपैठियों को रोकने और नष्ट करने के लिए हथियार प्रणालियों तक पहुँचाए जाते हैं।

एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टमऔर एचएमवी 6x6 गन टोइंग व्हीकल: 307 एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम और 327 एचएमवी 6x6 गन टोइंग व्हीकल का अनुबंध 26 मार्च 2025 को 6895.45 करोड़ रुपये की लागत से संपन्न हुआ। इसे कारगिल अभियान के बाद 2001 में भारतीय सेना की मानक गन प्रणाली के रूप में अपनाया गया था। यह सिस्टम गोला–बारूद की मारक क्षमता और रेंज में वृद्धि करते हुए भारतीय सेना की दुश्मन को नुकसान पहुँचाने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा।

नाग मिसाइल प्रणाली (एनएएमआईएस) ट्रैक्ड(सीमित श्रृंखला उत्पादन): एनएएमआईसीए और नाग मिसाइलों का अनुबंध 27 मार्च 2025 को 1801.34 करोड़ रुपये की लागत से संपन्न हुआ।टोही एवं सहायता (आर एंडएसपी)(ट्रैक्ड) बटालियनें भारतीय सेना की अग्रिम पंक्ति की लड़ाकू इकाइयाँ हैं, जिनका काम एक मज़बूत और प्रभावी टैंक–रोधी रक्षा प्रदान करना और मैदानी/रेगिस्तानी इलाकों में घुसपैठ करने वाले दुश्मन के कवच को अधिकतम नुकसान पहुँचाना है। एनएएमआईएस पर आधारित स्वदेशी तीसरी पीढ़ी की मिसाइल प्रणाली हमारी पश्चिमी सीमाओं पर हमारे शत्रुओं के साथ युद्ध में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखने के लिए एक सक्रियात्मक आवश्यकता बन गई है। एनएएमआईसीए और नाग मिसाइलों के साथ एनएएमआईएस, आर एंड एसपी (ट्रैक्ड) बटालियनों के मौजूदा इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल (आईसीवी) बीएमपी की जगह लेगी।

हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (एलसीए): रक्षा मंत्रालय ने 28 मार्च 2025 को 156 एलसीएच की खरीद के लिए एचएएल के साथ 27,771.99 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। स्वदेश में निर्मित एलसीएच हल्के, फुर्तीले, अत्यधिक मनूवरेबल हैं और मध्यम कवच सुरक्षा से लैस हैं और इनमें विभिन्न प्रकार की शक्तिशाली गोलाबारी क्षमता के साथ–साथ सटीक निशाना लगाने की क्षमता भी है। ये हेलीकॉप्टर इस अंतर को पाटेंगे और भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना को आक्रामक और रक्षात्मक दोनों अभियानों/मिशनों में समग्र नियोजनीयता को बढ़ाकर उभरती चुनौतियों का सामना करने में मदद करेंगे।

स्वदेशी एलआरएलएसीएम का परीक्षण

लंबी दूरी की भूमि पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल (एलआरएलएसीएम): स्वदेश में विकसित लंबी दूरी की भूमि पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल (एलआर–एलएसीएम) का पहला लाइव फायरिंग परीक्षण 2024 में सफलतापूर्वक किया गया है।

*****

रक्षा विभाग के अन्य संगठन

रक्षा संपदा महानिदेशालय

रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई), नई दिल्ली 61 छावनियों में रक्षा भूमि के प्रबंधन और नागरिक प्रशासन से संबंधित मामलों में सलाहकारी और कार्यकारी कार्य करता है। वर्तमान में, यह जम्मू, चंडीगढ़, कोलकाता, लखनऊ, पुणे और जयपुर में स्थित छह प्रधान निदेशालयों के जरिए कार्य करता है। प्रधान निदेशालय आगे कई फील्ड कार्यालयों अर्थात 43 रक्षा संपदा कार्यालयों, 4 सहायक रक्षा संपदा कार्यालयों और 61 छावनी बोर्डों का पर्यवेक्षण करते हैं।

रक्षा मंत्रालय के पास देश भर में लगभग 17.81 लाख एकड़ भूमि है। अधिसूचित छावनियों के अंदर लगभग 1.61 लाख एकड़ रक्षा भूमि है और शेष लगभग 16.20 लाख एकड़ भूमि छावनियों से बाहर है।

रक्षा भूमि के प्रबंधन के लिए की गई पहलः

विभाग ने पिछले कुछ वर्षों में प्रभावी भूमि प्रबंधन के लिए विभिन्न नई पहल की हैं:–

रियल–टाइम रिकॉर्ड प्रबंधनः रक्षा संपदा महानिदेशालय ने एक स्वचालित लीज़ विस्तार/नवीनीकरण सॉफ़्टवेयर मॉड्यूल विकसित किया है, जो 02.01.2025 से चालू हो गया है। इस मॉड्यूल को रक्षा भूमि के कुशल प्रबंधन के लिए ई–छावनी और रक्षा भूमि सॉफ़्टवेयर के साथ एकीकृत किया गया है।

भूमि उपयोग विश्लेषणः सीओई ने 'ओपन–सोर्स सैटेलाइट इमेजरी और 'ओपन–सोर्स जीआईएस प्लेटफ़ॉर्म' का उपयोग करके भूमि उपयोग पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए जीआईएस और रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए एक कस्टमाइज्ड'भूमि उपयोग विश्लेषण' एआई और एमएलटूल विकसित किया है। यह खाली भूमि,निर्मित क्षेत्र,वनस्पति/वन आवरण,सड़कों और जल निकायों का विवरण देता है। यह रक्षा बलों के लिए भूमि अधिग्रहण के विभिन्न चल रहे प्रस्तावों की प्रभावी जाँच सुनिश्चित करता है और इस प्रकार यह भूमि अधिग्रहण को लागत प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह निर्णय लेने की प्रक्रिया के रूप में सक्षम बनाता है। वर्ष 2024–25 में,इस उपकरण का उपयोग करके,300 पॉकेट्स की 65,000 एकड़ (लगभग) से अधिक रक्षा भूमि का विभिन्न निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के लिए विश्लेषण किया गया है।

बिल्डिंग फुटप्रिंटः बिल्डिंग फुटप्रिंट से संबंधित मॉड्यूल पर कार्य सीओई में चल रहा है। यह छावनी बोर्डों को छावनी क्षेत्र में संपत्तियों के नगरपालिका करों का आकलन करने और भवन निर्माण गतिविधियों के प्रबंधन में भी मदद करेगा। यह मॉड्यूल वर्तमान में परीक्षण/मशीन लर्निंग मोड में है। छावनी क्षेत्रों में बिल्डिंग फुटप्रिंट का लाभ उठाकर, कर अधिकारी संपत्ति मूल्यांकन की परिशुद्धता बढ़ा सकते हैं, कर अनुपालन में सुधार कर सकते हैं और समग्र कर संग्रह प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकते हैं।

अतिक्रमण रोकने और हटाने के लिए उठाए गए कदम

(क) रक्षा भूमि अभिलेखों के डिजीटाइजेशन और कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से रक्षा भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली को मजबूत किया गया है।

(ख) भूमि प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है जिसमें अतिक्रमण की जीआईएस परतें विकसित की गई हैं।

(ग) एक 'परिवर्तन संसूचक जीआईएस टूल' भी विकसित किया गया है जो एक निर्धारित अवधि के दौरान अतिक्रमण का विवरण प्रदान करता है।

(घ) 'भूमि रक्षा' मॉड्यूल विकसित किया गया है जहां पीपीई अधिनियम 1971 के अंतर्गत बेदखली की कार्यवाही शुरू की जा सकती है और ऑनलाइन आगे बढ़ाई जा सकती है।

(ङ) ''रक्षा भूमि पर अतिक्रमण के खतरे'' का मूल्यांकन करने के लिए कार्यप्रणाली तैयार की गई है।

(च) समस्त रक्षा भूमि का सर्वेक्षण, सीमांकन और सत्यापन किया गया है। रक्षा भूमि का सर्वेक्षण अब एक सतत् प्रक्रिया है।

(छ) रक्षा भूमि लेखापरीक्षा को वर्ष 2011–12 से एक सतत् प्रक्रिया के रूप में संस्थागत रूप दिया गया है ।

भूमि का अधिग्रहण/भवन और भूमि को किराए पर लेना एवं अधिग्रहण करना

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान रक्षा मंत्रालय द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए 667.8382 करोड़ रुपए तथा किराए पर लिए गए/अधिग्रहित भवनों और भूमि के लिए किराए के भुगतान हेतु 451.9285 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे और 31.03.2025 तक इसमें से 555.6614 करोड़ रुपए भूमि के अधिग्रहण और 437.4858 करोड़ रुपए भूमि और भवनों के किराए के भुगतान के लिए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा, प्रभारित शीर्ष के तहत, रक्षा उद्देश्य के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए बढ़े हुए मुआवजे के संबंध में 13.9691 करोड़ रुपए का भुगतान भी दिनांक 31.03.2025 तक किया गया है।

छावनी बोर्डों का प्रशासन

(क) देश में 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 61 छावनी बोर्ड हैं। छावनी बोर्ड शहरी स्थानीय निकाय हैं,जिन्हें छावनी अधिनियम,2006(पूर्व में छावनी अधिनियम,1924)के तहत छावनियों के प्रशासन हेतु निगमित किया गया है।

(ख) छावनी बोर्ड प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, औषधालयों और अस्पतालों के माध्यम से विशेषज्ञ सेवाओं और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं सहित नागरिक सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। कुछ मामलों में, बोर्डों ने प्रसूति कक्ष, लघु शल्य चिकित्सा के लिए ओटी, नैदानिक सेवाएँ, एक्स–रे, एम्बुलेंस, विशेष सेवाएँ आदि जैसी सुविधाएँ प्रदान करके अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करने के लिए कदम उठाए हैं।

(ग) वर्तमान में,विभिन्न छावनियों में 28 "दिव्यांग बच्चों के लिए केंद्र", 181 स्कूल (प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक) जिनमें लगभग 60,000 बच्चे पढ़ रहे हैं और 63 कौशल विकास केंद्र, 39 अस्पताल और 36 औषधालय हैं।

(घ) केंद्र सरकार छावनी बोर्डों को उनके बजट को संतुलित करने के लिए सामान्य अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 2024–25 के दौरान, 61 में से 52 छावनी बोर्डों को केंद्र सरकार से 551.2765 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्राप्त हुई। 2024–25 के दौरान स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के लिए 06 छावनी बोर्डों को 3 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता भी आवंटित की गई। इसके अलावा, पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता आवंटित की गई। छावनी बोर्डों को राज्य सरकारों से भी अनुदान के हिस्से के रूप में वित्त वर्ष 2024–25 में 68.2791 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

(ङ) एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने जैसे ऊर्जा संरक्षण उपाय किए गए हैं। प्रधानमंत्री सूर्य–घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए छावनी बोर्डों द्वारा कैपेक्स और रेस्को मोड के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है।

(च) 61 छावनी बोर्डों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उप–नियम, 2024 तैयार किए हैं, जिन्हें संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। ये उप–नियम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अधिदेशों को पूरा करने और गलत तरीके से कचरा निपटान/जलाने पर दंड लगाने में सहायक हैं। 35 छावनी बोर्डों ने ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान के लिए ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र (एसडब्ल्यूपीपी) स्थापित किए हैं।

(छ) "एक पेड़ मां के नाम अभियान" के तहत छावनी क्षेत्रों में वृक्षारोपण अभियान चलाकर 6,40,042 पेड़ लगाए गए, जिसमें छावनी के नागरिकों ने भी भाग लिया।

(ज) छावनी बोर्डों ने ''डिजिटल भारत'' का उद्देश्य प्राप्त करने और सर्विस डिलीवरी की गुणवत्ता सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। सभी छावनी बोर्डों द्वारा ई–टेंडरिंग तथा ई–प्रोक्योरमेंट को लागू किया गया है। सभी बोर्डों ने सामान की अधिप्राप्ति के लिए स्वयं को जीईएम पोर्टल पर रजिस्टर किया है।

सैनिक स्कूल सोसाइटी

सैनिक स्कूल सोसाइटी (एसएसएस)1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम XXI के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है और देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित सैनिक स्कूलों का प्रबंधन करती है। ये स्कूल कैडेटों को एक अच्छा नागरिक बनने और जीवन के सभी कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

प्रमुख उपलब्धियाँ

100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना: सरकार ने एनजीओ/न्यासों/निजी विद्यालयों/राज्य सरकार के स्कूलों के साथ साझेदारी में श्रेणीबद्ध तरीके से कक्षा 6 से आरंभ होने वाले 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की पहल को अनुमोदन प्रदान किया है । इस पहल के अंतर्गत, 44 नए सैनिक स्कूलों के अतिरिक्त, अप्रैल 2025 में 42 और नए सैनिक स्कूलों को अस्थायी रूप से मंजूरी दी गई है, जो संबंधित स्कूल द्वारा रक्षा मंत्रालय की सैनिक स्कूल सोसायटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अधीन है और इस प्रकार, साझेदारी मोड के तहत ऐसे नए सैनिक स्कूलों की संख्या 86 हो गई है।

सैनिक स्कूलों में बालिका कैडेटों का प्रवेश: अब सैनिक स्कूलों ने सभी 33 सैनिक स्कूलों में बालिकाओं के लिए प्रवेश शुरू कर दिया है। जनवरी, 2025 तक, कुल 1612 बालिका कैडेट पूर्ववर्ती पद्धति पर स्थापित 33 सैनिक स्कूलों में और 856 बालिका कैडेट साझेदारी मोड पर आधारित नए सैनिक स्कूलों में अध्ययन कर रही हैं।

सैनिक स्कूलों में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग: हिन्दी को गौरव और सांस्कृतिक महत्व की भाषा के रूप में बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए स्कूलों में कई पहलें शुरू की गई हैं। इन पहलों में हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा के लिए उत्सवों की योजना बनाना, वाद–विवाद, निबंध लेखन और हिंदी में कविता प्रतियोगिताएँ आयोजित करना और बच्चों को हिंदी भाषा बोलने के लिए प्रेरित करना शामिल हैं।

राष्ट्रीय अखंडता: शैक्षणिक वर्ष 2024–25 के दौरान,सैनिक स्कूलों में राष्ट्रीय अखंडता को प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कैडेटों ने भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलों जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव, एक भारत श्रेष्ठ भारत, योग दिवस, चंद्रयान 3, हर घर तिरंगा, सफलता उत्सव, वीर गाथा परियोजना और राष्ट्रीय ध्वज दिवस और कारगिल विजय दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसरों के स्मरणोत्सव में गहरी रुचि दिखाई।

मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान

मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (एमपी–आईडीएसए), एक गैर–पक्षपाती, स्वायत्त निकाय है जो रक्षा, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सभी पहलुओं पर वस्तुनिष्ठ अनुसंधान और नीति–संबंधित अध्ययनों के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य रक्षा और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर ज्ञान के सृजन और प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

2024–25 के दौरान एमपी–आईडीएसए की प्रमुख गतिविधियाँ

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

दिल्ली रक्षा वार्ता (डीडीडी): संस्थान ने 12–13 नवंबर 2024 तक "अनुकूली रक्षाः आधुनिक युद्ध के बदलते परिदृश्य से निपटना" विषय पर दिल्ली रक्षा वार्ता के उदघाटन संस्करण की मेजबानी की।

माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह दिल्ली रक्षा वार्ता के उद्घाटन दिवस पर विशेष अभिभाषण देते हुए।

भारत–अफ्रीका रणनीतिक वार्ता (आईएएसडी): "भारत और अफ्रीकाः अगले दशक में साझेदारी" विषय पर वार्ता का पाँचवाँ संस्करण 25–26 मार्च 2025 को आयोजित किया गया।

25 मार्च, 2025 को 5वें आईएएसडी के उद्घाटन सत्र के दौरान राजदूत सुजान आर.चिनॉय, महानिदेशक एमपी–आईडीएसए के साथ महामहिम राजदूत अनिल सूकलाल,भारत में दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के उच्चायुक्त, श्री दम्मू रवि, सचिव(ईआर), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ।

राष्ट्रीय सम्मेलन और संगोष्ठियाँ

''भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए वर्तमान चुनौतियाँ'' विषय पर 20 अगस्त 2024 को एक संगोष्ठी आयोजित की गई। 28–30 जनवरी 2025 तक चलने वाली एक अन्य संगोष्ठी में सैन्य क्षेत्र और घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों (एलएडब्ल्यूएस) में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रति भारत का दृष्टिकोण'' पर चर्चा की गई।

ज्ञान संबंधी कार्यक्रम और सहभागिता

वार्ताएँ और व्याख्यानः प्रख्यात वक्ताओं द्वारा 17 वार्ताएँ/व्याख्यान, 7 द्विपक्षीय वार्ताएँ, और 11 गोलमेज/पुस्तक चर्चाएँ की गई।

विशेष वार्ताएँः विभिन्न क्षेत्रों और देशों से आए प्रतिनिधिमंडलों और प्रतिष्ठित लोगों के साथ 22 विशेष वार्ताएँ आयोजित की गई।

प्रशिक्षणः वर्ष 2024–25 के दौरान एसएसबी(1), बीएसएफ(4), आईटीबीपी(2), मुख्यालय आईडीएस (2)आदि को शामिल करते हुए 10 प्रशिक्षण/अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सैन्य इंजीनियर सेवाएँ

एमईएस देश के सभी भागों में रणनीतिक और सक्रियात्मक परियोजनाओं का क्रियान्वयन करता है। एमईएस के निर्माण कार्यों में ऊँची इमारतें, क्षेत्रीय आवास, सड़कें, पुल, हैंगर, रनवे, डॉक, बंदरगाह, बिजली स्टेशन, जल आपूर्ति परियोजनाएँ और आपदाओं के दौरान भी आवश्यक सेवाओं का संचालन शामिल है। एमईएस का वार्षिक वित्तीय परिव्यय लगभग 25,000 करोड़ रूपये है और इसके लगभग 600 स्टेशन हैं।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप सरकारी तंत्र की प्रभावशीलता में सुधार,व्यापार में आसानी,मेक इन इंडिया,जीवन स्तर में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में नियामक/प्रक्रियात्मक दस्तावेजों में संशोधन किया गया है। कुछ प्रमुख सुधार इस प्रकार हैंः–

ई मापन पुस्तिका (ई एमबी)ः कार्यों/सेवाओं के लिए मात्राओं के बिल की डिजिटल रिकॉर्डिंग के लिए ईएमबी एप्लिकेशन विकसित किया जा रहा है, जिससे ठेकेदारों को भुगतान का आधार बनेगा। एप्लिकेशन के पहले चरण में विक्रेता द्वारा सीईआरटी–आईएन ऑडिट शामिल है जो पूरा हो चुका है और डीसीवाईए ऑडिट प्रगति पर है।

एमईएस एकीकृत निगरानी और प्रबंधन सॉफ्टवेयर (एमआईएमएएमएसए)ः एमआईएमएएमएसए एक अग्रणी क्लाउड–आधारित मध्यस्थता प्रबंधन प्रणाली है, एमईएसजी में मध्यस्थता की पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए विकसित की जा रही है, जिसमें मध्यस्थों की नियुक्ति,मध्यस्थता कार्यवाही की निगरानी से लेकर पंचाट के कार्यान्वयन/चुनौती तक शामिल है।

एमईएस में आईएफए प्रणाली का कार्यान्वयनः 1 अप्रैल 2023 से एमईएस में सभी अनुबंधों के निविदा चरणों में आईएफए प्रणाली लागू की गई है। प्रमुख इंजीनियर की शाखा और तीनों सेनाओं की चिंताओं के समाधान के लिए आईएफए प्रणालियों की समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया गया है।

हरित ऊर्जा/ऊर्जा संरक्षण पहलः

- **सौर संयंत्रः** एमईएस ने पूरे भारत में 123 स्टेशनों पर 135 मेगावाट के सौर संयंत्रों का निर्माण पूरा कर लिया है।

- **रूफ टॉप सोलर (आरटीएस) परियोजनाएं: प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना'** के अंतर्गत,एमईएस सेना, नौसेना और वायु सेना स्टेशनों पर 40 मेगावाट की आरटीएस परियोजनाओं की संस्थापना में तेजी ला रहा है। 54 स्टेशनों की पहचान की गई है और दिसंबर 2025 तक कार्य पूरा करने की योजना है।

- **ग्रीहा रेटिंग:** एमईएस ने सभी नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए न्यूनतम तीन स्टार ग्रीहा (जीआरआईएचए) रेटिंग अनिवार्य कर दी है, जिससे बिजली की खपत में पर्याप्त कमी सुनिश्चित हुई है। सभी नए कार्यों के लिए रूफ टॉप सोलर परियोजनाओं के माध्यम से न्यूनतम 10% बिजली भार की योजना बनाई जा रही है।

- **डीम्ड लाइसेंसधारी (डिस्कॉम) के रूप में बिजली खरीद:** एमईएस कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में डिस्कॉम के रूप में कार्य कर रहा है। ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में डिस्कॉम का दर्जा प्राप्त करने के मामले अग्रिम चरणों में हैं।

- **भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज (आईईएक्स) के माध्यम से ओपन एक्सेस में बिजली की खरीद:** एमईएस ने दिल्ली, चंडीमंदिर, मेरठ, बरेली, अंबाला और जयपुर में आईईएक्स के माध्यम से ओपन एक्सेस में बिजली खरीद का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त बचत हुई है।

- **झांसी सैन्य स्टेशन में सीडब्ल्यूई कार्यालय के लिए भू–तापीय एचवीएसी भवन का निर्माण**

  एमईएस द्वारा कार्बन मुक्त पर्यावरण की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है, जिसके तहत झांसी सैन्य स्टेशन में हाल ही में 150 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ एक भू–तापीय एचवीएसी भवन का निर्माण पूरा किया गया है। कार्बन मुक्त होने के अलावा, इस प्रकार का निर्माण लागत प्रभावी,कम रखरखाव वाला, पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल भी है।

पूरी हो चुकी महत्वपूर्ण परियोजनाएँ

एमसीटीई, महू में सभी आर्म्स के कार्यालयों के लिए अपूर्ण आवासों को पूरा करने का प्रावधान: कार्य के प्रशासनिक अनुमोदन की राशि 4.12 करोड़ रूपये है। संबंधित कार्य पूरा हो चुका है।

एमएच दानापुर कैंट में ओपीडी कॉम्प्लेक्स का प्रावधानः कार्य के प्रशासनिक अनुमोदन की राशि 9.27 करोड़ रूपये है। संबंधित कार्य पूरा हो चुका है।

आईएनएस द्रोणाचार्य के विवाहित अधिकारी आवास की कमीः कार्य के प्रशासनिक अनुमोदन की राशि 32.98 करोड़ रूपये है। संबंधित कार्य पूरा हो चुका है।

आईएनएस हमला में भारतीय नौसेना जिम्नास्टिक और बॉक्सिंग टीम के लिए खेल अवसंरचना का प्रावधानः कार्य के प्रशासनिक अनुमोदन की राशि 20.78 करोड़ रूपये है। संबंधित कार्य पूरा हो चुका है।

जारी परियोजनाएँ

रणनीतिक महत्व की कई विशिष्ट और प्रतिष्ठित परियोजनाओं की योजना बनाई गई है और वे एमईएस द्वारा स्वीकृति/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। इन परियोजनाओं की प्रगति और स्वीकृत लागत इस प्रकार है:–

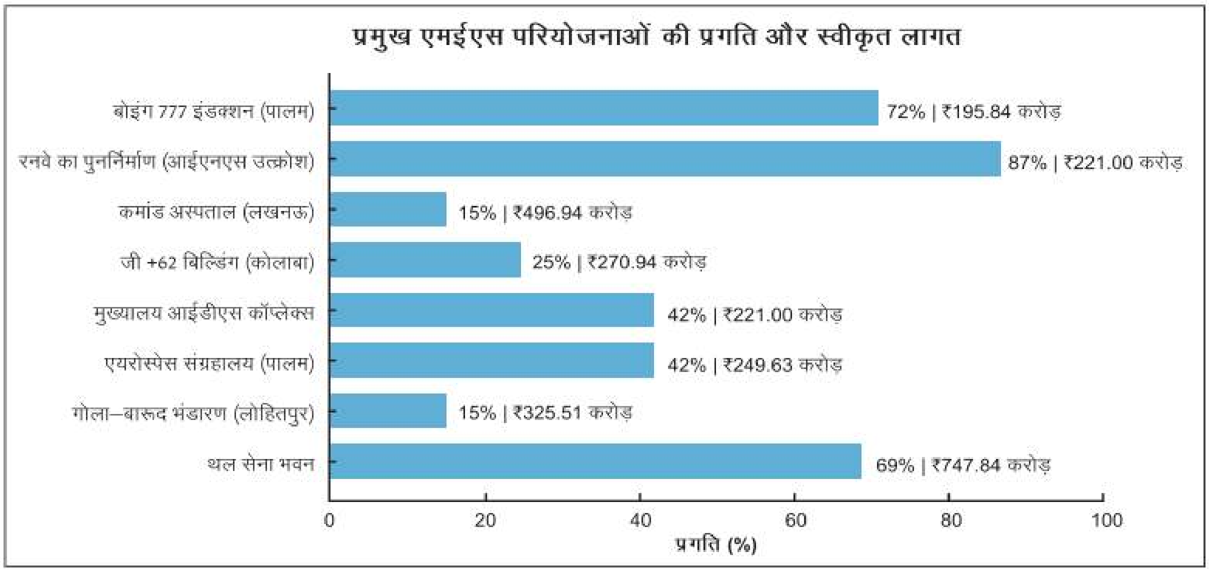

सेना खेल नियंत्रण बोर्ड

सेना खेल नियंत्रण बोर्ड (एसएससीबी) एक अंतर–सेना संगठन है जो सेना, नौसेना और वायु सेना अर्थात् तीनों सेनाओं में सेना कार्मिकों के लिए खेल गतिविधियों का प्रशासन, प्रोत्साहन एवं नियंत्रण करता है। बोर्ड को भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) और अधिकांश राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) का संस्थापक सदस्य होने का सम्मान प्राप्त है।एसएससीबी सशस्त्र बलों का शीर्ष खेल निकाय है जिसकी स्थापना का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने और पदक विजेता तैयार करने के लिए सेनाओं के खिलाड़ियों का चयन और प्रशिक्षण करने हेतु अंतर–सेना खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना है।

महत्वपूर्ण योगदान

एसएससीबी ने ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में देश के कुल पदकों में 20–25% पदक जीतकर भारत की पदक तालिका में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले पाँच वर्षों में, एसएससीबी राष्ट्रीय खेलों में पुरुष वर्ग में लगातार पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है।

38वें राष्ट्रीय खेल 2025: एसएससीबी ने 68 स्वर्ण, 26 रजत, 27 कांस्य और कुल 121 पदकों के साथ 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की ट्रॉफी जीती, जिसमें महाराष्ट्र और हरियाणा पदक तालिका में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

पेरिस ओलंपिक खेल 2024: कुल 117 सदस्यीय भारतीय दल में से सशस्त्र बलों के कुल 24 एथलीटों ने पेरिस ओलंपिक खेलों 2024 में भाग लिया। सूबेदार मेजर नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर के बेहतर थ्रो के साथ रजत पदक जीता है।

वर्ष 2024 के लिए काउंसिल इंटरनेशनलडु स्पोर्ट मिलिटेयर (सीआईएसएम)कार्यक्रमों में भागीदारीः एसएससीबी ने निम्नलिखित सीआईएसएम 2024 प्रतियोगिताओं में भाग लियाः –

क्र.सं	प्रतियोगिता	तारीख	स्थान	परिणाम
1	वॉलीबाल चैंपियनशिप	18–25 सितंबर 24	तेहरान, ईरान	दूसरा स्थान
2	कुश्ती चैंपियनशिप	17–24 नवंबर 24	यरेवान, अर्मिनिया	स्वर्ण–03 रजत–01 कांस्य–03
3	तैराकी चैंपियनशिप	09–14 दिसंबर 24	वेरॉनडोर्फ, जर्मनी	स्वर्ण–01 कांस्य–01

ओलंपिक खिलाड़ियों के चित्र

रैंक एवं नाम – ले. कर्नल नीरज चोपड़ा, वीएसएम, पीवीएसएम
खेल, प्रतिस्पर्धा एवं पदक – एथलेटिक्स/जैवलिन थ्रो – रजत पदक विजेता

रैंक एवं नाम –सीपीओ मोहम्मद अनास याहिया
खेल, प्रतिस्पर्धा एवं पदक – एथलेटिक्स /4x400 मीटर पुरूष रिले

रैंक एवं नाम – जेडब्ल्यूओ अबदुल्ला अबुबकर
खेल एवं प्रतिस्पर्धा – एथलेटिक्स /ट्रिपल जंप

रैंक एवं नाम – पीओ विकास सिंह
खेल – एथलेटिक्स/20 कि.मी. रेस वॉक

रैंक एवं नाम – सीपीओ रितिका हुड्डा
खेल एवं प्रतिस्पर्धा – कुश्ती/महिला 76 कि.ग्रा. फ्रीस्टाईल

रैंक एवं नाम – हवलदार जैसमीन लम्बोरिया
खेल – मुक्केबाजी/महिला फेदरवेट

एलीट एसएसबी खिलाड़ियों की तस्वीरें

रैंक एवं नाम – जीडीएसएम गुलवीर सिंह
खेल – एथलेटिक्स /10000 व 5000 मीटर

रैंक एवं नाम – पीओ हितेश गुलिया
खेल – मुक्केबाजी/70 कि.ग्रा.

रैंक एवं नाम – पीओ मो. अजमल वरियाथोड़ी
खेल एवं प्रतिस्पर्धा – एथलेटिक्स /4x400मीटर पुरूष रिले
पेरिस ओलंपिक खेलों 24 – 4x400 मीटर पुरूष रिले में भाग लिया

जनसंपर्क निदेशालय

जनसंपर्क निदेशालय (डीपीआर) संचार का अधिकृत माध्यम है, जिसका कार्य रक्षा मंत्रालय (एमओडी), सशस्त्र बलों, अंतर–सेवा संगठनों, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) आदि के प्रमुख नीतिगत निर्णयों, उपलब्धियों और आयोजनों के बारे में मीडिया के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुँचाना है। यह नियमित रूप से साक्षात्कारों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस दौरों के माध्यम से मंत्रालय के नेतृत्व और वरिष्ठ अधिकारियों और सशस्त्र बलों के अधिकारियों के साथ मीडिया बातचीत की सुविधा प्रदान करता है।

डीपीआर, मंत्रालय की नीतियों/ निर्णयों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्दों की समझ को बढ़ावा देने का प्रयास करता है ।यह गतिविधि देश भर में फैले इसके 25 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से पूरे भारत में संचालित की जाती है। निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में स्थित है। गणतन्त्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, रक्षा अलंकरण समारोह, एयरो इंडिया और डेफएक्सपो सहित सभी प्रमुख आयोजनों के लिए प्रचार गतिविधियां चलाई जाती हैं।

की गई गतिविधियां

प्रकाशन और प्रसारण: पाक्षिक पत्रिका सैनिक समाचार का 13 भाषाओं में प्रकाशन; सुदूर क्षेत्रों में सैनिकों के लिए रेडियो कार्यक्रम तैयार करना;रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के कार्यक्रमों की फोटो कवरेज प्रदान करना।

डिजिटल आउटरीच: X, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन पर सक्रिय रहना।

विशेष पहल: निम्नलिखित का प्रचार–प्रसार किया गया:

- डीआरडीओ, रक्षा उद्योग (डीपीएसयू सहित) और निजी क्षेत्र (स्टार्टअप और एमएसएमई सहित) की आत्मनिर्भरता की सफलता की कहानियाँ।
- वीरांगनाओं की कहानियाँ।
- रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' के लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में सरकार का दृष्टिकोण और सभी हितधारकों का योगदान।

मीडिया आउटपुट (अप्रैल 2024 – मार्च 2025):

- 977 प्रेस विज्ञप्तियाँ, 3207 फोटो विज्ञप्तियाँ
- 1,725 X पोस्ट, 837 फेसबुक पोस्ट, 1167 इंस्टाग्राम पोस्ट, 42 ऑडियो पॉडकास्ट
- 1,229 यूट्यूब पोस्ट, 1011 व्हाट्सएप चैनल पोस्ट, 1165 लिंक्डइन पोस्ट
- विभिन्न प्लेटफार्मों पर लगभग 55 मिलियन संचयी इंप्रेशन

क्षमता निर्माण: देश भर में 34 पत्रकारों के साथ रक्षा संवाददाता पाठ्यक्रम (अगस्त–सितंबर 2024) का आयोजन किया गया।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय

संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय अपने विशिष्ट प्रभागों के माध्यम से रक्षा मंत्रालय के सेना मुख्यालयों और अंतर–सेना संगठनों के विविध प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता है:

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सीएओ) कार्यालय के प्रभाग

जनशक्ति प्रभागः 821 सिविलियनों की नियुक्तियों का प्रबंधन किया। अनुकंपा नियुक्ति बोर्ड ने मृतक कर्मचारियों के 64 परिवारों पर विचार किया और 22 अनुकंपा नियुक्तियाँ प्रदान कीं।

आवास प्रभागः दिल्ली/नई दिल्ली स्थित रक्षा मंत्रालय/अंतर–सेना संगठनों के एकीकृत मुख्यालय में तैनात सेना के अधिकारियों को 51 बंगले और 1,222 फ्लैट आवंटित किए गए।

प्रशासनिक प्रभागः 6,780 सशस्त्र बल मुख्यालय सिविलियन कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्ते, अवकाश, संपत्ति लेनदेन का लेखा–जोखा,जीपीएफ/एनपीएस/यूपीएस मामलों, चिकित्सा दावों, पासपोर्ट/विदेश यात्रा/उच्च शिक्षा आदि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र और संबंधित सेवाओं का प्रबंधन किया।

पेंशन प्रकोष्ठः अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के 158 मामले, मृत्यु के 24 मामले और 10 अन्य मामले जैसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति, वीआरएस, अन्य संगठनों में आमेलन आदि का निपटान किया। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान पेंशन संशोधन के 36 मामले भी निपटाए गए।

वित्त एवं सामग्री प्रभागः बजट, खरीद, भंडार, सुरक्षा उपकरण और प्रत्यायोजन सहायता, प्रबंधन और 29.85 करोड़ रुपये के व्यय का पर्यवेक्षण किया।

कार्मिक एवं विधि प्रभागः 65 विभागीय पदोन्नति समितियाँ (डीपीसी) आयोजित कीं, 1,098 अधिकारियों को पदोन्नत किया और 220 तदर्थ पदोन्नति प्रदान की। मिशन नियुक्ति के अंतर्गत 871 नई नियुक्तियाँ कीं। न्यायालयों में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय का प्रतिनिधित्व किया और 10 रिव्यू डीपीसी की, जिनसे 2,855 अधिकारी प्रभावित हुए।

सुरक्षा कार्यालयः 18 डीएचक्यू भवनों में सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित की; लगभग 80,000 प्रवेश पास जारी किए, जिनमें कोई बड़ी चूक नहीं हुई। सुरक्षा कार्यालय, सेना मुख्यालयों के साथ इंट्रानेट पर एसएलएसी, डीएसीऔर अनुमतियाँ जारी करने के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन कार्य कर रहा है। सेना मुख्यालयों के लिए रक्षा मंत्रालय एक्सेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर (आरएएमएस) की शुरुआत के साथ पास जारी करने की क्षमता कई गुना बढ़ गई है।

विशेष परियोजना एवं निर्माण प्रभागः

(i) **आरडीसी 2025 के भाग के रूप में राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता 2024–25 :** गणतंत्र दिवस समारोह–2025 के भाग के रूप में राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता 2024–25, रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सहयोग से तीसरी बार आयोजित की गई। प्रतियोगिता तीन स्तरों पर अर्थात् राज्य स्तर, क्षेत्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर (फाइनल) और चार श्रेणियों (लड़कों का ब्रास बैंड,लड़कियों का ब्रास बैंड, लड़कों का पाइप बैंड और लड़कियों का पाइप बैंड) में आयोजित की गई थी। राज्य स्तर पर 568 टीमों (13999 बच्चों) ने भाग लिया। क्षेत्रीय स्तर पर 84 टीमों (2337 विद्यार्थियों) ने भाग लिया। प्रत्येक श्रेणी के फाइनलिस्टों को प्रमाण पत्र, ट्रॉफी और नकद पुरस्कार दिए गए। 16 फाइनलिस्ट टीमों में से, 3 स्कूली टीमों ने 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान विजय चौक के मंच पर प्रस्तुति दी।

(II) **राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में शामिल करना :** रक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी के संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों में निम्नलिखित अध्यायों/कविताओं को शामिल/प्रकाशित किया गया है:–

क्र.सं.	विषय/भाषा	कक्षा	अध्याय/कविता	प्रकाशन /वर्ष
(क)	अंग्रेजी	VI	राष्ट्रीय युद्ध स्मारक (कविता)	2024–25
(ख)	उर्दू	VI	वीर अब्दुल हमीद	2024–25

रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान (डीएचटीआई):–

(i) रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान (डीएचटीआई), संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक (एनएससीएसटीआई) के तहत प्रमाणित संस्थान है जो सशस्त्र बल मुख्यालय के अधिकारियों और पदाधिकारियों के विभिन्न संवर्गों और श्रेणियों के साथ–साथ विभिन्न रैंकों के सेना अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण, व्यावसायिक कार्यक्रमों और कार्यशालाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इसके अतिरिक्त, संस्थान ने भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और अन्य संगठनों के सिविलियन घटकों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम और कार्यशालाएँ भी आयोजित की गईं।

(ii) वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, संस्थान ने 36 प्रशिक्षण कार्यक्रम, 67 कार्यशालाएँ/विशेष पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए और 1700 से अधिक पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। इसके अतिरिक्त, संस्थान ने सशस्त्र बल ने मुख्यालय के अधिकारियों के लिए 05 दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों, अन्य संगठनों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 07 पाठ्यक्रमों और 02 कार्यशालाओं में प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की।

(iii) प्रशिक्षण प्रदायगी और संस्थागत विकास में उत्कृष्टता के लिए इसके निरंतर प्रयासों के सम्मान में, संस्थान को एनएससीएसटीआई द्वारा "उत्तम" सम्मान प्रदान किया गया।

मुख्य उपलब्धियां

नौसेना भवन का उद्घाटन

नौसेना भवन (एनएसबी) का उद्घाटन माननीय रक्षा मंत्री द्वारा मार्च 2024 में किया गया था। एनएसबी पूरी तरह से भर गया है और एक कुशल सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है।

डीएचक्यू सैनिक

- **सुरक्षा हथियारों और उपकरणों का उन्नयनः** डीएचक्यू सुरक्षा क्षेत्र के दायरे में आने वाले रक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठानों को पूर्ण सुरक्षा कवर सुनिश्चित करने के लिए डीएचक्यू सैनिकों के हथियारों/उपकरणों को उन्नत/नियोजित किया गया है।

- **डीएचक्यू सैनिकों के मेधावी बच्चों के लिए छात्रवृत्तिः** डीएचक्यू सैनिकों के मेधावी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की गई है। डीएचक्यू सैनिकों और उनके परिवारों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रति विद्यार्थी15,000/– रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। डीएससी सैनिकों के दिव्यांग बच्चों की सुविधा के लिए उन्हें 11,000/– रुपये का एकबारगी अनुदान दिया गया।

इतिहास प्रभाग

इतिहास प्रभाग, जिसे पहले ऐतिहासिक अनुभाग के नाम से जाना जाता था, की स्थापना 26 अक्टूबर, 1953 को स्वतंत्रता के बाद से भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा किए गए सैन्य अभियानों के इतिहास को संकलित करने के लिए की गई थी।

इतिहास प्रभाग रक्षा मंत्रालय और भारतीय सशस्त्र बलों के अभिलेख, अनुसंधान और संदर्भ कार्यालय के रूप में कार्य करता है। अब तक, इस प्रभाग ने 21 खंडों का संकलन और प्रकाशन किया है, जिनमें ऑपरेशन पोलो का इतिहास, ऑपरेशन विजय (गोवा), 1965 का भारत–पाकिस्तान युद्धः एक इतिहास, 1971 का भारत–पाकिस्तान युद्धः एक इतिहास, वीरता की गाथा और पराक्रम गाथा (परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता) शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के तहत भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा संचालित किए गए अभियानों का इतिहास भी प्रकाशित किया गया है। इस प्रभाग ने महावीर चक्र विजेताओं पर एक पुस्तक भी संकलित की है जो प्रकाशनाधीन है।

इसके अलावा, इतिहास प्रभाग ने अवर्गीकृत अभिलेखों का डिजिटलीकरण शुरू कर दिया है और इस प्रक्रिया में, अब तक लगभग 18 लाख पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। प्रभाग ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से 'समर अभिलेख' नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल में 38,000 से अधिक अवर्गीकृत अभिलेख, पुस्तकें, रिपोर्ट और तस्वीरें आदि हैं, जिनमें भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित लगभग 50 लाख पृष्ठ हैं। इस पोर्टल को इंटरनेट पर *samar.IIt.ac.in* पर देखा जा सकता है। प्रभाग ने 31,000 से अधिक अवर्गीकृत फाइलें भी राष्ट्रीय अभिलेखागार को हस्तांतरित की हैं।

प्रभाग के हेराल्डिक सेल ने तीनों सेनाओं और तटरक्षक बल को समारोह संबंधी कार्यों में सहायता प्रदान की, जिनमें प्रतिष्ठान का नामकरण, क्रेस्ट डिजाइन और आदर्श वाक्य निर्माण शामिल हैं। यह राष्ट्रपति कलर समारोहों के लिए भारतीय वायुसेना इकाई के इतिहास की समीक्षा भी करता है। इसने गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रश्नावली प्रदान करके और निबंध प्रतियोगिता आयोजित करने में भी रक्षा मंत्रालय (समारोह) की सहायता की।

यह प्रभाग रेजिमेंटल इतिहास, कॉफ़ी–टेबल पुस्तकों और सैन्य फ़िल्मों की पटकथाओं की समीक्षा करता है, फ़िल्मों के फ़िल्मांकन में सहायता प्रदान करता है और फ़िल्म रिलीज़ के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करता है।

इस प्रभाग के विभागीय पुस्तकालय में 8,000 से ज़्यादा पुस्तकें हैं, जिनमें 150 पुस्तकें प्रतिवर्ष जुड़ती रहती हैं। फ़ेलोशिप योजना के तहत हर तीन साल में दो फ़ेलोशिप प्रदान की जाती हैं,जिससे अब तक 22 शोधकर्ता लाभान्वित हुए हैं।

पर्वतारोहण संस्थान

रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में निम्नलिखित चार पर्वतारोहण संस्थान (जो स्वायत्त निकाय हैं और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत हैं) अपनी कार्यकारी परिषदों द्वारा शासित होते हैं, जिनकी अध्यक्षता माननीय रक्षा मंत्री करते हैं:–

1) हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान (एचएमआई), दार्जिलिंग

2) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (एनआईएम), उत्तरकाशी

3) जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान (जेआईएम एंड डब्ल्यूएस), पहलगाम

4) राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्थान (एनआईएमएएस), दिरांग

ये संस्थान पूरे वर्ष पर्वतारोहण और साहसिक खेलों में विभिन्न अल्पकालिक और दीर्घकालिक पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। इनकी वेबसाइटें पूरी तरह कार्यशील हैं और किसी विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इनसे संपर्क किया जा सकता है।

ये संस्थान वर्ष 2024 के दौरान अपनी कई उपलब्धियों के लिए सुर्खियों में रहे। इनमें से कुछ उपलब्धियाँ नीचे दी गई हैं:–

एचएमआई, दार्जिलिंग

माउंट किलिमंजारो (अफ्रीका की सबसे ऊँची चोटी) का अभियान एक टीम द्वारा किया गया था, जिसमें एक दिव्यांगजन सदस्य श्री उदय कुमार (तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार विजेता 2023) जिनके घुटने के ऊपर 91% अंग–विच्छेदन है, भी शामिल थें। अभियान दल ने माउंट किलिमंजारो (19,341 फीट) की चोटी पर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद, टीम ने तंजानिया के दार एस सलाम के पास हिंद महासागर में 35 फीट की गहराई पर पानी के नीचे राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया और उसके बाद अफ्रीकी महाद्वीप पर किसी दिव्यांगजन टीम द्वारा पहली बार टैंडम स्काईडाइव किया गया।

किलिमंजारो पर्वत शिखर पर

हिंद महासागर में 35 फीट की गहराई पर पानी के भीतर तिरंगा प्रदर्शन

दिव्यांग सदस्य द्वारा टैंडम स्काईडाइव और लीडर द्वारा सोलो स्काईडाइव.

एनआईएम, उत्तरकाशी

सहस्त्र ताल ट्रेक पर कर्नाटक के पर्यटकों के बचाव के लिए एनआईएम खोज एवं बचाव दल की तैनातीः संस्थान ने उत्तराखंड राज्य सरकार के अनुरोध पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए,सहस्त्र ताल ट्रेक पर कर्नाटक के पर्यटकों के लिए एक कुशल खोज एवं बचाव दल तैनात किया।

माउंट जोगिन पर चढ़ाईः एनआईएम ने माउंट जोगिन–III (6116 मीटर) और माउंट जोगिन–I (6465 मीटर) पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की।

माउंट जोगिन–III(6116 मीटर)

माउंट जोगिन–I(6465मीटर)

11 चोटियों का अभियान: एनआईएम ने उत्तराखंड के माना क्षेत्र में ग्यारह ऐसी चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की, जिन पर पहले कभी चढ़ाई नहीं की गई थी। यह उपलब्धि उन बहादुर प्रशिक्षुओं को समर्पित है, जिन्होंने 2022 के हिमस्खलन में दुखद रूप से अपनी जान गंवा दी। इस अभियान ने 8 दिनों के भीतर एक ही अभियान में 11 चोटियों पर चढ़ाई और 8 घंटे में 6000 मीटर से ऊँची 5 चोटियों पर चढ़ाई कर दो महत्वपूर्ण रिकॉर्ड स्थापित किए।

जेआईएम एंड डब्ल्यूएस, पहलगाम

माउंट कांग यात्से–I (6415 मीटर), माउंट कांग यात्से–II (6250 मीटर), माउंट चमसेर कांगड़ी (6630 मीटर), माउंट लुंगसेर कांगड़ी (6676 मीटर), माउंट ज़ो जोंगो (पश्चिम)–I (6307 मीटर) और माउंट ज़ो जोंगो (पूर्व)–II (6220 मीटर) के अभियान सफलतापूर्वक संचालित किए गए।

एनआईएमएएस, दिरांग

एमआईएमएएस ने एक स्वतंत्र अभियान के माध्यम से तीसरी बार माउंट गोरीचेन (6488 मीटर) की चोटी पर चढ़ाई की। गति, समन्वय और सहनशक्ति के असाधारण प्रदर्शन के साथ, 25 पर्वतारोही केवल 13 दिनों के भीतर शिखर पर पहुँच गए – जो इस चोटी पर अब तक की सबसे तेज़ चढ़ाई में से एक है।

राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय

राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय (एनडीसी) रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक अध्ययन से संबंधित मामलों में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाई है और यह रणनीतिक नेतृत्व का एक केंद्र है। यह भारत के सशस्त्र बलों और सिविल सेवाओं के चुनिंदा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ–साथ मित्र देशों के प्रतिभागियों के बौद्धिक विकास और रणनीतिक संस्कृतिकरण के लिए समर्पित है। वर्ष 2024 के दौरान 64वां एनडीसी पाठ्यक्रम 120 अधिकारियों के साथ शुरू हुआ, जिसमें सेना (42), नौसेना (07), वायु सेना (13), सिविल सेवा (19) और मित्र देशों (39) के अधिकारी शामिल थे।

राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय 64वां पाठ्यक्रम, 2024

पाठ्यक्रम और संरचनाः अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित 11 महीने के कार्यक्रम में प्रतिभागिता करते हैं,जिसमें भावी नीति निर्माताओं को तैयार करने के लिए घरेलू, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को शामिल किया जाता है। पाठ्यक्रम में सामाजिक–राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक और तकनीकी मुद्दों, रणनीतिक पड़ोस और राष्ट्रीय सुरक्षा संरचनाओं पर अध्ययन मॉड्यूल शामिल हैं। इसमें व्याख्यान, पैनल चर्चाएँ, रणनीतिक अभ्यास, क्षेत्र भ्रमण, शोध और शोध प्रबंध लेखन शामिल हैं। सफलतापूर्वक पूरा करने पर, प्रतिभागियों को संबद्ध संस्थान/विश्वविद्यालय से उपाधियाँ प्रदान की जाती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय जुड़ावः पाठ्यक्रम के दौरान,पाठ्यक्रम के सदस्यों को कई विदेशी प्रतिनिधिमंडलों और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गणमान्य व्यक्तियों, राष्ट्राध्यक्षों, मंत्रियों, राजदूतों, शिक्षाविदों और थिंक टैंकों के साथ प्रत्यक्ष बातचीत का लाभ मिलता है। दिनांक 29 फरवरी, 2024 को श्रीलंका के थल सेनाध्यक्ष, 8 अगस्त, 2024 को कज़ाकिस्तान के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कमांडेंट और 12 अगस्त, 2024 को फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने कॉलेज में पाठ्यक्रम के सदस्यों को संबोधित किया। भारत के उपराष्ट्रपति ने दिनांक 21 नवंबर, 2024 को एनडीसी का दौरा किया और पाठ्यक्रम के सदस्यों को संबोधित किया।

राष्ट्रपति का अभिभाषणः दिनांक 1 अक्टूबर, 2024 को आयोजित इस मुलाकात के दौरान, राष्ट्रपति ने पाठ्यक्रम के सदस्यों को संबोधित किया और भविष्य के जटिल सुरक्षा परिवेश से व्यापक रूप से निपटने के लिए रणनीतिक नेताओं को तैयार करने में एनडीसी द्वारा निभाई जा रही भूमिका की सराहना की।

दीक्षांत समारोहः 19 अक्टूबर, 2024 को माननीय रक्षा मंत्री की उपस्थिति में 62वें पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों को एम. फिल की उपाधि प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया।

नए कार्यक्रम और पहलः नई शिक्षा नीति, 2020 के तहत एम.फिल. कार्यक्रम बंद होने के कारण, मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध इस कॉलेज ने शैक्षणिक वर्ष 2023–24 से रक्षा एवं सामरिक अध्ययन में दो वर्षीय एम.एससी. कार्यक्रम और शैक्षणिक वर्ष 2024 से पीएच.डी. (रक्षा एवं सामरिक अध्ययन) (अंशकालिक) कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अलावा, एनडीसी पाठ्यक्रम के सदस्यों, संकाय और अन्य कर्मचारियों के लिए आईआईटी, मद्रास के तत्वावधान में 'रणनीतिक नेतृत्व एवं लोक नीति' में एक वर्षीय कार्यकारी एमबीए कार्यक्रम शैक्षणिक वर्ष 2024 से शुरू किया गया है।

पाठ्यक्रम की स्नातक उपाधि और अगला प्रवेशः 64वें एनडीसी पाठ्यक्रम के सदस्य 29 नवंबर, 2024 को स्नातक हुए और आगामी 65वां एनडीसी पाठ्यक्रम 6 जनवरी, 2025 को शुरू हुआ, जिसमें 124 पाठ्यक्रम सदस्य शामिल थे, जो सेना (41), नौसेना (07), वायु सेना (13), सिविल सेवा (19) और मित्र देशों (44) से थे।

विदेशी भाषा विद्यालय

विदेशी भाषा विद्यालय (एसएफएल) रक्षा विभाग के प्रशासनिक और कार्यात्मक नियंत्रण के अंतर्गत एक प्रतिष्ठित और विशिष्ट विदेशी भाषा संस्थान है। इसे वर्ष 1949 से रणनीतिक विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण देने का अधिकार प्राप्त है और यह भारतीय सशस्त्र बलों,सीएपीएफ, आसूचना एजेंसियों और अन्य सरकारी विभागों आदि के कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह अनिवार्य विदेशी भाषा (सीएफएल) प्रशिक्षण और परीक्षा आयोजित करने के लिए विदेश मंत्रालय के लिए विदेशी भाषा प्रशिक्षण और परीक्षा के संदर्भ में एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

पाठ्यक्रम

संस्थान विभिन्न संरचित भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करता है, जिनमें दक्षता प्रमाणपत्र (सीओपी) और दक्षता संबंधी एडवांस्ड डिप्लोमा (एडीओपी) (दोनों जुलाई से मई तक), दुभाषिया पाठ्यक्रम ($16\frac{1}{2}$ से $23\frac{1}{2}$ महीने), और विभिन्न अल्पकालिक पाठ्यक्रम (120 घंटे से अधिक) शामिल हैं, जो विविध सेवा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

परीक्षाएँ/परीक्षण

विदेशी भाषा विद्यालय प्रवीणता स्तर की जांच करने के लिए, भारतीय विदेश सेवा (परिवीक्षाधीन) के लिए नियमित आधार पर परीक्षाएँ आयोजित करके सरकारी एजेंसियों को सहायता प्रदान करता है। मूल्यांकन बाहरी एजेंसियों के भाषा विशेषज्ञों और आंतरिक व्याख्याताओं/संकाय द्वारा किया जाता है। पैटर्न और पाठ्यक्रम समय–समय पर आवश्यकतानुसार अद्यतन किए जाते हैं।

आँकड़े (2024–25)

- वर्ष के दौरान, कुल 199 कर्मियों ने दुभाषिया प्रशिक्षण एडीओपी, सीओपी और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों सहित विभिन्न विदेशी भाषा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भाषाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी, जैसे रूसी, चीनी, अरबी, स्पेनिश, फ्रेंच, फ़ारसी,जापानी, जर्मन, सिंहली, हिब्रू, इंडोनेशियाई, बर्मी और उर्दू। इन कार्यक्रमों ने सेना, नौसेना, वायु सेना और तटरक्षक बल की आवश्यकताओं को पूरा किया, जिससे परिचालनात्मक, कूटनीतिक और आसूचना संबंधी आवश्यकताओं के लिए सेनाओं की भाषाईक्षमता मजबूत हुई।
- वर्ष के दौरान, कुल 734 उम्मीदवार विभिन्न भाषा प्रवीणता परीक्षाओं में शामिल हुए,जिनमें दुभाषिया, सीओपी, एडीओपी (विभिन्न एजेंसियों के लिए) और विशेष प्रवीणता परीक्षाएँ शामिल हैं। ये परीक्षाएँ विभिन्न हितधारकों जैसे मंत्रिमंडल सचिवालय, विदेश मंत्रालय, सेना मुख्यालय, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और अन्य विशिष्ट एजेंसियों के लिए आयोजित की गई, जिससे सेनाओं की सक्रियात्मक और रणनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योग्य भाषाविदों का एक सतत समूह सुनिश्चित हुआ।

कैंटीन भंडार विभाग

वर्तमान कैंटीन भंडार विभाग की स्थापना 1 जनवरी 1948 को 48 लाख रुपये की कार्यशील पूंजी के साथ की गई थी जो इसे इसके पूर्ववर्ती युद्धकालीन संगठन की परिसंपत्तियों से तीन वर्षों के लिए प्रायोगिक आधार पर सौंपी गई थी। वर्ष 1950 में इस स्थिति की समीक्षा की गई और विभाग को एक स्थायी सरकारी उपक्रम के रूप में स्वीकार कर लिया गया और भारतीय सैनिकों के लिए कैंटीन सुविधाओं की अवधारणा को पुनर्जीवित किया गया।

1 अप्रैल 1977 को, इसे एक सरकारी उपक्रम से एक पूर्ण सरकारी विभाग में परिवर्तित कर दिया गया। यह परिवर्तन ऐतिहासिक महत्व का है, क्योंकि इसके बाद, विभाग द्वारा वर्षों से संचित समस्त धनराशि को भारत की संचित निधि (सीएफआई) में मिला दिया गया और इसके कर्मचारी केंद्र सरकार के नियमित कर्मचारी बन गए।

विजनः आधुनिक भारत की उभरती आर्थिक वास्तविकताओं की गतिशीलता का सामना करने के लिए कैंटीन भंडार विभाग के मानव, बुनियादी ढाँचे, भौतिक और वित्तीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग और विकास करने हेतु व्यावहारिक और सक्रिय रणनीतियों को अपनाकर उपभोक्ता संतुष्टि के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना।

लक्ष्यः अखिल भारतीय स्तर पर नवीनतम और गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता उत्पाद सस्ती दर पर उपलब्ध कराकर सशस्त्र बल समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करना।

भौगोलिक कवरेजः सीएसडी देश भर में कुल 34 केन्द्रों के साथ संचालित होता है, जो कुशल सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक रूप से वितरित हैं। विभाग के भौगोलिक कवरेज में पूर्वी (7), पश्चिमी (6), उत्तरी (7), दक्षिणी (8), और मध्य (6) क्षेत्र शामिल हैं, जिससे यह भारत के सभी प्रमुख क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएँ प्रदान कर पाता है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ और सफलताएं

भारत की सबसे बड़ी खुदरा श्रृंखलाओं में से एकः वित्त वर्ष 2024–25 में 30,000 करोड़ रुपये के अनुमानित वार्षिक कारोबार के साथ, यह विभाग भारत की सबसे बड़ी खुदरा श्रृंखलाओं में से एक है और लगभग 44.8 लाख लाभार्थियों को सेवा प्रदान कर रहा है, जिनका विवरण नीचे दी गई ग्राहक प्रोफ़ाइल में दिया गया हैः

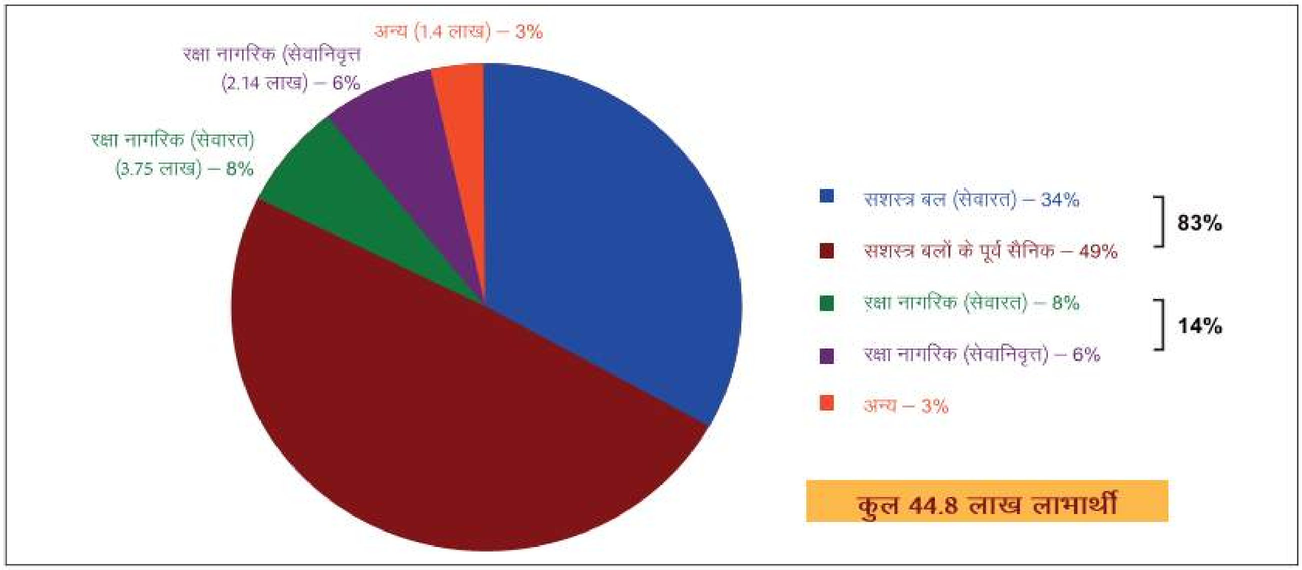

सैनिकों और परिवारों के कल्याण हेतु मात्रात्मक छूट (क्यूडी) और कैंटीन निवल व्यापार अधिशेष (सीटीएस) का वितरणः सीएसडी, रक्षा विभाग (एमओडी) के अंतर्गत एक राजस्व सृजन करने वाला विभाग है। इसके लाभार्थियों को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए कम लाभ मार्जिन के बावजूद, वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, लाभार्थी संगठनों को क्यूडीके रूप में 426.54 करोड़ रूपये और सीटीएसके रूप में 131.24 करोड़ रूपये की राशि वितरित की गई, जिसका उपयोग इस विषय पर रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए किया जाएगा।

सरकारी पहलों से जुड़े कार्यक्रम

वर्ष के दौरान, सीएसडी ने राष्ट्रीय गौरव, सामाजिक उत्तरदायित्व और कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहल कीं। प्रमुख गतिविधियों में राष्ट्रीय एकता को मज़बूत करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान और स्वच्छता एवं स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता ही सेवा अभियान में भागीदारी शामिल थी। सीएसडी ने समग्र स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र, अखंडता को मज़बूत करने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह और व्यसन मुक्त जीवन जीने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान का भी आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर, जागरूकता व्याख्यान, स्वास्थ्य जाँच शिविर और महिला कर्मचारियों के लिए सरकारी योजनाओं पर सत्र आयोजित किए गए।

इन कार्यक्रमों की कुछ झलकियाँ नीचे दी गई हैं:–

घाटकोपर एस्टेट में हर घर तिरंगा अभियान

घाटकोपर एस्टेट में एक पेड़ माँ के नाम अभियान

आगरा डिपो में स्वच्छता अभियान 2024

दिल्ली डिपो में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024

लखनऊ डिपो में नशा मुक्त भारत अभियान

सीएसडी, एचओ मुंबई में मेडिकल कैंप

माननीय रक्षा राज्य मंत्री का दौरा

माननीय रक्षा राज्य मंत्री ने 15 जनवरी, 2025 को सीएसएचओ, मुंबई का दौरा किया और उन्हें सीएसडी के समग्र कामकाज और विभाग द्वारा की गई पहलों के बारे में जानकारी दी गई।

माननीय रक्षा राज्य मंत्री का सीएसडी, एचओ मुंबई को दौरा

माननीय रक्षा राज्य मंत्री का सीएसडी, मुंबई में प्रदर्शित सामग्री का निरीक्षण करते हुए

कैंटीन भंडार विभाग का भावी रोडमैप

सीएसडी ई–कॉमर्स परियोजना का कार्यान्वयनः

सीएसडी लाभार्थियों को उनके इनटाइटलमेन्ट के 50% तक के सामान की घर पर डिलीवरी की सुविधा प्रदान करने के लिए, सीएसडी ने अपना ई–कॉमर्स पोर्टल लॉन्च करने की पहल की है। एग्रीगेटर के नियोजन के लिए निविदा प्रकाशित हो चुकी है और सीएसडी ई–कॉमर्स परियोजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रायोगिक चरण में सात डिपो में होने की उम्मीद है। यह परियोजना हमारे सम्मानित लाभार्थियों को बेहतर ग्राहक संतुष्टि प्रदान करने में बहुत सहायक होगी।

सीएसडी स्वचालन परियोजना का कार्यान्वयन

सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप, सीएसडी ईआरपी आधारित समाधान का उपयोग करके आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, वित्त और प्रशासन सहित संपूर्ण प्रचालनों को स्वचालित करने की प्रक्रिया में है। यह प्रक्रियाओं को इष्टतम बनाने और विभाग की समग्र दक्षता को बढ़ाने में मदद करेगा। वर्तमान में,परियोजना के लिए आरएफपी को अंतिम रूप दिया जा रहा है और वित्तीय वर्ष 2026–27 तक इसके कार्यान्वयन की उम्मीद है।

रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय

रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय (सीडीएम) एक त्रि–सेना संस्थान है जो तीनों सेनाओं, अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ नेतृत्व, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को समकालीन प्रबंधन का कौशल प्रदान करता है। सीडीएम में प्रदान की जाने वाली शिक्षा काएक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है जिसमें एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत द्वीप समूह के सैन्य अधिकारी (कर्नल और समकक्ष) शामिल हैं।

रक्षा सेना स्टाफ कॉलेज

रक्षा सेना स्टाफ कॉलेज (डीएसएससी) एक उत्साहवर्धक वातावरण प्रदान करता है और मध्य स्तरीय सैन्य नेतृत्व के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हुए, उत्कृष्ट स्टाफ अधिकारियों और विशिष्ट लीडर्स को सशस्त्र बलों के पथप्रदर्शकों के रूप में तैयार करता है, जिनमें व्यावसायिकता का उच्च स्तर होता है और जो 'कर्तव्य, सम्मान और वीरता' के गुणों को दृढ़ता से बनाए रखते हैं।

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण

सरकार ने तीनों सेनाओं (सेना, नौसेना और वायु सेना) के सदस्यों के सेवा मामलों और कोर्ट मार्शल के फैसलों से उत्पन्न अपीलों से संबंधित शिकायतों और विवादों के निपटारे और सशस्त्र बलों के सदस्यों को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) की स्थापना की है। वर्तमान में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण दिल्ली (प्रधान पीठ) और चेन्नई, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता, कोच्चि, गुवाहाटी, मुंबई, जबलपुर और श्रीनगर (जम्मू में कार्यरत) स्थित क्षेत्रीय पीठों में कार्यरत हैं।

*****

रक्षा वित्त

रक्षा मंत्रालय में वित्त प्रभाग उन सभी मामलों को देखता है जिनका वित्तीय प्रभाव होता है। इस प्रभाग की अध्यक्षता सचिव (रक्षा वित्त)/ वित्त सलाहकार (रक्षा सेवाएं) करते हैं।

निर्णय लेने में आसानी के लिए रक्षा मंत्रालय को ज़्यादा वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। इन शक्तियों का इस्तेमाल वित्त प्रभाग की सहमति से किया जाता है। वित्त प्रभाग रक्षा सेवा अनुमान, रक्षा मंत्रालय के सिविल अनुमान और रक्षा पेंशन के अनुमान तैयार करता है और उन पर निगरानी रखता है। इस मंत्रालय के चार अनुदानों के लिए साल 2023–24 के वास्तविक खर्च का ब्रेक–अप, 2024–25 के संशोधित अनुमान और 2025–26 के बजट अनुमान और रक्षा सेवा अनुमानों का सेवा/विभाग–वार ब्रेक–अप, तालिका क और तालिका ख में दिए गए हैं।

तालिका कः रक्षा व्यय का अनुदान–वार ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

अनुदान का विवरण	2023–24 के वास्तविक आंकड़े	2024–25 संशोधित अनुमान	2025–26 बजट अनुमान (निवल)
अनुदान संख्या 19 रक्षा मंत्रालय (सिविल) (निवल)	22,712.09	26,656.65	28,682.97
अनुदान संख्या 20 रक्षा सेवॉए– राजस्व (निविल)	2,90,442.92	2,97,222.35	3,11,732.30
अनुदान संख्या 21 (रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)	1,54,256.28	1,59,500.00	1,80,000.00
अनुदान संख्या 22 रक्षा पेंशन	1,42,092.99	1,57,681.00	1,60,795.00
कुल योग	**6,09,504.28**	**6,41,060.00**	**6,81,210.27**

तालिका खः रक्षा सेवा अनुमानों का सेवा/विभाग–वार ब्यौरा [राजस्व (निवल)+पूंजी]

(रुपये करोड़ में)

सेवा/विभाग	2023–24 के वास्तविक आंकड़े	2024–25 संशोधित अनुमान	2025–26 बजट अनुमान
सेना	220222.16	2,32,654.77	2,39,600.68
नौसेना	85,024.15	97,880.29	1,03,502.62
वायु सेना	1,13,782.54	98,142.91	1,18,511.68
आयुध निदेशालय (समन्वय एवं सेवाएँ)	1,787.61	2,097.85	1,965.50
महानिदेशक, गुणता आश्वासन	955.22	1,249.59	1,335.00
अनुसंधान एवं विकास	22,927.52	24,696.94	26,816.82
कुल	**4,44,699.20**	**4,56,722.35**	**4,91,732.30**

रक्षा लेखा विभाग

रक्षा लेखा विभाग (डीएडी), रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है और इसकी अध्यक्षता रक्षा लेखा महानियंत्रक करते हैं। यह भारत सरकार के सबसे पुराने विभागों में से एक है, जिसकी विरासत 277 साल से ज़्यादा पुरानी है। यह विभाग, रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले सभी संगठनों जैसे सेना, नौसेना, वायु सेना, भारतीय तटरक्षक, बीआरओ, डीआरडीओ, डीजीडीई, एमईएस इत्यादि की आतंरिक लेखा–परीक्षा, लेखा खातों, भुगतान और उनको वित्तीय सलाह देने संबंधी कार्य करने के लिए अधिदेशित है। इन कार्यों का उद्देश्य रक्षा संबंधी राष्ट्रीय सुरक्षा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए रक्षा वित्त का सबसे अच्छा और नतीजा देने वाला उपयोग और प्रबंधन सुनिश्चित करना है। रक्षा लेखा विभाग देश भर में 269 जगहों पर मौजूद 1,154 कार्यालयों के एक मज़बूत नेटवर्क के ज़रिए काम करता है। यह विभाग, रक्षा मंत्रालय के सकल बजट के प्रबंधन के लिए ज़िम्मेदार है।

प्रमुख उपलब्धियाँ

परियोजना ई–रक्षा आवास

प्रोजेक्ट ई–रक्षा आवास को रक्षा लेखा विभाग ने क्रियान्वित किया था ताकि रक्षा कार्मिकों, सिविलियनों द्वारा अधिभोग किए गए सरकारी आवासों और निजी/व्यावसायिक संपत्तियों के किराया बिलों और उससे संबंधित प्रभारों को तैयार करने और अग्रेषण को आसान बनाया जा सके।

एक केन्द्रीकृत एप्लिकेशन के तौर पर, ई–रक्षा आवास ने राजस्व का काम संभालने वाले सभी एएओ (बीएसओ) और एओ (जीई) कार्यालयों में पहले के स्टैंडअलोन एप्लिकेशन 'भवन' की जगह ले ली है। ई–रक्षा आवास पर 595.06 करोड़ रुपये के 33 लाख से ज़्यादा किराए के बिल तैयार किए गए हैं।

रक्षा यात्रा प्रणाली 2.0

डीटीएस 2.0 को माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डीएडी डे, यानी 1 अक्तूबर, 2024 को लॉन्च किया था। डीटीएस 2.0 में बेहतर निष्पादन और एप्लिकेशन आर्किटेक्चर की स्केलेबिलिटी जैसी बेहतर विशेषताएं हैं।

डीटीएस 2.0 काफी कम लेटेंसी और बेहतर सिस्टम रिलायबिलिटी के साथ बेहतर यूज़र इंटरफ़ेस देता है। रोज़ाना प्रोसेस होने वाली बुकिंग की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। डीटीएस 1.0 में प्रति दिन 20,000 रेल बुकिंग और 2,000 एयर बुकिंग की तुलना में, डीटीएस 2.0 में प्रति दिन 35,000 रेल बुकिंग और 3,500 एयर बुकिंग की गई हैं, जो इसकी बेहतर ऑपरेशनल कार्य–कुशलता को दर्शाता है।

ई–एचआरएमएस 2.0 का कार्यान्वयन

भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के अवकाश प्रबंधन, प्रतिपूर्ति, प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में एंड–टू–एंड ऑनलाइन एचआर सेवा प्रदान करने के लिए नए ई–एचआरएमएस 2.0 को लॉन्च किया। डीएडी में ई–एचआरएमएस 2.0 को नवंबर 2024 में लागू किया गया।

अग्निवीर भुगतान प्रणाली

रक्षा वित्त प्रबंधन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में अग्निवीर भुगतान प्रणाली एक अहम मील का पत्थर है। यह अग्निवीरों के लिए ऑन–बोडिंग से लेकर फाइनल फाइनेंशियल क्लोजर तक, कारगर, पारदर्शी और अकाउंटेबल पे–रोल सेवाएं सुनिश्चित करती है।

यह एक आधुनिक, सुरक्षित वेतन प्रबंधन प्रणाली है और वर्तमान में यह 1,43,194 भर्ती अग्निवीरों के वेतन और भत्तों के प्रबंधन द्वारा, इन कार्मिकों के संपूर्ण सेवा चक्र के लिए एक व्यापक समाधान प्रदान करते हुए प्रतिमाह 390 करोड़ रुपये (लगभग) का संवितरण करती है। वास्तव में, यह प्रणाली जरूरी कामों को ऑटोमेट करती है और वेतन–बिल जेनरेशन, डीओ II वैलिडेशन, यूज़र मैनेजमेंट, डीएके ट्रैकिंग और फ़ाइनल सेटलमेंट प्रोसेसिंग जैसे कई फ़ंक्शनल मॉड्यूलों को एकीकृत करती है ताकि एंड–टू–एंड सॉल्यूशन मिल सके। डेटा इंटीग्रिटी, ट्रांज़ैक्शनल ट्रेसेबिलिटी और आंतरिक लेखा–परीक्षा संबंधी ज़रूरतों के अनुरूप होना इसके डिज़ाइन के मुख्य आधार हैं।

साइबर सुरक्षा अभियान

अक्तूबर 2024 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरुकता महीने के तहत, सीजीडीए कार्यालय ने तीन दिन का ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया, जिसमें लगभग 12,000 डीएडी अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

डीएडी में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को मज़बूत करने और तुरंत घटना की रिपोटिंग और प्रतिक्रियात्मक प्रणाली की स्थापना के लिए, प्रत्येक पीसीएसडीए/सीएसडीए कार्यालय में साइबर इंसिडेंट मैनेजमेंट टीम बनाने के साथ–साथ इस कार्य विशेष के लिए डिप्टी सीआईएसओ को नामांकित किया गया है।

प्रोजेक्ट संपूर्ण

एसएएमपीयूआरएनए (सिस्टम ऑटोमेशन फॉर प्रोक्योरमेंट पेमेंट एंड यूनिफॉर्म रक्षा अकाउंटिंग) जिसे पहले डीईएफएमएपीपीएस (डिफेंस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट थ्रू ऑटोमेटेड प्रोक्योरमेंट एंड पेमेंट सिस्टम) कहा जाता था, जिसकी अवधारणात्मक संकल्पना महानियंत्रक, रक्षा लेखा (सीजीडीए) के द्वारा की गई थी, एक व्यापक अधिप्राप्ति और भुगतान प्रणाली है। इस प्रणाली का उद्देश्य डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके नीति निर्माताओं के लिए अधिप्राप्ति, भुगतान–प्रक्रिया और उच्चस्तरीय प्रबंधन सूचना का एंड–टू–एंड ऑटोमेशन सुनिश्चित करना है। यह प्रणाली रक्षा अधिप्राप्ति में पारदर्शिता और कार्य–कुशलता को भी सुनिश्चित करेगी।

परियोजना संपूर्ण / डेफमैप्स के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और आवश्यकता हेतु स्वीकृति (एओएन), अनुमानित लागत 205.35 करोड़ रुपये (अर्थात 174.03 करोड़ रुपये + 18% जीएसटी की दर से 31.32 करोड़ रुपये) को माननीय रक्षा मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है।

प्रोजेक्ट संपूर्ण के विकास, क्रियान्वयन और संचालन एवं देख–रेख के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन और नियुक्ति के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) तैयार किया जा रहा है।

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट (एमआईआर)

पहली मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट (एमआईआर) 2023–24, माननीय रक्षा मंत्री ने डीएडी दिवस 2024 पर जारी की थी। इसमें जीईएम प्लेटफॉर्म पर की गई अधिप्राप्ति से संबंधित वेंडर और प्रोडक्ट प्रोफाइल, रक्षा बलों के जीएसटी में योगदान सहित खर्च का विश्लेषण, जिससे राज्य और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है और भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना और डीआरडीओ द्वारा स्टोर्स और विविध जीईएम अधिप्राप्तियों का विस्तृत विश्लेषण शामिल है।

रक्षा लेखा विभाग हर साल मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट (एमआईआर) बनाता रहेगा। इसमें और सूचनाप्रद विचार शामिल किए जाएंगे। ये विचार नीति निर्माताओं, अधिप्राप्ति अधिकारियों और वित्त सलाहकारों को सही फैसले लेने और विनियामक मानदंडो का अनुपालन सुनिश्चित करने में मदद करेंगे।

ईसीएचएस बिलों की लेखापरीक्षा के पश्चात् पाए गए अधिक भुगतान की वसूली

मार्च 2025 में ईसीएचएस के तहत चिकित्सा उपचार संबंधी व्यय (एमटीआरई) बिलों की लेखापरीक्षा के पश्चात् की गई समीक्षा से पता चला है कि 2013–14 से 2024–25 के मध्य 202.62 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान हुआ है। कुल 55.67 करोड़ रुपये की धनराशि वसूल/समायोजित की गई है।

किराए के बिलों की वसूली से सरकार को प्राप्त राजस्व

एनुअल रिव्यू ऑफ़ वर्क्स एक्सपेंडिचर (एआरडब्ल्यूई) 2023–24 और ई–सूचना रिपोर्ट के अनुसार, किराए के बिल बनाने में देरी के कारण राजस्व का भारी नुकसान देखा गया है। अभी तक 367 करोड़ रुपये में से ₹143 करोड़ वसूल हो चुके हैं।

जुलाई 2024 से मार्च 2025 के दौरान वसूली गई रकम ₹142,18,08,354 है। वर्ष 2025 में मार्च माह के दौरान वसूल की गई रकम ₹12,12,86,886 है।

सीओएसएचई (रक्षा व्यय की व्यापक सांख्यिकीय पुस्तिका)

सीओएसएचई, जिसे पहले रक्षा व्यय की स्टैटिस्टिकल हैंडबुक के नाम से जाना जाता था, सीजीडीए के कार्यालय द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसमें रक्षा बजट और खर्च के साथ–साथ कई ज़रूरी विश्लेषणों का संकलन होता है। वर्ष 2024 का प्रकाशन, जो हैंडबुक का 8वां संस्करण था, में निम्नलिखित नई विशेषताएं हैं:

(क) रक्षा सेवाओं से जुड़े खर्च पर टाइम सीरीज़ डेटा को उचित ढंग से अपडेट करने वाला एक आशोधित और व्यापक फ़ॉर्मेट।

(ख) नया अध्याय जिसमें सशस्त्र बलों के ईसीएचएस, दिव्यांगता पेंशन और फैमिली पेंशन से जुड़ा डेटा शामिल है।

(ग) लेगेसी डेटा।

(घ) डेटाबेस का विस्तार किया गया जिसमें वित्त मंत्रालय, आरबीआई द्वारा जारी किए गए बजट दस्तावेज और संबंधित संगठन की वेबसाइट वगैरह से डेटा शामिल किया गया।

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भारतीय रक्षा खर्च का संक्षिप्त विवरण।

(च) बढ़ते भारतीय रक्षा उत्पादन और निर्यात डेटा के ज़रिए दर्शायी गई ''आत्मनिर्भर भारत'' नीति पर विचार

प्रशिक्षण

अरुण जेटली नेशनलइंस्टीट्यूट ऑफ़ फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट (एजेएनआईएफएम), फरीदाबाद के ज़रिए सीजीडीए कार्यालय, आईडीएएस अधिकारियों के लिए चरण III, IV और V के लिए मिड–करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीटीपी) चला रहा है। एजेएनआईएफएम के साथ समझौता ज्ञापन के मुताबिक, आईडीएएस अधिकारी आईएसबी, हैदराबाद (जो एजेएनआईएफएम का साझेदार संस्थान है) से चरण–3 में कुल 28 दिनों में से 19 दिन, चरण–4 में कुल 21 दिनों में से 12 दिन और चरण–5 में कुल 14 दिनों में से 10 दिन जुड़े रहेंगे।

स्पर्श

स्पर्श आउटरीच कार्यक्रम

रक्षा लेखा विभाग नियमित अंतराल पर सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन – रक्षा (स्पर्श) आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करता है ताकि देश भर में मौजूद रक्षा पेंशनभोगियों तक पहुंचा जा सके। इनका उद्देश्य पेंशनभोगियों को अंतिम गंतव्य तक कनेक्टिविटी देना और सवालों और शिकायतों का मौके पर ही समाधान प्रदान करना है।

आउटरीच कार्यक्रमों के दौरान, डिफेंस पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण–पत्र जमा करने, शिकायतें दर्ज करने, मृत्यु (मृत्यु/लापता/सजा वगैरह) की रिपोटिंग, आईटी बचत और घोषणा–पत्र वगैरह देने जैसी कई सेवाएं/स्पष्टीकरण देकर मदद की जाती है।

इन कार्यक्रमों का असर सेना मुख्यालयों, पेंशनभोगी कल्याणकारी–संगठनों, ज़िला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड और स्थानीय सैन्य प्राधिकरणों जैसे अलग–अलग हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान 94 स्पर्श आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए।

एएसआईएस मामलों का सामान्यीकरण

अक्तूबर 2020 में शुरू किए गए स्पर्श से रक्षा पेंशनभोगियों के लिए डेटा में पारदर्शिता और स्पष्टता बढ़ी है। इससे पेंशनभोगी को डेटा में सुधार करवाने या कोई दूसरी संबंधित शिकायत करने का मौका मिलता है, जो अब तक संभव नहीं था। पहले के पीडीए में मौजूद डेटा की खराब गुणवत्ता की वजह से, 6.43 लाख पुराने पेंशनभोगियों के लिए गड़बड़ियां पैदा हुईं, जो एएसआईएस आधार पर स्पर्श में चले गए थे। सीजीडीए कार्यालय और पीसीडीए (पेंशन) प्रयागराज ने मौजूदा एएसआईएस मामलों को सामान्य मामलों में परिवर्तित करने के लिए अतिरिक्त जनशक्ति लगाकर और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर मिशन मोड में एक ठोस मुहिम शुरू की है। इससे सही पीपीओ तैयार करने में आसानी हुई है। 8 मई, 2025 तक 3.69 लाख मामलों का डेटा अद्यतनीकरण और सामान्यीकरण पूरा हो चुका है ।

शिकायत निपटान

लोगों की शिकायतों का प्रभावपूर्ण तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के लिए, संवेदनशीलता, पहुंच और जवाबदेही बढ़ाकर शिकायत निवारण प्रणाली को मज़बूत किया गया है। ''संपूर्ण सरकार का नज़रिया'' अपनाते हुए, 21 दिनों के अंदर शिकायत का समाधान करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ील्ड कार्यालयों को सीपीग्राम पोर्टल के तहत मैप किया गया है।

वर्ष 2024 में 36000 से ज़्यादा शिकायतों/अपीलों का निपटारा किया गया, जो वर्ष 2023 में निपटाई गई शिकायतों/अपीलों से लगभग दोगुना है। यह, प्रणाली में नागरिकों के विश्वास के साथ–साथ संगठन की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

एकीकृत वित्तीय परामर्श

प्रधान आईएफए (पीआईएफए) और आईएफए वाली एकीकृत वित्त सलाहकार (आईएफए) प्रणाली ने भारतीय सेना और रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले दूसरे संगठनों को समय पर और असरदार तरीके से वित्तीय परामर्श देना सुनिश्चित किया है। जनवरी से दिसंबर 2024 के दौरान ₹1,03,468 करोड़ के कुल 80,531 अधिप्राप्ति प्रस्तावों को आवश्यकता हेतु स्वीकृति (एओएन) चरण पर मंजूरी दी गई और ₹87,125 करोड़ के 91,520 प्रस्तावों के लिए वित्तीय मंजूरी (खर्च के दृष्टिकोण से मंजूरी) दी गई।

सिनर्जी सम्मेलन

पीआईएफए/आईएफए और कार्यकारी अधिकारियों के बीच नियमित वार्ता और विचार– विमर्श को बढ़ावा देने के लिए कमान स्तर पर सिनर्जी सम्मेलन प्रारंभ किए गए हैं। डीएडी ने निम्न सिनर्जी सम्मेलनों में हिस्सा लियाः–

वित्तीय मुद्दों पर सामंजस्य और तालमेल बढ़ाने पर एक–दिवसीय वित्तीय सम्मेलनः 05 अगस्त, 2024 को मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली में मुख्यालय आईडीएस द्वारा आयोजित किया गया जिसमें रक्षा मंत्रालय (वित्त), सीजीडीए, पीआईएफए, सेना मुख्यालय और सीजीएचक्यू के प्रतिनिधि शामिल थे।

सीएफए–एफए सिनर्जी "संवाद"ः डीजीएफपी द्वारा13 दिसंबर 2024 को मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली में सीजीडीए, डीजीएफपी, एकीकृत सेना मुख्यालय, कमांड/कोर के कर्नल एफपी के प्रतिनिधित्व के साथ आयोजित किया गया।

*****

विभिन्न देशों के साथ रक्षा सहयोग

द्विपक्षीय

अल्जीरिया

भारत ने हमारे रक्षा प्रमुख (सीडीएस) के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल की 31 अक्टूबर से 4 नवंबर 2024 तक अल्जीरिया जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य की यात्रा के दौरान सैन्य क्षेत्र में सहयोग पर अल्जीरिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

ऑस्ट्रेलिया

(i) रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना प्रमुख ने 2–6 अप्रैल 2024 तक भारत का दौरा किया।

(ii) भारतीय वायु सेना (आईएएफ) और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना (आरएएएफ) के बीच द्विवार्षिक, बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 2024, 12 जुलाई 2024 से 2 अगस्त 2024 तक डार्विन, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। 'पिच ब्लैक' नाम बड़े, निर्जन क्षेत्रों में रात के समय उड़ान भरने पर जोर देने के कारण दिया गया। भारतीय वायुसेना के दल में पायलट, इंजीनियर, तकनीशियन, नियंत्रकों और अन्य विषय विशेषज्ञों सहित150 से अधिक कुशल वायु योद्धा शामिल थे जिन्होंने दुर्जेय एसयू–30 एमकेआई बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों का संचालन किया, साथ ही सी–17 ग्लोबमास्टर और आईएल–78 हवा से हवा में ईंधन भरने वाले विमानों ने भी युद्धक भूमिकाएँ निभाई। इस अभ्यास ने भारतीय वायुसेना को भाग लेने वाले देशों के साथ बल एकीकरण को आगे बढ़ाने और सर्वोत्तम प्रथाओं के पारस्परिक आदान–प्रदान का अवसर प्रदान किया।

(iii) संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्राहिंदका तीसरा संस्करण 8–21 नवंबर 2024 तक पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। ऑस्ट्राहिंदअभ्यास एक वार्षिक कार्यक्रम है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी–बारी से आयोजित किया जाता है।इसी अभ्यास का पिछला संस्करण दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था।

(iv) महानिदेशक रक्षा आसूचना एजेंसी (डीजी डीएआई) ने 19–21 मार्च2025 तक ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा आसूचना सहयोग को और मजबूत करना और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक जुड़ाव को बढ़ाना था।

(v) भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हवा से हवा में ईंधन भरने की व्यवस्था को लागू करने पर सहमति बनी।

(vi) भारत–ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता का 9वां संस्करण 17 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त सचिव ने किया, जबकि ऑस्ट्रेलियाई पक्ष का नेतृत्व प्रथमसहायक सचिव, अंतर्राष्ट्रीय नीति प्रभाग, रक्षा विभाग, ऑस्ट्रेलिया ने किया।

(vii) चौथा भारत–ऑस्ट्रेलिया 2+2 सचिव स्तरीय परामर्श 14 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने और विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्री ने किया, जबकि ऑस्ट्रेलियाई पक्ष का नेतृत्व रक्षा विभाग(डीओडी) के सचिव श्री ग्रेग मोरियार्टी और विदेश मामलों एवं व्यापार विभाग (डीएफएटी) की सचिव सुश्री जेन एडम्स ने किया।

ऑस्ट्रेलिया के सचिव (रक्षा विभाग) श्री ग्रेग मोरियार्टी 14 अक्टूबर, 2024 को नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हुए।

(viii) चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) ने 04–07 मार्च 2025 तक ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। इस यात्रा ने क्षेत्रीय सुरक्षा और सैन्य सहयोग के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर बल देते हुए व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत दोनों देशों के बीच बढ़ते जुड़ाव को रेखांकित किया।

(ix) आरआरएम ने 11–13 सितंबर 2024 को मेलबर्न कन्वेंशन एंड एक्जिबिशन सेंटर, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित लैंड फोर्सेज एक्सपो में भारत मंडप का उद्‌घाटन किया। यह मेलबर्न में आयोजित लैंड फोर्सेज एक्सपोजिशन में भारतीय रक्षा उद्योग की पहली भागीदारी थी।

ऑस्ट्रिया

रक्षा सचिव और ऑस्ट्रिया के महासचिव (रक्षा सचिव के समकक्ष) डॉ. अर्नोल्ड काम्मेल के बीच दिनांक 21.08.2024 को साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली में एक बैठक हुई। बैठक के दौरान रक्षा सहयोग से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।

बांग्लादेश

(i) एसएससी वेलिंगटन और डीएससीएससी मीरपुर के बीच "रणनीतिक और सक्रियात्मक अध्ययनों के क्षेत्र में सैन्य शिक्षा से संबंधित सहयोग" के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 22 जून, 2024 को हस्ताक्षर किए गए।

(ii) भारत के नौसेना प्रमुख (सीएनएस) ने 01–04 जुलाई, 2024 तक बांग्लादेश का दौरा किया।

बेल्जियम

बेल्जियम आर्थिक मिशन ने मार्च, 2025 में भारत का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान, माननीय रक्षा मंत्री ने बेल्जियम के रक्षा और विदेश व्यापार मंत्री श्री थियो फ्रेंकेन से 03.03.2025 को नई दिल्ली में मुलाकात की।

केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 03 मार्च, 2025 को नई दिल्ली में बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड और बेल्जियम के रक्षा मंत्री श्री थियो फ्रेंकेन से मुलाकात करते हुए।

भूटान

रॉयल भूटान आर्मी के मुख्य परिचालन अधिकारी ने 02–05 फ़रवरी 2025 के दौरान भारत का दौरा किया।

ब्रुनेई

(i) भारतीय तटरक्षक बल के प्रदूषण नियंत्रण पोत (पीसीवी) समुद्र पहरेदार ने आसियान देशों में अपनी विदेशी तैनाती के तहत 9 अप्रैल 2024 को ब्रुनेई के मुआरा बंदरगाह का दौरा किया। आईसीजी के विशेष पोत का आसियान देशों

का दौरा समुद्री प्रदूषण के संबंध में भारत–आसियान पहल के अनुसरण में है, जिसकी घोषणा रक्षा मंत्री ने वर्ष 2022 में कंबोडिया में आसियान रक्षा मंत्री प्लस बैठक के दौरान की थी।

(ii) भारतीय नौसेना के पोत किल्टन ने 25 मई 2024 को ब्रुनेई के मुआरा का दौरा किया और रॉयल ब्रुनेई नौसेना द्वारा उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। यह दौरा भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े की दक्षिण चीन सागर में प्रचालनात्मक तैनाती का हिस्सा था।

कंबोडिया

(i) भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास, सिनबैक्स का पहला संस्करण, 01–08 दिसंबर 2024 तक भारत में आयोजित किया गया।

(ii) भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन (आईटीएस) जिसमें आईएनएस सुजाता और आईसीजीएस वीरा शामिल थे, ने 14–17 फरवरी 2025 तक कंबोडिया के सिहानोकविले बंदरगाह का दौरा किया। तीन दिवसीय यात्रा के दौरान, भारतीय नौसेना ने विभिन्न मोर्चों पर रॉयल कंबोडियन नौसेना के साथ गहन समन्वय स्थापित करते हुए,सहयोग और अंतर संचालनीयता को बढ़ाया और मैत्री संबंधों को मजबूत किया। चल रहे आदान–प्रदान और रक्षा सहयोग के एक भाग के रूप में रॉयल कंबोडियन सेना को एक लघुशस्त्र सिम्युलेटर सौंपा गया। आईटीएस की सद्भावना यात्राओं ने भारत और कंबोडिया के बीच द्विपक्षीय सहयोग और स्थायी समुद्री साझेदारी की पुनःपुष्टि की, जो एसएजीएआर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य

भारत और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) के रक्षा मंत्रालयों के बीच पहली सचिव स्तरीय बैठक 5 जुलाई, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की संभावनाओं को साकार करने हेतु सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करना था।

मिस्र

10वीं भारत–मिस्र संयुक्त रक्षा समिति (जेडीसी) की बैठक 29 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की सह–अध्यक्षता संयुक्त सचिव (आईसी/एपी) ने की। बैठक में, दोनों पक्षों ने सैन्य सहयोग, प्रशिक्षण, रक्षा उद्योग, अनुसंधान एवं विकास आदि जैसे क्षेत्रों में रक्षा सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने नौसेना से नौसेना स्टाफ वार्ता को संस्थागत बनाने और 11वीं जेडीसीके दौरान एनएनसटी आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की।

फ्रांस

सीडीएस के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने 21–25 अप्रैल, 2024 तक फ्रांस का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान, सीडीएस ने फ्रांस के वरिष्ठ नागरिक और सैन्य नेतृत्व के साथ बातचीत की और फ्रांसीसी अंतरिक्ष कमान, थल सेना कमान और रक्षा उद्योग, जिसमें सफ्रान ग्रुप, नेवल ग्रुप और डसॉल्ट एविएशन शामिल हैं, का दौरा किया।

जर्मनी

(i) वायु सेना प्रमुख (सीएएस) के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने 5–8 जून, 2024 तक जर्मनी का दौरा किया। इस यात्रा ने भारत और जर्मनी के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को रेखांकित किया, जिसका उद्देश्य रक्षा सहयोग को और मजबूत करना और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देना है।

(ii) रक्षा सचिव ने 25 अक्टूबर, 2024 को नई दिल्ली में जर्मनी के स्टेट सेक्रेटरी श्री निल्स हिल्मर के साथ एक बैठक की सह–अध्यक्षता की। बैठक के दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग गतिविधियों पर चर्चा की गई।

ग्रीस

नौसेना प्रमुख (सीएनएस) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 26–29 सितंबर 2024 तक ग्रीस का आधिकारिक दौरा किया। इस यात्रा ने भारत और ग्रीस के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को रेखांकित किया, जिसका उद्देश्य रक्षा सहयोग को और मजबूत करना है।

गुयाना

ब्रिगेडियर उमर खान, सीडीएस गुयाना ने 4 से 8 नवंबर 2024 तक भारत का दौरा किया। सीडीएस गुयाना ने 5 नवंबर 2024 को रक्षा सचिव, सीडीएस और सेना प्रमुखों के साथ और 6 से 8 नवंबर 2024 तक विभिन्न रक्षा उद्योगों के साथ बातचीत की।

इंडोनेशिया

(i) भारत और इंडोनेशिया के बीच 7वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (जेडीसीसी) की बैठक 3 मई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक की सह–अध्यक्षता रक्षा सचिव और महासचिव, रक्षा मंत्रालय, इंडोनेशिया ने की।

(ii) भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) का अपतटीय गश्ती पोत सुजय, पूर्वी एशिया में अपनी चल रही विदेशी तैनाती के तहत, जकार्ता और बाली, इंडोनेशिया में बंदरगाहों पर रुका। भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) का अपतटीय गश्ती पोत सुजय, एक एकीकृत हेलीकॉप्टर के साथ, 21 अगस्त, 2024 को दो दिवसीय यात्रा के लिए जकार्ता बंदरगाह और 18 सितंबर, 2024 को तीन दिवसीय यात्रा के लिए बाली बंदरगाह पर रुका।

(iii) भारत–इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 का 9वां संस्करण जकार्ता, इंडोनेशिया में 01–12 नवंबर 2024 तक आयोजित किया गया। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल) के सैनिकों ने किया और 40 कर्मियों वाली इंडोनेशियाई टुकड़ी का प्रतिनिधित्व इंडोनेशियाई विशेष बल कोपासस ने किया।

(iv) नौसेना प्रमुख (सीएनएस) ने 15 से 18 दिसंबर 2024 तक इंडोनेशिया का दौरा किया। यह यात्रा भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के चल रहे प्रयासों का हिस्सा थी, जो नौसेना सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, गहन होती व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अनुरूप थी।

(v) इंडोनेशियाई नौसेना प्रमुख ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 के मुख्य अतिथि, राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में भारत का दौरा किया।

(vi) भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) और इंडोनेशिया तटरक्षक बल (बदन केमानन लाउट रिपब्लिक इंडोनेशिया–बीएकेएएमएलए) के बीच दूसरी उच्च स्तरीय बैठक (एचएलएम) 27 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक के दौरान, आईसीजीऔर इंडोनेशियाई तटरक्षक बल ने समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग पर अपने समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अगले तीन वर्षों के लिए नवीनीकृत किया। बीएकेएएमएलएके चीफ वाइस एडमिरल इरवांसियाह आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 24–28 जनवरी, 2025 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। आईसीजीजहाज शौनक को 27–30 जनवरी 2025 तक जकार्ता में तैनात किया गया था।

इज़राइल

भारत और इज़राइल के बीच रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की 16वीं बैठक 23 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव ने किया और इज़राइली प्रतिनिधिमंडल का

नेतृत्व इज़राइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक ने किया। रक्षा सचिव ने भारत और इज़राइल के बीच समग्र संबंधों के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में रक्षा सहयोग की भूमिका पर ज़ोर दिया। इज़राइली महानिदेशक ने इज़राइल के लिए भारत के महत्व पर प्रकाश डाला और क्षेत्र में वर्तमान युद्ध के बारे में विस्तार से बताया।

जापान

(i) द्विपक्षीय जापान–भारत समुद्री अभ्यास जेआईएमईएक्स 2024 का आठवां संस्करण जून 2024 में आयोजित किया गया।

(ii) भारत–जापान 2+2 वार्ता का तीसरा संस्करण 20 अगस्त, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बैठक के दौरान,रक्षा मंत्रियों ने मौजूदा रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की और सहयोग को और आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।

(iii) मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ (मुख्यालय आईडीएस) और जापान आत्मरक्षा बल (जेएसडीएफ) के संयुक्त स्टाफ के बीच दूसरी भारत–जापान संयुक्त सेना स्टाफ वार्ता (जेएसएसटी) 19–20 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

(iv) भारतीय नौसेना के जहाजों पर लगाने के लिए यूनिकॉर्न मस्तूल के सह–विकास हेतु भारत सरकार और जापान सरकार के बीच 15 नवंबर 2024 को टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में एक कार्यान्वयन ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

केन्या

(i) भारत और केन्या के बीच तीसरी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (जेडीसीसी) की बैठक 03 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की सह–अध्यक्षता संयुक्त सचिव (आईसी/एपी) ने की। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने सैन्य सहयोग, प्रशिक्षण, रक्षा उद्योग, अनुसंधान एवं विकास आदि जैसे क्षेत्रों में रक्षा सहयोग के विभिन्न अवसरों पर चर्चा की। भारत ने समुद्री चिकित्सा के क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण सहायता, आतंकवाद–रोधी, उग्रवाद–रोधी, आईईडी–रोधी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की पेशकश की।

(ii) रक्षा सचिव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 26–27 सितंबर, 2024 को केन्या का दौरा किया। केन्या के रक्षा मंत्रालय के प्रधान सचिव के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस यात्रा के दौरान, रक्षा सचिव ने केन्या के रक्षा मंत्रालय के प्रधान सचिव के साथ मिलकर एक नए रेडियोलॉजी कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी, जिसे भारत की मदद से निर्मित और सुसज्जित किया जा रहा है।

कुवैत

भारत गणराज्य सरकार और कुवैत सरकार के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर 22 दिसंबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए।

मलेशिया

(i) भारतीय नौसेना के दो जहाज दिल्ली और शक्ति ने भारतीय नौसेना की परिचालनात्मक तैनाती के तहत कोटा किनाबालु, मलेशिया का दौरा किया। इस बंदरगाह यात्रा के दौरान, भारतीय और मलेशियाई नौसेनाओं के कर्मियों ने विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान–प्रदान (एसएमईई) सत्रों में भाग लिया। भारतीय नौसेना के जहाजों ने रॉयल

मलेशियाई नौसेना के जहाजों के साथ समुद्र में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास (एमपीएक्स)/पीएएसएसईएक्स में भी भाग लिया। इसका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर–संचालन क्षमता को बढ़ाना था, जिसे हाल ही में संपन्न मिलन 2024 और समुद्र लक्ष्मण 2024 अभ्यास के दौरान दोहराया गया था।

(ii) रॉयल मलेशियाई वायु सेना (आरएमएएफ) और भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के बीच 05 से 09 अगस्त 2024 तक कुआंतन, मलेशिया में संयुक्त वायु अभ्यास, उदार शक्ति 2024 आयोजित किया गया। आईएएफने एसयू–30 एमकेआई लड़ाकू विमानों के साथ इसमें भाग लिया।

(iii) भारत–मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति का चौथा संस्करण 02–15 दिसंबर 2024 तक मलेशिया के पहांग जिले के बेंटोंग कैंप में आयोजित किया गया।

(iv) मलेशिया–भारत रक्षा सहयोग समिति (एमआईडीसीओएम) की 13वीं बैठक19 फरवरी 2025 को कुआलालंपुर में हुई। इस बैठक की सह–अध्यक्षता रक्षा सचिव और मलेशिया के रक्षा मंत्रालय के महासचिव ने की।

(v) भारत और मलेशिया के बीच सैन्य सहयोग उप–समिति (एससीएमसी) की 11वीं बैठक 18 फरवरी 2025 को मलेशिया में हुई। इस बैठक की सह–अध्यक्षता संयुक्त सचिव (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग), रक्षा मंत्रालय और असिस्टेंट चीफ ऑफ स्टाफ, रक्षा संचालन और प्रशिक्षण, मलेशिया ने की।

मालदीव

(i) पाँचवीं रक्षा सहयोग वार्ता (डीसीडी) 06–07 सितंबर 2024 के दौरान भारत में आयोजित की गई।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव ने किया।

(ii) मालदीव के रक्षा मंत्री, घासन मौमून 07–11 जनवरी 2025 के दौरान भारत आए।

केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 08 जनवरी, 2025 को नई दिल्ली में मालदीव के रक्षा मंत्री श्री मोहम्मद घासन मौमून के साथ द्विपक्षीय बैठक करते हुए।

मंगोलिया

(i) भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालयों के बीच 12वीं संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) बैठक 16–17 मई, 2024 को उलानबटार में हुई। इस बैठक की सह–अध्यक्षता संयुक्त सचिव (आईसी/एपी) ने की।

(ii) भारत और मंगोलिया के बीच 13वीं संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) बैठक 7 फ़रवरी 2025 को नई दिल्ली में हुई, जिसमें द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस बैठक की सह–अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालय के राज्य सचिव ने की। जेडब्ल्यूजी बैठक भारत और मंगोलिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करने के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है,जिसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसी पहल शामिल हैं।

नेपाल

(i) नेपाली सेना के थल सेनाध्यक्ष (सीओएएस) 11–14 दिसंबर 2024 के दौरान भारत आए।

(ii) भारत के थल सेनाध्यक्ष (सीओएएस) 21–24 नवंबर, 2024 के दौरान नेपाल के दौरे पर गए।

नीदरलैंड

माननीय रक्षा मंत्री की नीदरलैंड के रक्षा मंत्री के साथ बैठक 18.03.2025 को नई दिल्ली में हुई। भविष्य में संभावित सहयोग के लिए जहाज निर्माण और अंतरिक्ष क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की गई।

केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 18 मार्च, 2025 को नई दिल्ली मेंनीदरलैंड के रक्षा मंत्री श्री रूबेन ब्रेकेलमैन्स के साथ द्विपक्षीय बैठक में।

न्यूज़ीलैंड

(i) न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री ने नौसेना प्रमुख, रॉयल न्यूज़ीलैंड नेवी (सीएन–आरएनज़ेडएन) के साथ 20 मार्च 2025 को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेश निर्मित विध्वंसक, आईएनएस सूरत का दौरा किया।

(ii) भारत के रक्षा मंत्रालय और न्यूज़ीलैंड के रक्षा मंत्रालय के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर 17 मार्च 2025 को हस्ताक्षर किए गए। इससे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और मज़बूत होगा और नियमित द्विपक्षीय रक्षा संबंध स्थापित होंगे। दोनों पक्षों ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया और इस बात पर सहमत हुए कि समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा के लिए नियमित बातचीत की आवश्यकता है।

(iii) भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा के लिए रेनबो स्टाफ़ के हिस्से के रूप में, संयुक्त टास्क फोर्स–150 में न्यूज़ीलैंड नौसेना के साथ काम किया।

फिलीपींस

(i) भारतीय नौसेना के जहाज दिल्ली, शक्ति और किल्टन ने दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े की परिचालनात्मक तैनाती के एक भाग के रूप में मनीला, फिलीपींस का दौरा किया। इस बंदरगाह यात्रा में भारतीय नौसेना और फिलीपींस नौसेना के कर्मियों के बीच विषय विशेषज्ञ आदान–प्रदान (एसएमईई), खेल कार्यक्रम, क्रॉस डेक दौरे, सांस्कृतिक आदान–प्रदान और सहयोगात्मक सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम शामिल थे।

(ii) भारत–फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (जेडीसीसी) की 5वीं बैठक 11 सितंबर, 2024 को मनीला में आयोजित की गई। इस बैठक की सह–अध्यक्षता रक्षा सचिव और उनके समकक्ष वरिष्ठ अवर सचिव, राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय, फिलीपींस ने की।

(iii) भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने फिलीपींस तटरक्षक बल (पीसीजी) के साथ दोनों तटरक्षकों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत स्थापित सहयोग ढांचे के एक भाग के रूप में, 9 दिसंबर, 2024 को आसीजी मुख्यालय, नई दिल्ली में दूसरी द्विपक्षीय बैठक आयोजित की।

रवांडा

भारत और रवांडा ने 8 फ़रवरी 2024 को किगाली, रवांडा में संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (जोडीसीसी) की पहली बैठक आयोजित की जिसमें दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के व्यापक अवसरों पर चर्चा की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त सचिव (आईसी/एपी) ने किया। प्रशिक्षण सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा औद्योगिक सहयोग आदि क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने रवांडा राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज (एनडीसी) की स्थापना और नौसेना परिसंपत्तियों के सह–विकास, उच्च गतिशीलता वाहनों (एचएमवी) के सह–विकास और सह–उत्पादन पर चर्चा की।

कोरिया गणराज्य

भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) का अपतटीय गश्ती पोत सुजय, एक एकीकृत हेलीकॉप्टर के साथ, पूर्वी एशिया में अपनी चल रही विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में, 4 सितंबर, 2024 को दक्षिण कोरिया के इंचियोन बंदरगाह पर रुका। चार दिवसीय यात्रा के दौरान, आईसीजी दल ने कोरिया तट रक्षक (केसीजी) के साथ व्यावसायिक बातचीत की, जिसमें समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया, समुद्री खोज और बचाव तथा समुद्री कानून प्रवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया गया।

रोमानिया

रक्षा सहयोग पर भारत–रोमानिया संयुक्त समिति (जेसीडीसी) की पहली बैठक 22–23 अप्रैल 2024 को बुखारेस्ट, रोमानिया में आयोजित की गई। बैठक के दौरान, सैन्य–से–सैन्य सहयोग और रक्षा उद्योग सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की गई।

रूस

(i) आरईएलओएस समझौते पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय रूसी प्रतिनिधिमंडल ने 1 फ़रवरी 2024 को भारत का दौरा किया।

(ii) आईआरआईजीसी–एमएंडएमटीसी के भाग के रूप में निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गईः–

- आईआरआईजीसी–एमएंडएमटीसी के सैन्य सहयोग संबंधी कार्य समूह के अंतर्गत नौसेना संबंधी कार्य उपसमूह की बैठक 30 जनवरी से 01 फ़रवरी 2024 तक सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में आयोजित की गई।
- वायु सेना और वायु रक्षा के लिए सैन्य सहयोग संबंधी कार्य उपसमूह की बैठक 03–04 अप्रैल 2024 के बीच नई दिल्ली, भारत में आयोजित की गई।
- आईआरआईजीसी–एमएंडएमटीसी के सैन्य सहयोग संबंधी कार्य समूह के अंतर्गत थल सेनाओं के लिए सैन्य सहयोग पर उपसमूह की बैठक 26–28 जून 2024 को नई दिल्ली, भारत में आयोजित की गई।
- आईआरआईजीसी–एमएंडएमटीसी के सैन्य सहयोग संबंधी कार्य समूह के अंतर्गत सैन्य सहयोग की योजना संबंधी कार्य उपसमूह की बैठक 23–24 जुलाई, 2024 को नई दिल्ली, भारत में आयोजित की गई।
- आईआरआईजीसी–एम एंड एमटीसी के अंतर्गत सैन्य तकनीकी सहयोग पर कार्य समूह की बैठक 18–22 नवंबर 2024 को नई दिल्ली, भारत में आयोजित की गई।
- आईआरआईजीसी–एमएंडएमटीसी के अंतर्गत सैन्य सहयोग संबंधी कार्य समूह की चौथी बैठक मास्को, रूस में 25–27 नवंबर 2024 तक आयोजित की गई।

(iii) माननीय रक्षा मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने भारत–रूस अंतर–सरकारी सैन्य एवं सैन्य–तकनीकी सहयोग आयोग (आईआरआईजीसी–एमएंडएमटीसी) की 21वीं अंतर–मंत्रालयी बैठक के लिए 08–10 दिसंबर 2024 तक रूस का दौरा किया।

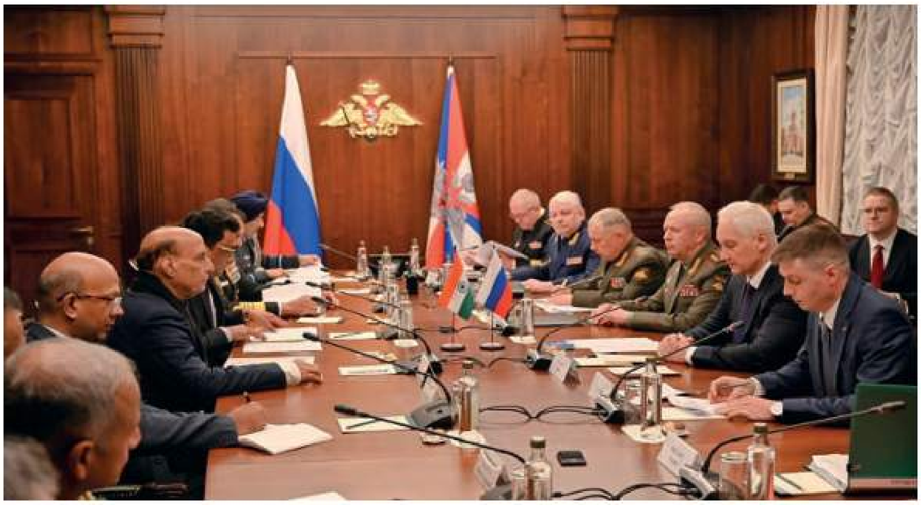

केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 24 दिसंबर को रूस में 21वीं आईआरआईजीसी बैठक में भाग लिया।

(iv) माननीय रक्षा मंत्री ने 09 दिसंबर 2024 को रूस के कलिनिनग्राद में आईएनएस 'तुशील' के कमीशनिंग समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, 9 दिसंबर, 2024 को रूस के कलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में आईएनएस तुशील के कमीशनिंग समारोह के दौरान एक सामूहिक तस्वीर में।

(v) डीसीएनएस के नेतृत्व में दो सदस्यीय भारतीय नौसेना उच्च–स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 27 से 30 जुलाई, 2024 तक रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित रूसी संघ नौसेना की मुख्य नौसेना परेड में भाग लिया। इसके अलावा, भारतीय नौसेना के युद्धपोत 'तबर' ने भी 25 से 29 जुलाई, 2024 तक रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित रूसी संघ नौसेना की मुख्य नौसेना परेड में भाग लिया।

सऊदी अरब

भारत और सऊदी अरब ने 04 सितंबर 2024 को रियाद, सऊदी अरब में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति (जेसीडीसी) की छठी बैठक आयोजित की। बैठक की सह–अध्यक्षता संयुक्त सचिव (आईसी/एपी) ने की। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने दीर्घकालिक और बहुआयामी रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के नए अवसरों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने तीनों सेनाओं के बीच स्टाफ वार्ता को संस्थागत रूप देने और 2025 की पहली तिमाही तक इसका उद्‌घाटन संस्करण आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की।

सर्बिया

पहली भारत–सर्बिया संयुक्त रक्षा समिति की बैठक 12 दिसंबर, 2024 को नई दिल्ली, भारत में आयोजित की गई। बैठक के दौरान दोनों देशों ने रक्षा और रक्षा औद्योगिक सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की।

सिंगापुर

(i) भारतीय नौसेना के जहाज दिल्ली, शक्ति और किल्टन ने 06–09 मई 24 तक सिंगापुर का दौरा किया। यह यात्रा दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े की सक्रियात्मक तैनाती का हिस्सा थी।

(ii) रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्री और उनके सिंगापुर के समकक्ष के बीच छठी भारत–सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता 22 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण सेना पर द्विपक्षीय समझौते को अगले पाँच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।

केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 22 अक्टूबर, 2024 को नई दिल्ली में छठी भारत–सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता से पहले अपने सिंगापुर के समकक्ष डॉ. एनजी इंग हेन का स्वागत करते हुए।

(iii) भारतीय वायु सेना (आईएएफ) और सिंगापुर गणराज्य वायु सेना (आरएसएएफ) के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण (जेएमटी) अभ्यास का 12वां संस्करण 21 अक्टूबर 2024 को पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा वायु सेना स्टेशन पर आयोजित किया गया। अभ्यास का द्विपक्षीय चरण 13 से 21 नवंबर 2024 तक आयोजित किया गया।

(iv) सिंगापुर भारतीय समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास (एसआईएमबीईएक्स) का 31वां संस्करण 23–29 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया गया। सिंगापुर गणराज्य नौसेना के आरएसएस टेनेशियस के साथ–साथ भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के आईएनएस शिवालिक और लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान पी81 ने इस अभ्यास में भाग लिया। अभ्यास का बंदरगाह चरण 23–25 अक्टूबर 2024 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया, जिसमें विषय–वस्तु विशेषज्ञों का आदान–प्रदान (एसएमईई), क्रॉस–डेक दौरे, खेल कार्यक्रम और प्री–सेल चर्चाएँ शामिल थीं। समुद्री चरण 28–29 अक्टूबर 2024 को बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में उन्नत वायु–रोधी, सतह–रोधी और पनडुब्बी–रोधी अभ्यास, नौसैन्य अभ्यास और सामरिक युद्धाभ्यास शामिल थे, जिससे दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर–संचालन क्षमता और भी बेहतर हुई।

(v) संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वारियर (एक्सएडब्ल्यू–2024), तीन दिवसीय द्विपक्षीय अभ्यास का 13वाँ संस्करण, भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच 28 से 30 नवंबर 2024 तक आयोजित किया गया।

(vi) भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन (आईटीएस) जिसमें आईएनएस सुजाता, आईएनएस शार्दुल और आईसीजीएस वीरा शामिल थे, ने 06–09 फ़रवरी 25 तक सिंगापुर के चांगी नौसेना बेस का दौरा किया।

तंजानिया

भारत और तंजानिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (जेडीसीसी) की तीसरी बैठक 26–27 नवंबर 2024 को गोवा में आयोजित की गई। बैठक की सह–अध्यक्षता संयुक्त सचिव (आईसी/एपी) ने की। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने समुद्री सहयोग, प्रशिक्षण और रक्षा क्षेत्र में सहयोग जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की। तंजानियाई पक्ष को अप्रैल/मई 2025 में दार–एस–सलाम में एआईकेईवाईएमई (बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास) की सह–मेजबानी करने के लिए राजी किया गया।

थाईलैंड

(i) भारत–थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 13वां संस्करण 01–15 जुलाई 2024 को थाईलैंड के टाक प्रांत के वाचिराप्राकन किले में आयोजित किया गया। इसी अभ्यास का पिछला संस्करण सितंबर 2019 में मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था।

(ii) 9वीं भारत–थाईलैंड रक्षा वार्ता 12 दिसंबर, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक की सह–अध्यक्षता संयुक्त सचिव (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) और थाईलैंड के उप–स्थायी रक्षा सचिव ने की।

यूएई

भारत और यूएई के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (जेडीसीसी) की 12वीं बैठक 09 जुलाई 2024 को अबू धाबी में आयोजित की गई। इस बैठक की सह–अध्यक्षता संयुक्त सचिव (आईसी/एपी) ने की। जेडीसीसी के दौरान, दोनों देशों की नौसेना और थल सेना के बीच स्टाफ वार्ता भी आयोजित की गई और सेवा–विशिष्ट सहयोग पर विस्तार से चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने वायु सेना से वायु सेना वार्ता को संस्थागत बनाने पर सहमति व्यक्त की।

अमेरिका

(i) माननीय रक्षा मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी रक्षा सचिव के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए 23–26 अगस्त, 2024 तक अमेरिका का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान, महत्वपूर्ण द्विपक्षीय रक्षा सहयोग गतिविधियों पर चर्चा की गई।

केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 23 अगस्त, 2024 को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में होने वाली द्विपक्षीय बैठक से पहले अमेरिकी रक्षा सचिव श्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की।

(ii) आपूर्ति सुरक्षा समझौता (एसओएसए) और संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति पर भारतीय रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी रक्षा विभाग के बीच समझौता ज्ञापन नामक दो समझौते अगस्त 2024 में संपन्न हुए।

(iii) माननीय रक्षा मंत्री की अमेरिका की राष्ट्रीय आसूचना निदेशक सुश्री तुलसी गबार्ड के साथ बैठक 17 मार्च 2025 को रायसीना वार्ता के दौरान हुई। बैठक के दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें रक्षा और सूचना साझाकरण शामिल हैं, जिनका उद्देश्य भारत–अमेरिका साझेदारी को और गहरा करना है।

उज़्बेकिस्तान

(i) भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की चौथी बैठक ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में 02–03 अप्रैल 2024 को आयोजित की गई।

(ii) थल सेनाध्यक्ष ने 15–18 अप्रैल, 2024 तक उज़्बेकिस्तान गणराज्य का दौरा किया, जो भारत और उज़्बेकिस्तान गणराज्य के बीच रक्षा सहयोग को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस यात्रा के दौरान, उन्होंने उज़्बेकिस्तान गणराज्य के शीर्ष रक्षा नेतृत्व के साथ बातचीत की। उन्होंने भारत और उज़्बेकिस्तान के सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त अभ्यास "डस्टलिक" का भी अवलोकन किया, जिसने दोनों देशों के बीच विकसित अंतर–संचालन क्षमता और सौहार्द को उजागर किया।

वियतनाम

(i) भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र पहरेदार, एक एकीकृत हेलीकॉप्टर के साथ, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) देशों में चल रही अपनी विदेशी तैनाती के तहत 02 अप्रैल, 2024 को वियतनाम के हो ची मिन्ह बंदरगाह पर पहुँचा।

(ii) रक्षा मंत्री ने 25 जुलाई, 2024 को नई दिल्ली स्थित वियतनाम दूतावास का दौरा किया और भारत सरकार और जनता की ओर से वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव श्री गुयेन फु ट्रोंग जिनका हाल ही में निधन हो गया थाको श्रद्धांजलि अर्पित की।

(iii) 14वीं भारत–वियतनाम रक्षा नीति वार्ता 01 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में हुई। इसकी सह–अध्यक्षता रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने और वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा उप मंत्री वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल होआंग जुआन चिएन ने की। आईएनएस किल्टन ने 12 मई 2024 को कैम रान्ह खाड़ी, वियतनाम का दौरा किया। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों समुद्रवर्ती देशों के बीच दीर्घकालिक मित्रता और सहयोग को और मज़बूत करना था।

बहुपक्षीय – बैठकें/वार्ता/अभ्यास/प्रशिक्षण

(i) संयुक्त सचिव (आईसी/एपी) के नेतृत्व में रक्षा मंत्रालय के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 28.02.2024 को अस्ताना, कज़ाकिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग के लिए ज़िम्मेदार एससीओ सदस्य देशों के रक्षा मंत्रालयों की संरचनात्मक इकाइयों के प्रमुखों की पहली बैठक में भाग लिया। यह बैठक 26.04.2024 को अस्ताना, कज़ाकिस्तान में होने वाली एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक (एससीओ–डीएमएम) की तैयारी के लिए आयोजित की गई थी।

(ii) रक्षा सचिव ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक के लिए 25–26 अप्रैल 2024 तक अस्ताना, कज़ाकिस्तान में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक में रक्षा सहयोग पहलों सहित एससीओ के भीतर क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान, उन्होंने मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य प्रस्तुत किया। उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एससीओ के मित्र देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ भी बैठकें कीं।

(iii) श्री विश्वेश नेगी, संयुक्त सचिव (आईसी), रक्षा मंत्रालय और ब्रिगेडियर एनएस ग्रेवाल, ब्रिगेडियर एसडी–3ए, सेना मुख्यालय ने 18 से 19 नवंबर 2024 तक संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क, अमेरिका में भारत–संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक वार्ता में भाग लिया।

एयरो–इंडिया 2025

एयरो इंडिया–2025 का 15वां संस्करण 10–14 फरवरी 2025 तक वायु सेना स्टेशन, येलहंका, बेंगलुरु,कर्नाटक में आयोजित किया गया। एयरो इंडिया कार्यक्रम के 15वें संस्करण में कुल 26 देशों ने भाग लिया। एयरो इंडिया 2025 के दौरान, निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए:

मंत्रिस्तरीय बातचीत

माननीय रक्षा मंत्री ने फिजी, दक्षिण सूडान, तंजानिया, अल्जीरिया, जाम्बिया, आर्मेनिया, मलावी, मेडागास्कर, जिम्बाब्वे, यमन, इथियोपिया, गाम्बिया और गैबॉन सहित 13 देशों के रक्षा समकक्षों के साथ बातचीत की।

केंद्रीय रक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह इथियोपिया की रक्षा मंत्री सुश्री आयशा मोहम्मद (ईएनजी) के साथ बेंगलुरु, कर्नाटक में

केंद्रीय रक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह ज़िम्बाब्वे की रक्षा मंत्री श्रीमती ओप्पमुचिंगुरी काशीरी के साथ बेंगलुरु, कर्नाटक में

माननीय रक्षा राज्य मंत्री ने 13 देशों इटली, यूके, लेसोथो,दक्षिण अफ्रीका, मालदीव, किर्गिज़ गणराज्य, फिलीपींस, डोमिनिकन गणराज्य, साइप्रस, वेनेजुएला, चाड, श्रीलंका और आर्मेनिया के साथ राज्य मंत्री स्तर की बातचीत की। इसके अतिरिक्त, सफ्रान एयरोस्पेस कंपनी के कार्यकारी उपाध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय विकास के साथ रक्षा उद्योग के मामलों पर चर्चा की।

सचिव स्तरीय बैठकें

रक्षा सचिव ने ब्रिटेन और इटली के साथ राज्य मंत्री स्तरीय बातचीत और 9 देशों इज़राइल, श्रीलंका, फ्रांस, मोज़ाम्बिक, नाइजीरिया, नेपाल, मॉरीशस, सूरीनाम और मंगोलिया के साथ सचिव स्तरीय चर्चाओं में भाग लिया: रक्षा सचिव ने यूके भारत व्यापार परिषद और एसआईडीएम सहित उद्योग निकायों के साथ भी बातचीत की और प्रमुख रक्षा कंपनियों रोल्स रॉयस, बीएई सिस्टम्स, रोसोबोरोन एक्सपोर्ट, सफ्रान, एस्टेरिया एयरोस्पेस, लियोनार्डो डसॉल्ट, और रेथियॉन टेक्नोलॉजीज के साथ रणनीतिक बैठकें की।

बहुपक्षीय

(i) बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2024 का 28वां संस्करण 08–18 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया गया। पूर्वी नौसेना कमान के तत्वावधान में मालाबार 2024 का उद्घाटन समारोह 09 अक्टूबर 2024 को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के जहाज सतपुड़ा पर आयोजित किया गया। मालाबार, जिसे 1992 में भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू किया गया था, ने एक महत्वपूर्ण समुद्री जुड़ाव के रूप में और अधिक लोकप्रियता हासिल की, जिसमें बाद में जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुए।

(ii) सिंगापुर, भारत और थाईलैंड की नौसेनाओं को शामिल करते हुए एसआईटीएमईएक्स का चौथा संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य तीनों नौसेनाओं के बीच अंतर–संचालन क्षमता और सहयोग को बढ़ाना है। एसआईटीएमईएक्स 2024 में एक बंदरगाह चरण (23–25 अक्टूबर तक विशाखापत्तनम) शामिल था, जिसमें विषय विशेषज्ञों के आदान–प्रदान और क्रॉस–डेक दौरे जैसी गतिविधियाँ शामिल थीं, जिसके बाद एक समुद्री चरण उन्नत नौसैनिक अभ्यास और सामरिक युद्धाभ्यास के साथ आयोजित किया गया।

(iii) रक्षा मंत्री ने 20–22 नवंबर, 2024 तक वियनतियाने, लाओ पीडीआर में आयोजित आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (एडीएमएम–प्लस) में भाग लिया। उन्होंने बैठक के दौरान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर मंच को संबोधित किया। एडीएमएम प्लस के दौरान, रक्षा मंत्री ने मलेशिया, लाओ, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।

(iv) आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक–प्लस (एडीएमएम–प्लस) आतंकवाद–प्रतिरोध पर विशेषज्ञ कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी ऑन सीटी) की 14वीं बैठक 19–20 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। आसियान सचिवालय, आसियान देशों (लाओ पीडीआर, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम), एडीएमएम–प्लस सदस्य देशों (चीन, अमेरिका, रूस,ऑस्ट्रेलिया, जापान और कोरिया गणराज्य) के प्रतिनिधिमंडलों ने बैठक में भाग लिया। भारत ने पहली बार आतंकवाद–प्रतिरोध पर ईडब्ल्यूजी की सह–अध्यक्षता की। उद्घाटन सत्र में, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह ने आधार व्याख्यान दिया और उद्घाटन समारोह के दौरान भाग लेने वाले प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद एक गतिशील और विकासशील चुनौती बनी हुई है और इसके खतरे तेजी से सीमाओं को पार कर रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र में आतंकवाद का मुकाबला करने की दिशा में भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला, जिसमें 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद–रोधी समिति की भारत की अध्यक्षता के दौरान दिल्ली घोषणा को अपनाना भी शामिल है।

(v) नौसेना प्रमुख ने 02 अक्टूबर 2024 को गोवा के आईएनएस मंडोवी स्थित महासागर नौकायन नोड से नाविका सागर परिक्रमा II अभियान को हरी झंडी दिखाई। यह ऐतिहासिक घटना नौसेना के महासागर नौकायन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई क्योंकि यह भारतीय महिलाओं द्वारा डबल हैंडेड मोड के अंतर्गत नौकायनपोत पर सवार होकर दुनिया की पहली समुद्री परिक्रमा थी। यह अभियान भारत के साहसिक समुद्री प्रयासों का प्रतीक है, जो वैश्विक समुद्री गतिविधियों में देश की प्रमुखता के साथ–साथ उत्कृष्टता एवं महिला सशक्तिकरण के प्रति भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

*****

महत्वपूर्ण पहल

दिव्यांगजन अधिकार(आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 का कार्यान्वयन

रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है। चयनित/नामांकित दिव्यांगजनों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्त किया जाता है और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मौजूदा निर्देशों के अनुसार अनारक्षित रिक्तियों के सापेक्ष भी समायोजित किया जाता है। दिव्यांगजनों की संख्या के संबंध में समूह क, ख और ग के संबंध में 31 दिसंबर, 2024 तक की स्थिति इस प्रकार है:—

समूह	दिव्यांगजनों की संख्या
क	76
ख	601
ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	3055
ग (सफाई कर्मचारी)	178
कुल	**3910**

जिन पदों/रिक्तियों के लिए रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय भर्ती एजेंसी नहीं है, उनकी सूचना यूपीएससी/एसएससी आदि को दी जाती है। ऐसी रिक्तियों पर भर्ती यूपीएससी/एसएससी आदि की सिफारिश के आधार पर की जाती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

रक्षा मंत्रालय में नोडल आरटीआई अनुभाग की स्थापना आरटीआई से संबंधित कार्यों के समन्वय, संबंधित सीपीआईओ/लोक प्राधिकारियों को आवेदन हस्तांतरित करने और केंद्रीय सूचना आयोग को तिमाही विवरण प्रस्तुत करने के लिए की गई है।

धारा 4(1) का अनुपालन: मंत्रालय के कार्यों और पदाधिकारियों की जानकारी आरटीआई पोर्टल – http://mod.gov.in पर अपलोड की गई है।

अधिकारियों का नामांकन: अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक स्तर के अधिकारियों को उनके द्वारा देखे जा रहे विषयों के अनुसार अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत सीपीआईओ के रूप में नामित किया गया है। सीपीआईओ के पद से ऊपर के अधिकारियों को अधिनियम की धारा 19(1) के अनुसार प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

आवेदन निपटान प्रक्रिया: केंद्रीय रजिस्ट्री आरटीआई आवेदनों/अपीलों को संबंधित प्राधिकारियों को हस्तांतरित करने के लिए नोडल आरटीआई कार्यालय को अग्रेषित करती है।

2024 के आँकड़े: 21136 आरटीआई आवेदन और 222 प्रथम अपीलें (ऑनलाइन और ऑफलाइन) प्राप्त हुई, जिन पर शीघ्रता से कार्रवाई की गई और हस्तांतरण किया गया।

पारदर्शिता के उपाय: सीपीआईओ/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों की अद्यतन सूची मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई। साथ ही, धारा 4 के अनुसार वेबसाइट पर नियमित रूप से सक्रिय खुलासे किए गए।

रक्षा उत्पादन विभाग

सत्यमेव जयते

रक्षा मंत्रालय

भारत सरकार

रक्षा उत्पादन विभाग

रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) की स्थापना नवंबर 1962 में रक्षा के लिए आवश्यक हथियारों/प्रणालियों/प्लेटफार्मों/उपस्करों के उत्पादन के लिए एक व्यापक उत्पादन अवसंरचना के विकास के उद्देश्य से की गई थी । पिछले कुछ वर्षो में, विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) के माध्यम से विभिन्न रक्षा उपस्करों के लिए व्यापक उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं और निजी रक्षा उद्योग को भी सुविधा प्रदान की है । इन इकाइयों द्वारा निर्मित उत्पादों में हथियार और गोला–बारूद, टैंक, बख्तरबंद वाहन, भारी वाहन, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर, युद्धपोत, पनडुब्बी, मिसाइल, गोला–बारूद, इलेकट्रॉनिक उपकरण, अर्थ मूविंग उपकरण, विशेष मिश्र धातु और विशेष प्रयोजन स्टील शामिल हैं।

एयरो इंडिया–25

एयरो इंडिया 2025 एशिया की प्रमुख एयरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी का 15वां संस्करण वायु सेना स्टेशन, येलाहंका, बैंगलुरू, कर्नाटक में दिनांक 11 से 14 फरवरी, 2025 को आयोजित हुआ । इस विशाल द्विवार्षिक समारोह का विषय "रनवे टू ए बिलियन ऑपर्च्युनिटीज" था जो एयरोस्पेस और रक्षा क्षमताओं में भारत की प्रगति को दर्शाते हुए एक मजबूत एवं आत्मनिर्भर नए भारत के उदय को प्रदर्शित करता है। सुरक्षित एवं समृद्ध भविष्य के लिए मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन के अनुरूप स्वदेशी उपस्कर/प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करना और विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी करने पर बल देना है । समारोह का उद्‌घाटन 90 देशों, 931 प्रदर्शकों की उपस्थिति में माननीय रक्षा मंत्री द्वारा किया गया। माननीय रक्षा मंत्री के सम्मान में पहली बार 53 वायुयानों ने फ्लाई पास्ट किया और 05 दिन में कुल 7 लाख से अधिक लोगों ने उपस्थिति दर्ज की।

(i) **रक्षा परीक्षण पोर्टल (डीपीटी)** – डीजीक्यूए ने डिजिटल डीजीक्यूए कार्यक्रम के हिस्से के रूप में एक केंद्रीकृत ऑनलाइन रक्षा परीक्षण पोर्टल कार्यान्वित किया है ताकि देश में उपलब्ध उद्योगों द्वारा प्रयोगशालाओं के ट्रायल तथा परीक्षण सुविधाओं एवं फायरिंग रेंजों का महत्तम उपयोग एक केंद्रीयकृत एवं सही नेटवर्क के माध्यम से किया जा सके। डीजीक्यूए, डीजीएक्यूए डीपीएसयू, डीआरडीओ, उद्योग और अकादमियों के पास उपलब्ध प्रयोगशाला/परीक्षण सुविधाओं को चरणबद्ध तरीके से शामिल करने का कार्य प्रगति पर है। रक्षा परीक्षण पोर्टल का शुभारंभ माननीय रक्षा मंत्री के द्वारा बैंगलुरू में आयोजित एयरो इंडिया 2025 के दौरान किया गया। एमओडी परीक्षण सुविधाओं के ऑनबॉर्डिंग के अलावा, रक्षा परीक्षण पोर्टल पर सरकारी राष्ट्रीय परीक्षण हाउस, अकादमियों और निजी फर्मो को सेवा नियोक्ता और सेवा प्रदाता के रूप में भी शामिल किया जा रहा है।

(ii) **डीजीक्यूए के 'रक्षा परीक्षण क्षमताओं' पर पुस्तिकाओं का विमोचन** – माननीय रक्षा मंत्री द्वारा एयरो इंडिया 2025 के साथ आयोजित सीईओ राउंडटेबल सम्मेलन में 10 फरवरी, 2025 को रक्षा उपस्करों/प्लेटफार्मों के लिए परीक्षण आवश्यकताओं पर 8 पुस्तिकाओं का विमोचन किया गया ।

भारतीय रक्षा उद्योग का निर्यात आयात प्रोफाइल

(i) **रक्षा निर्यात**: गत वित्तीय वर्ष की तुलना में 12.04 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारतीय रक्षा निर्यात अब तक का सर्वाधिक 23622 करोड़ रु. के स्तर पर पहुंच गया है । पिछले 7 वर्षो में रक्षा निर्यात में पाँच गुना वृद्धि हुई है। पिछले 05 वर्षो के दौरान निर्यात किए गए महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों में हथियार सिम्युलेटर, टियर गैस लांचर, टॉरपीडो लोडिंग मैकेनिज्म, अलार्म मॉनिटरिंग और कंट्रोल, नाइट विजन मोनोक्युलर और दूरबीन, हल्के वजन वाले टॉरपीडो और फायर कंट्रोल सिस्टम, बख्तरबंद सुरक्षा वाहन, हथियार लोकेटिंग रेडार, एचएफ रेडियो, तटीय निगरानी रेडार आदि शामिल हैं। अब भारतीय रक्षा वस्तुएं दुनिया भर के 80 से अधिक देशों को निर्यात की जाती हैं। पिछले सात वित्तीय वर्षो के निर्यात प्रदर्शन का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
निर्यात मूल्य (रु. करोड़ में)	10746	9116	8435	12815	15920	21083	23622

(ii) **रक्षा आयातः** विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) को केवल रक्षा उपयोग के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात हेतु लाइसेंस देने की शक्तियाँ सौंपी हैं। केवल रक्षा उपयोग के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात हेतु आयात लाइसेंस जारी करने की मानक संचालन प्रक्रिया को अधिसूचित कर वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है।

रक्षा उत्पादन

रक्षा उत्पादन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024–25 में 1.5 लाख करोड़ रु. (अनंतिम) मूल्य का उत्पादन (वीओपी) करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पिछले पांच वर्षों के उत्पादन का मूल्य इस प्रकार हैः

वर्ष	डीपीएसयू (करोड़ में)	नए डीपीएसयू (पूर्ववर्ती ओएफबी) (करोड़ में)	गैर डीपीएसयू (करोड़ में)	निजी कम्पनियाँ (करोड़ में)	कुल (करोड़ में)
2020–21	46711.00	14635.00	6029.00	17268.00	84643.00
2021–22	55790.00	11913.00	7222.00	19920.00	94845.00
2022–23	63466.00	16998.00	7137.00	21083.00	108684.00
2023–24	74434.00	19551.00	6774.00	26675.00	127434.00
2024–25 Q1	13587.00	3580.00	1982.00	6080.00	25229.00
2024–25 Q2	17643.00	4551.47	2279.00	7496.00	31970.00
2024–25 Q3 *अंतरिम	19032.00	4664.74	1273.67	7532.00	32502.00
कुल	**50262.00**	**12797.00**	**5535.00**	**21108.00**	**89701.00**

रक्षा क्षेत्र में लाइसेंसिंग

रक्षा लाइसेंस 2014 में 215 लाइसेंस से बढ़कर दिसंबर 2024 में 728 हो गए हैं । 203 लाइसेंसों को कवर करने वाली 134 कंपनियों ने या तो रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय को उत्पादन शुरू करने की सूचना दी है या दिसंबर 2024 तक गृह मंत्रालय से उत्पादन शुरू करने की अनुमति प्राप्त की है ।

रक्षा क्षेत्र में एफडीआई नीति

(i) अब तक की स्थिति के अनुसार रक्षा क्षेत्र में 46 प्रस्तावों/संयुक्त उद्यमों को मंजूरी दी गई है।

(ii) रक्षा क्षेत्र के खुलने से लेकर दिसंबर 2024 तक की अवधि में कुल संचयी एफडीआई प्रवाह का मूल्य 5516.16 करोड़ रुपये से अधिक है।

(iii) अप्रैल 2014 से दिसंबर 2024 तक की अवधि में कुल एफडीआई प्रवाह 4128.04 करोड़ रुपये है ।

स्वदेशीकरण के क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियां

रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में की गई पहलों का उद्देश्य रक्षा प्लेटफार्मों के लिए आवश्यक एलआरयू/प्रणाली/उप–प्रणाली/संयोजन/उपसंयोजन/कलपुर्जे एवं घटक/कच्चा माल आदि के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना और रक्षा पीएसयू (डीपीएसयू) द्वारा आयात को कम करना है। इस दिशा में, डीडीपी ने डीपीएसयू की 5012 आवश्यक मदों वाली पांच सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (पीआईएल) जारी की है, जिनमें से 3025 मदों का स्वदेशीकरण किया जा चुका है।

रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने अगस्त 2020 में 'srijandefence.gov.in' नामक एक स्वदेशीकरण पोर्टल लांच किया है। उद्योग द्वारा स्वदेशीकरण के लिए सृजन पोर्टल पर रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों (डीपीएसयू) और सेवा मुख्यालयों (एसएचक्यू) द्वारा 38000 से अधिक रक्षा मदों को अपलोड किया गया है । सृजन पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 13900 से अधिक मदों का सफलतापूर्वक स्वदेशीकरण किया गया है । जनवरी 24 से दिसंबर 24 तक, 105 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची सहित सृजन पोर्टल के 3402 मदों का स्वदेशीकरण किया गया है ।

रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग ने भारतीय रक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के बौद्धिक संपदा अधिकारों के निर्माण और प्रबंधन के लिए अप्रैल, 2018 में ''मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति'' (एमआरजीएस) नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। डीपीएसयू ने कुल 6187 आईपीआर आवेदन दर्ज किए हैं, जिनमें से 2901 आईपीआर स्वीकृत/पंजीकृत किए गए हैं ।

रक्षा नवाचार के लिए उभरते स्टार्टअप समुदाय को शामिल करने के लिए रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (आईडेक्स) को अप्रैल 2018 में लांच किया गया था। रक्षा नवाचार संगठन (आईडेक्स–डीआईओ) द्वारा प्रबंधित रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार कई उद्देश्यों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है, जिसमें रक्षा उद्यमों का विकास, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण शामिल है, जिससे बेहतर रक्षा तैयारी, छोटा खरीद चक्र, लागत में कमी, रिवर्स ब्रेन ड्रेन, नौकरियों का सृजन आदि शामिल है ।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्षमताओं का विकास करना

रक्षा उत्पादन विभाग ने राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा जरूरतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रणनीतिक प्रभावों का अध्ययन करने और इस संबंध में उचित सिफारिशें करने के लिए फरवरी 2018 में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। टास्क फोर्स ने जून 2018 में रक्षा मंत्रालय को अपनी सिफारिशें सौंपी । टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर, माननीय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा एआई परिषद (डीएआईसी) की स्थापना की गई, ताकि रक्षा में एआई कार्यान्वयन के लिए परिचालन ढांचे, नीति स्तर में बदलाव और संरचनात्मक सहयोग के विकास या अनुकूलन को सक्षम और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके। सेवाओं और अन्य रक्षा संगठनों में एआई आधारित प्रणालियों और एआई आधारित प्रक्रियाओं के डिजाइन, विकास और उत्पादन को सक्षम बनाने के लिए सचिव (डीपी) के साथ एक रक्षा एआई परियोजना एजेंसी (डीएआईपीए) की भी स्थापना की गई जिसमें वे इस एजेंसी के पदेन अध्यक्ष थे।

सिफारिशों को लागू करने के लिए रक्षा पीएसयू के लिए एआई रोडमैप को अंतिम रूप दिया गया था ताकि उनके प्लेटफार्म के लिए प्रासंगिक एआई आधारित उत्पाद/प्रौद्योगिकियां बनाई जा सकें और इसके लिए उचित निधि निर्धारित की जा सके। डीपीएसयू द्वारा कुल 146 एआई सक्षम परियोजनाएं शुरू की गई है, जिनमें से 77 उत्पाद 31 मार्च, 2025 तक डीपीएसयू द्वारा पहले ही विकसित किए जा चुके हैं। साथ ही, संगठनों को उनकी वर्तमान एआई क्षमताओं का मूल्यांकन करने में मदद करने के लिए एक एआई परिपक्वता मॉडल भी विकसित किया गया है।

रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (डीपीएसयू)

रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में 16 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम हैं, जो इस प्रकार हैं:

(I) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन दक्षिण एशिया में एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम तथा प्रमुख वैमानिकी कंपनी है। यह कंपनी भारत के 7 राज्यों और 10 भौगोलिक स्थानों में फैले 21 प्रभागों और 09 अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के साथ संचालन करती है और बिक्री के हिसाब से वैश्विक एयरोस्पेस कंपनियों में 31 वें स्थान पर है।

HAL एचएएल ने स्वदेशी रूप से 17 प्रकार के विमानों और हेलीकॉप्टरों को डिजाइन और विकसित किया है। इसके अलावा, एचएएल ने वैश्विक कंपनियों से लाइसेंस के तहत 14 प्रकार के विमानों और हेलीकॉप्टरों का उत्पादन किया है। अब तक, एचएएल ने 4342 विमानों, 5590 एयरो–इंजनों का उत्पादन किया है और संबंधित सहायक उपकरणों और एवियॉनिक्स के निर्माण और ओवरहाल के अलावा 12584 विमानों के ओवरहाल और 37148 इंजन के ओवरहाल किए हैं।

वर्ष के दौरान, एचएएल ने 208 आईपीआर आवेदन दायर किए हैं जो कंपनी द्वारा दायर किए गए संचयी रूप से 2620 आईपीआर बनते हैं। इसके अलावा, वर्ष के दौरान 94 आईपीआर को स्वीकृति प्रदान की गई हैं, जिससे संगठन द्वारा धारित संचयी आईपीआर 1127 (पेटेंट–371, औद्योगिक डिजाइन–171, कॉपीराइट–583, ट्रेडमार्क–2) हो गए हैं ।

प्रमुख उपलब्धियां

- दिनांक 09 फरवरी, 2025 को माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बैंगलुरू में एलसीए एमके1ए उत्पादन सुविधा केन्द्र का दौरा किया।

माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह फरवरी 2025 में बैंगलुरू में एलसीए एमके1ए उत्पादन सुविधा केन्द्र में उपस्थित थे ।

- एचएएल को एयरो इंडिया 2025 के दौरान रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ से एचटीटी40 के लिए प्रतिबंधित सैन्य प्रकार का प्रमाण–पत्र प्राप्त हुआ ।

एयरो इंडिया 2025 के दौरान एचएएल को माननीय रक्षा राज्य मंत्री से प्रतिबंधित सैन्य प्रकार का प्रणाम–पत्र प्राप्त हुआ ।

- एचएएल के उन्नत हिन्दुस्तान जेट ट्रेनर, एचजेटी–36 'यशस' का अनावरण 11 फरवरी, 2025 को किया गया था। श्री संजीव कुमार सचिव, (उत्पादन) ने एयरो इंडिया 2025 के दौरान एचएएल के सीएमडी डॉ. डी के सुनील और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में नए नाम का अनावरण किया।

एचएएल के उन्नत हिन्दुस्तान जेट ट्रेनर, एचजेटी–36 'यशस' का अनावरण फरवरी, 2025 में किया गया था

- एचएएल ने 30 सितंबर, 2024 को कोरापुट में सचिव (रक्षा उत्पादन) श्री संजीव कुमार की उपस्थिति में 240 इंजन अनुबंध के तहत एसयू–30एमकेआई का पहला एएल–31 एफपी एयरो इंजन भारतीय वायुसेना को सौंपा।

एचएएल ने 30 सितंबर, 2024 को कोरापुट में सचिव (उत्पादन) श्री संजीव कुमार की उपस्थिति में एसयू–30 एमकेआई का पहला एएल–31 एफपी एयरो इंजन भारतीय वायुसेना को सौंपा।

- दिनांक 12 अक्टूबर, 2024 को एचएएल प्रतिष्ठित ''महारत्न'' का दर्जा हासिल करने वाला पहला रक्षा सार्वजनिक उपक्रम बन गया है।

- सीएटीएस–डब्ल्यू अनुप्रयोगों के लिए टीडब्ल्यूआईएन इंजन कॉन्फिगरेशन में उन्नत पीटीएई–7 इंजनों का पहला परीक्षण दिनांक 21 नवंबर, 2024 को पूरा हुआ।

- आईएमआरएच और डीबीएमआरएच के लिए इंजनों के डिजाइन, विकास, विनिर्माण और आपूर्ति के लिए दिनांक 30 अगस्त, 2024 को एसएएफएचएएल हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एयरफ्रेमर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए।

(II) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)

बीईएल, रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंपनी है। बीईएल भारतीय रक्षा बलों और राष्ट्र को निर्णायक समाधानों के साथ सशक्त बनाने में अग्रणी रहा है।

प्रमुख उपलब्धियां

- बीईएल ने 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत टीएचडी–1955 रडार सिस्टम में एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय उन्नयन विकसित किया है। डिजिटाइज्ड टीएचडी 2.0 रडार का उद्घाटन दिनांक 29 जुलाई 2024 को बरनाला में एयर मार्शल वी राजशेखर, डीजी (प्रणाली) द्वारा किया गया था।
- बीईएल को टी–90 टैंकों के लिए थर्मल इमेजर प्रौद्योगिकी मॉड्यूलों के विकास के लिए आयात प्रतिस्थापन श्रेणी के तहत माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा एसआईडीएम चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया। बीईएल एसआईडीएम चैंपियनशिप पुरस्कार 2024 को प्राप्त करने वाला एक मात्र डीपीएसयू है।
- बीईएल ने सेना वायु रक्षा से किए गए अपने वादे को पूरा करते हुए स्वदेशी वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली (आकाशतीर) के लिए 100 नियंत्रण केन्द्रों की सुपुर्दगी सफलतापूर्वक की।

बीईएल ने वायु सेना नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली (आकाशतीर) के लए 100 नियंत्रण केन्द्रों की आपूर्ति पूरी कर दी है।

(III) बीईएमएल लिमिटेड

1964 में निगमित, बीईएमएल लिमिटेड, रक्षा मंत्रालय के अधीन एक अनुसूची 'ए' सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो कोयला, खनन, इस्पात, सीमेंट, बिजली, सिंचाई, निर्माण, सड़क निर्माण, रक्षा, रेलवे और मेट्रो परिवहन प्रणाली और एयरोस्पेस जैसे अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों के लिए उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के डिजाइन, विकास, विनिर्माण और बिक्री पश्चात सेवा में कार्यरत है। बीईएमएल एक सूचीबद्ध कंपनी है और भारत सरकार के पास कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी का लगभग 54% हिस्सा है।

BEML बीईएमएल तीन व्यावसायिक कार्य क्षेत्रों में काम करता है – खनन और निर्माण, रक्षा और एयरोस्पेस तथा रेल और मेट्रो जो विशिष्ट उत्पाद मिश्रण पर आधारित है। इसके अलावा व्यावसायिक कार्य क्षेत्रों के तहत विभिन्न क्षेत्रों में केंद्रित दृष्टिकोण रखने के लिए, बीईएमएल के वर्तमान व्यावसायिक क्षेत्रों को 11 रणनीतिक व्यावसायिक इकाइयों (एसबीयू) में पुनर्गठित किया गया है, जैसे खनन, निर्माण, निर्वाह, एचएमवी, बख्तरबंद, कम्प्यूटर रेल, मेट्रो रेल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभाग, हाइड्रोलिक्स और पावरलाइन, इंजन और एयरोस्पेस। इसके अलावा, एसबीयू एयरोस्पेस के तहत 02 माइक्रो एसबीयू अर्थात एसईजेड तथा मैरीटाइम बनाए गए हैं।

प्रमुख उपलब्धियां

- बीईएमएल के पास पूर्ण विकसित अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) केंद्र हैं। वर्ष के दौरान अनुसंधान एवं विकास ने उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों के इन–हाउस डिजाइन और विकास, मौजूदा उत्पादों के समुच्चय और उन्नयन के लिए पहल की है, जिसमें जहां लागू हो, उत्सर्जन अनुपालन को पूरा करने के लिए उन्नयन करना और तीनों व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों में विनियमन प्राधिकारियों द्वारा अनुशंसित सुरक्षा सुविधाओं की इंजीनियरिंग शामिल है।

- रक्षा और एयरोस्पेस में, मैसूर कॉम्प्लेक्स में मुख्य युद्धक टैंक के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित 1500 एचपी इंजन का विकास और पहला परीक्षण पूरा किया गया। बीईएमएल ने एलवीएम 3 कार्यक्रम के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, (वीएसएससी), इसरो को पहला स्ट्रैप ऑन बेस श्राउड (एसबीएस) स्ट्रक्चर आधार अवसंरचना पर पहला पट्टा (एसबीएस) सफलतापूर्वक सौंप दिया है। बीईएमएल को रक्षा मंत्रालय से 56 मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट (एमएमई) मार्क–II और 21 कमांड पोस्ट व्हीकल (सीपीवी) के निर्माण और आपूर्ति के लिए अनुबंध प्राप्त हुआ है।

- खनन और निर्माण में, बीईएमएल ने भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित 21 घन मीटर इलेक्ट्रिक रॉप शोवेल, बीईएमएल, कोलार गोल्ड फील्ड्स कॉम्प्लेक्स को आपूर्ति की।

- रेल और मेट्रो में, बीईएमएल के बैंगलुरू परिसर में भारत के पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसेट प्रोटोटाइप के उत्पादन की शुरूआत हुई। बीईएमएल ने वर्ष के दौरान मैसर्स लोराम, यूएसए को स्वदेशी रूप से निर्मित रेल ग्राइंडिंग मशीन (आरजीएम 96) का पहली रेक सौंपी है। कोलकाता को आपूर्ति किए गए बीईएमएल द्वारा डिजाइन और निर्मित मेट्रों कोचों का पूर्व परीक्षण हावड़ा में भारत की पहली अंडरवाटर रिवर टनल के माध्यम से शुरू किया गया था। बीईएमएल को बीएमआरसीएल से 318 मेट्रो कारों के निर्माण का अनुबंध मिला था।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन

(IV) भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल)

भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) एक मिनीरत्न श्रेणी–I कंपनी को वर्ष 1970 में रक्षा मंत्रालय के तहत एसएस 11 बी 1 एटीजीएम ATGM का निर्माण और भारतीय सेना को आपूर्ति करने लिए निगमित किया गया था। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (एटीजीएम) के निर्माण में अग्रणी अपनी स्थापना के बाद से यह सेवाओं को पूरा कर रहा है और एकल उत्पाद एकल ग्राहक से बहुउत्पाद विविध ग्राहक तक आगे बढ़ा है। वर्तमान में यह तीन प्रकार के एटीजीएम (कोंकर्स–एम, मिलान–2टी और इनवार) का निर्माण करता है। यह भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के लिए आकाश एसएएम का भी निर्माण करती है। आज बीडीएल ने भारतीय रक्षा बाजार में अच्छी तरह से पकड़ बना ली है।

प्रमुख उपलब्धियां

- माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने 14 जनवरी, 2024 को कंचनबाग, बीडीएल हैदराबाद में भारतीय वायु सेना के लिए स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित एस्ट्रा मिसाइलों की आपूर्ति की शुरूआत की।
- आंतरिक मूल्यांकन परिक्षणों के हिस्से के रूप में स्वदेशी महत्वपूर्ण उप–प्रणालियों के साथ मिलान–2टी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (एटीजीएम) का 07 दिसंबर 24 को महो में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

(V) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)

रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक मिनीरत्न, अनुसूची– एक कंपनी जीआरएसई ने भारतीय सशस्त्र बलों और मित्र देशों के लिए 110 युद्धपोतों सहित 790 से अधिक प्लेटफार्मों का निर्माण किया है जो किसी भी भारतीय शिपयार्ड द्वारा अब तक निर्मित और वितरित किए गए सबसे अधिक युद्धपोत हैं। जीआरएसई वर्तमान में 10 परियोजनाओं में 42 पोतों के निर्माण में लगा हुआ है। इनमें से 17 भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे युद्ध पोत हैं जिनमें तीन **पी–17ए स्टेल्थ फ्रिगेट, दो सर्वे वेसल (बड़े), आठ पनडुब्बी रोधी युद्धक शैलो वाटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यूएसडब्ल्यूसी) और चार अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत (एनजीओपीवी) शामिल हैं।**

प्रमुख उपलब्धियां

- **आपूर्ति** : दिनांक 08 अक्टूबर, 2024 को भारतीय नौसेना के लिए दूसरा सर्वेक्षण पोत बड़ा (एसवीएल) 'निर्देशक' और 02 नए प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म (पश्चिम बंगाल सरकार के लिए दिनांक 09 जनवरी, 2025 को एनजी इलेक्ट्रिक फेरी **'डीएचईयू'** और 28 अक्टूबर, 2024 को डीआरडीओ को यूएसवी **'जलदूत'**)
- **शुभारंभः** 13 मार्च, 2024 को 02 एएसडब्ल्यू–एसडब्ल्यूसी और दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 को 01 एएसडब्ल्यू–एसडब्ल्यूसी का एक साथ शुभारंभ ।
- **कील–लेइंग** : दिनांक 05 नवंबर, 2024 को 02 एनजीओपीवी और 10 मई, 2024 को 01 एएसडब्ल्यू–एसडब्ल्यूसी का एक साथ कील लेइंग।
- जीआरएसई ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए 4750 करोड़ रु. (अंतरिम एवं बिना लेखा परीक्षा के) का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक कारोबार हासिल किया तथा पिछले 05 वर्षों के दौरान 43 प्रतिशत सीएजीआर दर्ज किया गया है।
- जीआरएसई त्वरित नवाचार पोषण योजना जीएआईएनएस 2024 का दूसरा संस्करण– माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ द्वारा 10 जुलाई, 2024 को जीआरएसी, कोलकाता में लांच किया गया।
- जीआरएसई 10 जुलाई, 2024 को भारत सरकार द्वारा 100 आईपीआर प्रदान/पंजीकृत करवाने वाला देश का पहला डीपीएसयू शिपयार्ड बन गया है।
- 17 सितंबर, 2024 को जीआरएसई का अनुसूची ख से अनुसूची क में उन्नयन।

(VI) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल)

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल), एक मिनी रत्न ग्रुप–I श्रेणी वाली कंपनी ने इन–हाउस डिजाइन की क्षमताओं को साबित किया है और भारतीय रक्षा बलों और निर्यात बाजार सहित अन्य सभी ग्राहकों के लिए उन्नत उच्च प्रौद्योगिकी वाले युद्धपोतों का निर्माण कर रही है। जीएसएल ने युद्धपोतों की एक विस्तृत श्रृंखला जैसे फ्रिगेट, मिसाइल क्राफ्ट, गश्ती जहाजों, लैंडिंग क्राफ्ट, प्रशिक्षण जहाजों, सर्वेक्षण जहाजों, सेल प्रशिक्षण जहाजों, तेज गश्ती जहाजों आदि के डिजाइन और निर्माण के क्षेत्रों में अपनी मुख्य दक्षताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

प्रमुख उपलब्धियां

- दिनांक 19 जुलाई, 2024 को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप प्रशासन को पहला एलपीजी सिलेंडर कैरियर वेसल यार्ड 1261 की सुपुर्दगी।

- दिनांक 23 जुलाई, 2024 को गोवा के माननीय राज्यपाल श्री पी.एस. श्रीधरन पिल्लई की उपस्थिति में एडवोकेट श्रीमती रीता श्रीधरन द्वारा भारतीय नौसेना के लिए पहले मिसाइल फ्रिगेट यार्ड 1258 का शुभारंभ किया।

भारतीय नौसेना के लिए पहले मिसाइल फ्रिगेट यार्ड 1258 का शुभारंभ

- 29 अगस्त, 2024 को माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ की उपस्थिति में श्रीमती नीता सेठ द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत यार्ड 1267 का शुभारंभ किया गया।

भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत यार्ड 1267 का शुभारंभ

(VII) हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल)

हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के पूर्वीतट पर सबसे बड़ा और रणनीतिक रूप से स्थित शिपयार्ड है जो जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत, पनडुब्बी रीफिट के साथ–साथ उन्नत एवं अत्याधुनिक अपतटीय और तटवर्ती संरचनाओं के डिजाइन और निर्माण संबंधी कार्य करता है।

पुरस्कार

- **पीएसयू समर्पण पुरस्कारः** सीएमडी को दिनांक 03 मई 2024 को नई दिल्ली में शिपयार्ड के कायाकल्प कार्य को आगे बढ़ाने में उनके अनुकरणीय नेतृत्व को मान्यता देने के लिए आईलौज मीडिया की पहल गोव कनेक्ट द्वारा ''पीएसयू समर्पण पुरस्कार'' से सम्मानित किया गया।

- **14वें पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कारः** एचएसएल को दिनांक 21 दिसंबर, 2024 को दिल्ली में अपने 14वें संस्करण में पीएसई उत्कृष्टता द्वारा ओयोजित 'सीएमडी ऑफ द ईयर' और 'सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में महिलों का योगदान' और 'सीएसआर और स्थिरता' की श्रेणियों में तीन पुरस्कार प्राप्त हुए।

(VIII) माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड(एमडीएल) युद्धपोतों और पनडुब्बियों के निर्माण में लगे सभी रक्षा पीएसयू शिपयार्डों में अग्रणी शिपयार्ड है। एमडीएल भारत का एकमात्र शिपयार्ड है जिसमें भारतीय नौसेना के लिए विधवंसक और दो अलग–अलग प्रकार की पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण की सिद्ध क्षमता है, जिसकी सुविधाएं मुंबई और न्हावा में स्थित है। एमडीएल भी दुनिया के अनूठे शिपयार्डों में से एक है, जिसमें उत्पादों की ऐसी विविध रेंज है।

प्रमुख उपलब्धियां

- एमडीएल ने मई 2024 में सफल संचालन के 250 साल पूरे होने का जश्न मनाया, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और कंपनी की दृढ़ता और लचीलापन और विकास को प्रदर्शित करता है।
- एमडीएल को जून 2024 में डीपीई द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया था। इस प्रकार एमडीएल देश के सरकारी स्वामित्व वाले शिपयार्डों में से पहला बन गया है, जिसे ''नवरत्न'' का दर्जा प्राप्त है।
- प्रोजेक्ट 15बी का चौथा गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, आईएनएस सूरत और परियोजना का पहला स्टेल्थ फ्रिगेट 17ए, आईएनएस नीलगिरी को दिनांक 20 दिसंबर, 2024 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया।
- प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बी, आईएनएस वागशीर को दिनांक 09 जनवरी, 2025 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया।

भारतीय नौसेना को आईएनएस वागशीर की डिलीवरी

(IX) मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)

मिधानि, हैदराबाद में स्थित एक सूचीबद्ध पीएसयू (मिनी रत्न– I) है जो, दुनिया के कुछ एकीकृत और आधुनिक धातुकर्म संयंत्रों में से एक है, यह अत्याधुनिक उत्पादन सुविधाओं का उपयोग करके विभिन्न मिल रूपों में सुपरअलॉयज, टाइटेनियम और टाइटेनियम मिश्र धातुओं और विशेष स्टील्स की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण करता है।

20 नवंबर, 1973 को सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के रूप में कंपनी अधिनियम के तहत निगमित मिधानि की परिकल्पना भारत को महत्वपूर्ण और जटिल मिश्र धातुओं के व्यापक स्पेकट्रम के निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद करने के लिए की गई थी। रोहतक में मिधानि कवच सुविधा की स्थापना तीनों सेनाओं, सीएपीएफ और राज्य पुलिस के लिए वाहन कवच, बीपी जैकेट, हेलमेट आदि जैसे व्यक्तिगत और समूह सुरक्षा उपकरणों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई है।

अपनी स्थापना के बाद से मिधानि विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों जैसे, अंतरिक्ष रक्षा और ऊर्जा को सामग्री की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

प्रमुख उपलब्धियां

- मिश्र धातु आईएचटीए (एयूएससी परियोजना) के लिए और सुपरनी 41 (एयरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए) का विकास और इसे एयरो इंडिया 2025, बेंगलुरु में सामर्थ्य कार्यक्रम में माननीय रक्षा मंत्री द्वारा मान्यता दी गई थी।
- कास्ट स्टिक निर्माण में नई तकनीक की शुरुआत के परिणामस्वरूप उत्पादन में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई और वीआईएम 600 किलोग्राम से अब तक का उच्चतम कास्ट मिश्र धातु छड़ों का उत्पादन हुआ है।

(X) म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड (एमआईएल)

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत एक रक्षा सार्वजिनक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है, जिसे पूर्ववर्ती आयुध कारखाने के निगमन के बाद 01 अक्टूबर, 2021 को स्थापित किया गया था। भारत की सबसे बड़ी निर्माता और मार्केट लीडर एमआईएल सेना, नौसेना, वायु सेना और अर्ध–सैन्य बलों के लिए गोला–बारूद और विस्फोटकों की व्यापक रेंज के उत्पादन, परीक्षण अनुसंधान एवं विकास और विपणन में लगी हुई है। एमआईएल के उत्पाद पोर्टफोलियों में गोला बारूद, विस्फोटक, पायरोटेक्नीक और अन्य रक्षा संबंधी उत्पाद शामिल हैं। म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड अपने उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए जाना जाता है जो भारतीय सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और निर्यात के सख्त मानकों और आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

प्रमुख उपलब्धियां

- "सामग्रीलेखा नीति की जानकारी" के साथ "महत्वपूर्ण लेखा नीति" का प्रतिस्थापन और एमआईएल इंड–एएस सामग्री लेखा नीति की जानकारी को अपनाना।
- अधिकारियों (जीओ–ए और जीओ–बी) की तैनाती और तैनाती के उद्देश्य से संबंधित स्थान के आधार पर एमआईएल की इकाइयों की पहचान और वर्गीकरण और जनशक्ति तैनाती के उद्देश्य से मुख्य और गैर–मुख्य अनुभाग के रूप में एमआईएल की इकाइयों में अनुभाग/उप–समूहों की पहचान।
- एमआईएल आईटी नीतिः आईटी हार्डवेयर (लैपटॉप/नोटबुक/फैबलेट/ अल्ट्राबुक/ नोटपैड/इसी तरह के उपकरण) और एमआईएल आईटी नीति के लिए प्राधिकरण का मापदंड वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान वरिष्ठ कार्यकारी के लिए संचार उपकरण हेतु प्राधिकरण का मापदंड तैयार किया गया था।

(XI) बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड (एवीएनएल)

बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड (एवीएनएल) एक नवगठित पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है जिसने दिनांक 01.10.2021 से अपना परिचालन शुरू किया और दिनांक 14 अगस्त, 2021 को इसकी स्थापना की गई।

एवीएनएल ने लोगों और विश्व के लिए देखभाल और चिंता को अपने मूल व्यवसायिक दर्शन के रूप में अपनाया है, जो इसकी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) गतिविधियों को दर्शाता है। जम्मू–कश्मीर में सीमावर्ती क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा, कौशल, कल्याण और मेंटरशिप प्रदान करने के लिए भारतीय सेना के साथ साझेदारी करने के लिए एवीएनएल की विशिष्ट सीएसआर पहल को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है।

(XII) एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड(एडब्ल्यूईआईएल)

एडब्ल्यूईआईएल सात (7) नए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है, जिसे पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड वाले उद्यम में परिवर्तित करके निगमित किया गया है। एडब्ल्यूईआईएल को 14 अगस्त, 2021 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित किया गया और 01 अक्टूबर, 2021 से इसने अपना कारोबार शुरू किया है। इसमें आठ उत्पादन इकाइयां और दो गैर–उत्पादन इकाइयां शामिल हैं।

प्रमुख उपलब्धियां

- आयुध निर्माणी, तिरुचिरापल्ली (ओएफटी), एडब्ल्यूईआईएल की एक इकाई ने एक नया अत्याधुनिक हार्ड क्रोम प्लाटिंग संयंत्र स्थापित किया है। यह एक स्वचालित संयंत्र है जिसमें न्यूनतम पुनर्चक्रण योग्य अवशेष के साथ स्वचालित सामग्री प्रबंधन और अपशिष्ट उपचार प्रणाली है। यह बैरल की गुणवत्ता में काफी सुधार करेगा और आरएफआर और अस्वीकृति को काफी कम करेगा।
- आयुध निर्माणी मेडक (ओएफएमके), एवीएनएल की एक इकाई, ने सीएसआर पहल के तहत मुख्यालय तेलंगाना और आंध्र उप क्षेत्र (टीएएसए), सिकंदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) पॉलीक्लीनिक को चिकित्सा उपकरणों की खरीद और आपूर्ति की सुविधा प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों ओर उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को संवर्धित करना है।

(XIII) ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड (टीसीएल)

ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के तहत एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जिसका कॉरपोरेट कार्यलय कानपुर में है। टीसीएल का 16 अगस्त, 2021 को कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत भारत सरकार द्वारा धारित 100 प्रतिशत इक्विटि शेयर के साथ शामिल किया गया था। टीसीएल 04 विनिर्माण इकाइयों (ओईएफ, कानपुर, ओसीएफ शाहजहांपुर, ओसीएफअवाडी, ओईएफ, हजरतपुर और एक प्रशिक्षण संस्थान टीसीएलटी) का एक समूह है।

टीसीएल के पास+ 500 सेंटीग्रेड से –500 सेंटीग्रेड (रेगिस्तान से ग्लेशियर) तक परिवेश के तापमान रेंज में काम करने वाली वस्तुओं की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु समाधान प्रदान करने के लिए 160 से अधिक वर्षों की विशेषज्ञता है। टीसीएल ट्रूप कंफर्ट्स वस्तुओं की विस्तृत उत्पाद श्रृंखला के उत्पादन, परीक्षण, अनुसंधान एवं विकास और विपणन में शामिल है।

प्रमुख उपलब्धियां

- टीसीएल के औद्योगिक कर्मचारियों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रेरित करने हेतु टीसीएल विनिर्माण इकाइयों में प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना(पीएलआई) का कार्यान्वयन।
- ट्रूप कंफर्ट्स वस्तुओं के लिए भारतीय सेना के उपयोगकर्ता संचालित उत्पाद सुधार अभियान में टीसीएल को शमिल करना।
- रिपोर्ट किए गए वर्ष के दौरान, टीसीएल ने भारतीय सेना की नई वस्तुओं जैसे बैग स्लीपिंग लाइट वेट, मैट्रेस ईसीसी और बूट हाई एंकल पीयू रबर सोल और टेंट हाई एल्टीट्यूड के निर्माण के लिए उत्पादन श्रृंख्ला भी स्थापित की हैं।
- उक्त वर्ष के दौरान, टीसीएल ने आत्मनिर्भर भारत के तहत निम्नलिखित पूर्व–आयतित वस्तुओं का स्वदेशी संस्करण विकसित किया है, जिसे भारतीय सेना द्वारा आयात किया जा रहा था:

  (क) -50°C तापमान तक के अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए बूट क्रैम्पन।

  (ख) -50°C तापमान तक के अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए मॉडयूलर दस्ताने।

(XIV) यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल)

रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के तहत भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली उद्यम यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल) को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत शामिल किया गया है और 1 अक्टूबर, 2021 से परिचालन में है।

वाईआईएल गोला बारूद हार्डवेयर और आयुध घटकों के उत्पादन में लगी हुई है। वाईआईएल "आत्मनिर्भर"– सशस्त्र सेनाओं का सशक्तिकरण के प्राथमिक उद्देश्य के लिए प्रयास करता है– सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक युद्धक्षेत्र उपकरणों से लैस करने में आत्मनिर्भरता। यंत्र इंडिया लिमिटेड 8 उत्पादन इकाइयों, प्रशिक्षण संस्थान और विपणन केंद्र का एक समूह है। उत्पादन इकाइयां पश्चिम बंगाल (2), उत्तर प्रदेश (1), मध्य प्रदेश (2), महाराष्ट्र (3) में स्थित है।

प्रमुख उपलब्धियां

- वाईआईएल के पास भारतीय रेलवे/कॉनकॉर (सीओएनसीओआर) को विभिन्न प्रकार के रेलवे एक्सल की आपूर्ति के लिए 750 करोड़ रुपये के ऑर्डर थे और वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान 317 करोड़ रुपये की एक्सल की आपूर्ति की गई थी।

(XV) इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)

इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल), जो एक अनुसूची 'ख' सार्वजिनक क्षेत्र का उपक्रम है, मुख्य रूप से सेवाओं और गृह मंत्रालय के लिए ऑप्टो–इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम के उत्पादन में शामिल है।

आईओएल का मुख्यालय देहरादून (उत्तराखंड) में है, जिसकी दो विनिर्माण इकाइयां देहरादून में और एक इकाई चंडीगढ़ में है। इसके अतिरिक्त, आईओएल सभी संवर्गों में अपनी जनशक्ति के प्रशिक्षण के लिए और आईओएल द्वारा बनाए गए विभिन्न उपकरणों के परिचालन और रखरखाव में अपने उपभोक्ताओं के कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान भी परिचालित करता है।

(XVI) ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल)

ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड रक्षा उत्पादन विभाग के तहत भारत सरकार का उपक्रम है और इसे 14 अगस्त, 2021 को भारत सरकार के 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। आयुध पैराशूट फैक्ट्री ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के तहत एकमात्र उत्पादन इकाई है और इसे वर्ष 1941 में कानपुर (यूपी), भारत में स्थापित किया गया था।

रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत अन्य कार्यालय (संबद्ध/अधीनस्थ)

(I) गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए)

गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) एक अंतर सेवा संगठन है जो रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। डीजीक्यूए सभी रक्षा भंडारों और भारतीय सेना, नौसेना (नौसेना आयुध को छोड़कर) के लिए आयतित और स्वदेशी उपस्करों दोनों तरह के उपस्करों और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) और निजी क्षेत्र से खरीदी गई वायु सेना के लिए आम उपयोगकर्ता मदों के गुणवत्ता आश्वासन के लिए जिम्मेदार है।

वर्ष के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय

(क) **डीजीक्यू का पुनर्गठनः** डीजीक्यूए के पुनर्गठन के लिए रक्षा मंत्रालय/डीडीपी द्वारा 15 मार्च, 2024 को मंजूरी जारी की गई थी। पुनर्गठित ढांचे में, उद्योग को उत्पाद आधारित क्यूए सेवाओं की सुविधा के लिए मौजूदा 95 प्रतिष्ठानों को 53 प्रतिष्ठानों में विलय/पुनर्गठित किया गया है। इसके अलावा, 03 तकनीकी निदेशालयों का विलय करके 09 तकनीकी निदेशालयों को 06 में समेकित किया गया है। डीजीक्यूए के तकनीकी निदेशालयों को सेना के लाइन निदेशालय से जोड़ा गया है और सीक्यूए को उत्पाद केंद्रित नोडल एएसएचएसपी के रूप में पुनः आकार दिया गया है। पुनर्गठित डीजीक्यू के पदानुक्रमित कामकाज और जवाबदेही पर एक सामान्य संचालन प्रक्रिया भी लागू की गई है।

(ख) पीएससी और उपभोग्य सामग्रियों के प्रावधान पर सामान्य संचालन प्रक्रिया। डीजीक्यूए द्वारा सभी हितधारकों के परामर्श से हथियार और गोला–बारूद के प्रूफ/ट्रायल/परीक्षण के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के पीएससी और उपभोग्य सामग्रियों के प्रावधान के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए एक व्यापक सामान्य संचालन प्रक्रिया तैयार की गई थी।

मुख्य गतिविधियां और महत्वपूर्ण रूचिकर कार्यक्रमः

(क) **डिजीटल डीजीक्यूए कार्यक्रम–** इस कार्यक्रम में डीजीक्यूए तकनीकी प्रक्रियाओं के स्वचालन के लिए वेब पोर्टल आधारित उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) एप्लीकशन, डीजीक्यूए संस्थाओं के बीच सुरक्षित नेटवर्किंग और संगठन के सभी पीसी के लिए सुरक्षित सी–डैक बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम शामिल हैं।

(ख) **उद्योग 4.0/क्यूए 4.0–** उद्योग 4.0 को अपनाने के लिए सभी डीपीएसयू में कुल 511 उत्पादों का चयन किया गया है, जो उत्पादन स्तर पर लगभग 2923 प्रक्रियाओं को स्वचालित करेगा। इसी तरह क्यूए 4.0 के लिए, गुणवत्ता आश्वासन चरणों में स्वचालन के लिए 3029 प्रक्रियाओं को शामिल करने वाले कुल 217 उत्पादों का चयन किया जा रहा है।

(ग) **ग्रीन चैनल योजना (जीसीएस) और स्व–प्रमाणन योजना (एससीएस) के लिए नीति का संवर्धन /विस्तार–** अधिक से अधिक रक्षा उद्योगों को ग्रीन चैनल/स्व–प्रमाणन प्रास्थिति के दायरे में लाने के लिए हरित चैनल प्रास्थिति नीति और स्व–प्रमाणन योजना पर नीति की समीक्षा की जा रही है। योजनाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए योजनाओं की मुख्य विशेषताओं की समीक्षा की जा रही है।

महत्वपूर्ण योगदान

(क) **परीक्षणों के लिए समय कम करने की पद्धति–** डीजीक्यूए स्थापनाओं द्वारा तकनीकी मूल्यांकन करने में समय सीमा को कम करने/अनुकूलित करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। जारी किए गए निर्देशों के मुख्य पहलू इस प्रकार हैं:

(i) गैर महत्वपूर्ण मापदंडों के लिए एसडीओसी/सीओसी की स्वीकृति।

(ii) परीक्षण के तहत उपकरण (ईयूटी) में समवर्ती मूल्यांकन।

(iii) मूल्यांकन चरण में परीक्षणों की पुनरावृत्ति न होना यदि यह पहले से ही डिजाइन/विकास चरण में किए जा चुके हैं।

(iv) अतिरिक्त परीक्षण सुविधाओं का सृजन।

प्रमुख उपलब्धियां

(क) **रक्षा मंत्रालय की योजनाओं को बढ़ावा देना**– सरकार की **"मेक इन इंडिया"** और **"ईज ऑफ डूइंग बिजनेस"** की नीति के तहत कई नई सरकारी योजनाएं शुरू और लागू की गई। 31 मार्च, 2025 तक, उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है:–

क्रम सं.	रक्षा मंत्रालय की योजना	उपलब्धियां
(i)	हरित चैनल स्थिति	31 फर्मों को मंजूरी दी गई, जिसमें 123 उपकरण और 38,216 मदें शामिल हैं।
(ii)	स्व–प्रमाणन योजना	58 उपकरण और 11,643 कलपुर्जों वाली 21 फर्मों को प्रदान किया गया।
(iii)	तृतीय पक्ष निरीक्षण	17,258 मदों के लिए अब तक 08 फर्मों का पंजीकरण (04 पंजीकरण 21 मार्च 2025 तक वैध)
(iv)	रक्षा निर्यात संवर्धन	12 वाहनों/उपकरणों के लिए 06 फर्मों को 'फिट फॉर मिलिट्री यूज सर्टिफिकेट' जारी किया गया।
(v)	आईडीईएक्स परियोजनाएं	डीजीक्यूए वर्तमान में 78 आईडीईएक्स परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है।

(ख) **क्यूए कार्यभार**– पिछले 03 वर्षों से डीजीक्यूए द्वारा निरीक्षण किए गए रक्षा भंडारों का मूल्य इस प्रकार है।

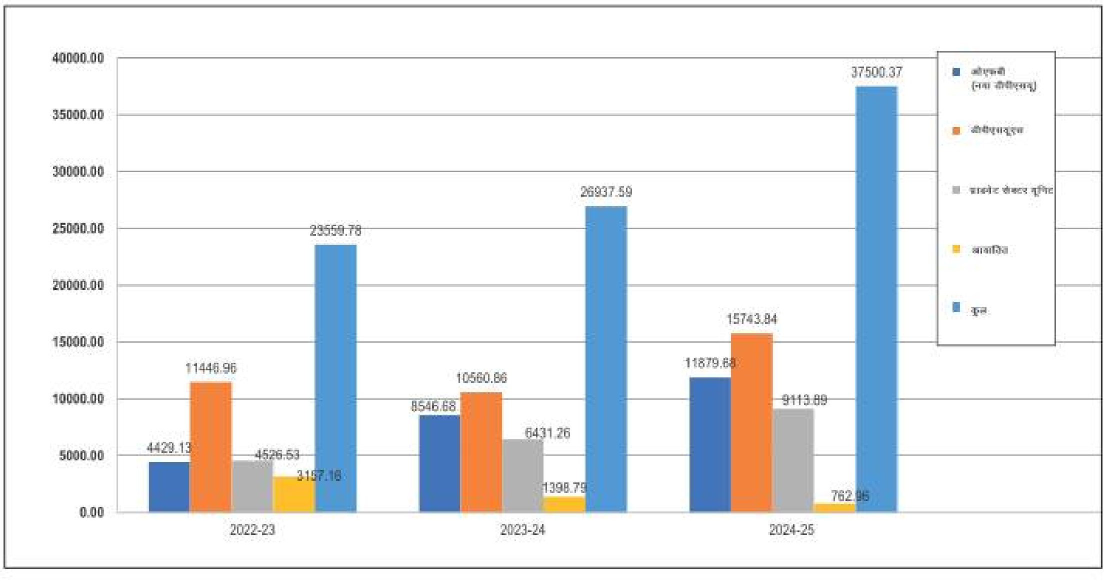

(II) वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीएक्यूए)

वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीएक्यूए) विभिन्न रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम (डीपीएसयू) आयुध निर्माणियों, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (ओएफ–डीपीएसयू), डीआरडीओ प्रयोगशालाएं, तेल रिफाइनरियां और निजी फर्म में डिजाइन एवं विकास, उत्पादन, मरम्मत, संशोधन, जीवन विस्तार और ओवरहाल के दौरान सैन्य विमानों, मानव रहित हवाई वाहनों, एयरो इंजन, एयरबोर्न सिस्टम, एवियोनिक्स, आयुध, उपभोग्य सामग्रियों (एविएशन ग्रेड ईंधन, तेल एवं स्नेहक, संबद्ध ग्राउंड सिस्टम और मिसाइलों की गुणता आश्वासन और अंतिम स्वीकृति के लिए सरकारी गुणता आश्वासन (जीक्यूए) नियामक प्राधिकरण है।

डीजीएक्यूए की प्राथमिक भूमिका सैन्य विमानन और संबद्ध भंडारों के संबंध में सरकारी गुणता आश्वासन (जीक्यूए) कार्यों को निष्पादित करना है। डीजीक्यूए उपयोगकर्ता सेवाओं, रक्षा मंत्रालय और डिजाइन एवं विकास/ उत्पादन/रखरखाव, मरम्मत एवं ओवरहॉलिंग एजेंसियों को तकनीकी परामर्श प्रदान करना है। डीजीएक्यूए विमान दुर्घटनाओं/घटनाओं से संबंधित दोषों की जांच और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में भाग लेता है। डीजीएक्यूए फर्मों और परीक्षण प्रयोगशालाओं की क्षमता मूल्यांकन और पंजीकरण में भी शामिल है।

डीजीएक्यूए सैन्य प्रणाली गुणता आश्वासन एजेंसी (एमएसक्यूएए) और सामरिक प्रणाली गुणता आश्वासन समूह (एसएसक्यूएजी) के लिए नोडल एजेंसी है।

प्रमुख उपलब्धियां

- **डीडीपीएमएएस दस्तावेज का संशोधनः**– आईएमएपी–23 (भारतीय सैन्य उड़ान योग्यता प्रक्रिया) दस्तावेज डीजीक्यूए और सीईएमआईएलएसी द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है जो भारतीय सैन्य उड़ान योग्यता प्रक्रियाओं को सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं और वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करेगा।

(III) मानकीकरण निदेशालय (डीओएस)

मानकीकरण निदेशालय (डीओएस) रक्षा मंत्रालय में मानकीकरण और संहिताकरण गतिविधियों के संचालन, निर्देशन और समन्वय के लिए रक्षा उत्पादन विभाग(डीडीपी), रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नोडल संगठन है। जिसका उद्देश्य रक्षा इन्वेंटरी में प्रविष्टि नियंत्रण, विविधता में कमी और अनुकूलन/युक्तिकरण प्राप्त करना है।

वर्ष के दौरान, कुल 11,259 वस्तुओं को संहिताबद्ध किया गया था। वर्ष के दौरान सेवाओं की सूची में कलपुर्जों सहित 43,394 मदों को शामिल करते हुए 94 सामान्य उपयोग वाले उपस्कर (तीन/दो सेवा उपयोग के साथ) का संहिताकरण पूरा कर लिया गया है।

(IV) योजना एवं समन्वय निदेशालय (पी एंड सी निदेशालय)

योजना और समन्वय निदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग का एक संबद्ध कार्यालय है जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। निदेशालय को मुख्य रूप से 'आत्मनिर्भरता' पहल के तहत विभिन्न सक्षम नीतियां तैयार करने का अधिकार दिया गया है ताकि विभिन्न मार्गों के माध्यम से रक्षा उपस्करों के डिजाइन, विकास और निर्माण में घरेलू उद्योग की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। सेवाओं की पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए स्वदेशी मार्ग से खरीद को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करना; स्टार्टअप इकोसिस्टम को संभालना और प्रेरित करना ओर आईडीईएक्स योजना के माध्यम से नवाचार की एक सतत संस्कृति को बढ़ावा देना और निजी क्षेत्र को समान अवसर प्रदान करने के लिए नीतियां तैयार करना।

इसके अतिरिक्त, निदेशालय सेना मुख्यालयों के पूंजी अर्जन प्रस्तावों पर सलाह देता है और रक्षा प्रक्रिया (डीएपी) को सुव्यवस्थित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निदेशालय नौसेना शिपयार्ड के आधुनिकीकरण के लिए चल रहे प्रयासों में तेजी लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(V) रक्षा प्रदर्शनी संगठन (डीईओ)

रक्षा प्रदर्शनी संगठन (डीईओ) की स्थापना 1981 में भारत और विदेशों में एयरोस्पेस और रक्षा (ए एंड डी) प्रदर्शनियों के माध्यम से स्वदेशी एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र और इसके पारितंत्र की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। यह आयोजित प्रदर्शनियों के माध्यम से भारतीय रक्षा उद्योग की क्षमताओं को प्रदर्शित करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करती है। कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। यह मंच वरिष्ठ विदेशी प्रतिनिधि मंडलों के साथ बातचीत की सुविधा भी प्रदान करता है। इसका प्रथमिक उद्देश्य रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और भारतीय निजी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों दोनों से रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना है।

(VI) आयुध निदेशालय (समन्वय ओर सेवाएं)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जून, 2021 को रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) की 41 उत्पादन इकाइयों (आयुध निर्माणियों) के कार्यों को निगमित करने का निर्णय लिया। 41 उत्पादन इकाइयों का प्रबंध, नियंत्रण, संचालन और रखरखाव 1 अक्टूबर, 2021 से नवगठित 7 डीपीएसयू को सौंप दिया गया था, जिनमें म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल), आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (एवीएनएल), ट्रूप कम्फर्ट लिमिटेड (टीसीएल), इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल), एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूईआईएल), यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल) ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल) शामिल हैं। आयुध निर्माणी संगठन के पुनर्गठन के तहत, आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) को 1 अक्टूबर, 2021 को भंग कर दिया गया था और ओएफबी के मुख्यालय का नाम बदलकर आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) कर दिया गया था।

निदेशालय की संरचना निम्नलिखित है:

(क) डीओओ (सी एंड एस), कोलकाता में 6 प्रभाग शामिल हैं– ओएफ अस्पताल एवं स्कूल, श्रेणी–ख अधिकारी; एनआईई एवं आई; बजट एवं संपत्ति प्रबंधन; प्रशासन और समन्वय और आईटी। अंबाझरी, अवाडी, देहरादून, जबलपुर, कानपुर, खड़की और कोलकाता में स्थित 7 फील्ड इकाइयां।

(ख) डीओओ (सीएंडएस), दिल्ली में 2 प्रभाग शामिल हैं, नामतः ग्रेड 'ए' राजपत्रित और न्यू डिफेंस कंपनियां।

(VII) रक्षा ऑफसेट प्रबंधन विंग (डीओएमडब्ल्यू)

रक्षा विभाग के तहत रक्षा ऑफसेट प्रबंधन विंग (डीओएमडब्लयू), रक्षा ऑफसेट दिशा–निर्देश तैयार करने और पोस्ट ऑफसेट अनुबंध प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों के लिए उत्तरदायी है।

ऑफसेट अनुबंधों के प्रबंधन में अनुभव के आधार पर रक्षा ऑफसेट दिशानिर्देश लगातार विकसित हो रहे हैं। इन दिशानिर्देशों में समय–समय पर हितधारकों के परामर्श से संशोधन किए गए हैं, जिससे खरीद अनुबंधों को तेजी से पूरा करने, ऑफसेट अनुबंधों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति और ऑफसेट डिस्चार्ज दावों के सत्यापन में वृद्धि हुई है। निजी क्षेत्र विदेशी ओईएम के साथ भारतीय ऑफसेट भागीदार (आईओपी) बनने के लिए तेजी से प्रतिस्पर्धी हो गया है और तदनुसार रक्षा विनिर्माण में निजी क्षेत्र के निवेश की संभावनाओं में काफी सुधार हुआ है।

लाइसेंस की आवश्यकता वाली मदों की सूची में काफी कटौती की गई है और अधिकांश घटकों को लाइसेंसिग के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इसलिए, रक्षा ऑफसेट के अंतर्गत कई पात्र मदों का निर्माण औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता के बिना निजी क्षेत्र में आईओपी द्वारा किया जा रहा है। आज की तारीख में, विदेशी विक्रेताओं के लिए ऑफसेट दायित्वों को पूरा करने वाले भारतीय ऑफसेट भागीदारों (आईओपी) की संख्या बढ़कर 350 से अधिक हो गई है, जिनमें 146 आईओपी एमएसएमई है। 31 दिसंबर, 2024 तक 6.00 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऑफसेट राशि को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है और ऑफसेट की शुरुआत से ही विदेशी विक्रेताओं द्वारा दावा किया गया है।

अन्य संस्थान/प्रभाग/प्रकोष्ठ

(I) राष्ट्रीय रक्षा पोत निर्माण अनुसंधान और विकास संस्थान

निर्देश, रक्षा मंत्रालय/रक्षा उत्पादन विभाग (एमओडी/डीडीपी) की एक सोसायटी है, जिसे 20 नवंबर, 2010 को 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI के तहत पंजीकृत किया गया था। निर्देश एक सामान्य निकाय (जीबी) और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) द्वारा निर्देशित होता है और कामकाज एक कार्यक्रम समिति (ईसी) के निर्देशों के तहत होता है। सदस्य संगठन भारतीय नौसेना (आईएन), भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी), डीआरडीओ और चार डीपीएसयू शिपयार्ड है। निर्देश की स्थापना युद्धपोत और पनडुब्बी निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से की गई थी। निर्देश अब भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और डीआरडीओ के सह–चयनित सदस्यों के साथ डीपीएसयू शिपयार्डों की एक सोसायटी के रूप में पुनर्गठन की प्रक्रिया में है। पुनर्गठित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) की अध्यक्षता एमडीएल के सीएमडी करेंगे।

(II) रक्षा औद्योगिक गलियारे

रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने और देश में रक्षा विनिर्माण पारितंत्र सृजित करने के लिए, भारत सरकार ने दो रक्षा औद्योगिक गलियारे (डीआईसी) स्थापित किए हैं, एक उत्तर प्रदेश में 6 नोड्स के साथ आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ और दूसरा तमिलनाडु में 05 नोड्स के साथ चैन्नई, कोयंबटूर, होसुर, सलेम और तिरुचिरापल्ली में है।

इन गलियारों में निवेश के प्रमुख क्षेत्रों में ड्रोन एवं यूएवी, गोला–बारूद एवं विस्फोटक, छोटे हथियार, उन्नत कंपोजिट, ऑप्टिकल उपकरण, रक्षा पैकेजिंग, सामान्य सुविधा केंद्र, मिसाइल एवं उपग्रह प्रणाली, एमआरओ, अनुसंधान एवं विकास, एयरो इंजन एवं घटक, इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार प्रणाली, कपड़ा, उत्कृष्टता केंद्र, ए एंड डी सामग्री और घटक आदि शामिल हैं।

31 दिसंबर, 2024 तक, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे (यूपीडीआईसी) में 172 समझौता ज्ञापनों आदि के माध्यम से 31,528 करोड़ रुपये का प्रस्तावित निवेश पहले ही किया जा चुका है और 3,828 करोड़ रुपये का वास्तविक निवेश किया गया है।

इसी तरह, तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे (टीएनडीआईसी) में 80 समझौता ज्ञापनों आदि के माध्यम से 21,825 करोड़ रुपये का प्रस्तावित निवेश पहले ही आकर्षित किया जा चुका है और 4,669 करोड़ रुपये का वास्तविक निवेश किया गया है।

इन गलियारों में निवेश के प्रमुख क्षेत्रों में ड्रोन एवं यूएवी, गोला–बारूद एवं विस्फोटक, छोटे हथियार, उन्नत कंपोजिट, ऑप्टिकल उपकरण, रक्षा पैकेजिंग, सामान्य सुविधा केंद्र, मिसाइल एवं उपग्रह प्रणाली, एमआरओ, अनुसंधान एवं विकास, एयरो इंजन एवं घटक, इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार प्रणाली, कपड़ा, उत्कृष्टता केंद्र, ए एंड डी सामग्री और घटक आदि शामिल हैं।

रक्षा परीक्षण और अवसंरचना योजना (डीटीआईएस) के अंतर्गत रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) दोनों रक्षा औद्योगिक गलियारों (डीआईसी) में एमएसएमई सहित उद्योग के लिए अत्याधुनिक परीक्षण और प्रमाणन सुविधाओं की स्थापना कर रहा है। यूपीडीआईसी में, मानव रहित हवाई प्रणाली, संचार और मैकेनिकल एवं सामग्री संबंधी सुविधाएं और टीएनडीआईसी में, मानव रहित हवाई प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, इलेक्ट्रो–ऑप्टिक्स और मैकेनिकल और सामग्री संबंधी सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं।

(III) रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ (डीआईसी)

रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ का गठन जनवरी 2018 में रक्षा उद्यमियों एवं एमएसएमई के लिए एक इंटीग्रेटर और सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए किया गया था। यह रक्षा उत्पादन में नीति और निवेश के अवसरों से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए उद्यमियों/उद्योगों के संपर्क के एकल बिंदु के रूप में कार्य करता है, जिससे रक्षा उत्पादन क्षेत्र में निवेश की सुविधा मिलती है। रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ (डीआईसी) को https://defenceinvestorcell.gov.in पर ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। डीआईसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाएं निःशुल्क हैं।

(IV) रक्षा उत्पादन सूचना प्रौद्योगिकी (डीपीआईटी) प्रभाग

डीपीआईटी का गठन 2018 में माननीय रक्षा मंत्री की मंजूरी से डीडीपी और डीपीएसयू में आईटी संबंधी पहलों को लागू करने के लिए किया गया था। डीपीआईटी ने रक्षा उत्पादन विभाग और डीओडी के तहत कई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पहल की है। विभिन्न परियोजनाओं में डीडीपी बेबसाइट, डीडीपी डैशबोर्ड, सृजन रक्षा पोर्टल, रक्षा ऑफसेट प्रबंधन पोर्टल, रक्षा एक्जिम पोर्टल, भारत रक्षा मार्ट(आईडीएम) पोर्टल, डेफएक्सपो बेबसाइट, एयरोइंडिया बेबसाइट, आरएम पुरस्कार पोर्टल आदि शामिल हैं।

साझा प्रतिबद्धताएं

मुख्य परिचालन उपलब्धियों के अतिरिक्त, डीडीपी के घटक संगठनों ने राष्ट्रीय महत्व और संस्थागत सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के क्षेत्रों में कई पहल की है। वर्ष के दौरान कई सामान्य पहल की गई, जो जिम्मेदारी के सामूहिक लोकाचार को दर्शाती हैं जो व्यवसाय संचालन से कहीं आगे तक जाती हैं। इन प्रयासों को विषयगत रूप से नीचे प्रस्तुत किया गया है।

राजभाषा हिंदी का प्रचार

संगठनों ने अधिकारिक संप्रेषण में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए दृढ़ प्रयास किए। कार्यशालाओं, प्रतियोगिताओं और जागरुकता कार्यक्रमों में सक्रिय कर्मचारियों की भागीदारी के साथ इकाइयों में हिंदी पखवाड़ा और हिंदी दिवस मनाया गया। कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए कई संस्थाओं को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (टीओएलआईसी) में मान्यता मिली, उनमें कोलकाता में जीआरएसई, हैदराबाद–सिकंदराबाद में मिधानि और गोवा में जीएसएल शामिल हैं।

एचएएल की इन–हाउस हिंदी पत्रिकाओं, बीईएमएल की "बीडीएल भारती"ई–पत्रिका और मिधानि की पुरस्कार विजेता पत्रिका 'संकल्प'जैसे प्रकाशनों ने तकनीकी और गैर–तकनीकी दोनों क्षेत्रों में मूल हिंदी लेखन के साथ साहित्यिक जगत को समृद्ध किया।

पर्यावरण संरक्षण और वनीकरण

पर्यावरण प्रबंधन एक साझा प्राथमिकता बनी रही। लगभग सभी संगठन आईएसओ 14001 प्रमाणित है ओर उत्सर्जन, अपशिष्ट प्रबंधन और अपशिष्ट उपचार की सख्ती से निगरानी की जाती है। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान पूरे बोर्ड में एक दृश्यमान विशेषता थी। विशेष रूप से, बीडीएल ने राष्ट्रीय "एक पेड़ मां के नाम"अभियान के तहत 8,366 से अधिक विभिन्न प्रजातियों का रोपण किया, जबकि मिधानि ने प्रभावी जीवित दर के साथ 12,144 पौधे लगाए।

जीआरएसई ने 12,000 मैंगरोव और फलदार पौधों के रोपण के माध्यम से पारिस्थितिक लचीलेपन को मजबूत किया पेड़, जबकि टीसीएल, जीआईएल,एडब्ल्यूईआईएल और अन्य ने मिलकर नियमित वृक्षारोपण और प्लास्टिक विरोधी जागरुकता अभियानों के साथ स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। एचएएल में, अपशिष्ट से ऊर्जा पहल का विस्तार बेंगलुरु में 500 केजी बायोगैस संयंत्र के साथ किया गया था जो वर्ष में 1,400 टन से अधिक जैविक अपशिष्ट का प्रसंस्करण करती है।

ऊर्जा का उपयोग और संरक्षण

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव ने गति पकड़ी, सौर प्रतिष्ठान एक सामान्य विशेषता के रूप में उभरे। अकेले एचएएल ने अपनी बिजली की जरूरतों का लगभग 40 प्रतिशत पूरा करते हुए लगभग 50 मेगावाट की स्थापित नवीकरणीय क्षमता तक पहुंच गया है, जबकि बीडीएल और जीआरएसई ने वर्ष के दौरान पर्याप्त रूफटॉप संयंत्र जोड़े हैं। एमडीएल ने 1,375 किलोवाट सौर परियोजना के लिए एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, और एडब्ल्यूईआईएल ने अपनी मांग का लगभग 40 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करने की सूचना दी।

पीढ़ी दर पीढ़ी ऊर्जा संरक्षण के प्रयास व्यापक थे। संगठनों ने पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था को एलईडी और बीएलडीसी उपकरणों में बदल दिया, 5 स्टार रेटेड उपकरणों की शुरुआत की, ऊर्जा–कुशल ट्रांसफार्मर और वीएफडी लगाए गए, और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तलाशा गया। जीएसएल ने जनवरी, 2025 तक अपनी सुविधाओं में 100 प्रतिशत एलईडी लाईटिंग सुविधा हासिल की, जबकि जीआईएल ने अपनी उत्पादन इकाइयों के भीतर बैटरी संचालित परिवहन में अग्रणी भूमिका निभाई। एमआईएल की लागू छह–सूत्री कार्य योजना ने भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप एक दीर्घकालिक ढांचा प्रदान किया।

सीएसआर और सार्वजनिक पहुंच

कई संगठनों ने स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से समाज के साथ अपने जुड़ाव में वृद्धि की। जीआरएसई ने सामुदायिक स्वास्थ्य शिविरों, टीबी जागरुकता और विलांग बच्चों की सहायता की, साथ ही युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण की सुविधा भी प्रदान की। जीएसएल ने पारंपरिक बुनाई प्रक्रियाओं को पुनर्जीवित करने और वंचित समुदायों को आजीविका सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय संस्थानों के साथ भागीदारी की।

एमडीएल ने मुंबई के अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करके, टीकाकरण अभियान का समर्थन करके और कैंसर रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके सार्वजनिक स्वास्थ्य में निवेश किया। कई संगठनों में स्वच्छता, कौशल प्रशिक्षण और ग्राम विकास में इसी तरह की पहल की सूचना दी गई, जो समावेशी राष्ट्रीय विकास में इस क्षेत्र की भूमिका की पुष्टि करती है।

साइबर सुरक्षा और डिजीटल अनुपालन

साइबर स्वच्छता और समुत्थान कार्यसूची में प्रमुखता से शामिल था। टीसीएल और जीआईएल जैसे संगठनों ने नियमित सीईआरटी आंतरिक लेखा परीक्षा के साथ–साथ माया ओएस और चक्रव्यूह सहित मंत्रालय के सुरक्षित आईटी प्लेटफार्मे को अपनाया। जीआईएल में मासिक "साइबर जागरूकता दिवस" कार्यक्रमों ने कर्मचारियों को उभरते खतरों के प्रति संवेदनशील रखा, जबकि कार्यशालाओं और जागरूकता अभियानों ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, ये साझा पहल संगठनों में जिम्मेदारी और दूरदर्शिता की संस्कृति को रेखांकित करती हैं। चाहे नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के माध्यम से, भाषाई समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता हो, या सक्रिय सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से यह सामूहिक प्रयास परिचालन अधिदेश से कहीं आगे तक जाते हैं। वे एक भविष्योन्मुखी लोकाचार के प्रतीक हैं– जो पर्यावरण देखभाल, तकनीकी सुरक्षा और सामाजिक विकास के साथ औद्योगिक विकास को संतुलित करते हैं।

*****

सैन्य कार्य विभाग

सत्यमेव जयते

रक्षा मंत्रालय

भारत सरकार

सैन्य कार्य विभाग

सैन्य कार्य विभाग (डीएमए), जिसकी अध्यक्षता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) इसके सचिव के रूप में करते हैं, को सुरक्षा मामलें संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस) की स्वीकृति से गठित किया गया था। इसका उद्देश्य देश के तीनों सशस्त्र बलों के बीच प्रशिक्षण, स्टाफिंग, खरीद और संक्रियाओं में समन्वय स्थापित करना, संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना और अंतर–सेवा सहयोग को बढ़ावा देना है। इसलिए, विशेष रूप से सैन्य मामलों से संबंधित कार्य सैन्य कार्य विभाग के अधिकार क्षेत्र में रखे गए, जबकि रक्षा विभाग को रक्षा नीति सहित देश की रक्षा से संबंधित बड़े मुद्दों से निपटने का दायित्व सौंपा गया।

सीडीएस एवं सचिव, डीएमए की नियुक्ति

सेना प्रमुखों के समान वेतन और सुविधाओं के साथ चार सितारा जनरल के रैंक का सीडीएस का पद दिसंबर, 2019 में सृजित किया गया था। सरकार ने उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को भी परिभाषित किया है। सीडीएस, रक्षा मंत्रालय के सचिव के रूप में दोहरी भूमिका निभाने के अलावा, चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष भी होते हैं। वे तीनों सेनाओं के सभी मामलों पर माननीय रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, जबकि तीनों सेना प्रमुख अपनी–अपनी सेनाओं से संबंधित मामलों पर माननीय रक्षा मंत्री को सलाह देते हैं। चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में, सीडीएस को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में एकीकृत रक्षा स्टाफ के मुख्यालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

जनरल बिपिन रावत पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एसएम, वीएसएम, एडीसी को भारत सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2019 से पहला सीडीएस और सीओएससी का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। जनरल अनिल चौहान पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम को 30 सितंबर 2022 से वर्तमान सीडीएस एवं सचिव, सैन्य कार्य विभाग नियुक्त किया गया है।

विभाग का चार्टर

कार्य आवंटन नियम, 1961 में संशोधन के बाद नए सैन्य कार्य विभाग को निम्नलिखित विषय आवंटित किए गए:–

(क) संघ के सशस्त्र बल, अर्थात् थल सेना, नौसेना और वायु सेना;

(ख) रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय जिसमें सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय, वायु सेना मुख्यालय और डिफेंस स्टाफ मुख्यालय शामिल हैं;

(ग) प्रादेशिक सेना;

(घ) सेना, नौसेना और वायु सेना से संबंधित कार्य;

(ङ) प्रचलित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार पूंजीगत अधिग्रहणों को छोड़कर, सेनाओं के लिए विशेष खरीद।

विभाग की संरचना

सीसीएस अनुमोदन द्वारा विभाग में अपर सचिव का एक पद और संयुक्त सचिव के तीन पद सृजित किए गए, जिसके बाद विभाग की संरचना इस प्रकार बन गई है:

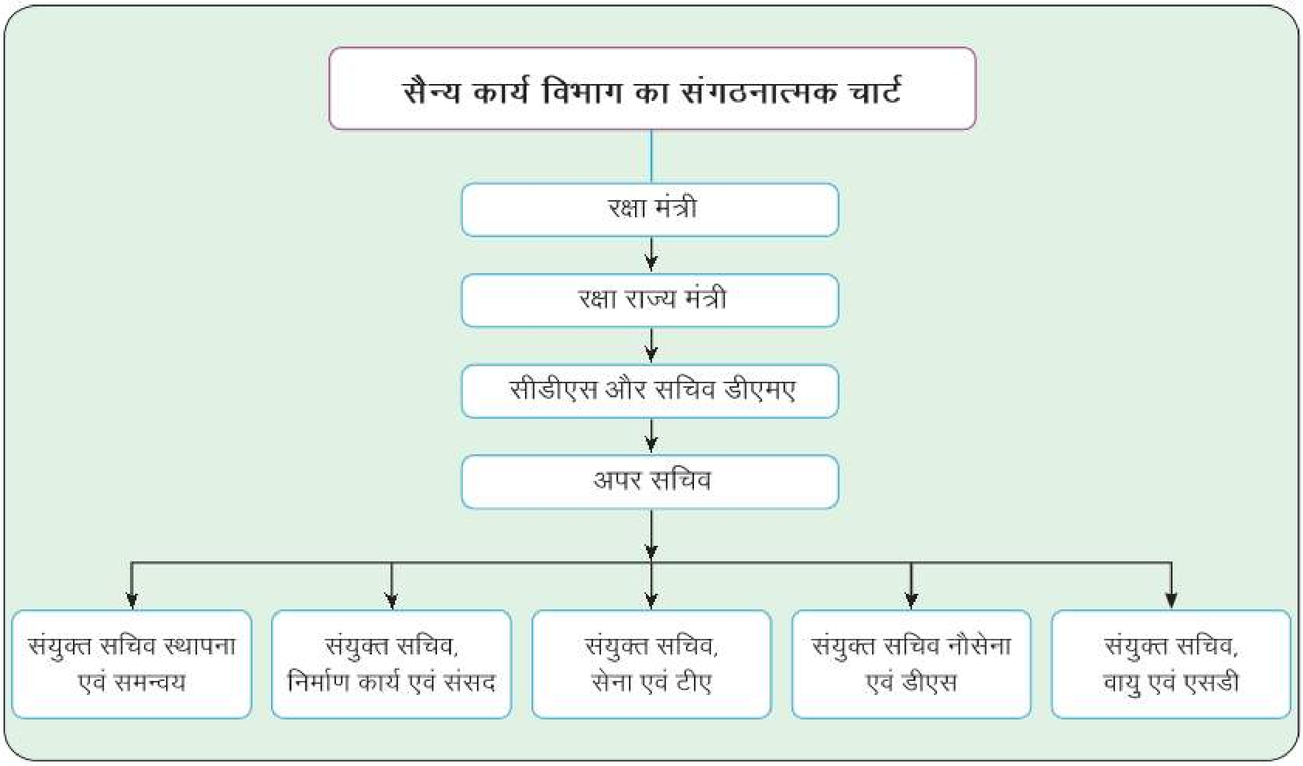

संबद्ध कार्यालय : रक्षा मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय इस प्रकार हैं:–

(क) सेना मुख्यालय

(ख) नौसेना मुख्यालय

(ग) वायु सेना मुख्यालय

(घ) मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ।

भारतीय सेना

हमारे देश के सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियाँ विविध और जटिल हैं। भारतीय सेना (आईए) तेजी से बदलते भू–राजनीतिक, सामाजिक–आर्थिक और तकनीकी परिदृश्य के साथ–साथ इन जटिलताओं को भी पहचानती है। परिणामस्वरूप, भारतीय नौसेना ने भविष्य के लिए तैयार सेना के निर्माण हेतु वर्ष 2022 से वर्ष 2032 तक की अवधि को 'परिवर्तन का दशक' घोषित किया है। प्रचालन तत्परता का निरंतर आकलन करते हुए, भारतीय सेना राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने और देश की संप्रभुता एवं एकता को बाहरी एवं आंतरिक, दोनों ही खतरों से बचाने के लिए समर्पित है। भारतीय सेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाने हेतु सक्रिय रूप से कार्यरत है।

प्रचालन तत्परता

संक्रियाएं

भारतीय सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) और नियंत्रण रेखा (एलसी) पर पूरी तरह से अपनी प्रचालनात्मक तैयारियाँ बनाए हुए है। लगातार आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं, साथ ही उभरते और भविष्य के खतरों की निरंतर समीक्षा भी की जा रही है।

एलएसी पर स्थिति : एलएसी पर कुल मिलाकर स्थिति स्थिर लेकिन संवेदनशील बनी हुई है। भारतीय सेना की तैनाती मज़बूत है और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त भंडार मौजूद है। राजनयिक और सैन्य स्तरों पर लंबी बातचीत के बाद, 21 अक्तूबर 2024 को समान और पारस्परिक सुरक्षा के सिद्धांतों के आधार पर ज़मीनी स्थिति बहाल करने पर व्यापक सहमति बन गई है। देपसांग और डेमचोक में पारंपरिक गश्त वाले क्षेत्रों में गश्त शुरू हो गई है। इस प्रस्ताव के बाद, इन क्षेत्रों में स्थिति यथास्थिति पर वापस आ गई है।

जम्मू और कश्मीर (जे एंड के) : केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुज़र रहा है। रुक–रुक कर हो रही हिंसा के बावजूद, जम्मू और कश्मीर में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। मज़बूत घुसपैठ–रोधी ग्रिड बनाए रखने और लगातार अभियानों को चलाते रहने से चुनावों के सफल संचालन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है।

मज़बूत घुसपैठ रोधी ग्रिड बनाए रखना

नियंत्रण रेखा पर स्थितिः नियंत्रण रेखा पर स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। भारतीय सेना स्थिति पर कड़ी नज़र रख रही है और नियंत्रण रेखा पर किसी भी आक्रमक कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार है। पिछले वर्षों की तुलना में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की तीव्रता में कमी देखी गई है।

आंतरिक क्षेत्रों की स्थिति

- वर्ष 2019 से, आंतरिक क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। शुरुआती सामान्य स्थिति के परिणामस्वरूप पर्यटन में वृद्धि हुई है।

- **अमरनाथ यात्रा – 2024:** जुलाई और अगस्त 2024 में, बढ़ते खतरों की पृष्ठभूमि में अमरनाथ यात्रा आयोजित की गई थी। ऑपरेशन शिवा के तहत, लगभग 5,000 सैनिकों और अन्य संसाधनों को एहतियाती सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। नागरिक प्रशासन के अनुरोध पर, दोनों मार्गों पर टेंट और चिकित्सा कवर जैसे संसाधन भी उपलब्ध कराए गए थे। सुरक्षा तंत्र के अथक और समन्वित प्रयासों के कारण, यात्रा निर्बाध संपन्न हुई।

- **स्थानीय भर्तीः** स्थानीय युवाओं ने हिंसा के मार्ग से नाता तोड़ लिया है और वे विभिन्न सरकारी योजनाओं और नीतियों का लाभ उठा रहे हैं। वर्ष 2020 से वर्ष 2024 की अवधि में आतंकवादी रैंकों में शामिल होने वाले स्थानीय लोगों की संख्या 191 से घटकर 4 रह गई है, जिससे पाकिस्तान के घरेलू आतंकवाद के आख्यान की साख धूमिल हो गई है।

- समग्र स्थिति में सुधार के बावजूद, रुक–रुक कर होने वाली हिंसात्मक गतिविधियां देखी गई। खासकर गैर–स्थानीय नागरिकों, अल्पसंख्यकों और सुरक्षा बलों के जवानों की लक्षित हत्याओं के स्वरूप में। इस वर्ष आंतरिक इलाकों में तीव्र आतंकवाद–रोधी (सीटी) अभियानों में 48 आतंकवादियों (जिनमें 18 पाकिस्तानी आतंकवादी शामिल हैं) का सफाया किया गया। इस वर्ष मारे गए कुल आतंकवादियों में लगभग 55% पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, जो स्पष्ट रूप से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर में तनाव बनाए रखने के पाकिस्तान के इरादे को दर्शाता है।

पूर्वोत्तर (एनई) में सुरक्षा स्थितिः मणिपुर को छोड़कर, पूर्वोत्तर राज्यों में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति स्थिर रही है। मणिपुर में मई 2023 में भड़काई गई हिंसा की चक्रीय घटनाएँ अब काफी हद तक स्थिर हो गई हैं। पिछले डेढ़ वर्षों में सुरक्षा बलों के समन्वित प्रयासों और सरकार की सक्रिय पहलों से स्थिति नियंत्रण में आ गई है। अगस्त 2024 में, सेनाध्यक्ष (सीओएएस) ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की, जिसके दौरान उन्होंने मणिपुर में तैनात सैन्य दलों के साथ बातचीत की। उन्होंने मणिपुर में राज्य प्रशासन के साथ भी बातचीत की और वर्तमान स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

सेनाध्यक्ष (सीओएएस) ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की

सक्रियात्मक संभारिकी

सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे का विकास सक्रियात्मक तैयारियों की प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है। सक्रियात्मक दृष्टिकोण से आवश्यक बुनियादी ढाँचे का विकास समग्र और व्यापक तरीके से किया जा रहा है।

सक्रियात्मक कार्य : प्रचालन अवसंरचना में सुधार हेतु सक्रियात्मक कार्यों हेतु धनराशि का बढ़ा हुआ आवंटन (लगभग 1,884 करोड़ रुपये) सुनिश्चित किया गया है। निर्माण कार्य बल संरक्षण परिसंपत्तियों, सक्रियात्मक संभार अवसंरचना, बिलेटिंग, अग्रिम संपर्कता की स्थापना, घुसपैठ–रोधी प्रणाली और विमानन संबंधी अवसंरचना सहित समग्र अवसंरचना के विकास पर केंद्रित हैं। 1,800 से भी अधिक सैनिकों के लिए आवासों का निर्माण किया गया है।

सिक्किम पुनरुद्धार कार्य: अक्तूबर 2023 में ग्लेशियल झील के फटने से आई बाढ़ के कारण सिक्किम में संपर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इसके अलावा, मई 2024 में आई अचानक बाढ़ ने सिक्किम में सड़कों और पुलों को बुरी तरह प्रभावित किया। भारतीय सेना की टुकड़ियों ने पुनरुद्धार कार्यों और अवसंरचना के विकास के लिए नागरिक प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से भागीदारी की थीं।

सिक्किम में अचानक आई बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण कार्य

शिंकुनला सुरंग: शिंकुनला सुरंग, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नीमू–पदम–दारचा मार्ग पर लगभग 1,681 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 4.1 किलोमीटर लंबी सुरंग है। कारगिल विजय दिवस (26 जुलाई 2024) के अवसर पर, माननीय प्रधानमंत्री ने इस सुरंग का वर्चुअल उद्घाटन किया।

अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) केंद्र: भारत को एक वैश्विक एमआरओ देश बनाने की सरकार की पहल के अनुरूप, सेना विमानन बेड़े के लिए एमआरओ केंद्र पूरी क्षमता से विकसित होने की प्रक्रिया में हैं। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के लिए क्रमशः मामून और मिसामारी में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर (एएलएच) बेड़े के लिए एमआरओ केंद्र स्थापित किए गए हैं। रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम (आरपीएएस) बेड़े के लिए एमआरओ हब भिवानी (हरियाणा) में स्थापित किया गया है और संयुक्त सेवा व्यापक वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध के माध्यम से तीनों सेनाओं की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसका विस्तार किया जा रहा है।

रखरखाव मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) केन्द्र

टैंक टी–90 का ओवरहालः रक्षा क्षेत्र में तकनीकी और रसद आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप, आर्मी बेस वर्कशॉप ने पहले टैंक टी–90 का पूर्ण ओवरहाल किया है, जिसका अपने निर्धारित जीवनकाल में त्वरित और व्यापक उपयोग किया गया था। ओवरहाल किए गए इस टैंक को अक्तूबर 2024 में सफलतापूर्वक सेना में शामिल किया गया।

राष्ट्रीय संभार नीति : प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएम जीएस एनएमपी) के अनुरूप, सीमावर्ती सड़कों, अस्पतालों, रेलवे लाइनों आदि जैसे दोहरे उपयोग वाले बुनियादी ढांचे का विवरण जीएस एनएमपी पोर्टल पर अपलोड किया गया है। आईए के 103 प्रस्तावों को शामिल किया गया है, जिससे रक्षा संभार को राष्ट्रीय संभार के ढांचे में एकीकृत करने में सुविधा प्राप्त होगी। संभार, प्रधानमंत्री गति शक्ति और राष्ट्रीय संभार नीति जैसे विषयों में भारतीय सेना कर्मियों के कौशल विकास हेतु गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। सेना में क्षमता निर्माण कार्यशालाएँ भी आयोजित की गई हैं, जिनमें 300 से अधिक अधिकारियों को आईगोट (आई जीओटी) कर्मयोगी प्लेटफ़ॉर्म पर प्रशिक्षित किया गया है और अब तक 50 से अधिक अधिकारियों को बीआईएसएजी एन में प्रशिक्षित किया जा चुका है।

गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन

क्षमता विकास और आधुनिकीकरण

क्षमता विकास

सेना आधुनिकीकरण और 'आत्मनिर्भरता' के माध्यम से क्षमता विकास सतत गति से आगे बढ़ रहा है। दुनिया भर के सक्रिय युद्ध क्षेत्रों में विकसित और नियोजित किए जा रहे उच्च तकनीक वाले युद्ध उपकरणों पर ध्यान दिया जा रहा है, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी)–2020 में 2025 में पूर्ण परिवर्तन होने की संभावना है। अगले 15 वर्षों में शक्तिशाली युद्ध क्षमता प्राप्त करने के लिए 500 से अधिक योजनाओं की योजना बनाई गई है।

आत्मनिर्भरता

'आत्मनिर्भरता' के संदर्भ में, भारतीय सेना अपने युद्धक भंडार के दायरे और पैमाने के कारण सबसे बड़े हितधारकों में से एक है। पिछले चार वित्तीय वर्षों (2021–22 से 2024–25) में संपन्न 164 पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों में से, 148 पूंजी अधिग्रहण अनुबंध (90%) सामान्य/ईपी अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत भारतीय विक्रेताओं के साथ हस्ताक्षरित किए गए हैं। 1 जनवरी से दिसंबर 2024 तक, 19 अनुबंध संपन्न हुए हैं, जिनमें से 17 स्वदेशी उद्योगों के साथ हस्ताक्षरित हैं।

गोला–बारूद अधिप्राप्ति : 'भारतीय उद्योग द्वारा भारतीय सेना के लिए गोला–बारूद निर्माण' के अंतर्गत दीर्घकालिक आवश्यकता के लिए गोला–बारूद अधिप्राप्ति हेतु एक स्पष्ट रोडमैप तैयार किया गया है। निरंतर सक्रिय प्रयासों के परिणामस्वरूप, अन्य एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय से 175 में से 154 (लगभग 88%) गोला–बारूद प्रकारों का स्वदेशीकरण किया गया है। शेष को वर्ष 2030 तक स्वदेशी बनाने का लक्ष्य है।

वार्षिक स्वदेशीकरण योजना (एआईपी) : सभी सेवारत हथियार प्लेटफार्मों के पुर्जों और घटकों में 'आत्मनिर्भरता' प्राप्त करने के लिए, एआईपी 2024–25 प्रख्यापित की गई है। इसमें 109 परियोजनाएँ शामिल हैं और इसमें लगभग 74.97 करोड़ रुपये की लागत वाली 357 असेंबली/सब–असेंबली/घटक पैकेजों का स्वदेशीकरण शामिल है।

सृजन वेब पोर्टल: भारतीय रक्षा उद्योग को हमारी स्वदेशीकरण आवश्यकताओं की व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए भारतीय सेना द्वारा विकसित सृजन पोर्टल का लाभकारी उपयोग किया जा रहा है। अब तक, पोर्टल पर 551 वस्तुएँ अपलोड की जा चुकी हैं।

सेना डिज़ाइन ब्यूरो (एडीबी) की पहल

- एडीबी तकनीकी अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) प्रयासों और मेक प्रोजेक्ट्स, आर्मी टेक्नोलॉजी बोर्ड (एटीबी), टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (टीडीएफ) आदि जैसे विभिन्न माध्यमों से स्वदेशी रूप से विकसित हथियारों और उपकरणों की खरीद में एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करता है।

- एटीबी के तहत संचालित परियोजनाओं की संख्या एक वर्ष में 17 से बढ़कर 62 हो गई है। ये परियोजनाएँ भारत के अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से शुरू की जा रही हैं, जो रैमजेट प्रोजेक्टाइल, लो लाइट इमेजिंग तकनीक और विभिन्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित परियोजनाओं जैसी विशिष्ट तकनीकों के विकास से संबंधित हैं।

- टीडीएफ को सरकार द्वारा अवधारणा–सिद्धि चरण से आगे अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए शुरू किया गया है। वर्तमान में, टीडीएफ के माध्यम से एडीबी द्वारा पाँच परियोजनाओं (लगभग 50 करोड़ रुपये) पर काम चल रहा है। 49 डिज़ाइन एवं विकास (डीएंडडी) परियोजनाओं और 61 प्रौद्योगिकी प्रदर्शक (टीडी) परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) के साथ प्रभावी तालमेल स्थापित किया गया है।

- **नवाचार**: रक्षा उत्कृष्टता में नवाचार (आई–डेक्स) और आई–डेक्स के साथ नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास में सफलता (एडीआईटीआई) जैसी पहलों की घोषणा सरकार द्वारा देश में नवाचार संस्कृति को समन्वित करने और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने वाला एक पारि–प्रणाली बनाने के लिए की गई है। आई–डेक्स चुनौतियों के तहत, वर्तमान में 88 परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

- **आईए विचार और नवाचार प्रतियोगिता–2024** : समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने, नए विचारों को आत्मसात करने और लीक से हटकर सोचने को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 'विचार और नवाचार प्रतियोगिता' आयोजित की जाती है। इस वर्ष, संपूर्ण भारतीय सेना में कुल 72 नवाचारों का चयन किया गया। इनमें से 22 नवाचारों को दिसंबर 2024 में प्रतियोगिता के समापन चरण के दौरान अंतिम प्रदर्शन के लिए चुना गया।

विचार एवं नवाचार प्रतियोगिता–2024

स्वावलंबन शक्ति अभ्यास: अक्तूबर 2024 में बबीना फील्ड फायरिंग रेंज (बीएफएफआर) में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया था। यह एक युद्ध समूह स्तरीय एकीकृत अग्नि और युद्धाभ्यास अभ्यास था। इस अभ्यास का उद्देश्य सामरिक और प्रचालन स्तर पर सभी उपलब्ध नवीन प्रौद्योगिकी उपकरणों (एनटीई) को एकीकृत करना था। इस अभ्यास ने उभरते स्टार्ट–अप्स को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच भी प्रदान किया। लगभग 1,800 कर्मियों, 210 सशस्त्र वाहनों, 50 विशेषज्ञ वाहनों और कई हवाई उपकरणों ने इस अभ्यास में भाग लिया। इसके अलावा, डीआरडीओ प्रयोगशालाओं सहित 40 से अधिक प्रमुख उद्योग भागीदारों के 50 से अधिक एनटीई ने भी इस अभ्यास में भाग लिया।

स्वावलंबन शक्ति अभ्यास

आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी समावेशन

हानिकारक प्रौद्योगिकियां आधुनिक युद्ध की प्रकृति को बदल रही हैं। हाल के संघर्षों के विश्लेषण से पता चलता है कि युद्धक प्लेटफार्मों में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों तक पहुँच किसी भी राष्ट्र के लिए भविष्य के संघर्षों में जीवित रहने और फलने–फूलने के लिए आवश्यक है। भारतीय सेना एक आधुनिक, चुस्त, अनुकूलनीय और प्रौद्योगिकी–सक्षम भविष्य के लिए तैयार सेना में परिवर्तित होने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रौद्योगिकी के समावेशन के लिए नवाचार, समावेशन और अनुकूलन की आवश्यकता होती है। वर्ष 2024 और 2025 को 'प्रौद्योगिकी समावेशन के वर्ष' और 2022–32 को 'परिवर्तन के दशक' के रूप में घोषित किया जाना, प्रौद्योगिकी के समावेशन द्वारा सेना आधुनिकीकरण प्राप्त करने और 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण में योगदान देने के उद्देश्य से है।

भारतीय सेना प्रौद्योगिकी समिति: भारतीय सेना (आईए) अब राष्ट्रीय क्वांटम मिशन जैसे प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय मिशनों का हिस्सा है। आईए में प्रौद्योगिकी समावेशन हेतु एक ढाँचा स्थापित करने के लिए, पूर्ववर्ती प्रौद्योगिकी समितियों और स्वचालन समितियों को मिलाकर एक त्रि–स्तरीय प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया गया है। 16 तकनीकी क्लस्टरों की पहचान की गई है, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट तकनीकी क्षेत्र जैसे एआई, ब्लॉकचेन, 3–डी प्रिंटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी आदि से संबंधित है। इनके सामरिक, प्रचालनात्मक और रणनीतिक लक्ष्य सुपरिभाषित हैं। इन क्लस्टरों का संचालन प्रमुख निदेशालयों द्वारा किया जा रहा है, जो एक प्रमुख प्रधान स्टाफ ऑफिसर के अधीन समयबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं।

सिग्नल तकनीकी मूल्यांकन एवं अनुकूलन समूह (एसटीईएजी) का गठन: युद्ध क्षेत्र में प्रभावी संचार हेतु 5जी, 6जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो जैसी उन्नत संचार तकनीकों का लाभ उठाने हेतु विशिष्ट एसटीईएजी का गठन किया गया है।

भारतीय सेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्क्यूबेशन सेंटर (आईएएआईसी): एआई को अपने प्रचालन ढांचे में एकीकृत करने के लिए, एक एआई रोडमैप तैयार किया गया है जिसमें कार्यान्वयन के लिए प्रयासों और समय–सीमा का उल्लेख किया गया है। संयुक्त प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप, बेंगलुरु स्थित बीईएल के अनुसंधान एवं विकास केंद्र में एआई के लिए एआई इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है। आईएएआईआईसी, भारतीय सेना की तकनीकी आकांक्षाओं को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करेगा, जो सैन्य एआई अनुप्रयोगों में वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और इसे एक 'एआई रेडी फोर्स' बनाएगा।

भारतीय सेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनक्यूबेशन सेंटर (आईएएआईआईसी)

क्वांटम कुंजी वितरण (क्यूकेडी) परियोजना: 'आत्मनिर्भरता' की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सितंबर 2024 में क्यूकेडी परियोजना के विकास हेतु एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए, जो मौजूदा एल्गोरिथम–आधारित एन्क्रिप्शन प्रणाली का स्थान लेगी और इस प्रकार बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

नवाचार से लेकर समावेशन तक: आंतरिक रूप से विकसित निम्नलिखित नवाचारों का समावेशन किया गया है:

- **विद्युत रक्षक:** सैन्य कर्मियों द्वारा विकसित एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स सक्षम एकीकृत जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली को उत्तरी कमान में शामिल किया गया है।

विद्युत रक्षक

- सैन्य कर्मियों द्वारा विकसित दो नवाचारों, अर्थात् 'एक्सप्लोडर–इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस डिस्पोजल एंड रूम इंटरवेंशन अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल (यूजीवी)' और 'अग्निअस्त्र'– एक पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस, का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) दो निजी उद्योगों के साथ किया गया है। दोनों नवाचारों का पारंपरिक और सह–पारंपरिक अभियानों में व्यापक रूप से उपयोग किया गया है।

डिजिटलीकरण और स्वचालन

प्रचालन, कार्यात्मक और मानव संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजिटल, नेटवर्कयुक्त और स्वचालित आंतरिक समाधानों की खोज की जा रही है। डिजिटलीकरण और स्वचालन पहल किस प्रकार भारत के डिजिटल परिदृश्य को नया रूप दे रही हैं, इसकी एक झलक माननीय रक्षा मंत्री द्वारा अक्तूबर 2024 में 'चाणक्य रक्षा संवाद–2024' के दौरान विमोचित एक पुस्तक में मिलती है। इस पुस्तक में ऑपरेशन, इंटेलिजेंस, रसद, मानव संसाधन, प्रशासनिक कार्यप्रणाली और विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में आंतरिक रूप से विकसित 100 से अधिक सॉफ्टवेयर/अनुप्रयोगों पर प्रकाश डाला गया है।

चाणक्य रक्षा संवाद–2024

परियोजना संजय (युद्धक्षेत्र निगरानी प्रणाली) चरण 2: परियोजना "संजय" का उद्देश्य एक अनुकूलित भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) प्लेटफ़ॉर्म पर संरचना स्तर पर एसएटीए सेंसरों को एकीकृत करना है। यह त्वरित निर्णय लेने में सहायता के लिए लगभग वास्तविक समय में स्थिति का आकलन प्रदान करता है। यह प्रणाली सेना एकीकृत निर्णय सहायता प्रणाली (एआईडीएसएस), एसीसीसीएस को भी इनपुट प्रदान करती है और सेना के लिए स्थितिजन्य जागरूकता मॉड्यूल (एसएएमए) सहित सामरिक सी3आई प्रणाली के अन्य घटकों के साथ परस्पर क्रिया करती है।

परियोजना संजय

अधिकारी की स्वचालित एवं संरचना सूचना प्रणाली (ओएएसआईएस): ओएसिस (ओएएसआईएस) सॉफ़्टवेयर को 2019 में अधिकारी रिकॉर्ड संगठन (ओआरओ), सेवारत अधिकारियों और इकाइयों के लिए एक इंटरफ़ेस के रूप में लॉन्च किया गया था। यह सॉफ़्टवेयर सभी सेवारत अधिकारियों के सेवा अभिलेख का एक केंद्रीय डेटा संग्रह बनाने में सहायता करता है। ओएसिस के माध्यम से मार्च 2024 तक सभी सेवारत अधिकारियों का 100% डिजिटलीकरण प्राप्त कर लिया गया था।

एसएएमए 2.0 (बुद्धिमान एसएएमए): एसएएमए एक वेब–आधारित अनुप्रयोग है जिसमें एआई विशेषताएँ हैं जो सभी प्रचालन सूचना प्रणालियों, प्रबंधन सूचना प्रणालियों और अन्य खुफिया स्रोतों से इनपुट प्राप्त और एकीकृत करता है। इस परियोजना की योजना कमांडरों को विश्वसनीय खुफिया इनपुट के आधार पर यथासमय और सूचित निर्णय लेने हेतु वास्तविक समय स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।

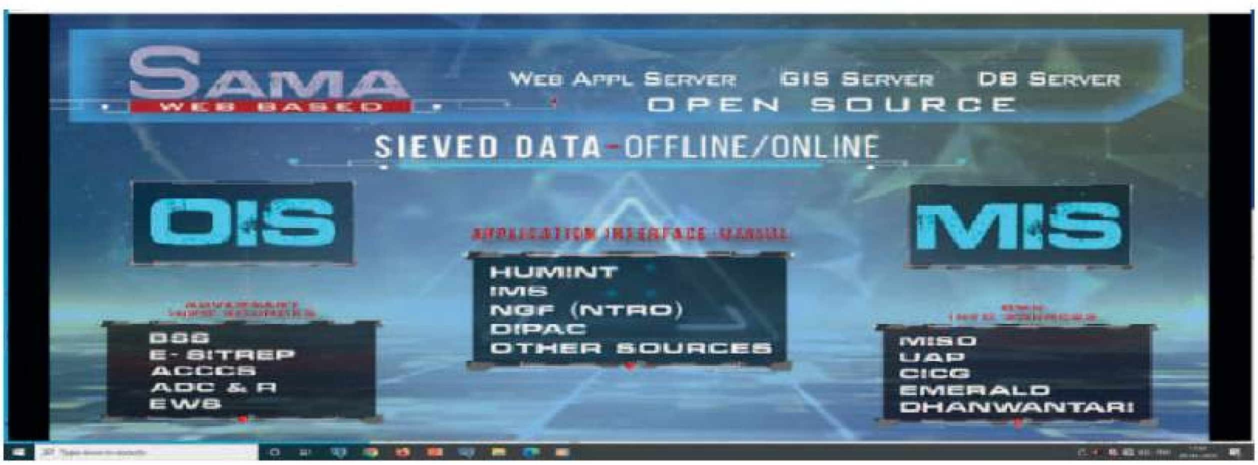

एसएएमए 2.0

परियोजना अनुमान 2.0: अनुमान 2.0 मेट्रोलॉजिकल एप्लिकेशन को लगभग वास्तविक समय निष्क्रिय मेट्रोलॉजिकल पूर्वानुमान प्रणाली के रूप में आंतरिक रूप से विकसित किया गया है। यह जमीनी स्तर से लेकर 30,000 मीटर (लगभग) तक की क्षैतिज परतों के लिए, तोपखाने इकाइयों को फील्ड फायरिंग करने के लिए, प्रति घंटे 72 घंटों के अंतराल पर मेट्रोलॉजिकल संदेश प्रदान करता है। यह भारतीय वायु सेना (आईएएफ) और भारतीय नौसेना (आईएन) मौसम पूर्वानुमान

प्रणालियों के साथ एकीकृत है।

यू–विनः सैन्य अस्पतालों को यू–विन पोर्टल पर जोड़ा जा रहा है, जो टीकाकरण और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए व्यक्तिगत अनुरेखण हेतु सभी गर्भवती महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन नियुक्ति और पंजीकरण हेतु एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है। स्वास्थ्य सेवा कर्मी कुशल योजना और टीका वितरण के लिए वास्तविक समय डेटा तैयार कर सकेंगे।

एकलव्य (दूरस्थ शिक्षा सॉफ्टवेयर) परियोजनाः 'एकलव्य परियोजना' का उद्देश्य ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से भारतीय सेना में व्यावसायिक सैन्य शिक्षा में क्रांति लाना है। यह प्लेटफ़ॉर्म युवा अधिकारी पाठ्यक्रम, जूनियर कमांड पाठ्यक्रम, विशेषज्ञ नियुक्तियों से जुड़े विशेष पाठ्यक्रम और रुचि के अन्य विभिन्न पाठ्यक्रम जैसे बुनियादी अनिवार्य पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसमें खोज योग्य "ज्ञान भंडार" भी है जिसमें अनेक शोध पत्र, सैन्य लेख और पत्रिकाएँ शामिल हैं। इस परियोजना का उद्घाटन नवंबर 2024 में किया गया था।

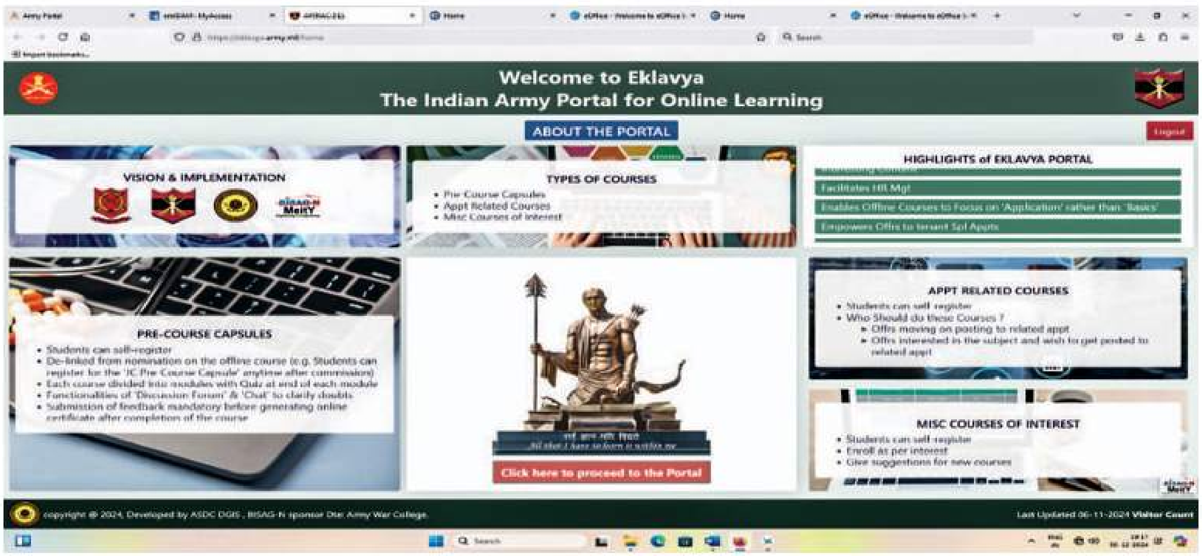

एकलव्य परियोजना–ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल

ई–ग्रंथालयः ई–ग्रंथालय एप्लिकेशन का शुभारंभ माननीय रक्षा मंत्री द्वारा सितंबर 2024 में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दौरान किया गया था। यह तीनों सेनाओं के लिए एक प्रमुख ज्ञान साझाकरण मंच है, जो सहयोगी संस्थागत डेटाबेस के साथ–साथ तीनों सेनाओं के ज्ञान और अध्ययन सामग्री के एकल ऑनलाइन भंडार के रूप में कार्य करता है। 26 त्रि–सेवा संस्थानों से लगभग नौ लाख पुस्तकों की सूची प्राप्त की गई है।

अनुबंध डेटा का स्वचालनः प्रोमो (अधिप्राप्ति निगरानी) एप्लिकेशनः एक वेब–आधारित एप्लिकेशन 'प्रोमो' को आंतरिक रूप से विकसित किया गया है और फरवरी 2024 में होस्ट किया गया। यह बहु–चरणीय पूंजीगत खरीद में वास्तविक समय की सटीकता के साथ समसामयिक डेटा दृश्यता सुनिश्चित करता है, जहाँ प्रत्येक चरण में कई हितधारक शामिल होते हैं। यह पूंजीगत खरीद प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाता है और खरीद के विभिन्न चरणों में संभावित त्रुटियों को नकारता है।

रक्षा यात्रा प्रणाली (डीटीएस) संस्करण 2.0 का संचालनः माननीय रक्षा मंत्री द्वारा 01 अक्तूबर 2024 को डीटीएस संस्करण 2.0 का शुभारंभ किया गया है। इस प्रणाली का उद्देश्य तेज़ प्रदर्शन और कम डाउनटाइम के साथ बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करना है। आईए ने सफलतापूर्वक इस नई प्रणाली को अपनाया है जो रेल और हवाई यात्रा के लिए ई–टिकटिंग समाधान प्रदान करती है।

सेना सिविलियन डेटा प्रबंधन प्रणाली (संचय): संचय एक इंटरनेट–आधारित एप्लिकेशन है जिसे आंतरिक रूप से विकसित किया गया है और जनवरी 2024 में एनआईसी क्लाउड पर होस्ट किया गया है। अब तक लगभग 58,000 सेना सिविलियन कर्मियों का डेटा एकत्र किया जा चुका है। यह हितधारकों द्वारा विश्लेषण और त्वरित निर्णय लेने के लिए डेटा/आँकड़ों के उपयोग की सुविधा प्रदान करता है।

त्रि–सेवा सहक्रिया

भारतीय सशस्त्र सेनाओं की प्रचालन सहक्रिया और दक्षता बढ़ाने के लिए भारतीय सशस्त्र सेना संगठन प्रतिबद्ध है। तीनों सेनाओं के बीच एकीकरण इस प्रयास का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा आगामी थिएटरीकरण को समर्थ और सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। तीनों सेनाओं से संबंधित मुद्दों पर समान नीतियाँ बनाने के प्रयास किए गए हैं, जिनमें अनिवार्य त्रि–सेवा अनुभव, मूल्यांकन और पदोन्नति शामिल हैं।

एकीकृत थिएटर कमान (आईटीसी): वर्तमान तीनों सेनाओं की कमानों को संयुक्त/एकीकृत थिएटर कमानों में पुनर्गठित करना हमारी सेनाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है और यह अंतर–संचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए 'कमान की एकता' और 'प्रयास की सहक्रिया' पर आधारित है। यह संचालन योजना और कार्यान्वयन में सहक्रिया करने, संयुक्त प्रभावों के माध्यम से विषमता को कम करने, प्रयासों को अनुकूलित करने और वित्तीय विवेक का प्रयोग करने में सहायक है। भारतीय सेना थिएटरीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सर्वसम्मति–आधारित दृष्टिकोण की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है और विभिन्न स्तरों पर आपसी चर्चाओं के माध्यम से, जिसमें सेना अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के स्तर पर भी शामिल हैं, अलग अलग सेना चिंताओं का समाधान किया जा रहा है।

अभ्यास भारत शक्ति : मार्च 2024 में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में तीनों सेनाओं की लाइव फायरिंग और युद्धाभ्यास के रूप में स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का एक समन्वित प्रदर्शन किया गया। इस अभ्यास ने राष्ट्र की आत्मनिर्भरता पहल पर आधारित देश के कौशल का प्रदर्शन किया।

अभ्यास भारत शक्ति

संयुक्त प्रशिक्षण

- **अभ्यास जलप्रहार–I और II** : भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त उभयचर प्रशिक्षण अभ्यास, अभ्यास जलप्रहार–I और II, क्रमशः जनवरी और सितंबर 2024 में विशाखापत्तनम में आयोजित किए गए। इसके बाद अक्तूबर 2024 में काकीनाडा में आईएनएस जलश्व का ऑपरेशन सी टेस्ट (ओएसटी) किया गया।

अभ्यास जलप्रहार–I और II

- **अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ–2024** : टाइगर ट्रायम्फ–2024, भारतीय सेना और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय त्रि–सेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) अभ्यास है। यह मार्च 2024 में काकीनाडा समुद्र तट पर आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य एचएडीआर अभियानों को अंजाम देने के लिए दोनों सेनाओं के बीच अंतर–संचालन क्षमता में सुधार करना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान त्वरित तैनाती और त्रुटिहीन समन्वय को सक्षम करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को परिष्कृत करना था।

अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ–2024

- **अभ्यास तटरक्षा**: फरवरी 2024 में भुज में अभ्यास तटरक्षा आयोजित किया गया था। यह कच्छ प्रायद्वीप की सुरक्षा के लिए एक बहु–एजेंसी अभ्यास है।

अभ्यास तटरक्षा

- **अभ्यास संयुक्त विमोचन – 2024: (वार्षिक संयुक्त एचएडीआर अभ्यास)** – वार्षिक संयुक्त एचएडीआर अभ्यास **'संयुक्त विमोचन 2024'** नवंबर 2024 में अहमदाबाद और पोरबंदर में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य आपदा प्रतिक्रिया की दक्षता का आकलन करना और मौजूदा आपदा प्रबंधन संरचनाओं का अनुकूलन करना था। इस कार्यक्रम में एक टेबल टॉप एक्सरसाइज़, प्राकृतिक आपदाओं के लिए संयुक्त प्रतिक्रिया का प्रदर्शन और ऐसे अभियानों को अंजाम देने के लिए स्वदेशी उपकरणों का औद्योगिक प्रदर्शन शामिल था। नौ मित्र देशों (एफएफसी) के प्रतिनिधियों ने इस आयोजन में भाग लिया और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया। इस अभ्यास ने प्रतिभागियों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और विशेषज्ञता हासिल करने का एक मंच प्रदान किया है।

अभ्यास संयुक्त विमोचन–2024

संयुक्त सिद्धांत

उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त सिद्धांत और परिचालन योजनाएँ विकसित करने हेतु सेनाएँ मिलकर काम कर रही हैं। राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने हेतु ऐसा एकीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- **साइबरस्पेस प्रचालन** : आधुनिक युद्ध में साइबरस्पेस एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है। जून 2024 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) द्वारा साइबरस्पेस प्रचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत जारी किया गया था। यह सिद्धांत सशस्त्र सेनाओं को साइबरस्पेस क्षेत्र में निर्बाध संचालन की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

- **जल–थल प्रचालन** : जल–थल प्रचालन क्षमता भारतीय सशस्त्र बलों को युद्ध और शांति दोनों ही समय हिंद महासागर क्षेत्र में अनेक अभियानों के संचालन में सक्षम बनाती है। यह सशस्त्र बलों के बीच सामंजस्य और एकीकरण का सर्वोत्तम उदाहरण है। सीडीएस द्वारा सितंबर 2024 में 'जल–थल प्रचालनों' के संचालन हेतु एक संयुक्त सिद्धांत जारी किया गया था।

संयुक्त संचार ढांचा (जेसीए) : तीनों सेनाओं और मुख्यालय आईडीएस के नेटवर्क को एकीकृत करने का प्रयास किया गया जिसमें भारतीय सेना को अग्रणी रखा गया। सेवा नेटवर्क अब मुख्यालय आईडीएस और मुख्यालय अंडमान निकोबार कमांड के साथ एकीकृत हो गए हैं। जेसीए के माध्यम से सेनाओं को विभिन्न वेबसाइटें उपलब्ध कराई गई हैं। भारतीय सेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीनों सेनाओं के लिए संदेश एप्लिकेशन (एमएटी) का उपयोग अब सेनाओं और मुख्यालय आईडीएस के बीच वर्गीकृत संदेशों के आदान–प्रदान के लिए किया जा रहा है।

त्रि–सेना संभार प्रबंधन एप्लिकेशन (टीएलएमए) : इस एप्लिकेशन को तीनों सेनाओं के अनुकूलित/उद्यम संसाधन नियोजन (ईआरपी) सूची प्रबंधन स्वचालन प्लेटफार्मों के बीच एक इंटरफेस के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य शुरुआत में सामान्य भंडारों की दृश्यता प्रदान करना है, उसके बाद माँगें जारी करना और इन सामान्य भंडारों के

प्रावधान के लिए एक सेना को ज़िम्मेदार बनाना है। चुनिंदा उपकरण सूची वाले टीएलएमए के पहले चरण को एडीएन पर होस्ट कर दिया गया है।

तीनों सेनाओं के छोटे शस्त्रों (एसए) के रखरखाव पर केंद्रीकृत नीति : तीनों सेनाओं के लिए समान अभिचिन्हित किए गए नौ छोटे शस्त्रों के संयुक्त रखरखाव हेतु एक केंद्रीकृत नीति तैयार की गई है। तीनों सेनाओं के कुल 22 बेस रिपेयर पॉइंट (भारतीय वायुसेना के 19, भारतीय नौसेना के दो और भारतीय वायुसेना का एक) की पहचान साझा मरम्मत के लिए की गई है।

एकीकृत अनुरक्षण कार्य समूह (आईएमडब्ल्यूजी) : तीनों सेनाओं के बीच साझा उपकरणों के लिए संयुक्त अनुरक्षण उपायों के कार्यान्वयन का अध्ययन करने हेतु, प्रमुख सेना अवधारणा के साथ सात आईएमडब्ल्यूजी स्थापित किए गए हैं। आईए को प्रमुख सेना के रूप में रखते हुए, ये आईएमडब्ल्यूजी छोटे हथियारों और एएलएच बेड़े की मरम्मत प्रणाली पर केंद्रित हैं।

सैन्य कूटनीति

मित्र देशों (एफएफसी) के साथ रक्षा सहयोग हमारे राष्ट्रीय हितों और विदेश नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। हाल के वर्षों में भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा के अनुरूप, आईए द्वारा की जाने वाली राजनयिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्तमान में, आईए विभिन्न रक्षा सहयोग गतिविधियों के माध्यम से 118 देशों के साथ जुड़ी हुई है।

नए रक्षा विंग : रक्षा विंगों के पुनर्गठन के हिस्से के रूप में, रक्षा विंगों की संख्या 45 से बढ़ाकर 52 कर दी गई है। जून 2024 में पोलैंड और अल्जीरिया में और अक्टूबर 2024 में इथियोपिया और मोजाम्बिक में चार नए रक्षा विंग स्थापित किए गए हैं।

दौरे : सशस्त्र सेनाओं के बीच साझा और पारस्परिक हितों के क्षेत्रों को स्थापित करने के लिए विभिन्न एफएफसी के साथ सभी स्तरों पर नियमित रूप से बहुस्तरीय 'सुरक्षा और रणनीतिक वार्ता' आयोजित की जाती है। 2024 में, एफएफसी के लिए सेना प्रमुखों के कुल चार दौरे और एफएफसी के सेना प्रमुखों के सात आंतरिक दौरे आयोजित किए गए हैं। महत्वपूर्ण दौरों का विवरण नीचे दिया गया है:

विदेशी सैन्य गणमान्य व्यक्तियों का दौरा	
देश	**गणमान्य अतिथि**
फ्रांस फरवरी 2024	जनरल पियरे शिल, फ्रांसीसी सेना के प्रमुख
जापान फरवरी– मार्च 2024	लेफ्टिनेंट जनरल तोगाशी युइची, कमांडिंग जनरल, पूर्वी सेना, जापान
ग्रीस अप्रैल 2024	जनरल दिमित्रियोस चौपिस, हेलेनिक राष्ट्रीय रक्षा जनरल स्टाफ के प्रमुख
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जुलाई 2024	महामहिम मेजर जनरल लुकविकिला मेटिकविज़ा मार्सेल, रक्षा मंत्रालय के स्थायी सचिव
मंगोलिया जुलाई 2024	मेजर जनरल ज्ञानब्याम्बा सनरेव, मंगोलियाई सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सशस्त्र बल
जापान अक्टूबर 2024	जनरल योशिहिदे योशिदा, चीफ ऑफ स्टाफ ज्वाइंट स्टाफ, जापान
नेपाल दिसंबर 2024	सुप्रबल जनसेवाश्री जनरल अशोक राज सिगडेल, नेपाली सेना के सेनाध्यक्ष

संयुक्त अभ्यास : एफएफसी के साथ संयुक्त अभ्यास हमारे रक्षा सहयोग की प्रमुख गतिविधियाँ हैं। भारतीय सेना ने 39 संयुक्त अभ्यासों में भाग लिया है। इन 39 संयुक्त अभ्यासों में से 16 तीनों सेनाओं के, नौ दो सेनाओं के और 14 एक सेना के हैं। मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब (केएसए) और कंबोडिया के साथ भी नए द्विपक्षीय अभ्यासों की योजना बनाई जा रही है। इन संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यासों के दौरान 'आत्मनिर्भरता', 'योग' और 'नारी शक्ति' विषयों पर विशेष बल दिया जा रहा है।

सीओएएस के दौरे
उज़्बेकिस्तान गणराज्य अप्रैल 2024
जापान अक्टूबर 2024
नेपाल नवंबर 2024
वियतनाम दिसंबर 2024

एफएफसी के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास

एफएफसी के साथ जुड़ाव : एफएफसी के साथ प्रशिक्षण जुड़ाव के महत्वपूर्ण पहलुओं को नीचे स्पष्ट किया गया है:

- **दीर्घकालिक प्रशिक्षण दल** : वर्तमान में, 12 एफएफसी में विभिन्न भारतीय प्रशिक्षण दलों (भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल को छोड़कर) में सभी रैंकों के 34 सैनिक तैनात हैं। नए प्रशिक्षण दल, अर्थात् भारतीय सेना प्रशिक्षण दल (आईएटीटी), मेडागास्कर और आईएटीटी, इन्फैंट्री स्कूल, तंजानिया विनियोजन के अग्रिम चरण में हैं।

- **विदेश में गैर–कमीशन अधिकारी (एनसीओ)/अन्य रैंक (ओआर) पाठ्यक्रम** : विदेश में सैन्य विशेष पाठ्यक्रमों में आईए एनसीओ की भागीदारी वर्ष 2024 में 2 से बढ़ाकर 17 कर दी गई है।

- **महिलाओं का प्रशिक्षण** : चेन्नई स्थित अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में विदेशी महिला अधिकारी कैडेटों की भागीदारी 4 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। एफएफसी की महिला अधिकारियों के लिए पर्वतीय युद्ध और निम्न तीव्रता संघर्ष प्रचालन जैसे पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए हैं।

- **मोबाइल प्रशिक्षण दल (एमटीटी)** : विदेशों में एमटीटी की तैनाती पहले प्रति वर्ष 2 से अब बढ़ाकर 10 कर दी गई है। वर्ष 2024 में केन्या, म्यांमार, कंबोडिया, कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में पाँच एमटीटी तैनात किए गए।

- **आउटबाउंड पाठ्यक्रम** : वार्षिक प्रशिक्षण सहयोग भागीदारी को पूर्व के 40 एफएफसी से बढ़ाकर अब 65 एफएफसी कर दिया गया है।

- **इनबाउंड पाठ्यक्रम** : वर्तमान प्रशिक्षण वर्ष में एफएफसी को कुल 3,382 रिक्तियों की पेशकश की गई है। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में एम.टेक जैसे प्रमुख पाठ्यक्रम की पेशकश अब जून 2024 से एफएफसी को की जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) शांति स्थापना

भारत संयुक्त राष्ट्र के मूल संस्थापक सदस्यों में से एक है। तटस्थता और गतिशीलता के सिद्धांतों का पालन करते हुए, भारतीय सेना (आईए) संवेदनशीलता और तटस्थता की सूक्ष्म समझ के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित कार्यों को पूरा करती है। भारतीय सेना के शांति सैनिकों को उनके संचालन, आचरण और अनुशासन में उनकी व्यावसायिकता के लिए सराहा जाता है और उनके योगदान को विभिन्न प्रशंसाएँ और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अब तक, भारत ने 72 संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में से 53 में भाग लिया है और 2,92,000 से अधिक कर्मियों का योगदान दिया है। 181 भारतीय शांति सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। शांति स्थापना के प्रति भारत का दृष्टिकोण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित पांच एस, अर्थात सम्मान, संवाद, सहयोग, समृद्धि और शांति, द्वारा निर्देशित है।

UNITED NATIONS
United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo

MONUSCO

NATIONS UNIES
Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République Démocratique du Congo

NO 9011

FORCE COMMANDER'S UNIT CITATION

Awarded to

INDIA LEVEL III HOSPITAL
FORCE ASSET, MONUSCO

In recognition of sustained operational contribution while serving with the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo
MONUSCO

The 31st Day of January 2024

Khar Diouf
Major General
Acting Force Commander

प्रशंसा	
यूनिट	**उद्देश्य**
इंडबैट–I	यूएनएमआईएसएस
इंडबैट–II	
सेना सिग्नल यूनिट	
इंडबैट–I	एमयूएनयूएससीओ
इंडबैट	यूएनआईएसएफए
इंडबैट	यूएनआईएफआईएल
रसद कंपनी	यूएनडीओएफ

वर्तमान में, आईए ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दक्षिण सूडान, अबेई, पश्चिमी सहारा, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, अदीस अबाबा, लेबनान, सीरिया, इज़राइल और साइप्रस में दस संयुक्त राष्ट्र मिशनों में स्टाफ अधिकारियों/सैन्य पर्यवेक्षकों के अलावा, पाँच इन्फैंट्री बटालियनों और 11 फॉर्म्ड यूनिटों में लगभग 5,200 सैन्य कर्मियों को तैनात किया है। संघर्ष क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को कम करने के लिए, महिला सहभागिता दल (एफईटी), महिला मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता और सैन्य नर्सिंग सेवा (एमएनएस) अधिकारियों को विभिन्न मिशनों में तैनात किया गया है।

यूएन जर्नल 2024 : यूएन जर्नल 2024 का शीर्षक 'ब्लू हेलमेट ओडिसी – लचीलापन और अनुकूलनशीलता' था। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना का नया युग का विमोचन माननीय रक्षा मंत्री ने 02 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान किया। यह पत्रिका हमारे शांति सैनिकों के असंख्य अनुभवों और चुनौतियों को समेटे हुए है और वरिष्ठ सैन्य एवं राजनयिक नेतृत्व, प्रतिष्ठित शिक्षाविदों और मिशन क्षेत्र के अनुभवजन्य सुझावों द्वारा लिखे गए बौद्धिक और विचारोत्तेजक लेखों के माध्यम से प्रतीकूल परिस्थितियों में उनके स्थायी लचीलेपन और अनुकूलनशीलता की प्रशंसा करती है।

संयुक्त राष्ट्र जर्नल 2024 का विमोचन

राष्ट्र निर्माण में योगदान

सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास

सैन्य नागरिक कार्रवाई कार्यक्रमः आईए ने ऑपरेशन सद्भावना और ऑपरेशन समारिटन के तहत बड़ी संख्या में सैन्य नागरिक कार्रवाई परियोजनाओं को शुरू करके सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में बसे लोगों का 'दिल और दिमाग जीतने' के अपने प्रयासों को जारी रखा। लगभग ₹150 करोड़ के वार्षिक वित्तीय परिव्यय वाली इन परियोजनाओं में स्वास्थ्य सेवा, मानव संसाधन विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, खेल और राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में कई गतिविधियाँ शामिल हैं।

सैन्य नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम

सीमा क्षेत्र विकास बैठक : भारतीय सीमा शुल्क संघ द्वारा सितंबर 2024 में नई दिल्ली में 'सीमा क्षेत्र विकास' पर एक अंतर–मंत्रालयी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य सीमा क्षेत्र विकास (सुरक्षित – विकसित सीमाएँ) को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र तैयार करना था। भारतीय सीमा शुल्क संघ और सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए चार प्रमुख स्तंभों अर्थात् शिक्षा, अवसंरचना विकास, पर्यटन और संचार की पहचान की गई है।

सीमा क्षेत्र विकास बैठक

पारिस्थितिकीय बहाली और संरक्षण

पारिस्थितिकीय कार्य बल (ईटीएफ) द्वारा पारिस्थितिकीय पुनरुद्धार : देश भर में तैनात ईटीएफ बटालियनें क्षरित क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय पुनरुद्धार गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। अब तक, इन इकाइयों ने संयुक्त रूप से वर्ष 2024–25 के लिए लगभग 3,422 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 37.35 लाख पौधे रोपे हैं। प्रादेशिक सेना की प्लेटिनम जयंती के उपलक्ष्य में, 128 ईटीएफ बटालियन ने जैसलमेर में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से 22 सितंबर 2024 को तीन विश्व रिकॉर्ड स्थापित करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की।

पारिस्थितिकीय कार्य बल द्वारा पारिस्थितिक बहाली

'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान : 22 जुलाई 2024 को आईए में एक विशेष वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य 26 जनवरी 2025 तक 65 लाख पेड़ लगाना है। इस अभियान का उद्देश्य धरती माता और पर्यावरण के बीच संबंधों पर जोर देना था, जिसमें सभी सेना कर्मियों, उनके परिवारों और पूर्व सैनिकों को एक–एक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था।

हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रो–ग्रिड परियोजना : राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के समन्वय में, आईए ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के सहयोग से चुशुल में माइक्रो ग्रिड विद्युत संयंत्र की स्थापना का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस परियोजना में 200 किलोवाट क्षमता का एक हरित हाइड्रोजन विद्युत संयंत्र स्थापित करना शामिल है, जो गैर–सौर घंटों के दौरान हाइड्रोजन उत्पादन हेतु जल के हाइड्रोलिसिस द्वारा हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। इस प्रकार उत्पादित हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं के माध्यम से विद्युत प्रदान करेगा। यह परियोजना स्थायित्व के एक नए युग की शुरुआत करेगी।

विश्व पर्यावरण दिवस 2024: विश्व पर्यावरण दिवस 2024 भूमि पुनर्स्थापन का महत्व, मरुस्थलीकरण से निपटने और सूखे से निपटने की क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित थीम के साथ मनाया गया। भारतीय सेना के सभी सैन्य स्टेशनों ने बंजर भूमि, लैंडफिल, जल निकायों के पुनर्जीवन और पुनर्स्थापन, तालाबों का निर्माण, वर्षा जल संचयन, '3 आर (रिड्यूस, री–यूज़, री–साइकिल) अभियान, साइकिल रैलियाँ, जागरूकता अभियान और अन्य पर्यावरणीय गतिविधियाँ आयोजित कीं।

स्वच्छ भारत

स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) : 'स्वच्छ भारत अभियान' के अंतर्गत साफ–सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने की राष्ट्रीय पहल के अनुरूप, एसएचएस अभियान चलाया गया। ' स्वच्छता की भागीदारी', 'संपूर्ण स्वच्छता' और 'सफाई मित्र सुरक्षा शिविर' जैसे विषयों पर 1,500 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सेना और नागरिक कर्मचारियों दोनों को सार्थक गतिविधियों में शामिल करते हुए स्वच्छता की संस्कृति को बढ़ावा देना था।

विशेष अभियान 4.0: 'स्वच्छता' को संस्थागत रूप देने, संगठनात्मक दक्षता बढ़ाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए, भारतीय सेना ने सरकार के विशेष अभियान 4.0 में भाग लिया। इस अभियान के तहत, अब तक कुल 2,667 स्थलों की सफाई की गई है, लगभग 6.25 लाख फाइलें वर्गीकृत व अभिलिखित की गईं और उनकी समीक्षा भी की गई तथा 62 जटिल नियमों को सरल बनाया गया है।

मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) अभियान

अपनी परिचालन प्रतिबद्धताओं के बावजूद, भारतीय सेना आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सहायता प्रदान करने में आगे रही है। वर्ष के दौरान, भारतीय सेना ने चौदह राज्यों में 92 टुकड़ियाँ (इंजीनियर टास्क फोर्स सहित) तैनात कीं और 30,972 नागरिकों को बचाया। एचएडीआर अभियानों के तहत लगभग 3000 नागरिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई और 13,000 से अधिक नागरिकों को राहत सामग्री वितरित की गई। मणिपुर (मई 2024), वायनाड भूस्खलन, केरल (जुलाई 2024), उत्तराखंड भूस्खलन (जुलाई 2024) और गुजरात बाढ़ (अगस्त 2024) में प्रमुख राहत अभियान चलाए गए।

गुजरात में बाढ़ राहत प्रचालन

वायनाड, केरल में बाढ़ राहत प्रचालन

खेल और साहसिक कार्यों में उपलब्धियाँ

'खेलो इंडिया' की सच्ची भावना से, भारतीय सेना के खिलाड़ियों ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में अपनी छाप छोड़ी। भारतीय सेना के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 109 स्वर्ण, 78 रजत और 86 कांस्य पदक तथा अलग–अलग अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 31 स्वर्ण, 26 रजत और 24 कांस्य पदक जीते हैं।

पेरिस ओलंपिक 2024 : पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय सेना के 13 प्रसिद्ध खिलाड़ियों ने भाग लिया और हमारे राष्ट्र को गौरवान्वित किया।

पैरालिंपिक खेल 2024 : पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में, श्रीमती सिमरन (जन्म से दृष्टिबाधित), नायक गजेंद्र कुमार की पत्नी ने महिलाओं की 200 मीटर टी–12 श्रेणी में कांस्य पदक जीता। उन्होंने टी–12, 100 मीटर स्पर्धा में चौथा स्थान भी प्राप्त किया।

आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव : सितंबर 2024 में, आईए ने नई दिल्ली में 'आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव' की मेजबानी की, जिसमें भारत की खेल पारिप्रणाली में आईए की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। 'आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव' में भारत की वैश्विक आकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ सहयोगात्मक रणनीति बनाने के महत्व पर ज़ोर दिया गया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

इस वर्ष 10वां 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' मनाया गया, जिसकी थीम थी ' स्वयं और समाज के लिए योग'। भारतीय सेना ने देश भर में योगाभ्यास करके इस अवसर को उत्साह के साथ मनाया। उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी (तमिलनाडु) के तटीय इलाकों और पश्चिम में लोंगेवाला (राजस्थान) और कच्छ (गुजरात) से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के किबिथु और इम्फाल (मणिपुर) के पहाड़ी इलाकों तक, सैनिकों द्वारा योग का अभ्यास किया गया। माननीय रक्षा मंत्री ने सभी रैंकों के सैनिकों और उनके परिवारों के साथ प्राचीन शहर मथुरा में योग का अभ्यास किया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024

सेना साहसिक विंग (एएडब्ल्यू) की गतिविधियाँ

एएडब्ल्यू, भारतीय सेना में साहसिक गतिविधियों के आयोजन हेतु शीर्ष निकाय है और इसने एयरो, एक्वा और लैंड साहसिक प्रशिक्षण एवं अभियानों में उत्कृष्टता प्राप्त की है। यह विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं में भी भाग लेती है। एएडब्ल्यू की उल्लेखनीय गतिविधियाँ नीचे वर्णित हैं:

- **पर्वतारोहण** : तीन अधिकारियों और तीन अन्य रैंकों वाली आईए पर्वतारोहण टीम ने 13 सीआईएसएम देशों की टीमों के साथ संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय अभियान में तीसरे काउंसिल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मिलिट्री (सीआईएसएम) क्लाइम्बिंग फॉर पीस कार्यक्रम में भाग लिया, जिसका उद्देश्य 25 जुलाई 2024 को रूस के टेरेस्कोल में माउंट एल्ब्रस (5,642 मीटर) पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करना है, जो यूरोप का सबसे ऊंचा स्थान है।

एल्ब्रुस पर्वत पर चढ़ाई

- **माउंटेन टेरेन बाइकिंग (एमटीबी)** : भारतीय सेना माउंटेन बाइक टीम के राइफलमैन कुशिमन गार्टी ने मई 2024 में मलेशिया के पुत्रजया में आयोजित एशियाई माउंटेन बाइक चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें सीएफआई द्वारा इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए चुना गया था।

- **एयरो मिशन प्रतियोगिताएं और अभियान**

    - **टेलोमोयो कप (इंडोनेशिया)** : आईए हैंग ग्लाइडिंग और पैरा ग्लाइडिंग टीमों ने जुलाई–अगस्त 2024 में आयोजित टेलोमोयो कप 2024 में सफलतापूर्वक भाग लिया। आईए हैंग ग्लाइडिंग टीम को समग्र सर्वश्रेष्ठ टीम चुना गया।

टेलोमोयो कप (इंडोनेशिया)

    - भारतीय वायुसेना के एक दिव्यांग सेवारत अधिकारी द्वारा 26 मार्च 2024 को बठिंडा में बिना किसी कृत्रिम अंग के 10,000 फीट की ऊँचाई से पहली बार दो आर्मी एडवेंचर विंग प्रशिक्षकों के साथ एक्सेलरेटेड फ्रीफॉल (एएफएफ) पद्धति से स्काईडाइविंग की गई। इस अधिकारी की यह उत्कृष्ट उपलब्धि मानवीय साहस, दृढ़ता और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण है।

दिव्यांग सेवारत अधिकारी द्वारा स्काईडाइव

मानव संसाधन प्रबंधन

डोमेन विशेषज्ञता का समावेश : संगठन में अधिकारियों के विभिन्न कौशल समूहों और क्षमता का उपयोग करके दक्षता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इस दिशा में उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं:

- पिछले कुछ वर्षों में प्रत्येक अधिकारी द्वारा प्राप्त दक्षताओं के मानचित्रण और संग्रहण हेतु अतिरिक्त डेटा फ़ील्ड जोड़े गए हैं। इस जानकारी का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में अधिकारियों की योग्यता और कौशल के अनुसार उनकी नियोजन/तैनाती योजना बनाने के लिए किया जाता है।

- तकनीकी विशेषज्ञों को उनके कौशल के बेहतर उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना।

- स्थिरता और आधुनिकीकरण की संगठनात्मक आवश्यकता को पूरा करने हेतु सहायता करने के लिए विस्तारित कार्यकाल/अत्यधिक तकनीकी/अत्यधिक तकनीकी (विशिष्ट) कार्यकाल के माध्यम से निरंतरता के प्रावधानों की समीक्षा की गई है।

- सभी अधिकारियों के लिए प्रतिनियुक्ति के अवसरों में काफी वृद्धि की गई है। इसके अलावा, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में पार्श्विक समामेलन को भी सुगम बनाया गया है।

- बड़ी संख्या में अधिकारियों को विदेशी कार्यों और राजनयिक अनुभव के अवसर प्रदान किए गए हैं, जिनमें महिला अधिकारी और गैर–पैनलित अधिकारी भी शामिल है।

सुस्पष्ट पदोन्नति नीति : नई सुस्पष्ट पदोन्नति नीति लागू की गई है जो एकरूप प्रावधान, योग्यता के आधार पर पदोन्नति, अधिकारियों की आकांक्षाओं का ध्यान रखना और चिकित्सा आवश्यकताओं को सटीक प्रचालन आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने पर ज़ोर देती है। यह नीति उत्कृष्टता और अनुकूलनशीलता की संस्कृति को सुदृढ़ करती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य है।

अधिकारियों का प्रवेश/अधिकारियों का चयन

- **आर्मी कैडेट कोर (एसीसी) (स्नातक) प्रवेश** : स्नातक सैनिकों को एसीसी प्रवेश जैसी चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद 18 महीने के प्रशिक्षण के लिए आईएमए, देहरादून में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। लिखित परीक्षा और एसएसबी दोनों में चयन के स्नातक स्तर के मानक शामिल होंगे। इससे सैनिकों को उच्च शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा मिलेगी, जिससे आईए में एक सांस्कृतिक बदलाव आएगा और संगठन के समग्र शिक्षा स्तर में सुधार होने की संभावना है।

- **सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) का क्षमता निर्माण** : अधिकारी चयन क्षमता को समग्र और संवर्द्धित, दोनों रूपों में बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। मौजूदा एसएसबी की समग्र क्षमता में लगभग बीस प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी और संवर्द्धित क्षमता, अर्थात तीन अतिरिक्त एसएसबी के गठन का मामला भी योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है।

- **अधिकारी कैडेटों का प्रवेश** : वर्ष 2024 के दौरान, कुल 1,981 उम्मीदवारों को पूर्व–कमीशन प्रशिक्षण अकादमियों में अधिकारी कैडेट के रूप में प्रवेश दिया गया। यह प्रवेश पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक है।

सेना कल्याण नियोजन संगठन (एडब्ल्यूपीओ) : एडब्ल्यूपीओ एक कल्याणकारी संगठन है जो एक सोसाइटी के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों, सेना के पूर्व सैनिकों, विधवाओं और उनके आश्रितों को कॉर्पोरेट और अन्य संगठनों में उपयुक्त नियोजन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना है। वर्ष 2010 में इसकी स्थापना के बाद से, इसने कुल 2,342 अधिकारियों, 23,613 जेसीओ, 1,10,384 ओआर और 1,835 विधवाओं/आश्रितों को सफलतापूर्वक नियोजन प्रदान किया है। वर्ष 2024 में, एडब्ल्यूपीओ के माध्यम से नियुक्तियों में भारी वृद्धि देखी गई और 416 अधिकारियों, 14,542 जेसीओ/ओआर को नियुक्त किया गया। इसके अलावा, विधवाओं और आश्रितों की नियुक्ति में कुल 27% की वृद्धि हुई है और वर्ष 2024 में 290 विधवाओं को नियुक्त किया गया है।

कल्याणकारी पहल

सैनिकों के लिए कल्याणकारी पहल

- **क्षेत्रीय भाषाओं में 'आफ्टर मी' फोल्डर** : सेवारत, सेवानिवृत्त जेसीओ और अन्य रैंक को अंग्रेजी, रोमन, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में सृजित सूचना पुस्तिका 'आफ्टर मी फोल्डर' जारी की गयी है। इसका डिजिटल पाठ भी उपलब्ध कराया गया है।

- **स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी पहल** : भारतीय सेना ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए पाँच उपशामक देखभाल केंद्र, दो पैराप्लेजिक पुनर्वास केंद्र और 20 प्रारंभिक इंटरवेंशन केन्द्र (ईआईसी) स्थापित किए हैं। प्रारंभिक इंटरवेंशन केंद्रों की स्थापना रोग की उत्पत्ति का शुरुआती अवस्था में पता लगाने और रोगी की कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए समय पर हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से की गई है। 6,000 से अधिक विशेष रूप से सक्षम बच्चे इन ईआईसी में पंजीकृत किए गए हैं। स्थापना के बाद से अब तक 1,40,417 से अधिक व्यावसायिक, मनोवैज्ञानिक और वाक् चिकित्सा सत्र आयोजित किए जा चुके हैं।

- **अखिल भारतीय सेना हेल्पलाइन नंबर (155306) की स्थापना** : सेवारत सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर डायल '100' की तरह स्थापित किया गया है, ताकि यातायात दुर्घटनाओं, चिकित्सा अत्यावश्यकता, प्राकृतिक आपदाओं और प्रमुख आपराधिक गतिविधियों जैसी संकट की स्थितियों के दौरान मदद के लिए आपातकालीन मोबाइल और लैंडलाइन कॉल पर कार्रवाई की जा सके।

- **खेल छात्रवृत्ति** : भारतीय सेना के कर्मियों के बच्चों में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले बच्चों के लिए खेल छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। यह योजना व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं, टीम प्रतिस्पर्धाओं और पैरालंपिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए लागू है। प्रोत्साहन राशि इस प्रकार हैं:

पदक	राष्ट्रीय	अंतर्राष्ट्रीय
स्वर्ण	₹ 1,00,000/–	₹ 2,00,000/–
रजत	₹ 80,000/–	₹ 1,50,000/–
कांस्य	₹ 60,000/–	₹ 1,00,000/–
प्रतिभागिता	₹ 30,000/–	₹ 50,000/–

भारतीय सेना पूर्व सैनिक विभाग (डीआईएवी) की पहल : डीआईएवी पूर्व सैनिकों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के प्रबंधन और समाधान हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह विभिन्न नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सूचनाओं के बेहतर संचार और प्रसार में भी सहायता करता है। पूर्व सैनिकों के कल्याण और बेहतरी के लिए डीआईएवी द्वारा की गई पहलों का विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया गया है:

- **पेंशन व्यवस्था रक्षा प्रणाली (स्पर्श)** : डीआईएवी सभी हितधारकों जैसे रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए), प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक पीसीडीए (पी) इलाहाबाद, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और अभिलेख कार्यालयों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि पेंशनभोगियों को रक्षा पेंशन की मंजूरी और वितरण के लिए नई प्रणाली यानी स्पर्श में स्थानांतरित करने में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित किया जा सके।

- **चैटबॉट संबंध** : जनवरी 2024 में 'सेना दिवस' के अवसर पर सीओएएस द्वारा चैटबॉट संबंध शुरू किया गया। इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त सैनिकों और संगठन के बीच संबंधों को जीवंत और सार्थक बनाए रखना है। यह चैटबॉट स्पर्श, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस), कैंटीन स्टोर्स विभाग आदि के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप का उपयोग करता है।

- **प्रोजेक्ट नमन :** प्रोजेक्ट नमन का उद्घाटन अगस्त 2024 में नई दिल्ली में किया गया था। इसका उद्देश्य एक ही स्थान पर पेंशनभोगियों के लिए स्पर्श–सक्षम सेवाएँ, सरकार से नागरिक (जी2सी) सेवाएँ और व्यवसाय से ग्राहक (बी2सी) सेवाएँ प्रदान करने वाला एक स्वागत–सह–सुविधा केंद्र स्थापित करना है। यह साझा सेवा केंद्र (सीएससी) भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और निकटतम परिजनों को समर्पित है।

प्रोजेक्ट नमन

- **शिकायत निवारण :** डीआईएवी को सीपीजीआरएएमएस, ऑनलाइन पूछताछ, ऑफ़लाइन पत्रों और निदेशालय में प्रत्यक्ष आगंतुकों के माध्यम से कुल 42,649 शिकायतें प्राप्त हुईं। अब तक 41,492 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है और शेष शिकायतों पर कार्रवाई प्रगति पर है। विभिन्न पेंशन विसंगतियों के समाधान अभियान के तहत, बड़ी संख्या में मामलों का समाधान किया गया है और पेंशनभोगियों के खातों में लगभग ₹11,94,12,734 जमा किए गए हैं।

शौर्य संप्रवाह 1.0 : एक दूरदर्शी पहल के तहत, 19 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में वरिष्ठ सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ एक औपचारिक संवादात्मक सत्र, 'शौर्य संप्रवाह 1.0' आयोजित किया गया। यह आयोजन भारतीय सेना के भविष्य को आकार देने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने तथा विकसित भारत @2047 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुभवी समुदाय के समृद्ध अनुभव और अंतर्दृष्टि का उपयोग करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

शौर्य संप्रवाह 1.0

वेटरन अचीवर्स अवार्ड : 'वेटरन अचीवर्स अवार्ड' की शुरुआत पूर्व सैनिकों की उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए की गई है। इस पुरस्कार का उद्देश्य समाज और राष्ट्र निर्माण में पूर्व सैनिकों के योगदान को रेखांकित करना है। यह पुरस्कार सेना प्रमुख द्वारा मासिक सेवानिवृत्त अधिकारी के सेमिनार के दौरान और विभिन्न फॉर्मेशनों के अपने दौरे के दौरान प्रदान किया जाता है।

पूर्व सैनिक उपलब्धि पुरस्कार

उद्यमिता प्रशिक्षण : भारतीय सेना, एक मान्यता प्राप्त गैर–लाभकारी संस्था, 'आई क्रिएट इंडिया' के साथ एक समझौता ज्ञापन के तहत, वर्ष 2018 से स्वयंसेवी भावी सेवानिवृत्त लोगों को उद्यमिता प्रशिक्षण में सशक्त बनाने में सहायता प्रदान कर रही है। इस पहल का उद्देश्य प्रशिक्षुओं को 'नौकरी चाहने वाले' से 'नौकरी सृजक' बनाना है। इस कार्यक्रम में इच्छुक उद्यमियों को व्यवसाय योजना तैयार करने के लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना, उनके व्यवसाय के लिए वित्तीय सहायता और स्थिरता प्रदान करना शामिल है। प्रशिक्षण की पूरी लागत प्रशिक्षण भागीदार द्वारा वहन की जाती है।

उद्यमिता प्रशिक्षण

औपचारिक कार्यक्रम

सेना दिवस–2024

सेना दिवस परेडः सेना दिवस परेड – 2024, 15 जनवरी 2024 को लखनऊ में आयोजित की गई। दिल्ली के बाहर 'सेना दिवस' मनाने का उद्देश्य देश की परंपरा और सैन्य प्रगति को जन–जन तक पहुँचाना है। थल सेनाध्यक्ष ने स्मृतिका युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और भव्य परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने शौर्य पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया और कर्तव्य निर्वहन में असाधारण प्रदर्शन के लिए योग्य यूनिटों को थल सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र प्रदान किए।

लखनऊ में सेना दिवस परेड 2024

स्वागत समारोह : 14 जनवरी 2024 को सेना दिवस की पूर्व संध्या पर लखनऊ में 'स्वागत समारोह – एट होम' का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्र सेवा में भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान की गाथा को दर्शाया गया। माननीय रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ–साथ विभिन्न देशों के रक्षा अताशे और वाणिज्य दूतावास के प्रतिनिधि भी इस अवसर पर उपस्थित थे। ' स्वागत समारोह' के दौरान वीर नारियों, शौर्य पुरस्कार विजेताओं और उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वालों को सम्मानित किया गया ।

स्वागत समारोह

शौर्य संध्या : 15 जनवरी 2024 को लखनऊ में 'शौर्य संध्या' का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रतीकूल परिस्थितियों में भारतीय सेना के साहस और पराक्रम को रेखांकित किया गया। माननीय रक्षा मंत्री की उपस्थिति में, इस संध्या में 'सेना दिवस' का समापन हुआ, जिसमें मार्शल आर्ट, मोटर साइकिल प्रदर्शन और भारतीय सेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वदेशी तकनीक के समावेशन का अद्‌भुत प्रदर्शन किया गया।

शौर्य संध्या

गणतंत्र दिवस समारोह 2024

कर्तव्य पथ पर परेड : 26 जनवरी 2024 को कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन किया गया। इस शानदार कार्यक्रम में स्वदेशी 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन (एलएफजी) से औपचारिक गोलाबारी का प्रदर्शन शामिल था। परेड में पहली बार कर्तव्य पथ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं की दो महिला मार्चिंग टुकड़ियों ने भी भाग लिया।

कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की झलकियां

बीटिंग रिट्रीट समारोह : यह समारोह 29 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया और इसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बैंड ने प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में भारत के माननीय राष्ट्रपति, भारत के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, सीडीएस और तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों ने भाग लिया।

कारगिल विजय दिवस : कारगिल विजय दिवस का 'रजत जयंती समारोह' 26 जुलाई 2024 को आयोजित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा राज्य मंत्री, वरिष्ठ सरकारी और सैन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई। इसके अतिरिक्त, 24 पूर्व सैनिकों, 26 वीर नारियों, तीन वीर माताओं और 17 वीरों के आश्रितों/निकटतम संबंधियों ने भी इस भव्य समारोह में भाग लिया। देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण का संवर्द्धन करने उद्देश्य से पूरे देश में कई महत्वपूर्ण गतिविधियाँ भी आयोजित की गईं। कारगिल युद्ध शहीदों को श्रद्धांजलि और स्मृति चिन्ह के रूप में एक स्मारक डाक टिकट और 'प्रथम दिवस आवरण' जारी किया गया।

रजत जयंती समारोह

स्वतंत्रता दिवस समारोह

78वां स्वतंत्रता दिवस नई दिल्ली में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस समारोह के दौरान निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए गए:

- **लाल किले पर ध्वजारोहण :** भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस के जवानों ने राष्ट्रीय ध्वज को 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया।
- **21 तोपों की सलामी :** राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय सलामी देते समय, स्वदेशी 105 मिलीमीटर एलएफजी से 21 तोपों की सलामी दी गई।

78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह

प्रादेशिक सेना (टीए) की प्लेटिनम जयंती

प्रादेशिक सेना ने 09 अक्टूबर 2024 को अपनी प्लेटिनम जयंती मनाई, जिस अवसर पर टीए यूनिटों द्वारा जागरूकता अभियान, साहसिक गतिविधियाँ, वृक्षारोपण अभियान और रक्तदान शिविरों सहित अनेक राष्ट्र निर्माण गतिविधियाँ आयोजित की गईं। कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियाँ नीचे दी गई हैं:

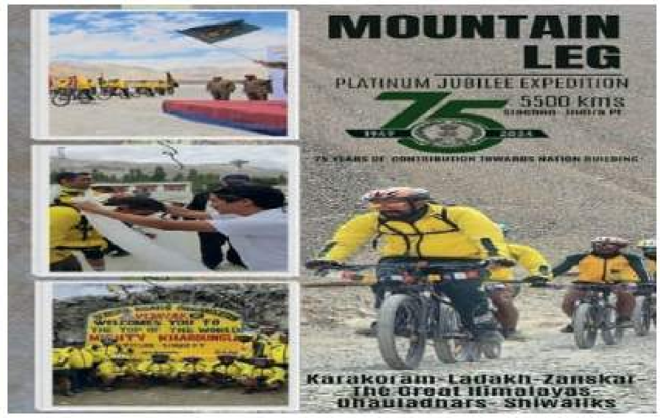

प्लेटिनम जयंती अभियान

सेमिनार/सम्मेलन

चाणक्य रक्षा संवाद (सीडीडी)– 2024 : प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, सीडीडी–2024, का दूसरा संस्करण अक्टूबर 2024 में आयोजित किया गया। इस दो दिवसीय संगोष्ठी में राष्ट्र निर्माण और सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। माननीय रक्षा मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम में भारत और विदेश के नीति निर्माताओं, रणनीतिक विचारकों, शिक्षाविदों, रक्षा कर्मियों, पूर्व सैनिकों, वैज्ञानिकों और विषय विशेषज्ञों ने भारत के रणनीतिक मार्गों और विकास एजेंडा पर चर्चा की। सेमिनार के दौरान, माननीय रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना की 'हरित पहल 1.0' और 'भारतीय सेना का डिजिटलीकरण 1.0' का भी उद्‌घाटन किया।

सेना कमांडरों का सम्मेलन (एसीसी) 2024 : वर्ष 2024 में एसीसी का प्रथम संस्करण मार्च–अप्रैल 2024 में नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था, जबकि इस शीर्ष स्तरीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण अक्टूबर 2024 में गंगटोक और नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भारतीय सेना की युद्ध क्षमताओं में वृद्धि करने, सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण, क्षमता विकास के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और उभरती मानव संसाधन चुनौतियों का समाधान करने के उपायों के लिए उभरती चुनौतियों और रणनीतियों पर चर्चा की।

सेना कमांडरों का सम्मेलन 2024

प्रौद्योगिकी समावेशन वर्ष – सैनिकों का सशक्तिकरण' विषय पर सेमिनार एवं प्रदर्शनी : भारत के रक्षा क्षेत्र की प्रगति और क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाली एक सेमिनार एवं प्रदर्शनी अप्रैल 2024 में नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस सेमिनार का विषय था 'प्रौद्योगिकी समावेशन वर्ष – सैनिकों का सशक्तिकरण'। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सेना में तकनीकी समावेशन की मौजूदा पहलों को गति देने के लिए शिक्षा जगत और रक्षा उद्योग के बीच एक सहयोगात्मक वातावरण का संवर्द्धन करना था। विशेषज्ञ और उद्योग जगत के पेशेवर एक साथ आए और रक्षा क्षेत्र में विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण पर विचार–विमर्श किया।

प्रौद्योगिकी समावेशन का वर्ष

हिमटेक संगोष्ठी –2024 : भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) के तत्वावधान में भारतीय सेना ने 20–21 सितंबर 2024 को लेह, लद्दाख में 'हिमटेक 2024' (एचआएमटीईसीएच) का आयोजन किया। इस सेमिनार का विषय था 'उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग'। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तरी सीमाओं पर सक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी और प्रणालियों को रेखांकित करना था।

हिमटेक संगोष्ठी –2024

परियोजना 'उदभव' : स्वदेशी सैन्य प्रणाली, युद्धकला और सामरिक चिंतन के विकास का अध्ययन करने हेतु परियोजना 'उद्भव' शुरू की गई है ताकि भारत के दर्शन और संस्कृति में निहित एक स्वदेशी शब्दावली विकसित की जा सके। माननीय रक्षा मंत्री द्वारा 21 अक्टूबर 2023 को इस परियोजना का उद्घाटन किया गया था। विभिन्न बुद्धिजीवियों और विषय विशेषज्ञों द्वारा कई विचार–विमर्शों के बाद, यह परियोजना 21 मई 2024 को राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में 'भारतीय सामरिक संस्कृति के ऐतिहासिक प्रतिरूप' विषय पर एक संगोष्ठी के साथ संपन्न हुई।

भारतीय नौसेना

हिंद महासागर में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नौवहन मार्गों पर स्थित एक समुद्री राष्ट्र होने के नाते, भारत अंतर्राष्ट्रीय पहुँच के लिए अपनी नौसैनिक क्षमताओं पर बहुत अधिक निर्भर करता है, और इसका 95% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। अपनी स्थलीय सीमाओं पर भू–राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए, भारतीय नौसेना (आईएन) इस क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने और हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भारतीय नौसेना पारंपरिक और गैर–पारंपरिक, दोनों ही स्रोतों से लगातार बढ़ते खतरों का सामना करती है, जिसके लिए समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए निरंतर अनुकूलन की आवश्यकता है। उच्च समुद्री क्षेत्र जागरूकता (एमडीए) बनाए रखने के लिए, नौसेना महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों और चोकपॉइंट्स पर अपनी परिसंपत्तियाँ तैनात करती है। इसके अतिरिक्त, भारत के व्यापक सुरक्षा दृष्टिकोण – क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (सागर) के अनुरूप, भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में भागीदार देशों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करती है, उनकी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाती है और प्रशिक्षण, प्लेटफ़ॉर्म स्थानांतरण और तकनीकी सहायता के माध्यम से समुद्री अवसंरचना को मज़बूत करती है।

2024 में महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी गश्त (ऑपरेशन पीओजी) : भारतीय ध्वज वाले व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी गश्त वर्ष 2008 में शुरू की गई थी और तब से अदन की खाड़ी में 127 भारतीय जहाज तैनात किए जा चुके हैं। इसके अलावा, भारतीय नौसेना ने वर्ष 2022 से अफ्रीका के पश्चिमी तट, गिनी की खाड़ी में समुद्री डकैती का मुकाबला करने के लिए भी तैनाती शुरू कर दी है। पिछले एक साल में, भारतीय नौसेना ने छह समुद्री डकैती रोधी ऑपरेशन सफलतापूर्वक संचालित किए हैं, जिससे 120 लोगों की जान बचायी जा सकी है। इनमें एमवी रुएन, एमवी लीला नॉरफ़ॉक, मछली पकड़ने वाले जहाज इमान, मछली पकड़ने वाले पोत अलनईमी और मछली पकड़ने वाले जहाज अल कम्बोर 786 की रिहाई शामिल है। एम.वी. रुएन की रिहाई के लिए समुद्री डकैती रोधी अभियान का भारतीय तट से अत्यधिक दूरी पर सफलतापूर्वक संचालन भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना के समन्वय और संयुक्त क्षमता को भी उजागर करता है ।

समुद्री–डकैती रोधी संक्रियाएं

समुद्री सुरक्षा अभियान : समुद्री क्षेत्र में इज़राइल–हमास संघर्ष के शुरू होने के परिणामस्वरूप, भारतीय नौसेना ने इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा अभियान शुरू किया। भारतीय नौसेना परिसंपत्तियों की प्रचालन तैनाती की उच्च गति को बनाए रखा गया है, जिसमें भारतीय ध्वज वाले व्यापारिक पोतों (आईएफएमवी) और भारत के लिए महत्वपूर्ण वस्तुओं को ले जाने वाले जहाजों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पिछले एक साल में, हौथी शिपिंग हमलों और पश्चिमी अरब सागर में समुद्री डकैती की बढ़ती घटनाओं के जवाब में, भारतीय नौसेना ने इस क्षेत्र में 30 से अधिक जहाजों को तैनात किया है, और 25 से अधिक घटनाओं का जवाब दिया है। चालक दल की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना, आईएन की विश्वसनीय और त्वरित कार्रवाइयों ने 400 से अधिक लोगों की जान बचाई। नवंबर 2024 तक, भारतीय नौसेना ने 230 से अधिक व्यापारिक पोतों

को सुरक्षित रूप से मार्ग रक्षा प्रदान की है, जो 90 लाख मैट्रिक टन सामग्री, जिसकी कीमत चार बिलियन यूएसडी से ज्यादा थी ले जा रहे थे। भारतीय नौसेना के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रशंसा प्राप्त हुई है। जिससे '**वरीय सुरक्षा भागीदार**' और '**फर्स्ट रिस्पॉन्डर**' के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई है।

समुद्री घटनाओं पर भारतीय नौसेना की प्रतिक्रिया : अदन की खाड़ी (जीओए) और आसपास के समुद्रों में तैनात मिशन की यूनिटों ने अनेक समुद्री घटनाओं का दृढ़ संकल्प और तत्परता से जवाब दिया है। संचालित प्रमुख ऑपरेशन/प्रदान की गई सहायता इस प्रकार हैः

- **एमवी मार्लिन लुआंडा** : जनवरी 2024 में, मास्टर ऑफ मार्शल द्वीप के ध्वज वाले तेल टैंकर एमवी मार्लिन लुआंडा के अनुरोध पर, मिशन पर तैनात भारतीय नौसेना के कर्मियों की एक टीम संकटग्रस्त पोत पर पहुंची। जिबूती से 160 नॉटिकल मील पूर्व में संभावित मिसाइल हमले के बाद, पोत में भीषण आग लगने की सूचना मिली थी। भारतीय नौसेना की टीम ने चालक दल को अग्निशमन (एफएफ) के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की। इसके अलावा, लगभग 1300 लीटर एफएफ घोल भी नाव द्वारा संकटग्रस्त पोत तक पहुँचाया गया। आग बुझाने के बाद, भारतीय नौसेना के जहाज ने मोटर टैंकर को सुरक्षित रूप से बंदरगाह तक पहुँचाया।

एमटी मार्लिन लुआंडा को सहायता

- **एमवी रुएन** : मार्च 2024 में, एमवी रुएन के सोमालिया के पूर्वी तट से समुद्र की ओर एक समुद्री डाकू मातृ जहाज के रूप में संदिग्ध समुद्री डकैती गतिविधियों के लिए संचालन पर खुफिया जानकारी के आधार पर, तैनात भारतीय जहाज ने इस जहाज को रोक लिया और जहाज पर समुद्री डाकुओं की मौजूदगी की पुष्टि की। इसके बाद, अगले 40 घंटों तक चली सुनियोजित सामरिक कार्रवाई में, जिसमें भारतीय वायुसेना के सी–17 विमान द्वारा मार्कोस को हवाई मार्ग से उतारना भी शामिल था, जहाज सभी 17 चालक दल के सदस्यों की रिहाई सुनिश्चित करने में सफल रहा, साथ ही सभी 35 समुद्री डाकुओं को पकड़कर आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए मुंबई में पुलिस अधिकारियों को सौंप दिया गया।

एमवी रुएन का बचाव अभियान

- **एमवी ट्रू कॉन्फिडेंस :** मार्च 2024 में, यमन के अदन से लगभग 54 नॉटिकल मील दक्षिण पश्चिम में ड्रोन/मिसाइल हमले के कारण, बारबाडोस ध्वजांकित बल्क कैरियर एमवी ट्रू कॉन्फिडेंस पर आग लगने के संबंध में प्राप्त इनपुट के आधार पर, तैनात भारतीय जहाजों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए मोड़ दिया गया और चालक दल के कुल 21 सदस्यों को हेलीकॉप्टरों और नावों की मदद से एमवी के आसपास स्थित एक लाइफ़ राफ्ट से बचाया गया। हालांकि गंभीर रूप से घायल चालक दल के एक सदस्य की मृत्यु हो गई, लेकिन चालक दल के शेष 20 सदस्यों को उसी दिन आगे की चिकित्सा देखभाल के लिए तुरंत जिबूती ले जाया गया।

एमटी ट्रू कॉन्फिडेंस को सहायता

मिलन 2024 : मिलन 2024 का आयोजन 19 से 27 फरवरी, 2024 के दौरान विशाखापत्तनम में/के पास किया गया। इस वर्ष का आयोजन अभूतपूर्व पैमाने पर किया गया, जिसमें छह महाद्वीपों के 36 से अधिक जहाजों, दो पनडुब्बियों, 55 विमानों और 47 विदेशी मित्र देशों (एफएफसी) के उच्चाधिकारियों ने भाग लिया। इस आयोजन में 25,000 से अधिक सैन्य/नागरिक कर्मियों ने भाग लिया, और सात लाख से अधिक दर्शकों/आगंतुकों ने इसे देखा ।

मिलन 2024

ट्विन कैरियर ऑपरेशनः भारतीय नौसेना के वाहकों ने मिलन 2024 में भाग लिया और मार्च 2024 में, द्विवार्षिक कमांडरों के पहले सम्मेलन के अवसर पर, गोवा के तट पर ट्विन कैरियर ऑपरेशन चलाए गए। ये अभियान भारतीय नौसेना की तेज़ी से बढ़ती समुद्री क्षमता का एक सशक्त प्रदर्शन थे और इन अभियानों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का काफ़ी ध्यान आकर्षित किया।

ट्विन कैरियर ऑपरेशन

अभ्यास पूर्वी लहर (एक्सपीओएल) 2024 : भारतीय नौसेना ने मार्च 2024 में भारत के पूर्वी तट पर कई चरणों में अभ्यास पूर्वी लहर (एक्सपीओएल –24) का आयोजन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने हेतु भारतीय नौसेना की तैयारियों के आकलन करने की प्रक्रियाओं का सत्यापन करना था।

एक्सपीओएल 24 के दौरान मिसाइल फायरिंग

तटीय सुरक्षा : तटीय सुरक्षा संरचना का अभ्यास विभिन्न हितधारकों के समन्वय में नियमित रूप से किया जाता है। नियमित तटीय सुरक्षा तैनाती और अभ्यासों ने मानक संचालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और अंतर–संचालन क्षमता को बढ़ाने में बहुत मदद की है। तटीय सुरक्षा अभ्यास सी विजिल, प्रस्थान और ऑपरेशन सेंटिनल वर्ष 2024 में आयोजित किए गए हैं।

तटीय सुरक्षा अभियान

आईएनएस विक्रांत की अंतिम संक्रिया मंजूरी (एफओसी) : भारतीय नौसेना के पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत, आईएनएस विक्रांत को विमानन सुविधाओं के प्रमाणन के बाद, जनवरी 2024 में लगभग एक वर्ष की अवधि के लिए अंतिम संक्रिया मंजूरी (एफओसी) मिल गई। अब तक, एफओसी के तहत, विक्रांत से विभिन्न प्रकार के वाहक–सवार विमानों ने 750 घंटे से अधिक की उड़ान भरी है, जिसमें लड़ाकू विमानों और भारतीय नौसेना के सभी प्रकार के हेलीकॉप्टरों द्वारा दिन–रात की व्यापक उड़ान शामिल है।

विक्रांत पर अंतिम संक्रिया मंजूरी कार्य

एमवी प्रेस्टीज फाल्कन को खोज एवं बचाव सहायता : 15 जुलाई, 2024 को, भारतीय नौसेना ने कोमोरोस ध्वज वाले तेल टैंकर एमवी प्रेस्टीज फाल्कन के चालक दल का पता लगाने और बचाव के लिए एसएआर सहायता प्रदान करने में सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया दी, जो ओमान के दुक़्म से लगभग 70 नॉटिकल मील दक्षिण में (मुंबई से लगभग 800 नॉटिकल मील पश्चिम में) पलट गया था। तदनुसार, मिशन ने भारतीय नौसेना जहाज़ को तैनात किया और भारतीय नौसेना के एलआरएमपी विमानों ने ओमानी अधिकारियों के साथ समन्वय में खोज और बचाव अभियान चलाया। भारतीय नौसेना के जहाज तेग ने चालक दल के नौ जीवित सदस्यों (आठ भारतीय और एक श्रीलंकाई) को सुरक्षित बचा लिया और चालक दल के एक सदस्य (भारतीय) का पार्थिव शरीर प्राप्त किया। चालक दल को ओमान के दुक़्म में उतारा गया।

एमवी प्रेस्टीज फाल्कन को एसएआर सहायता

एम.वी. ट्रू कॉन्फिडेंस को एस.ए.आर. सहायता : भारतीय नौसेना हेलीकॉप्टर ने मिसाइल हमले से क्षतिग्रस्त एम.वी. ट्रू कॉन्फिडेंस के 21 घायल चालक दल सदस्यों को ले जा रहे परित्यक्त जीवन रक्षक बेड़े की खोज की और जीवित बचे कुल आठ लोगों को सुरक्षित निकाला।

एमवी ट्रू कॉन्फिडेंस को एसएआर सहायता

विदेशी नौसेनाओं के साथ अभ्यास

अभ्यास–मालाबार : भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच एक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास, मालाबार अभ्यास का 28वां संस्करण भारतीय नौसेना द्वारा 8 से 18 अक्टूबर, 2024 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। जापान (जेएस अरियाके), ऑस्ट्रेलिया (एचएमएएस स्टुअर्ट) और अमेरिका (यूएसएस डेवी) के जहाजों ने अमेरिकी पी8 विमानों के साथ इस अभ्यास में भाग लिया। अभ्यास के समुद्री चरण में लाइव हथियार फायरिंग, जटिल सतह, वायु–रोधी और पनडुब्बी–रोधी युद्ध अभ्यास और संयुक्त युद्धाभ्यास शामिल थे।

मालाबार अभ्यास

एक्स आरआईएमपीएसी : भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक, भारतीय नौसेना के एलआरएमपी विमान और मरीन कमांडो की एक टीम को 27 जून से 2 अगस्त, 2024 तक पर्ल हार्बर, हवाई में/से दूर बहुराष्ट्रीय अभ्यास रिमपैक के 29वें संस्करण में भाग लेने के लिए मई से अगस्त 2024 तक दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में तैनात किया गया था। रिमपैक–24 के समापन समारोह के दौरान, भारतीय नौसेना के जहाज को भाग लेने वाली यूनिटों के बीच गनरी फायरिंग में उत्कृष्टता के लिए रोडियो ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।

अभ्यास रिमपैक

रोडियो ट्रॉफी – सर्वश्रेष्ठ गनरी फायरिंग शिप

जिमेक्स 24 : भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल (जेएमएसडीएफ) के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आठवां संस्करण, जिमेक्स 24, 11 से 14 जून, 2024 तक दो चरणों में जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया। जिमेक्स 24 ने दोनों देशों को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, अपनी सक्रियात्मक अतःक्रिया को मजबूत करने और भारत–प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का अवसर प्रदान किया।

जिमेक्स 2024

अभ्यास वरुण : अभ्यास वरुण का 22वां संस्करण 01 से 04 सितंबर, 2024 तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रथम आईएन एलआरएमपी यूरोपीय टुकड़ी ने अभ्यास वरुण 24 में भाग लेने के लिए फ्रांस के इस्ट्रेस में अभ्यास किया था।

आईबीएसएएमएआर VIII: एक नौसेना जहाज ने 10 से 16 अक्टूबर, 2024 तक साइमन टाउन, दक्षिण अफ्रीका में भारत–दक्षिण अफ्रीका–ब्राजील त्रिपक्षीय अभ्यास आईबीएसएएमएआर VIII में भाग लिया।

अभ्यास आईबीएसएएमएआर 2024

अभ्यास–समुद्र लक्ष्मण : भारतीय नौसेना और मलेशियाई नौसेना के बीच द्विपक्षीय *समुद्र लक्ष्मण* समुद्री अभ्यास का तीसरा संस्करण 28 फरवरी से 2 मार्च, 2024 तक विशाखापत्तनम तट पर आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना के कोर्वेट और रॉयल मलेशियाई जहाज केडी लेकिर के साथ–साथ इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के समुद्री गश्ती विमान और जहाज पर सवार हेलीकॉप्टर ने भाग लिया।

एक्स– समुद्रलक्ष्मण

भारत – म्यांमार नौसैनिक अभ्यास (आईएमएनईएक्स 2024) : एक भारतीय नौसेना के जहाज ने म्यांमार नौसेना के जहाज कोंग सिंग फ्यू शिन के साथ 28 फरवरी से 02 मार्च, 2024 तक विशाखापत्तनम के पास आईएमएनईएक्स 24 में भाग लिया। म्यांमार नौसेना के जवानों ने अभ्यास के हार्बर चरण के दौरान विशाखापत्तनम का दौरा किया, जिसमें टॉवर वर्क–अप और समुद्री अवरोधन संक्रिया (एमआईओ) प्रशिक्षण लिया गया।

आईएमएनईएक्स 2024

सिम्बेक्स : सिंगापुर–भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास (सिम्बेक्स) का 31वाँ संस्करण 23 से 29 अक्टूबर, 2024 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में आरएसएस टेनेशियस और एक भारतीय नौसेना जहाज शिवालिक के साथ–साथ भारतीय नौसेना के एमआर विमान, हॉक्स और पोत–सवार हेलीकॉप्टरों ने भाग लिया। इस वर्ष के अभ्यास का उद्देश्य अंतर–संक्रिया क्षमता को बढ़ाकर, समुद्री क्षेत्र जागरूकता में सुधार लाकर और साझा समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ावा देकर भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मज़बूत करना था।

विशाखापत्तनम में/के पास सिम्बेक्स 24 का संचालन

अभ्यास–सी ड्रैगन : आईएन एलआरएमपी विमान 08 से 22 जनवरी, 2024 तक बहुपक्षीय अभ्यास सी ड्रैगन के लिए एंडरसन एयर फोर्स बेस, गुआम से प्रचालित किया गया। भारतीय नौसेना एलआरएमपी चालक दल को टोनल की पहचान में प्रथम घोषित किया गया।

अभ्यास सी ड्रैगन

समन्वित गश्त (सीओआरपीएटी) : समुद्रीय सुरक्षा सहयोग के भाग के रूप में समुद्री पड़ोसियों के साथ आईएमबीएल पर समन्वित गश्त, आईओआर तटवर्ती नौसेनाओं के साथ, स्थापित समझौता ज्ञापनों/एसओपी के अनुसार, निम्नानुसार की जा रही हैं:

- **37वां भारत–थाई समन्वित गश्त (सीओआरपीएटी) :** भारतीय नौसेना और थाईलैंड नौसेना के बीच समन्वित गश्त (सीओआरपीएटी) का 37वां संस्करण 14 से 15 फरवरी, 2024 तक आयोजित किया गया।

- **भारतीय नौसेना–म्यांमार नौसेना (एमएन) समन्वित गश्त (आईएमसीओआर) 2024 :** दो आईएन जहाजों ने 01 से 10 मई, 2024 तक म्यांमार नौसेना के साथ आईएमसीओआर के 16वें संस्करण में भाग लिया। बंदरगाह चरण 01 से 03 मई, 2024 तक यांगून, म्यांमार में आयोजित किया गया था, इसके बाद 04 से 07 मई, 2024 तक समुद्री चरण आयोजित किया गया था।

आईएन– म्यांमार सीओआरपीएटी

- **आईएनडी–आईएनडीओ समन्वित गश्त :** समन्वित गश्त का 42वां संस्करण भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा 16 से 25 मई, 2024 तक आयोजित किया गया।

इंड–इंडो सीओआरपीएटी

एफएफसी के लिए विदेशी सहयोग सहायता

श्रीलंका को सहायता

- **श्रीलंका के लिए समुद्री गश्ती विमान की तैनाती :** समुद्री निगरानी, खोज एवं बचाव कार्यों के लिए श्रीलंका में एक समुद्री गश्ती विमान की तैनाती हेतु भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच एक विनिमय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। एक समुद्री गश्ती विमान 27 अगस्त, 2024 को कोच्चि में वार्षिक आधार पर श्रीलंकाई वायु सेना को सौंप दिया गया है। विमान के प्रचालन और रखरखाव में श्रीलंकाई वायु सेना के चालक दल को प्रशिक्षित करने और सहायता प्रदान करने के लिए पाँच वायु तकनीकी कर्मियों की एक टीम को विमान के साथ तैनात किया गया है।

- **समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (श्रीलंका) :** भारत सरकार द्वारा श्रीलंका को अनुदान पर एक एमआरसीसी परियोजना प्रदान की गई है जिसमें कोलंबो में एक एमआरसीसी, हंबनटोटा में एक समुद्री बचाव उप–केंद्र और सात उप–स्टेशन शामिल हैं (6 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की परियोजना)। एमआरसीसी का उद्घाटन माननीय विदेश मंत्री द्वारा 20 जून, 2024 को अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान किया गया था।

- **श्रीलंका एयरक्रू के लिए प्रथम अंडरवाटर इग्रेस ट्रेनिंग (यूडब्ल्यूईटी) कोर्स:** चार श्रीलंका वायु सेना अधिकारियों और तीन श्रीलंका नौसेना अधिकारियों के लिए प्रथम यूडब्ल्यूईटी कोर्स 07 से 12 जनवरी, 2024 तक वाटर सर्वाइवल ट्रेनिंग फैसिलिटी (डब्ल्यूएसटीएफ) द्वारा आयोजित किया गया था। इस कोर्स में डूबे हुए विमान से बाहर निकलने का प्रशिक्षण, समुद्री उत्तरजीविता प्रशिक्षण का अभ्यास, लाइफ राफ्ट पर चढ़ना और उतरना और बचाव उत्तोलक प्रशिक्षण शामिल था।

- **एसएलएनएस सिंधुराला के लिए सीपीपी पुर्जों का प्रावधान :** जब जहाज को प्रोपेलर की मरम्मत के लिए कोलंबो डॉकयार्ड में खड़ा किया गया था, एसएलएन पक्ष ने दो महत्वपूर्ण पुर्जों अर्थात् ब्लेड कैरियर और मूविंग योक सिलेंडर की तत्काल आधार पर व्यवस्था के लिए अनुरोध किया। मूविंग सिलेंडर योक जुलाई 2024 में एसएलएन को भेज दिया गया था और ब्लेड कैरियर जुलाई 2024 के अंत तक भेज दिया जाएगा।

- **श्रीलंका को हैलोन बोतलों का प्रेषण :** विदेशी सहयोग पहल के एक भाग के रूप में, भारतीय नौसेना ने नौ हैलोन बोतलों का मेजर ओवरहाल किया, जिसमें एसएलएनएस सागर और एसएलसीजीएस सुरक्षा द्वारा बोतलों के परिवहन के लिए नए पालनों का निर्माण भी शामिल है।

श्रीलंका को हैलोन बोतलों का उपहार देते हुए

मालदीव को सहायता

- **एमएनडीएफ सीजीएस हुरावी की मरम्मत :** एमएनडीएफ सीजीएस हुरावी की मरम्मत संबंधी प्रारंभिक गतिविधियों के एक भाग के रूप में, नौसेना डॉकयार्ड (मुंबई) से तीन सदस्यीय भारतीय नौसेना तकनीकी प्रतिनिधिमंडल को कार्य के दायरे का आकलन करने के लिए 23 से 26 जून, 2024 तक मालदीव में तैनात किया गया था। इस दल ने संभावित दोषों पर विस्तृत चर्चा की और विभिन्न मशीनरी/सहायक उपकरणों की कार्यशील स्थिति का आकलन करने के लिए एक दिवसीय उड़ान भी भरी।

- **एमसीजीएस हुरावी के लिए मशीनरी पुर्जों की व्यवस्था :** सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद, एमसीजीएस हुरावी (अभ्यास– तरमुगली; भारतीय नौसेना द्वारा एमएनडीएफ को उपहार में दिया गया) के रखरखाव के लिए अगस्त 2024 में मालदीव को नियंत्रण प्रणालियों सहित मशीनरी पुर्जों की शीघ्र व्यवस्था की गई।

मोजाम्बिक को सहायता

दो फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट (एफआईसी) का उपहार : भारतीय नौसेना के भंडार से दो फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट (एफआईसी) मोजाम्बिक सरकार को उपहार में दिए गए हैं। इन एफआईसी को अक्टूबर 2024 में भारतीय नौसेना जहाज घड़ियाल पर मोजाम्बिक पहुँचाया गया।

म्यांमार को सहायता

- **म्यांमार नौसेना को रडार पुर्जों की व्यवस्था :** फरवरी 2024 में म्यांमार नौसेना को रडार आरएडब्ल्यूएल 02 एमके II के पुर्जों की आपूर्ति की गई।

- **मेडक गन माउंट में दोष सुधार :** भारतीय नौसेना के प्रतिनिधियों की एक टीम को 21 से 23 मई, 2024 तक एमएन प्लेटफॉर्म पर मेडक गन माउंट्स में दोष सर्वेक्षण और उसके बाद दोष सुधार के लिए म्यांमार भेजा गया था। यूएमएस 559 पर दोष सर्वेक्षण, दोष परिशोधन और कार्यात्मक जाँच संबंधी कार्य किया गया। इसके अलावा, यूएमएस 560 पर ऑप्टिकल संरेखण जाँच और संरेखण पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

- **म्यांमार प्रतिनिधिमंडल द्वारा आईएनएस सतवाहन का दौरा :** म्यांमार नौसेना के एक प्रतिनिधिमंडल ने ईकेएम श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए म्यांमार में पनडुब्बी प्रशिक्षण सुविधा स्थापित करने पर चर्चा के लिए 26 जून, 2024 को आईएनएस सतवाहन का दौरा किया।

म्यांमार प्रतिनिधिमंडल का आईएनएस सतवाहन का दौरा

मॉरीशस को सहायता

- **एमसीजीएस विक्ट्री के शॉर्ट रिफिट का सफल समापन** : एमसीजीएस विक्ट्री का पहला शॉर्ट रिफिट 15 अक्टूबर, 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक किया गया। जहाज का रिफिट निर्धारित समय–सीमा के भीतर सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इसके अलावा, स्थानीय वर्कअप टीम द्वारा चालक दल का प्रशिक्षण भी 12 से 17 फरवरी, 2024 तक किया गया। इसके बाद जहाज ने मिलन 24 के बंदरगाह और समुद्री चरणों में भाग लिया और 01 मार्च, 2024 को मॉरीशस लौट आया।

- **समुद्रीय कूटनीति** : सुनयना ने पीएस जोरोस्टर को कोच्चि से पोर्ट विक्टोरिया, मॉरीशस तक पहुंचाया और 24 जून, 2024 को पोर्ट लुईस में मॉरीशस की नौसेना के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस–24 में भाग लिया। जहाज ने सेशेल्स के 48वें राष्ट्रीय दिवस में भी भाग लिया, जिसमें सेशेल्स के राष्ट्रपति के समक्ष एएलएच क्षमता का प्रदर्शन किया गया और दूरवर्ती सेशेल्स से ईईजेड निगरानी का कार्य किया गया।

एफएफसी के लिए प्रशिक्षण सहायता

- **आरएसएनएफ कैडेटों के लिए अफ्लोट चरण प्रशिक्षण** : आईओआर में पसंदीदा प्रशिक्षण भागीदार बनने की दिशा में भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए, 76 आरएसएनएफ कैडेटों के दूसरे समूह के लिए जून और जुलाई, 2024 में 29 दिनों तक अफ्लोट प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

आरएसएनएफ कैडेटों के लिए अफ्लोट–प्रशिक्षण

- **संयुक्त ईईजेड निगरानी :** पिछले वर्ष मॉरीशस, तंजानिया, सेशेल्स और मोजाम्बिक की ईईजेड निगरानी संबंधित नौसेनाओं के साथ मिलकर की गई है।

हाइड्रोग्राफिक सहयोग

भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण विभाग (आईएनएचडी) ने हिंद महासागर क्षेत्र में जल सर्वेक्षण में अग्रणी भूमिका निभाई है। विदेशी सहयोग पहल के रूप में संचालित गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **भारत–म्यांमार :** हाइड्रोग्राफी पर तीसरी भारत –म्यांमार संयुक्त समिति बैठक (जेसीएम) 23 से 25 जुलाई, 2024 तक यांगून, म्यांमार में आयोजित की गई। मुख्य हाइड्रोग्राफर के नेतृत्व में दो सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में भाग लिया। भारत और म्यांमार के बीच हाइड्रोग्राफी पर कार्यान्वयन व्यवस्था को दिसंबर 2023 से अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। मार्च 2024 में म्यांमार के जलक्षेत्र के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए एक भारतीय सर्वेक्षण जहाज म्यांमार में तैनात किया गया था।

म्यांमार नौसेना को चार्ट की प्रस्तुति

- **भारत – कजाकिस्तान :** भारतीय हाइड्रोग्राफिक प्रशिक्षण दल ने कजाकिस्तान के कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए 19 से 31 अगस्त, 2024 तक कजाकिस्तान का दौरा किया।

- **राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संस्थान (एनआईएच), गोवा में जल सर्वेक्षण पाठ्यक्रम :** 41 विदेशी कार्मिक (05 श्रीलंका, 01 इंडोनेशिया, 02 बांग्लादेश, 05 घाना, 02 वियतनाम, 04 मलेशिया, 02 नामीबिया, 06 म्यांमार, 04 तंजानिया, 02 दक्षिण अफ्रीका, 02 मालदीव, 02 कैमरून, 03 मॉरीशस, और 01 मेडागास्कर) एनआईएच, गोवा में विभिन्न जल सर्वेक्षण पाठ्यक्रम कर रहे हैं।

- **चार्टों की बिक्री :** आईएनएचडी ने हिंद महासागर क्षेत्र में आधे मिलियन से अधिक इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन चार्ट (ईएनसी) की महत्वपूर्ण मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया।

हिंद–प्रशांत क्षेत्रीय संवाद (आईपीआरडी)–2024 : भारतीय नौसेना के वार्षिक शीर्ष–स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, हिंद–प्रशांत क्षेत्रीय संवाद (आईपीआरडी) का 2024 संस्करण, 3 से 5 अक्टूबर, 2024 तक आयोजित किया गया। आईपीआरडी, भारतीय नौसेना की रणनीतिक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी का प्रमुख उदाहरण है जो हिंद–प्रशांत क्षेत्र में समग्र रूप से समुद्री सुरक्षा के मुद्दों को संबोधित करता है। आईपीआरडी–2024 का मुख्य विषय **'हिंद–प्रशांत में संसाधन –भू–राजनीति और सुरक्षा'** था। माननीय रक्षा मंत्री इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने 4 अक्टूबर, 2024 को स्मारक सत्र के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित किया।

पनडुब्बी खोज एवं बचाव सहयोग : हिंद महासागर क्षेत्र में 'पनडुब्बी खोज एवं बचाव सहयोग' के क्षेत्र में एक पसंदीदा भागीदार के रूप में, भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में संकटग्रस्त किसी भी पनडुब्बी को बचाव सहायता प्रदान करने के लिए क्षेत्र के मित्र देशों (एफएफसी) के साथ समझौते कर रही है। इस संबंध में, सिंगापुर के साथ मौजूदा कार्यान्वयन समझौते के अलावा, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पनडुब्बी बचाव सहायता एवं सहयोग पर एक कार्यान्वयन समझौते (आईए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

नौसेना से नौसेना की बातचीत

सेशेल्स राष्ट्रीय दिवस समारोह : जून से जुलाई, 2024 तक दक्षिण पश्चिम आईओआर में तैनात आईएन जहाज ने सेशेल्स राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया, साथ ही सेशेल्स के विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों जिसमें माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सम्मिलित थे, के समक्ष स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) क्षमताओं का प्रदर्शन भी किया।

सेशेल्स राष्ट्रीय दिवस समारोह और एएलएच प्रदर्शन

रूसी नौसेना दिवस समारोह : जून से सितंबर, 2024 तक भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में तैनात भारतीय जहाज ने सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में रूसी नौसेना दिवस समारोह में भाग लिया और 25 जुलाई से 1 अगस्त, 2024 तक रूसी नौसेना के साथ इंद्र 24 अभ्यास किया।

सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में आईएन जहाज

भारत–अमेरिका जेडब्ल्यूजीएसीटीसी की 7वीं बैठक: विमान वाहक प्रौद्योगिकी सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजीएसीटीसी) की 7वीं बैठक के लिए चार सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 10 से 12 अप्रैल 24 तक अमेरिका का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी नौसेना के पीईओ (परियोजना कार्यकारी अधिकारी) वाहकों के साथ नौसेना सतह

युद्ध केंद्र (एनएसडब्ल्यूसी), कार्डेरॉक और वर्जीनिया एडवांस्ड शिपबिल्डिंग कैरियर इंटीग्रेशन सेंटर (वीएएससीआईसी) सहित विभिन्न अत्याधुनिक अमेरिकी सुविधाओं का दौरा किया।

अमेरिकी विमानवाहक पोतों पर आईएन प्रतिनिधिमंडल का दौरा

सऊदी और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना प्रतिनिधिमंडल का दौरा : रॉयल सऊदी नौसेना बलों और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों का कोच्चि में दौरा आयोजित किया गया। रॉयल सऊदी नौसेना बलों के कमांडर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने 12 से 13 जनवरी, 2024 तक कोच्चि का दौरा किया और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना प्रमुख के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने 3 से 5 अप्रैल, 2024 तक कोच्चि का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान, प्रतिनिधिमंडलों ने विभिन्न प्रशिक्षण स्कूलों का दौरा किया और सीएसएल में भारत की स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता से अवगत हुए।

नौसेना प्रमुख, आरएएन का दौरा

सीओएस, आरएसएनएफ के साथ बातचीत

ओमान प्रशिक्षण प्रतिनिधिमंडल का दौरा : दो अधिकारियों और एक नाविक वाले ओमान प्रशिक्षण प्रतिनिधिमंडल ने तटीय प्रतिष्ठानों के वार्षिक निरीक्षण के संचालन पर कार्यशाला में हिस्सा लेने के लिए 21 से 27 अप्रैल, 2024 तक दक्षिणी नौसेना कमान (एसएनसी), कोच्चि का दौरा किया। तटीय प्रतिष्ठानों के वार्षिक निरीक्षण के संचालन पर कार्यशाला 23 से 25 अप्रैल, 2024 तक आयोजित की गई, जिसमें प्रतिनिधिमंडल को एचक्यूएसएनसी द्वारा वार्षिक निरीक्षण करने की बारीकियों और एआई के संचालन के तौर–तरीकों जैसे पुस्तकों और अभिलेखों के रखरखाव और निरीक्षण, एसओपी, ऑडिट और रिपोर्ट और चेक–ऑफ सूचियों के बारे में जानकारी दी गई।

वार्षिक निरीक्षण के संचालन पर कार्यशाला

जॉर्डन प्रशिक्षण प्रतिनिधिमंडल का दौरा : रॉयल जॉर्डनियन नौसेना के कमांडर हेज़म आई मैताह, लेफ्टिनेंट कमांडर अहमद अब्दुलसलाम अलकातवनेह और लेफ्टिनेंट कमांडर अब्देल रहमान फलाह अलहवामलेह के एक प्रशिक्षण प्रतिनिधिमंडल ने 30 अप्रैल, 2024 से 5 मई, 2024 तक कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान के तहत प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों का दौरा किया, ताकि द्विपक्षीय नौसेना सहयोग को मजबूत किया जा सके और प्रशिक्षण मुद्दों पर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जा सके, जैसा कि 2023 में रक्षा सहयोग पर दूसरी परामर्शदात्री बैठक के दौरान सहमति हुई थी।

जॉर्डन प्रशिक्षण प्रतिनिधिमंडल का एसएनसी दौरा

भारतीय नौसेना अकादमी (आईएनए) के लिए विदेशी प्रतिनिधिमंडल के दौरे : आईएनए में विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का दौरा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और रणनीतिक साझेदारी बनाने का अभिन्न अंग है। ये दौरे ज्ञान के आदान–प्रदान, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और राजनयिक संबंधों को मज़बूत करने के साथ–साथ दुनिया के सामने हमारे उत्कृष्ट प्रशिक्षण मानकों को गर्व से प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करते हैं।

जॉर्डन सशस्त्र बल प्रतिनिधिमंडल

फ्रांसीसी नौसेना प्रतिनिधिमंडल

दक्षिण अफ्रीकी नौसेना (एसएएन) कार्य दल का दौरा : रियर एडमिरल (जेजी) एनके हॉवेल के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीकी नौसेना वर्कअप टीम के नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय नौसेना के जहाज तेग के वर्कअप को देखने के लिए 21 से 31 अक्टूबर, 2024 तक कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान का दौरा किया। नौसेना यात्रा के दौरान, रियर एडमिरल (जेजी) एनके हॉवेल ने चीफ ऑफ स्टाफ और फ्लैग ऑफिसर सी ट्रेनिंग से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों का दौरा किया और भारतीय नौसेना में प्रशिक्षण पद्धति से अवगत हुए। उन्हें भारतीय नौसेना के जहाज पर समुद्री दौरे भी करवाए गए और उन्हें पायलट, उड़ान संचालन, टैंकर वर्क–अप और गन फायरिंग अभ्यास जैसे विकासात्मक कार्यों की जानकारी दी गई।

भारतीय नौसेना के जहाज पर एसएएन अधिकारियों का दौरा

रियर एडमिरल (जेजी) एनके हॉवेल द्वारा भेंट

जहाज निर्माण परियोजना

भारतीय नौसेना (आईएन) ने भारत में निर्मित 137 से ज़्यादा जहाजों और पनडुब्बियों को कमीशन किया है, जिससे घरेलू जहाज निर्माण को काफ़ी बढ़ावा मिला है और रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है। 62 प्रस्तावित युद्धपोतों में से 61 का निर्माण स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है, और 62 और युद्धपोतों के ऑर्डर मंजूरी के करीब हैं। नौसेना की रणनीतिक योजनाएँ भारतीय जहाज निर्माण उद्योग के दीर्घकालिक विकास के अनुरूप हैं, जिसमें हथियारों, सेंसरों और उपकरणों के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया गया है। जिन जहाजों/पनडुब्बियों का कमीशन हो चुका है/वितरण हो चुका है और जिनकी इस वर्ष प्रदायगी की जानी है, वे इस प्रकार हैं:

- **बड़े सर्वेक्षण पोतों की कमीशनिंग :** चार बड़े सर्वेक्षण पोतों (एसवीएल) में से पहला, आईएनएस सन्धायक, 3 फरवरी, 2024 को विशाखापत्तनम में माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। एसवीएल परियोजना का दूसरा पोत, यार्ड 3026 (निर्देशक), 18 दिसंबर, 2024 को शामिल किया गया। इन पोतों के शामिल होने से नौसेना और राष्ट्र की जल सर्वेक्षण क्षमताओं में वृद्धि हुई है।

सन्धायक का जलावतरण

निर्देशक का जलावतरण

- **पी1135.6 अनुवर्ती पोत (एक्स–यंतर, शिपयार्ड, रूस) का जलावतरण :** दो पोतों, अतिरिक्त पी1135.6, एफओ, एक्स रशिया, के निर्माण हेतु 23 अक्टूबर, 2018 को रक्षा मंत्रालय और जेएससी आरओई के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इन दोनों पोतों में से पहला पोत, आईएनएस तुशिल, 9 दिसंबर, 2024 को जलावतरण के लिए तैयार किया गया। इस पोत में अत्याधुनिक हथियार और सेंसर लगे हैं और यह भारतीय नौसेना की युद्धक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा।

तुशिल का कमीशनिंग समारोह

- **बार्जेस और यार्ड क्राफ्ट की सुपुर्दगी :** एमएसएमई शिपयार्ड द्वारा 2024 में भारतीय नौसेना को तीन 25 टन बोलार्ड पुल टग, ग्यारह गोला–बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल (एसीटीसीएम) बार्जेस में से चार और आठ मिसाइल–सह–गोला–बारूद (एमसीए) बार्जों में से पांचवां प्रदान किया गया।

यार्डक्राफ्ट को शामिल करना

जहाजों/यार्डक्राफ्ट को लॉन्च किया जाना

- **16 x एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यू :** 5वें और 6वें एंटी–सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (यार्ड 3033 और 3036), एक्स जीआरएसई, 13 मार्च, 2024 को लॉन्च किए गए। इसके अलावा, 7वें क्राफ्ट (यार्ड 3032), एक्स जीआरएसई को 25 अक्टूबर, 2024 को लॉन्च किया गया। मेसर्स सीएसएल से अनुबंधित जहाजों के संबंध में, चौथे और पांचवे क्राफ्ट (यार्ड 526 और 527) 09 सितंबर, 2024 को लॉन्च किए गए।

यार्ड 3033, एक्स–जीआरएसई का शुभारंभ

यार्ड 526/527 एक्स–सीएसएल का शुभारंभ

- **02x अतिरिक्त पी1135.6 फॉलो–ऑन जहाज (जीएसएल)** : पी1135.6 अतिरिक्त फॉलो–ऑन जहाजों का 9वां जहाज/यार्ड 1258, 23 जुलाई, 2024 को जीएसएल, गोवा में लॉन्च किया गया।

- **02x बहुउद्देशीय पोत (एल एंड टी)** : पहला बहुउद्देशीय पोत (एमपीवी) (यार्ड 18001) एक्स एल एंड टी, 14 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया।

यार्ड 1258 (त्रिपुट) का जलावतरण

यार्ड 18001 (समर्थक) का जलावतरण

- **11x गोला–बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल बार्ज (एक्स सूर्यदीप्ता)** : 4वें, 5वें, 6वें और 7वें गोला–बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल बार्ज को क्रमशः 24 जनवरी, 2024, 28 फरवरी, 2024, 29 अप्रैल, 2024 और 5 सितंबर, 2024 को मेसर्स सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ठाणे द्वारा लॉन्च किया गया।

एलएसएएम 20 की लांचिंग

- **08x मिसाइल सह गोला बारूद बार्ज (एक्स–एसईसीओएन)** : 5वें और 6वें मिसाइल सह गोला बारूद बार्ज को क्रमशः 10 जून, 2024 और 10 अक्टूबर, 2024 को मेसर्स एसईसीओएन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, विशाखापत्तनम द्वारा लॉन्च किया गया।

नौसेना विमानन

दृष्टि–10 एमएएलई आरपीए को शामिल करना : दृष्टि–10 एमएएलई आरपीएएस का शामिल होना भारतीय नौसेना के आरपीए भंडार में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। तकनीकी रूप से उन्नत यह विमान भारतीय नौसेना की निगरानी क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा और समुद्री क्षेत्र जागरूकता (एमडीए) प्रयासों को बढ़ावा देगा।

नौसेना शिपबोर्न मानवरहित हवाई प्रणाली (एनएसयूएएस) का समावेश : रोटरी नौसेना शिपबोर्न मानवरहित हवाई प्रणाली (एनएसयूएएस) को 2024 की शुरुआत में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।

दृष्टि–10 एमएएलई आरपीए

एनएसयूएएस का जहाज पर उतरना

एमएच 60आर स्क्वाड्रन की कमीशनिंग : पहला एमएच 60आर स्क्वाड्रन आईएनएएस 334 को 06 मार्च, 2024 को आईएनएस गरुड़, कोच्चि में कमीशन किया गया।

भर्ती और प्रशिक्षण

भारतीय नौसेना, जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों और तटीय प्रतिष्ठानों के कुशल प्रचालन हेतु कार्मिकों की भर्ती करती है। भारतीय नौसेना की भर्ती प्रणाली सुव्यवस्थित, पारदर्शी, शीघ्र और उम्मीदवार–अनुकूल है। भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर की जाती है और भर्ती के दौरान या उसके बाद किसी भी समय धर्म/जाति/पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

भारतीय नौसेना में अधिकारियों की भर्ती

भारतीय नौसेना की विभिन्न शाखाओं में अधिकारियों की भर्ती निम्नलिखित तरीकों/योजनाओं में से किसी एक के माध्यम से की जाती है:

- **यूपीएससी प्रवेश** : यूपीएससी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) और भारतीय नौसेना अकादमी (आईएनए) में स्थायी कमीशन (पीसी) के रूप में प्रवेश के लिए वर्ष में दो बार परीक्षा आयोजित करता है। उम्मीदवार 10+2 (पीसीएम) पूरा करने के बाद या 12वीं कक्षा में रहते हुए पात्र होते हैं। चयन लिखित परीक्षा और उसके बाद विभिन्न स्थानों पर सेवा चयन बोर्डों (एसएसबी) में साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है। एसएसबी और चिकित्सा परीक्षण उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को एनडीए/आईएनए में नियुक्त किया जाता है, जिसके बाद उन्हें कोच्चि में जलयात्रा प्रशिक्षण दिया जाता है। स्नातकों के लिए, संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (सीडीएसई) वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है।

- **10+2 बी.टेक प्रवेश योजना :** यह योजना भारतीय नौसेना की कार्यकारी, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल शाखाओं में स्थायी कमीशन प्रदान करती है। 10+2 (पीसीएम) योग्यता वाले उम्मीदवारों को उनकी जेईई (मुख्य) रैंक के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है। एसएसबी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, उन्हें बी.टेक पाठ्यक्रम के लिए भारतीय नौसेना अकादमी भेजा जाता है। पाठ्यक्रम पूरा होने पर, उन्हें नौसेना की निर्दिष्ट शाखाओं में स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है।

- **एनसीसी के माध्यम से भर्ती :** नौसेना विंग सीनियर डिवीजन एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र धारकों और बीई/बीटेक डिग्री धारकों के लिए रिक्तियां सीडीएसई विज्ञापन के साथ प्रकाशित की जाती हैं। इस पद के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाती है। योग्य उम्मीदवारों को डीजीएनसीसी के माध्यम से सीधे एनएचक्यू को अपना आवेदन भेजना होगा, जिसके बाद उम्मीदवारों को एसएसबी साक्षात्कार के लिए भेजा जाएगा। चुने गए उम्मीदवारों को अखिल भारतीय योग्यता के आधार पर भारतीय नौसेना में शामिल किया जाता है।

- **सीधी भर्ती – स्नातक स्तर पर स्थायी कमीशनः** यह प्रवेश संगीतकारों और खेल क्षेत्र के स्नातकों सहित स्थायी और अल्पकालिक सेवा कमीशन, दोनों के लिए है। योग्य अविवाहित उम्मीदवार प्रमुख समाचार पत्रों और रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापनों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभिक स्क्रीनिंग के बाद, चयनित उम्मीदवार एसएसबी साक्षात्कार में भाग लेते हैं, और मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को योग्यता के आधार पर नौसेना में शामिल किया जाता है।

- **भारतीय नौसेना प्रवेश परीक्षा (आईएनईटी) :** आईएनईटी एक कंप्यूटर–आधारित परीक्षा है जो स्थायी और अल्पकालिक सेवा आयोगों (एसएसबी) दोनों के लिए वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है। एनएचक्यू उम्मीदवारों को उनकी आईएनईटी रैंक और वरीयताओं के आधार पर शॉर्टलिस्ट करता है। एसएसबी साक्षात्कार के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा के सभी खंडों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अंतिम मेरिट सूची आईएनईटी स्कोर के 50% और एसएसबी प्रदर्शन के 50% वेटेज पर आधारित होती है।

- **दिवंगत सैन्य कार्मिकों की विधवाओं के लिए अवसर :** सेवाकाल के दौरान मृत सैन्य कार्मिकों की विधवाओं को अधिकारी प्रवेश योजनाओं के लिए 35 वर्ष की आयु तक की छूट दी जाती है।

- **पासिंग आउट परेड – आईएनएः** आईएनए में स्प्रिंग टर्म 24 के लिए 220 प्रशिक्षुओं के लिए पासिंग आउट परेड 25 मई, 2024 को आयोजित की गई। परेड की समीक्षा वायु सेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएम, एडीसी द्वारा की गई।

पासिंग आउट परेड – आईएनए

नाविकों की भर्ती

- **अग्निपथ योजना** : अग्निपथ योजना के कार्यान्वयन के बाद, अग्निवीरों की सुचारू भर्ती, प्रशिक्षण और करियर परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए कई पहल शुरू की गई हैं। भारतीय नौसेना में, अग्निवीर 34 सप्ताह का प्रशिक्षण लेते हैं, जिसमें बुनियादी और व्यावसायिक दोनों तरह का प्रशिक्षण शामिल है। अपनी चार साल की नियोजन अवधि के दौरान, अग्निवीर नई शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप शैक्षणिक क्रेडिट अर्जित करते हैं। इन क्रेडिट का उपयोग उनके कार्यकाल के बाद उच्च शिक्षा के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, 25% अग्निवीरों को योग्यता के आधार पर पुनः नामांकित किया जा सकता है।

- **भर्ती की पद्धति** : किसी विशेष राज्य से भर्ती किए जाने वाले कार्मिकों की संख्या, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, भारतीय नौसेना प्रवेश परीक्षा (आईएनईटी), शारीरिक फिटनेस परीक्षण और चिकित्सा परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले पात्र आवेदकों की संख्या और योग्यता में उनकी सापेक्ष स्थिति पर निर्भर करती है।

- **अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड** : अग्निवीरों (बैच 01/24) की पासिंग आउट परेड 09 अगस्त, 2024 को आयोजित की गई। परेड की समीक्षा नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, पीवीएसएम, एवीएसएम, एनएम ने की।

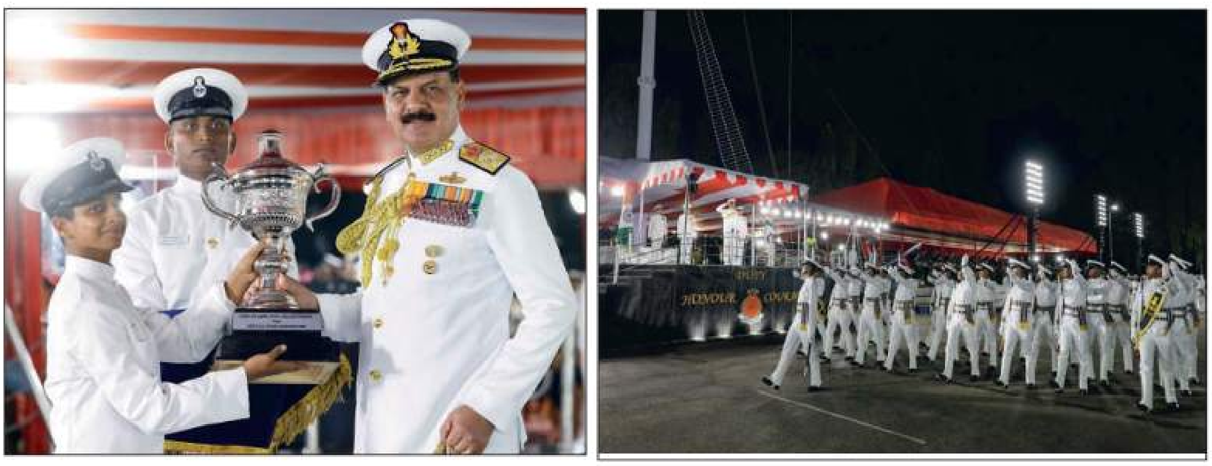

पासिंग आउट परेड – अग्निवीर 01/24

अधिकारियों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण

भारतीय नौसेना अकादमी (आईएनए), एझिमाला : भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य अकादमियों में से एक है। आईएनए परिसर 2580 एकड़ क्षेत्र में फैला है, जिसमें से 40% अनिवार्य आरक्षित वन है। आईएनए में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ–साथ बाहरी गतिविधियों के लिए भी विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचे की सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

आईएनए नौसेना, तटरक्षक बल और मित्र देशों की समुद्री सेनाओं के लिए चार प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित करता है। प्रमुख आईएनएसी पाठ्यक्रम के अलावा, आईएनए नौसेना अभिविन्यास पाठ्यक्रम (एनओसी), एनओसी (एक्सट) और लघु नौसेना अभिविन्यास पाठ्यक्रम (एसएनओसी) भी संचालित करता है, जिनमें महिला अधिकारी सहित भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के प्रशिक्षु, शामिल होते हैं। दिसंबर 2015 से, मित्र देशों के कैडेटों को भी आईएनए में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तकनीकी प्रशिक्षण के अलावा, अकादमी अपने कैडेटों को मानविकी और नौसेना इतिहास में प्रशिक्षण का एक स्वस्थ मिश्रण प्रदान करती है।

नाविकों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण

आईएनएस चिल्का : आईएनएस चिल्का भारतीय नौसेना का प्रमुख प्रारंभिक नाविक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है। पिछले कुछ वर्षों में, चिल्का ने उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। 1,235 प्रशिक्षुओं की वार्षिक क्षमता से शुरू होकर, इसकी वार्षिक प्रशिक्षण क्षमता बढ़कर 6,000 से अधिक प्रशिक्षुओं तक पहुँच गई है। अग्निपथ योजना की शुरुआत के बाद, आईएनएस चिल्का महिला अग्निवीरों को भी प्रशिक्षण दे रहा है।

चिल्का में विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित होते हैं जिनमें भारतीय नौसेना के अग्निवीरों के लिए वरिष्ठ माध्यमिक भर्ती पाठ्यक्रम और मैट्रिक भर्ती पाठ्यक्रम शामिल हैं। यह बेस तटरक्षक बल के रंगरूटों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण भी संचालित करता है, जैसे नाविक (सामान्य ड्यूटी), नाविक (घरेलू शाखा) और यांत्रिक पाठ्यक्रम। इसके अलावा, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और राज्य समुद्री पुलिस के कर्मियों के लिए बुनियादी परिचय पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं।

विदेशी प्रशिक्षण

भारतीय नौसेना (आईएन) ने प्रशिक्षण सहयोग को अपनी विदेशी संलग्नता पहलों का एक प्रमुख तत्व बनाया है, जो हिंद–प्रशांत क्षेत्र और उसके बाहर विदेशी मित्र देशों (एफएफसी) के साथ जुड़ने की सरकार की नीति के अनुरूप है। यह सहयोग आईएन को अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार करने में सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त, सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, विशिष्ट तकनीकों से अद्यतन रहने और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए, आईएन विकसित देशों में तकनीकी, क्षेत्र–विशिष्ट और सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों के लिए कर्मियों को भेज रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) के भीतर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देशों में पाठ्यक्रमों में भागीदारी, मजबूत संबंधों को भी बढ़ावा देती है और अन्य देशों की सशस्त्र सेनाओं के संचालन दर्शन के संबंध में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण

नौसेना युद्ध महाविद्यालय : नौसेना युद्ध महाविद्यालय (एनडब्ल्यूसी) का उद्देश्य भारतीय नौसेना और संयुक्त सेनाओं के अधिकारियों को आलोचनात्मक सोच, विश्लेषणात्मक क्षमता, रणनीतिक दृष्टि और संचालन कला में दक्षता विकसित करके रणनीतिक और संचालन स्तरों पर नेतृत्व के लिए तैयार करना है। यह महाविद्यालय रणनीतिक और संचालन स्तरों पर उच्च शिक्षा, युद्ध अभ्यास और समुद्री सुरक्षा एवं युद्ध कौशल पर अत्याधुनिक अनुसंधान की सुविधा प्रदान करने वाले एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में उभरा है। एनडब्ल्यूसी, गोवा में नए प्रशासनिक–सह–प्रशिक्षण भवन – 'द चोल भवन' का उद्घाटन 05 मार्च, 2024 को माननीय रक्षा मंत्री द्वारा किया गया।

माननीय रक्षा मंत्री द्वारा चोल भवन का उद्घाटन

एनडब्ल्यूसी में पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण: एनडब्ल्यूसी कैप्टन/कमांडर रैंक के अधिकारियों, नेवल स्टाफ के लिए नेवल हायर कमांड कोर्स (एनएचसीसी) आयोजित करता है, और समकालीन नेतृत्व में और प्रबंधन तकनीकों में कमांडर/लेफ्टिनेंट कमांडर रैंक के अधिकारियों के लिए नेवल स्टाफ एंड टेक्नीकल मैनेजमेंट कोर्स (एनएसटीएमसी), फ्रेंडली फॉरन कंटरीज (एफएफसी) के समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के कैप्टन/समकक्ष रैंक के अधिकारियों के लिए मेरिटाइम सेक्योरिटी कोर्स (एमएससी) तथा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम (पीएचडी) डिजाइन किया गया है।

एनडब्ल्यूसी में समुद्री सुरक्षा पाठ्यक्रम (एमएससी) : भारतीय नौसेना ने 2016 से हिंद महासागर क्षेत्र और उससे आगे के देशों के प्रतिभागियों के लिए एनडब्ल्यूसी, गोवा में एमएससी शुरू किया है। यह एनएचसीसी में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना अधिकारियों को विदेशी प्रतिभागियों के साथ बातचीत करने और साझा हितों के मुद्दों पर क्षेत्रीय नौसेनाओं के दृष्टिकोण को समझने का अवसर भी प्रदान करता है । इस मॉड्यूल में अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून, यूएनसीएलओएस, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन सुरक्षा, सूचना साझाकरण, एमडीए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, हिंद महासागर अध्ययन, साथ ही टेबल–टॉप एचएडीआर/ओओएसी अभ्यास शामिल हैं।

सशस्त्र बलों और नागरिक प्राधिकारियों के बीच सहयोग

झारखंड के चांडिल बांध में एसएआर सहायता : झारखंड के सरायकेला–खरसावां जिला प्रशासन के अनुरोध पर भारतीय नौसेना ने 22 से 27 अगस्त, 2024 तक चांडिल जलाशय (रांची से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व) में दो सीटर प्रशिक्षण विमान (सेसना वीटी–टीएजे, दो पायलटों के साथ) के लिए एसएआर सहायता प्रदान की, जो कथित तौर पर 20 अगस्त, 2024 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दोनों पायलटों के पार्थिव शरीर बरामद किए गए और विमान के मलबे/अवशेष को भारतीय नौसेना की टीम द्वारा निकाला गया और 27 अगस्त, 2024 को जिला प्रशासन को सौंप दिया गया।

झारखंड के चांडिल बांध पर एसएआर ऑपरेशन

नुजिवीडु (एलुरु), आंध्र प्रदेश में खोज एवं बचाव सहायता : 1 सितंबर, 2024 को, लगातार बारिश के बाद, आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के जिला कलेक्टर के अनुरोध पर, खोज एवं बचाव कार्यों के लिए भारतीय नौसेना की टीमों को नुजिवीडु शहर (विजयवाड़ा से लगभग 60 किमी और विशाखापत्तनम से 280 किमी दूर) में तैनात किया गया। कुल 751 नागरिकों को बचाया गया और 4537 किलोग्राम राहत सामग्री पहुँचाई गई।

वायनाड, केरल में आपदा राहत अभियान : 30 जुलाई, 2024 को, केरल के वायनाड जिले में मेप्पडी के पास हुए भीषण भूस्खलन के बाद, एसएआर सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना के जवानों को वायनाड में तैनात किया गया। तैनात भारतीय नौसेना के जवानों ने चिकित्सा सहायता प्रदान की, व्यापक विशेष राहत अभियान चलाए और राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने पुनर्वास प्रयासों, आपदा राहत स्थलों के सुदृढ़ीकरण और सहायता केंद्रों की स्थापना में भी प्रभावित लोगों की सहायता की।

वायनाड में एचएडीआर सहायता

विजयवाड़ा में खाद्य राहत : 1 से 4 सितंबर, 2024 तक विजयवाड़ा में आई बाढ़ के दौरान, प्रभावित क्षेत्रों में दो एएलएच, दो चेतक और एक डोर्नियर विमान तैनात किए गए। 22 फंसे हुए लोगों को बचाया गया और 1000 किलोग्राम से अधिक खाद्य सहायता हवाई मार्ग से गिराई गई। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में फंसे नागरिकों को बचाने के लिए दस बाढ़ राहत दल (एफआरटी) भी तैनात किए गए।

विजयवाड़ा में बाढ़ राहत अभियान

कोयमादरम में खाद्य राहत : आंध्र प्रदेश के कोयमादरम में बाढ़ के दौरान, भारतीय नौसेना ने 29 जून, 2024 को पी8आई, डोर्नियर, सी किंग और एएलएच हेलीकॉप्टरों सहित सात विमानों के साथ व्यापक एसएआर अभियान शुरू किया। चुनौतीपूर्ण मौसम के बावजूद, भारतीय नौसेना की टीम ने कोयमादरम से 28 फंसे हुए व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।

कोयमादरम में बाढ़ राहत अभियान

एफवी इन्फैन धास को सहायता : भारतीय नौसेना के एक कोर्वेट द्वारा 7 जून, 2024 को एफवी इन्फैन धास को तकनीकी सहायता प्रदान की गई, जिसके इंजन में खराबी आ गई थी और वह श्री विजयपुरम से 75 नॉटिकल मील पूर्व में बह गया था। जहाज की तकनीकी टीम ने खराबी को ठीक किया और नाव को चालू कर दिया।

एफवी इन्फैन धास को सहायता

बेहतर सहयोग के लिए डिजिटल पहल

तटीय सुरक्षा डैशबोर्ड : भारतीय नौसेना अनुसंधान एवं विकास संगठन, डब्ल्यूईएसईई ने एक तटीय सुरक्षा डैशबोर्ड एप्लिकेशन विकसित किया है, जो तटीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक समन्वय समाधान के रूप में कार्य करता है। जून 2024 में बहु–एजेंसी समुद्री सुरक्षा समूह (एमएएमएसजी) की आठवीं बैठक के दौरान तटीय पुलिस और तटरक्षक बल सहित सभी राज्य सुरक्षा समन्वयकों के समक्ष इस प्रणाली का प्रदर्शन किया गया है। वर्तमान में, एनएससीएस के साथ मिलकर क्लाउड पर एप्लिकेशन को होस्ट करने और बाद में इसे लागू करने के तौर–तरीकों की जाँच की जा रही है।

सेवियर नेट : डब्ल्यूईएसईई ने एक ब्राउज़र–आधारित एप्लिकेशन 'सेवियर–नेट' विकसित किया है, जिसका उपयोग कम बैंडविड्थ नेटवर्क पर किया जा सकता है और इसका उद्देश्य नौसैनिक जहाजों और व्यापारिक जहाजों के बीच समन्वय स्थापित करना है। इस एप्लिकेशन की प्रमुख विशेषताओं में उपयोगकर्ता–अनुकूल सिंगल विंडो, सूचनाओं का आदान–प्रदान, इवेंट लेयर (वैकल्पिक जीआईएस) और चैट विंडो शामिल हैं।

समारोहिक, शैक्षणिक और साहसिक गतिविधियाँ

राष्ट्रपति का समुद्र में एक दिवस : भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 07 दिसंबर, 2024 को गोवा के तट पर 'समुद्र में एक दिवस' कार्यक्रम में भाग लिया। यात्रा के दौरान, माननीय राष्ट्रपति ने मिसाइल फायरिंग अभ्यास और विक्रांत के डेक से लड़ाकू विमान संचालन सहित कई नौसैनिक अभियानों को देखा और उन्हें भारतीय नौसेना की भूमिका और संचालन की नौसेना अवधारणा के बारे में भी जानकारी दी गई।

आईएनएस विक्रांत पर माननीय राष्ट्रपति

माननीय रक्षा मंत्री का समुद्र में एक दिवस : नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2024 के पहले संस्करण के हिस्से के रूप में, माननीय रक्षा मंत्री ने 05 मार्च, 2024 को सम्मेलन के उद्घाटन दिवस पर नौसेना कमांडरों के साथ बातचीत की और ट्विन कैरियर प्रचालनों सहित नौसेना का प्रचालनात्मक प्रदर्शन देखा।

आईएन कैरियर जहाज पर माननीय रक्षा मंत्री

माननीय रक्षा राज्य मंत्री का दौरा : माननीय रक्षा राज्य मंत्री, श्री संजय सेठ ने 20 जून, 2024 को राजाली का दौरा किया। गणमान्य अतिथि को नौसेना के हवाई संचालन की जानकारी दी गई और इस दौरे में वायु स्टेशन पर नियुक्त पुरुषों और महिलाओं के साथ बातचीत भी शामिल थी।

माननीय रक्षा राज्य मंत्री का दौरा

ऑपरेशनल डेमो 2024 : नौसेना दिवस समारोह के एक भाग के रूप में, 04 दिसंबर, 2024 को पुरी (गोल्डन बीच), ओडिशा में, समुद्री खतरों और चुनौतियों का सामना करने हेतु भारतीय नौसेना की तैयारी का प्रदर्शन करने हेतु, अग्रिम पंक्ति के नौसैनिक जहाजों और विमानों द्वारा एक ऑपरेशनल डेमो आयोजित किया गया। यह आयोजन दिल्ली के अलावा विभिन्न शहरों में सेवा दिवस मनाने की भारत सरकार की नीति के अनुरूप है। माननीय राष्ट्रपति ने मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

ओडिशा के पुरी में नौसेना प्रचालनों का प्रदर्शन

भारतीय नौसेना के जहाजों का सेवामुक्ति समारोह : भारतीय नौसेना के जहाज चीता, गुलदार और कुंभीर को 12 जनवरी, 2024 को सेवामुक्त कर दिया गया। कार्यक्रमों में सूर्यास्त समारोह, बड़ाखाना और रात्रिभोज शामिल थे, जिसमें माननीय उपराज्यपाल (अंडमान और निकोबार) मुख्य अतिथि थे।

एलएसटी(एम) का सेवामुक्ति समारोह

हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश : 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, गौरव और राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए, 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया।

हर घर तिरंगा अभियान

खेल/पुरस्कार

ओलंपिक खेल 2024 : पेरिस, फ्रांस में 26 जुलाई से 11 अगस्त, 2024 तक आयोजित ओलंपिक खेल 2024 में नौ नौसेना खिलाड़ियों ने भाग लिया।

भारतीय नौसेना पोलो और घुड़सवारी दल (आईएनपीईसी) क्रियाकलाप : वर्ष 2024 में निम्नलिखित पोलो और घुड़सवारी कार्यक्रम आयोजित किए गए:–

क्रमांक	आयोजन	तिथियां/ स्थान	परिणाम
(1)	राष्ट्रीय घुड़सवारी चैम्पियनशिप	09–16 फरवरी, 2024 चंडीगढ़	समग्र टीम स्पर्धा में उपविजेता
(2)	मेजर रणधीर सिंह मेमोरियल ट्रॉफी	15–17 मार्च, 2024 चंडीगढ़	उपविजेता
(3)	बैंगलोर पोलो सीज़न	05–25 अगस्त, 2024 बैंगलोर	दो पोलो कप (वाडियार कप और ज्ञान ज्योति कप) जीते
(4)	सप्त शक्ति अश्व प्रदर्शनी	11–19 अगस्त, 2024 जयपुर	टेंट पेगिंग में टीम सिल्वर

पर्वतारोहण और साहसिक कार्य : नौसेना द्वारा किए गए प्रमुख पर्वतारोहण और साहसिक क्रियाकलाप इस प्रकार हैं:

- **चादर ट्रेक :** 10 से 18 फरवरी, 2024 तक जांस्कर नदी पर लेह में चादर ट्रेक का आयोजन किया गया। इस क्रियाकलाप में एक महिला अधिकारी सहित 25 नौसेना कर्मियों ने भाग लिया।
- **कुआरी दर्रा ट्रेक :** उत्तराखंड में 09 से 16 मार्च, 2024 तक कुआरी दर्रा ट्रेक आयोजित किया गया। इस ट्रेक में आश्रितों सहित 30 नौसेना कर्मियों ने भाग लिया।
- **माउंट नन अभियान (7135एम):** लद्दाख में माउंट नन अभियान 06 अगस्त से 02 सितंबर, 2024 तक आयोजित किया गया था। इस अभियान में दो महिला अधिकारियों सहित 15 नौसेना कर्मियों ने भाग लिया।

खेल उपलब्धियों के लिए पदक तालिका : वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप के लिए पदक तालिका नीचे दी गई है:

आयोजन	सम्मिलित खिलाड़ी	स्वर्ण	रजत	कांस्य
अंतर्राष्ट्रीय	62	07	04	04
राष्ट्रीय	78	17	05	16

सतर्कता इकाइयों की गतिविधियाँ

मादक पदार्थ–विरोधी अभियान (एएनओ) : वर्ष 2021 से अब तक, भारतीय नौसेना द्वारा 15 मादक पदार्थ–विरोधी अभियान (एएनओ) चलाए गए हैं , जिसके परिणामस्वरूप लगभग 35,000 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। वर्ष 2024 में किए गए अभियानों का विवरण इस प्रकार है:–

- फरवरी 2024 में, एक भारतीय नौसेना जहाज ने उत्तरी अरब सागर में 3300 कि.ग्रा. मादक पदार्थों की मात्रा की दृष्टि से अब तक की सबसे बड़ी खेप (जिसमें 3110 किलोग्राम हशीश/चरस, 158.3 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन

और 24.6 किलोग्राम संदिग्ध हेरोइन शामिल है) जब्त की । इसके बाद, चालक दल (पाँच कर्मियों) के साथ नाव और प्रतिबंधित सामग्री को आगे की कार्रवाई के लिए पोरबंदर में विधि प्रवर्तन एजेंसियों को सौंप दिया गया।

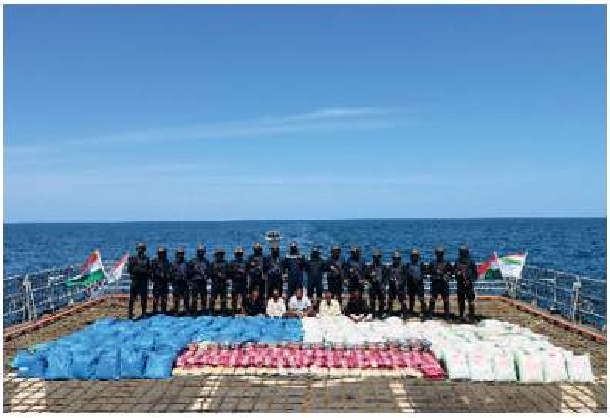

फरवरी 24 में मादक पदार्थ विरोधी अभियान

- अप्रैल 2024 में, सीटीएफ 150 के तत्वावधान में फोकस्ड ऑपरेशंस (एफओ) क्रिमसन बाराकुडा के लिए तैनात आईएन जहाज ने दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में मछली पकड़ने वाले जहाज से लगभग 940 किलोग्राम प्रतिबंधित सामग्री जब्त की।

- नवंबर 2024 में, दो भारतीय नौसेना जहाजों ने अलग–अलग घटनाओं में मादक पदार्थ ले जा रहे जहाजों को पकड़ा और क्रमशः 600 किलोग्राम और 500 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए।

नवंबर 24 में मादक पदार्थ विरोधी अभियान

स्वदेशीकरण/आत्मनिर्भर भारत और व्यवसाय करने की सहजता की दिशा में पहल

भारतीय नौसेना का इतिहास और भावी दूरदर्शिता, आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप है। भारतीय नौसेना एक युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय, एकजुट और भविष्य के लिए तैयार' बल बनने के अपने दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है, जिसका आधुनिकीकरण कार्यक्रम आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है ।

स्वदेशीकरण योजनाएँ : भारतीय नौसेना भारत सरकार की प्रमुख स्वदेशीकरण योजनाओं, जैसे 'मेक इन इंडिया', 'प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ)' और 'रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (आईडीईएक्स)', में एक प्रमुख हितधारक और

अग्रणी है। 120 से अधिक नए स्टार्ट–अप और एमएसएमई अब नौसेना के साथ मिलकर नवीन तकनीकों और उत्पादों के स्वदेशी विकास में लगे हुए हैं, जिनमें से कई संभावित रूप से 'वैश्विक स्तर पर प्रथम' हैं।

अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) मार्ग के अंतर्गत परियोजनाएँ : अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) शीर्ष के अंतर्गत डीएफपीडीएस–2021 के प्रावधानों का उद्योग और शिक्षा जगत के साथ प्रभावी ढंग से काम में लाने के लिए उपयोग किया जा रहा है ताकि उत्पादों के विकास और समस्या समाधान हेतु उनकी क्षमता का लाभ उठाया जा सके। भारतीय नौसेना उद्योग, आईआईटी और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के साथ कई परियोजनाओं पर काम कर रही है। जिन 156 मामलों पर काम चल रहा है, उनमें से लगभग 154 करोड़ रुपये के 101 अनुबंध पहले ही पूरे किए जा चुके हैं।

मेक स्कीम : भारतीय नौसेना डीएपी 2020 के अनुसार 42 मेक परियोजनाओं पर काम कर रही है। वर्तमान में, मेक–II श्रेणी के अंतर्गत 29 परियोजनाएँ, मेक I श्रेणी के अंतर्गत 11 परियोजनाएँ और मेक III श्रेणी के अंतर्गत दो परियोजनाएँ चल रही हैं, जो विकास/अनुमोदन/प्रक्रमण के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त, नौ मेक II, तीन मेक III और एक मेक I संयुक्त परियोजनाओं का संचालन भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के साथ प्रमुख सेवाओं के रूप में किया जा रहा है।

प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) योजना : भारतीय नौसेना के प्लेटफार्मों पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी लागू करने के उद्देश्य से, 'प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ)' योजना के अंतर्गत 26 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। 42.48 करोड़ रुपये की लागत से 11 परियोजनाओं के लिए संविदाएं संपन्न हो चुकी हैं। एक परियोजना संविदा समापन चरण में है, दो परियोजनाएँ सीएनसी चरण में हैं, चार परियोजनाओं के लिए ईओआई मूल्यांकन प्रगति पर है, और आठ परियोजनाएँ पूर्व–एओएन चरण में हैं।

विशिष्ट प्रौद्योगिकियों का समावेश : लंबी दूरी की निगरानी और सटीक हमले की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा, लक्ष्यीकरण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भूमि और समुद्र आधारित संस्करणों में सहज चलने वाले लड़ाई के सामानों को शामिल किया जा रहा है, और प्रचालनों में प्रचालन क्षमता/लचीलापन बढ़ाने के लिए कंटेनरयुक्त मिसाइल प्रणालियां समावेशित की जा रही हैं।

डिजिटल इंडिया

डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप, व्यवसाय करने में सहजता (ईओडीबी) की दिशा में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:

- **आईएनजीआरएएमएसः** भारतीय नौसेना शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (आईएनजीआरएएमएस) एप्लिकेशन इंटरनेट पर उपलब्ध है और इसका उपयोग पूर्व सैनिकों द्वारा शिकायतों को दर्ज करने/ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है। यह प्रणाली शिकायत निवारण प्राधिकारी को शिकायतों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से ट्रैक करने, निगरानी करने और उनका निवारण करने के लिए एकल खिड़की सुविधा प्रदान करती है।

- **ई–विगम** : सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के लिए कार्यप्रवाह को आसान बनाने हेतु, ई–विगम नामक एक एप्लिकेशन विकसित किया गया है। इस एप्लिकेशन का संस्करण 2.0 लॉन्च किया गया है, जो सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों से संबंधित जानकारी पहले से प्राप्त करने के लिए कार्मिक निदेशालय (डीओपी) के डेटाबेस के साथ एकीकृत होता है, सभी सेवानिवृत्ति प्रपत्रों के निर्माण को स्वचालित करता है, स्पर्श पोर्टल पर मंगाने के लिए एक एक्सएमएल फ़ाइल तैयार करता है, और प्रपत्रों पर डिजिटल हस्ताक्षर सक्षम बनाने के लिए इसे पीकेआई (पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर) के साथ भी एकीकृत किया गया है।

- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान – एकायन** : एकायन संस्करण 2.0 एंड–टू–एंड हॉप एन्क्रिप्शन को सपोर्ट करता है और अन्य समान प्लेटफार्मों की तुलना में अधिक बैंडविड्थ सक्षम है।

- **हॉक सिक्योर** : 'हॉक सिक्योर' नामक एक स्वदेशी एआई आधारित ट्रैफ़िक विश्लेषण समाधान को नौसेना उद्यम–व्यापी नेटवर्क (एनईडब्ल्यूएन) पर पूरे नौसेना में तैनात किया गया है। इसका उपयोग नेटवर्क ट्रैफ़िक की

निगरानी के लिए किया जाता है और यह विसंगतियों का पता लगाने के लिए व्यवहारिक विश्लेषण करता है। इसमें एआई/एमएल का उपयोग करके ट्रैफ़िक विश्लेषण सीखने और उसे बेहतर बनाने की क्षमता है।

- **आयुप्रविधा (ईएएमई/पीएमई):** आयुप्रविधा एक आईएन इंट्रानेट बेस्ड एप्लीकेशन है जिसे डीआईटी और डीजीएमएस (नेवी) ने एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन (एएमई)/पीरियोडिक मेडिकल एक्जामिनेशन (पीएमई) और उसके डॉक्यूमेंटस की डिजिटल प्रोसेसिंग के लिए डेवलप किया है। आयुप्रविधा पीएलयूएस एप्लीकेशन जिसमें एएफएमएसएफ–15 (कैट/री–कैट/सिक लीव) और एएफएमएसएफ–16 (रिलीज मेडिकल बोर्ड) शामिल हैं, भी डेवलप किया गया है। एएफएमएसएफ–15 मॉड्यूल सितंबर में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2024 के दौरान लॉन्च किया गया था।

- **इंडियन डिफेंस रिसोर्स फॉर वेदर एनालिसिस (आईएनडीआरए):** आईएनडीआरए पूरी तरह से मौसम का अनुमान, मौसम/समुद्र के पैरामीटर, साइक्लोनिक ट्रैकिंग, रियल–टाइम लाइटनिंग सेंसर डेटा के साथ रियल–टाइम सेटेलाइट इमेज और दुनिया भर की किसी भी जगह के लिए इंटरैक्टिव चार्ट तक रियल–टाइम एक्सेस देता है। खास बात यह है कि यह समुद्र की स्थिति, थर्मल इनवर्जन इत्यादि जैसे विशिष्ट फीचर्स देता है, जो कमर्शियल ऑफ–द–शेल्फ (सीओटीएस) एप्लीकेशन में नहीं मिलते।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता

भारतीय नौसेना ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। कार्यान्वित की गई प्रमुख परियोजनाएँ नीचे सूचीबद्ध हैं:

- **अंतरभाषी-एआई** : बीईएल के साथ साझेदारी में, आठ हिंद महासागरीय और आठ तटीय भाषाओं का पता लगाने और उनका अनुवाद करने में सक्षम एक ऑफ़लाइन भाषा अनुवादक समाधान विकसित किया गया है। इस समाधान का व्यापक रूप से समुद्री डकैती–रोधी और अदन की खाड़ी में गश्त के लिए तैनात जहाजों द्वारा उपयोग किया जाता है।

- **प्रशिक्षण-एआई:** प्रशिक्षक और विदेशी छात्रों के बीच संचार की बाधा को कम करने के लिए, एक एआई एप्लिकेशन विकसित किया गया है जो प्रशिक्षक के भाषण को लगभग वास्तविक समय में विदेशी छात्र की मूल भाषा के पाठ में और विलोमतः अनुवाद करता है। यह एप्लिकेशन सिंहली, वियतनामी, बांग्ला और फ्रेंच में प्रशिक्षित है। वर्तमान में, कोच्चि स्थित सिग्नल स्कूल में एक पूर्ण प्रणाली स्थापित है।

- **सत्यापन-एआई :** समुद्र में सामना किए जाने वाले समुद्री डाकुओं की पहचान करने और एमओसी में समुद्री डाकुओं के चेहरे की विशेषताओं का डेटाबेस बनाने के लिए एक पोर्टेबल चेहरा पहचान प्रणाली विकसित की गई है। यह समाधान पश्चिमी नौसेना कमान में तैनात है और समुद्री डकैती–रोधी अभियानों में तैनात जहाजों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है।

- **दृष्टि-एआई** : ऊपरी डेक पर कर्मियों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए एक एआई आधारित एमओबी और ऊपरी डेक निगरानी सॉफ़्टवेयर विकसित किया गया है। एक आईआर कैमरा और मौजूदा एम सीसीटीवी कैमरों का उपयोग करके आईएनएस विशाखापत्तनम पर प्रोटोटाइप परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं।

- **नेवल एआई रिस्पॉन्स फॉर एडवांस्ड डायलॉग्स (एनएआरएडी):** डब्ल्यूईएसईई ने एक एडवांस्ड प्राइवेट और ऑफलाइन कस्टम लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया है, जिसे नेवल नेटवर्क पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स से जानकारी की क्वेरी और समराइज़ेशन के लिए बनाया गया है। नेवल एआई रिस्पॉन्स एंड एडवांस्ड डायलॉग्स (एनएआरएडी) नाम का यह सॉल्यूशन एक सुरक्षित और कंट्रोल्ड माहौल में जानकारी निकालने, समझने और फैसले लेने को बेहतर बनाएगा। इस सॉल्यूशन को ई–पहचान आईडी के साथ इंटीग्रेट किया गया है और एनयूडी पर होस्ट किया गया है, जिससे सभी यूनिट्स में आसानी से एक्सेस और इस्तेमाल हो सके।

भारतीय वायु सेना

भारतीय वायु सेना (आईएएफ) भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो महत्वपूर्ण एयरोस्पेस शक्ति प्रदान करती है और संघर्षों को रोकने और शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- **सामरिक भूमिका:** एयरोस्पेस शक्ति राष्ट्रीय रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दुश्मन के इलाके में प्रवेश किए बिना दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करने की क्षमता प्रदान करती है। भारतीय वायुसेना ने 1965 और 1971 के भारत–पाक युद्धों और 1999 के कारगिल युद्धों सहित पिछले संघर्षों में अपने महत्व को प्रदर्शित किया है।

- **ताकत एवं क्षमताएँ:** भारतीय वायुसेना की ताकत इसकी आधुनिक वायु क्षमताओं में निहित है, जो विमानन अनुसंधान एवं विकास द्वारा समर्थित है। एयरोस्पेस शक्ति की प्रमुख विशेषताओं में पहुँच, लचीलापन, गतिशीलता और आक्रामक क्षमताएँ शामिल हैं। भारतीय वायुसेना वैश्विक स्तर पर मानवीय मिशनों में भी प्रमुख भूमिका निभाती है।

- **अंतरिक्ष एवं रक्षा:** भारतीय वायुसेना की भूमिका अंतरिक्ष तक विस्तारित है, जहाँ उपग्रह–आधारित उपकरण खुफिया जानकारी, निगरानी और सुरक्षित संचार प्रदान करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक वाहनों जैसी तकनीकों के बढ़ते उपयोग से मज़बूत वायु और अंतरिक्ष रक्षा की आवश्यकता बढ़ गई है।

- **भविष्य की तैयारी:** भारतीय वायुसेना ड्रोन तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष–आधारित प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर भविष्य के तकनीक–संचालित संघर्षों के लिए तैयारी कर रही है। पूर्वी लद्दाख की स्थिति में इसकी त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता स्पष्ट रूप से दिखाई दी।

- **प्रमुखता:** आधुनिक विमानों और एकीकृत रक्षा प्रणालियों के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा में भारतीय वायुसेना की भूमिका बढ़ी है। यह सेना युद्ध की बदलती प्रकृति के अनुरूप ढल रही है और भारत की रक्षा रणनीति में एक प्रमुख भूमिका निभा रही है।

- **एकीकरण और खरीद के माध्यम से सैन्य प्रौद्योगिकी उन्नयन:** भारतीय वायुसेना ने पिछले कुछ वर्षों में विमान और हथियार प्रणालियों (एस–400, राफेल, अपाचे, चिनूक, सी–17, सी–130जे, सी–295) को शामिल करके वायु शक्ति में हुए विकास के साथ तालमेल बनाए रखा है। इसके अलावा, तेजस विमान जैसे नए प्लेटफार्मों पर मौजूदा हथियारों का एकीकरण और सुखोई–30एमकेआई जैसे मौजूदा प्लेटफार्मों पर ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों जैसे नए हथियारों का एकीकरण सफलतापूर्वक हासिल किया गया है।

सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण

परिवहन विमान

सी–295 की खरीद: यह रक्षा क्षेत्र के निजी क्षेत्र में भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की दिशा में 'बाय एंड मेक' प्रक्रिया के तहत पहला प्रयास है। यह पहली बार होगा जब भारत में निजी उद्योग द्वारा विश्व स्तरीय सामरिक एयरलिफ्ट परिवहन विमान का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना विमानन क्षेत्र को गति प्रदान करेगी और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्र में उत्प्रेरक का काम करेगी। भारत में निर्मित होने वाले पहले विमान की डिलीवरी 2026 में की जाएगी।

सी–295

फ्लाइट रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट (एफआरए) की खरीद : भारतीय वायुसेना रिसीवरों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए अपनी फ्लाइट रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है। इस दिशा में, डीपीबी द्वारा नवंबर 2023 में डीएसी के विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए एफआरए के मामले की सिफारिश की गई है। आरएफपी जुलाई 2024 में जारी किया गया था।

फ्लाइट रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट (एफआरए)

हथियार/हथियार प्रणालियाँ

शौर्य (एमआरएसएएम): एमआरएसएएम का विकास आईएआई, इज़राइल और डीआरडीओ द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। डीआरडीओ द्वारा आईएआई, इज़राइल के सहयोग से फायरिंग यूनिट्स (एफयू) के विकास और डिलीवरी के लिए एमआरएसएएम अनुबंध पर फरवरी 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे।

शौर्य (एमआरएसएएम)

आकाश मिसाइल प्रणाली: स्वदेशी आरएफ सीकर, जो मिसाइलों की उच्च सटीकता सुनिश्चित करते हैं, के साथ उन्नत आकाश मिसाइल के परीक्षण, दिसंबर 2024 में वार्षिक अभ्यास–अस्त्रशक्ति के दौरान सफलतापूर्वक आयोजित किए गए थे।

आकाश मिसाइल प्रणाली

नई पीढ़ी की विकिरण–रोधी मिसाइल (एनजीएआरएम): डीएसी द्वारा 24 जनवरी, 2023 को एओएन प्रदान किया गया था। वर्तमान में यह परियोजना डीएंडडी के अधीन है और डीआरडीएल प्रमुख प्रयोगशाला है। पीएसक्यूआर को एएसक्यूआर में परिवर्तित करने के बाद डीसीपीपी को आरएफपी जारी किया जाएगा।

नई पीढ़ी की विकिरण–रोधी मिसाइल (एनजीएआरएम)

स्मार्ट एंटी–एयरफील्ड वेपन (एसएएडब्ल्यू): भारतीय नौसेना के लिए सैट एसएएडब्ल्यू के साथ–साथ सैट एसएएडब्ल्यू + ईओ एसएएडब्ल्यू बमों की खरीद के मामले को अक्टूबर 2020 में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) द्वारा एओएन प्रदान किया गया था। इन हथियारों के शामिल होने के बाद, दुश्मन के हवाई अड्डों पर सटीक निशाना लगाने की हमारी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। वर्तमान में, एओएन में संशोधन हेतु एसओसी पर सभी हितधारकों की सहमति हो गई है और इसे आगामी डीपीबी में प्रस्तुत किया जाएगा।

स्मार्ट एंटी–एयरफील्ड वेपन (एसएएडब्ल्यू)

लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल (एलआरएलएसीएम): स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल (एलआर–एलएसीएम) का पहला लाइव फायरिंग परीक्षण 2024 में सफलतापूर्वक किया गया है।

क्लोज इन वेपन्स सिस्टम (सीआईडब्ल्यूएस): सीआईडब्ल्यूएस की खरीद के लिए अनुबंध, जो एक खरीद और निर्माण (भारतीय) परियोजना है, पर मेसर्स एलएंडटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मार्च 2024 में हस्ताक्षर किए गए हैं। इसे शीघ्र ही शामिल किए जाने की योजना है, जिससे पारंपरिक और उप–पारंपरिक वायु रक्षा खतरों के सापेक्ष वीए/वीपी की रक्षा और सुरक्षा को और बढ़ाया जा सकेगा।

क्लोज इन वेपन्स सिस्टम (सीआईडब्ल्यूएस)

आत्मनिर्भरता/ स्वदेशीकरण

भारतीय वायु सेना आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है। नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय वायु सेना ने एयरोस्पेस डिज़ाइन निदेशालय (डीएडी) नामक एक नया निदेशालय गठित किया है। यह निदेशालय एयरोस्पेस क्षेत्र में विशिष्ट तकनीकों का पता लगाने और स्वदेशी संसाधनों का उपयोग करके उन्हें सामरिक और रणनीतिक युद्ध समाधानों में परिवर्तित करने हेतु कार्यविधि विकसित करने के लिए उद्योगों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और शिक्षाविदों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क करता है।

- **प्रौद्योगिकी विकास कोष (टीडीएफ):** 'मेक इन इंडिया' पहल के एक भाग के रूप में रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए टीडीएफ की स्थापना की गई है। यह कार्यक्रम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा तीनों सेनाओं, रक्षा उत्पादन और डीआरडीओ की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्रियान्वित किया जाता है। यह योजना सार्वजनिक/निजी उद्योगों, विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्ट–अप्स की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है, ताकि रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा सके।

- **रक्षा उत्कृष्टता में नवाचार (आईडीईएक्स):** यह भारतीय रक्षा क्षेत्र में नवाचारों को प्रोत्साहित करने और पोषित करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। भारतीय वायु सेना ने उत्पाद विकास में सह–निर्माण और सह–नवाचार के सिद्धांत पर चुनिंदा स्टार्ट–अप्स को 'सहायता' देने के लिए नवप्रवर्तकों से संपर्क किया है। वर्तमान में, भारतीय वायु सेना द्वारा विभिन्न चरणों में आईडीईएक्स के 42 से अधिक मामले प्रोसेस किए जा रहे हैं, जिनमें से दो खरीद चरण में हैं।

- **'मेक' प्रक्रिया:** 'मेक' प्रक्रिया के अंतर्गत, भारतीय वायुसेना ने 52 मामलों के लिए एआईपी प्रदान किया है। इनमें से 7 मामलों के लिए डिज़ाइन और विकास हेतु परियोजना स्वीकृति आदेश प्रदान किए गए हैं। इन मामलों ने भारतीय उद्योग के लिए 3729.22 करोड़ रुपये के व्यावसायिक अवसर उत्पन्न किए हैं।

विमान टायरों और बैटरियों का स्वदेशीकरणः आत्मनिर्भरता के प्रयासों के तहत विमान टायरों और बैटरियों का स्वदेशीकरण शुरू किया गया है। वर्तमान में, सात बेड़ों के विमान टायरों का स्वदेशीकरण हो चुका है और 10 बेड़ों का स्वदेशीकरण प्रगति पर है। इसी प्रकार, 22 बेड़ों की विमान बैटरियों का स्वदेशीकरण हो चुका है और चार बेड़ों का स्वदेशीकरण प्रगति पर है।

एफओएल का स्वदेशीकरणः एफओएल स्टोर्स की 146 लाइनों का स्वदेशीकरण शुरू किया गया है। स्वदेशीकरण के लिए एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी और सीएसआईआर–आईआईपी से संपर्क किया गया है।

नवाचार/विकास

- **लाइट वेट मैन पोर्टेबल एचएफ सेटः** भारतीय वायु सेना ने 216 लाइट वेट मैन पोर्टेबल एचएफ सेटों की खरीद के लिए फरवरी 2024 में मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्नत सुरक्षा विशेषताओं वाले और स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो (एसडीआर) तकनीक पर आधारित ये एचएफ सेट, आत्मनिर्भर भारत की सरकारी नीति के अनुरूप भारतीय वायु सेना के वायु रक्षा संचार नेटवर्क को मजबूती प्रदान करेंगे।

- **भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू की गई नवोन्मेषी परियोजनाएंः** विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को अपनाने, स्वच्छ पर्यावरण और एफओएल के सुधार की दिशा में भारतीय वायुसेना द्वारा निम्नलिखित नवोन्मेषी और अग्रणी परियोजनाएं शुरू की गई हैं:

  - **एडिटिव मैन्युफैक्चरिंगः** एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (एएम) एक गेम चेंजर तकनीक है, जो पाउडर बेड फ्यूजन और निर्देशित ऊर्जा निक्षेपण का उपयोग करती है। भारतीय वायुसेना ने 3डी प्रिंटिंग के माध्यम से ब्रैकेट, वाल्व केसिंग, मैनिफोल्ड, पैनल आदि जैसी 233 वस्तुओं का सफलतापूर्वक निर्माण किया है। शुरुआती प्रयास गैर–महत्वपूर्ण पुर्जों के निर्माण की ओर केंद्रित थे। भारतीय वायुसेना ने एक कदम आगे बढ़कर एक उच्च–गुणवत्ता वाली धातु पाउडर एएम मशीन खरीदी है। कुल 47 विशिष्ट रेखाएँ मुद्रित की गई हैं।

  - **सतत विमानन ईंधनः** बायो–जेट ईंधन परियोजना, सीएसआईआर आईआईपी लैब, देहरादून के माध्यम से 8,700 लीटर बायो–जेट ईंधन विकसित करने हेतु एक प्रौद्योगिकी प्रमाणन परियोजना है। इस परियोजना में प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं: जनवरी 2019 में गणतंत्र दिवस परेड में एएन–32 का फ्लाई पास्ट, जनवरी 2020 में लेह हवाई क्षेत्र में लैंडिंग और जनवरी 2024 में गणतंत्र दिवस परेड फ्लाई पास्ट में डकोटा विमान के साथ दो डीओ–228 विमान द्वारा फॉर्मेशन उड़ान। आज तक, एएन–32 और डीओ–228 विमान पर बायो–जेट ईंधन के उपयोग को मंजूरी दे दी गई है। भारतीय वायुसेना विशिष्ट प्लेटफार्मों (एमआई–17, मिग–29 उन्नत और एलसीए) पर चरणबद्ध तरीके से बायो–जेट ईंधन के उपयोग और प्रमाणन की योजना बना रही है।

- **ई–रखरखाव प्रबंधन प्रणाली लाइट (ई–लाइट) का विकासः** भारतीय वायुसेना ने अपनी रखरखाव गतिविधियों को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करने के लिए, दुनिया के सबसे बड़े रखरखाव मरम्मत ओवरहॉल (एमआरओ) समाधानों में से एक अर्थात ई–रखरखाव प्रबंधन प्रणाली (ई–एमएमएस) परियोजना को सभी इकाइयों में लागू किया है। ई–एमएमएस के उपयोग को बढ़ाने के लिए, इस एप्लिकेशन (ई–लाइट) का एक गतिशीलता संस्करण विकसित किया गया और मार्च, 2024 में शुरू किया गया ताकि विदेशी अभ्यासों सहित गैर–भारतीय वायुसेना ठिकानों से संचालन के दौरान रखरखाव गतिविधियों को रिकॉर्ड करना आसान हो सके। 2024 में भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित विभिन्न अभ्यासों के दौरान इस एप्लिकेशन की प्रभावशीलता की पुष्टि भी की गई।

- **स्टैटिक एचएफ ट्रांस–रिसीवर सेटः** भारतीय वायु सेना ने अगस्त 2024 में 124 स्टैटिक एचएफ ट्रांस–रिसीवर सेटों की खरीद के लिए मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो (एसडीआर) तकनीक पर आधारित, ये सेट उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किए गए हैं। यह खरीद भारतीय वायु सेना के वायु रक्षा संचार नेटवर्क को बढ़ावा देती है, जिससे भारतीय वायु सेना की आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रतिबद्धता और मजबूत होती है।

गगनयान कार्यक्रम

- भारतीय वायु सेना (आईएएफ) नामित अंतरिक्ष यात्रियों (एडी) के चयन हेतु प्रमुख एजेंसी है। इसके अतिरिक्त, भारतीय वायु सेना नामित अंतरिक्ष यात्रियों के शारीरिक प्रशिक्षण, एकीकृत क्रू रिकवरी ऑपरेशन (आईसीआरओ), क्रू मॉड्यूल डिज़ाइन एवं परीक्षण, अंतरिक्ष में जीवन रक्षक प्रणाली और मानव जीवन के अनुरक्षण में सक्रिय रूप से शामिल है। आईएएम, नामित अंतरिक्ष यात्रियों के एयरोस्पेस चिकित्सा प्रशिक्षण और आवधिक मूल्यांकन के लिए ज़िम्मेदार है। कठोर चयन प्रक्रिया के बाद केवल चार ईटीपी का चयन किया गया। इसमें ग्रुप कैप्टन पीबी नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला शामिल हैं ।

- चारों ने 2019 में रूस में सामान्य अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण लिया और उसके बाद, भारतीय प्रशिक्षण चरण में भाग लिया। 27 फ़रवरी 2024 को, माननीय प्रधानमंत्री ने उन्हें 'स्पेस विंग्स' से सम्मानित किया। दो मानवरहित मिशनों के प्रक्षेपण के बाद, गगनयान मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान 2026 में होने की उम्मीद है।

- **एक्सिओम–4 मिशनः** इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अंतरिक्ष मिशन हेतु नासा के नेतृत्व में एक्सिओम (निजी कंपनी) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। शीर्षस्थ बोर्ड ने विभिन्न इनपुट और सिफारिशों के आधार पर एक मुख्य और एक स्टैंडबाय अंतरिक्ष यात्री का चयन किया है। चयनित अंतरिक्ष यात्री अगस्त 24 में नासा के लिए रवाना हो गए हैं, जिनका मिशन संभवतः 2025 के मध्य में होगा।

एयरो इंडिया 2025

एयरो इंडिया का 15वां संस्करण 10 से 14 फ़रवरी, 2025 तक एएफएस येलहंका में आयोजित किया गया। यह भारत की एयरोस्पेस क्षमताओं का एक भव्य प्रदर्शन था, जिसमें भारतीय वायु सेना की नवाचार, आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाया गया। इस आयोजन की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- भारतीय वायु सेना ने भारतीय पवेलियन में पाँच प्रमुख परियोजनाओं का प्रदर्शन किया, जिससे तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और भी पुष्ट हुई। इसके अतिरिक्त, स्वदेशीकरण से संबंधित 126 स्टॉल और 17 सफलता की कहानियाँ भी प्रदर्शित की गईं जिनके मार्फत स्वदेशी रक्षा निर्माण में प्रगति को दर्शाया गया।

- उद्घाटन समारोह में 42 विमानों ने फ्लाईपास्ट किया तथा रूस, ब्राजील, अमेरिका और जर्मनी के प्लेटफार्मों सहित 27 विमानों का स्थिर प्रदर्शन किया गया, जो वैश्विक भागीदारी और सहयोग को दर्शाता है।

- 'नवाचार उत्कृष्टम भविष्यम्' (नवाचार बेहतर भविष्य का मार्ग है) विषय पर भारतीय वायुसेना संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य रक्षा बलों, उद्योग और अनुसंधान एवं विकास एजेंसियों के बीच तालमेल को बढ़ावा देकर एक सुदृढ़ नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना था। इस आयोजन के माध्यम से निम्नलिखित उपलब्धियाँ हासिल की गईः
  - भारतीय उद्योग के लिए चुनौतियों और अवसरों पर भारतीय वायुसेना के "सामर्थ्य मार्गदर्शिका" नामक संकलन का विमोचन।
  - मेहर बाबा–II प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा एवं सम्मान तथा मेहर बाबा–III का शुभारंभ।
  - भारतीय वायुसेना और एचएएल के बीच डिजिटल वाणिज्य मंच "वायु वित्त" का शुभारंभ।
  - "मानव–मानव रहित टीमिंग (एमयूएम–टी) अवधारणा से लक्ष्य निर्धारण" पर एक पैनल चर्चा।

'नवाचार उत्कृष्टतम भविष्यम्' पर आईएएफ सेमिनार

- **वायु सेना प्रमुखों की गोलमेज बैठक:** इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में एस्वातिनी और बुर्किना फ़ासो के सीडीएस, 17 वायु सेना प्रमुखों और 32 अन्य प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। परिचर्चाएँ भविष्य के संघर्षों पर यूएवी और यूसीएवी के प्रभाव पर केंद्रित रहीं, जो वैश्विक चिंताओं और हवाई युद्ध में रणनीतिक प्रगति को दर्शाती हैं।

वायु सेना प्रमुखों की गोलमेज बैठक

- **भारत–अफ्रीका वायु सेना वार्ता**: भारतीय वायु सेना की इस ऐतिहासिक पहल में एक सीडीएस, नौ वायु सेना प्रमुखों और सात अन्य अफ्रीकी प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। परिचर्चाएँ एयरोस्पेस सहयोग पर केंद्रित रहीं, जिसमें हवाई अभ्यास, एचएडीआर अभियान, वायु क्षेत्र जागरूकता, प्रशिक्षण, उद्योग सहयोग और वायु अवसंरचना विकास जैसे क्षेत्र शामिल थे। इस वार्ता ने भारतीय वायु सेना और अफ्रीकी वायु सेनाओं के बीच सक्रिय सहभागिता और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा दिया।

भारत–अफ्रीका वायु सेना वार्ता–2025

- **द्विपक्षीय संबंध**: भारतीय वायुसेना ने 38 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिससे भारत की रक्षा साझेदारी मजबूत हुई और एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिला।

- **तकनीकी और रणनीतिक प्रदर्शन**: एयरो इंडिया 2025 ने वैश्विक एयरोस्पेस प्रगति के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान किया, जिससे ज्ञान के आदान–प्रदान और उद्योग सहयोग को सुविधा मिली।

  - ➢ एयरो इंडिया 2025 ने एयरोस्पेस नवाचार, रक्षा सहयोग और सैन्य कूटनीति में भारत के नेतृत्व की पुष्टि की तथा भारतीय वायुसेना को राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में स्थापित किया।

  - ➢ भारतीय वायुसेना को राज्य सरकार के साथ समन्वय में फ्लाइंग डिस्प्ले, स्टेटिक डिस्प्ले, सुरक्षा, स्टेशन के भीतर आपदा प्रबंधन, चिकित्सा सेवाएं और अग्नि निवारण उपायों के संचालन का कार्य सौंपा गया था।

  - ➢ हवाई प्रदर्शन एक बार व्यावसायिक दिनों (10 से 14 फरवरी 25) के दौरान और दो बार सार्वजनिक दिनों (13 और 14 फरवरी 25) के दौरान आयोजित किया गया था।

एयरो इंडिया 2025 के दौरान तेजस की उड़ान के बाद सीएएस और सीओएएस

एयरो इंडिया 2025 के दौरान एसकेएटी फॉर्मेशन

एयरो इंडिया 2025 के दौरान एचजेटी टैक्सीईंग

एयरो इंडिया 2025 के दौरान तेजस फॉर्मेशन एयर शो

मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर)

2024 में, भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने देश भर में कई प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों के संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए महत्वपूर्ण मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) प्रदान की। प्रमुख अभियानों और प्रयासों का सारांश नीचे दिया गया है:

- **वन अग्नि अभियान:** भारतीय वायुसेना ने तमिलनाडु और उत्तराखंड में हवाई अग्निशमन अभियान चलाया। बांबी बकेट अभियानों के माध्यम से 134,500 लीटर से अधिक पानी डाला गया।

- **बाढ़ राहत अभियान:** भारतीय वायुसेना ने असम, केरल, उत्तराखंड, त्रिपुरा, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर बाढ़ राहत प्रदान की। विभिन्न अभियानों के तहत 700 से अधिक लोगों को बचाया गया और 150 टन से अधिक राहत सामग्री को हवाई मार्ग से पहुँचाया गया और बड़े पैमाने पर एयरलिफ्ट और एयर ड्रॉप सहित 200 से अधिक उड़ानें भरी गईं।

- **केसवैक / चिकित्सा निकासी:** लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू—कश्मीर और तमिलनाडु में चिकित्सा निकासी का संचालन किया गया और तात्कालिक आधार पर रोगी और अंग स्थानांतरण के लिए हेलीकॉप्टर और परिवहन विमान तैनात किए गए।

- **हवाई खोज और अग्निशमन:** लापता रेलवे अधिकारी के लिए पूर्वोत्तर में खोज अभियान चलाया गया और सेना और सामग्री को हवाई मार्ग से पहुंचाकर जम्मू—कश्मीर में अग्निशमन में सहायता की गई।

राष्ट्र निर्माण और आंतरिक सुरक्षा

- **भारतीय वायुसेना आउटरीच कार्यक्रम:** 16 वर्षों के अंतराल के बाद, सारंग टीम ने मुंबई के युवाओं को भारतीय वायु सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने हेतु 8 जनवरी से 15 जनवरी, 2024 तक मरीन ड्राइव, मुंबई में एक प्रदर्शन किया। लगभग पाँच लाख नागरिक साहस और पराक्रम के इस शानदार प्रदर्शन को देखने के लिए एकत्रित हुए।
- **मणिपुर (इम्फाल) आकस्मिकता:** भारतीय वायुसेना ने 15 जनवरी से 18 जनवरी, 2024 तक भारतीय वायुसेना के सी–130जे विमान द्वारा इम्फाल से जोरहाट तक 1756 मणिपुर पुलिस कर्मियों को हवाई मार्ग से पहुँचाकर अपना सहयोग प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, 18 जनवरी, 2024 को एएलएच ने 2100 किलोग्राम गोला–बारूद, पाँच कर्मियों और एक पार्थिव शरीर को हवाई मार्ग से पहुँचाया। इसके अलावा, 22 नवंबर, 2024 तक बागडोगरा/गुवाहाटी/कलाईकुंडा से इम्फाल और सिलचर तक तात्कालिक आधार पर सीएपीएफ के 2288 कर्मियों सहित 492 टन भार को हवाई मार्ग से पहुँचाया गया।
- **एचएएल–228 एयरक्राफ्ट को हवाई मार्ग से गुयाना ले जाना:** 30 मार्च, 2024 से 6 अप्रैल, 2024 तक गुयाना गणराज्य तक दो "मेड इन इंडिया" एचएएल–228 एयरक्राफ्ट को एयरलिफ्ट करने के लिए आईएएफ सी–17 एयरक्राफ्ट उपलब्ध कराया गया।
- **ब्रह्मोस मिसाइलों का फिलीपींस तक एयरलिफ्ट:** भारतीय वायुसेना ने 19 अप्रैल से 20 अप्रैल, 2024 तक फिलिपिंस गणराज्य में ब्रह्मोस मिसाइलों की डिलीवरी के लिए सी–17 एयरक्राफ्ट उपलब्ध कराया।
- **ऑपरेशन स्वर्ण कुबेर (यूके):** भारतीय वायुसेना के विमानों को यूके से भारत सरकार का सामान हवाई मार्ग से लाने का काम सौंपा गया था। ऑपरेशन 'स्वर्ण–कुबेर' अगस्त से अक्टूबर 2024 के बीच जामनगर से यूके और नागपुर वापसी के लिए चलाया गया।

एफएफसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अभ्यास

भारतीय वायुसेना के विमान विदेशों में अक्सर अभियानों में शामिल रहे हैं। इन अभियानों में अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों में भागीदारी, भारतीय टुकड़ियों का शामिल होना/हटाना, विदेशों में लड़ाकू विमानों की तैनाती के लिए एएआर ऑपरेशन और राष्ट्रीय हितों से जुड़े कार्य शामिल हैं। इस वर्ष की शुरुआत से परिवहन बेड़े द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- **अभ्यास सदर्न डिस्कवरी:** भारतीय वायुसेना के तीन सी–17 कर्मी दल ने 16 फरवरी से 24 फरवरी, 2024 तक ऑपरेशन सदर्न डिस्कवरी के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना (आरएएएफ) सी–17 विमान पर सवार होकर अंटार्कटिका के लिए परिचय उड़ान के लिए पर्यवेक्षकों के रूप में भाग लिया। 15 फरवरी, 2024 को सिविल एयरलाइंस द्वारा इंडक्शन किया गया।
- **अभ्यास मिलन:** 20 फ़रवरी, 2024 को सी–17 विमान ने अभ्यास मिलन (भारतीय नौसेना) के प्रयोजनार्थ 46 मीडियाकर्मियों को हिंडन से विशाखापत्तनम और 160 विदेशी सैन्य अधिकारियों को विशाखापत्तनम से आगरा और वापस पहुँचाया। 23 फ़रवरी, 2024 को एक ए–321 विमान ने विदेशी सैन्य अधिकारियों की सांस्कृतिक यात्रा के लिए उन्हें विशाखापत्तनम से गया और वापस विशाखापत्तनम पहुँचाया।
- **भगवान बुद्ध के अवशेषों का हवाई परिवहन:** एक सी–130जे विमान का उपयोग भगवान बुद्ध के अवशेषों को बैंकॉक, थाईलैंड ले जाने/वापस लाने के लिए दो अलग–अलग शटलों में हवाई परिवहन (प्रवेश/वापसी) के लिए किया गया। बैंकॉक, थाईलैंड में प्रवेश 23 फ़रवरी, 2024 को किया गया। बैंकॉक, थाईलैंड से वापसी 19 मार्च, 2024 को हवाई परिवहन के माध्यम से की गई। अवशेषों के साथ बिहार के माननीय राज्यपाल और एक मंत्रिस्तरीय दल भी मौजूद था।
- **सारंग प्रदर्शन – एयर शो:** भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर एरोबैटिक प्रदर्शन दल सारंग ने 20 फरवरी से 25 फरवरी, 2024 तक सिंगापुर के चांगी प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सिंगापुर एयर शो – 2024 में भाग लिया। प्रदर्शन में पांच एएलएच हेलीकॉप्टरों ने भाग लिया। इन विमानों को भारतीय वायुसेना के हेवी

लिफ्ट (3xसी–17) विमान द्वारा ले जाया गया और वापस लाया गया। इसके अलावा, सारंग टीम ने 3 सितम्बर से 5 सितम्बर, 2024 तक मिस्र अंतर्राष्ट्रीय एयर शो – 2024 में और 13 नवम्बर से 15 नवम्बर, 2024 तक बहरीन अंतर्राष्ट्रीय एयर शो – 2024 में भाग लिया।

- **एचएएल का एएलएच प्रदर्शन – मिस्र एयर शो:** हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के दो एएलएच ने 03 सितंबर से 05 सितंबर, 2024 तक स्थिर प्रदर्शन के हिस्से के रूप में मिस्र अंतर्राष्ट्रीय एयर शो – 2024 में भाग लिया। दो एएलएच हेलीकॉप्टरों को 03 सितंबर, 2024 को एक सी–17 विमान द्वारा ले जाया गया और 09 सितंबर, 2024 को वापस लाया गया।
- **बहरीन अंतर्राष्ट्रीय एयर शो (बीआईएएस)–2024:** सारंग हेलीकॉप्टर प्रदर्शन दल ने 13 नवंबर से 15 नवंबर, 2024 तक बहरीन के साखिर एयर बेस पर आयोजित बहरीन अंतर्राष्ट्रीय एयर शो 2024 में भाग लिया। सारंग के पाँच एएलएच एमके–I को शामिल करने और हटाने के लिए तीन सी–17 विमानों का उपयोग किया गया।
- **भारतीय नौसेना के लघु शस्त्र एवं गोलाबारूद (एसएए) भार का मोरक्को तक हवाई परिवहन:** आईएनएस तुशिल के लिए एसएए का कलिनिनग्राद, रूस तक परिवहन 26 दिसंबर, 2024 को मुंबई से कैसाब्लांका, मोरक्को तक एक आईएल–76 विमान द्वारा किया गया।
- **अभ्यास हरिमौ शक्ति:** अभ्यास हरिमौ शक्ति में भाग लेने वाली आईए टीम के इंडक्शन के भाग के रूप में, 01 दिसंबर, 2024 को 7 टन भार के साथ 78 कर्मियों वाली आईए टुकड़ी को सुभांग, मलेशिया ले जाने के लिए एक आईएल–76 विमान का उपयोग किया गया। 16 दिसंबर, 2024 को विप्रेषण किया गया।

मित्र विदेशी सेनाओं के साथ अभ्यास

भारतीय वायु सेना ने इस वर्ष भी संयुक्तता बढ़ाने के लिए न केवल सहयोगी सेनाओं के साथ, बल्कि भविष्य के लिए तैयार रहने हेतु मित्र देशों की वायु सेनाओं के साथ भी गहन अभ्यास जारी रखा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों की सूची नीचे दी गई है:

- **रेड फ्लैग अलास्का–24–2 :** भारतीय वायुसेना ने मई से 14 जून, 2024 तक अमेरिका में आयोजित रेड फ्लैग अलास्का–24–2 अभ्यास में भाग लिया। यह भारतीय वायुसेना की पहुंच को प्रदर्शित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा की गई सबसे लंबी यात्रा थी।
- **हॉप अभ्यास (ग्रीस और मिस्र):** संयुक्त राज्य अमेरिका में अभ्यास रेड फ्लैग–24 से वापसी के दौरान, भारतीय वायुसेना ने 20 जून से 25 जून, 2024 तक ग्रीस और मिस्र के साथ हॉप अभ्यास में भाग लिया।
- **अभ्यास पिच ब्लैक–24 :** भारतीय वायुसेना ने 12 जुलाई से 2 अगस्त, 2024 तक ऑस्ट्रेलिया में अभ्यास पिच ब्लैक–24 में भाग लिया। इस आयोजन में सहयोगात्मक भावना देखी गई, जिससे एक–दूसरे की क्षमताओं की बेहतर समझ विकसित हुई और एक ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण बना, जिससे प्रतिभागी देशों के बीच स्थायी संबंध बनेंगे।

अभ्यास पिच ब्लैक– 2024

- **उदार शक्ति–24 अभ्यासः** भारतीय वायुसेना ने 5 अगस्त से 9 अगस्त, 2024 तक मलेशिया में उदार शक्ति–24 अभ्यास में भाग लिया। यह अभ्यास मलेशिया के साथ द्विपक्षीय अभ्यास का दूसरा संस्करण था और पिच ब्लैक–24 अभ्यास के बाद ऑस्ट्रेलिया से वापसी के दौरान किया गया था।

- **आईटीएस कैवोर (आईएन) के साथ एयर टू एयर मिशन (5 अक्टूबर, 2024)** : भारतीय वायुसेना ने 5 अक्टूबर, 2024 को आईओआर (गोवा तट के पास) में इटली के विमानवाहक पोत आईटीएस कैवोर के साथ भाग लिया। भारतीय वायुसेना ने अपने विमानों के साथ आईटीएस कैवोर पर मौजूद (एफ–35बी और 8बी हैरियर–II प्लस सहित उन्नत विमानों) के साथ अभ्यास किया। यह इटली के विमानवाहक पोत के साथ भारतीय वायुसेना का पहला अभ्यास था।

- **आरएसएएफ (आईएन) के साथ जेएमटी–24 अभ्यासः** भारतीय वायुसेना ने वायु सेना स्टेशन कलाईकुंडा में 21 अक्टूबर से 6 दिसंबर, 2024 तक सिंगापुर गणराज्य वायु सेना (आरएसएएफ) के लिए जेएमटी–24 अभ्यास की मेजबानी की। इस अभ्यास का द्विपक्षीय चरण 13 नवंबर से 22 नवंबर, 2024 तक आयोजित किया गया था।

जेएमटी 2024 अभ्यास

- **डेजर्ट नाइट 24.2 अभ्यास (इन–सीटू) (11 दिसंबर, 2024):** भारतीय वायुसेना ने 11 दिसंबर, 2024 को हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल (एफएएसएफ) और यूएई वायु सेना और वायु रक्षा बल (यूएईएएफ) के साथ इन–सीटू बहुराष्ट्रीय डेजर्ट नाइट–24.2 अभ्यास का संचालन किया।

डेजर्ट नाइट अभ्यास 24.2

अखिल भारतीय वायुसेना अभ्यास

- **वायुशक्ति–24 अभ्यासः** जैसलमेर के निकट पोखरण रेंज में 17 फरवरी, 2024 को वायुशक्ति–24 अभ्यास आयोजित किया गया। इसमें स्वदेशी तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 121 विमानों ने भाग लिया। अन्य भाग लेने वाले विमानों में राफेल, मिराज–2000, सुखोई–30 एमकेआई, जगुआर, हॉक, सी–130जे, चिनूक, अपाचे और एमआई–17 शामिल थे। स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाली हथियार प्रणालियों आकाश और समर ने कई हवाई अड्डों से संचालन करते हुए लंबी दूरी, सटीक क्षमता वाले हथियारों के साथ–साथ पारंपरिक हथियारों को भी सटीक, समय पर और विनाशकारी प्रभाव के साथ मार गिराने की भारतीय वायुसेना की क्षमता का भी प्रदर्शन किया।

वायुशक्ति अभ्यास–2024

- **गगनशक्ति अभ्यास–24:** भारतीय वायु सेना ने 01 अप्रैल से 10 अप्रैल, 2024 तक अखिल भारतीय त्रि–सेना अभ्यास के रूप में गगनशक्ति अभ्यास–2024 का आयोजन किया। इस अभ्यास में, हमारी सक्रियात्मक योजनाओं की विस्तृत समीक्षा के लिए, विभिन्न ऑपरेशनल स्तरीय चर्चाओं के साथ–साथ तीनों सेनाओं की भागीदारी वाला एक युद्धाभ्यास भी शामिल था। इस अभ्यास में संयुक्त वातावरण में सभी क्षेत्रों में संचालन के पूर्ण स्पेक्ट्रम को शामिल किया गया, जिसमें भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना के साथ समन्वित उड़ान अभियानों का निष्पादन शामिल था।

- **तरंग शक्ति अभ्यास–24** : भारतीय वायुसेना ने अगस्त–सितंबर 24 के दौरान दो चरणों में एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति– अभ्यास 24 का आयोजन किया। **तरंग शक्ति अभ्यास** इस तरह का पहला और भारत में आयोजित सबसे बड़ा वायु अभ्यास था। अभ्यास का पहला चरण 6 अगस्त से 14 अगस्त, 2024 तक वायुसेना स्टेशन सुलूर में आयोजित किया गया। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन ने अपने सैन्य उपकरणों के साथ इस अभ्यास में भाग लिया। तरंग शक्ति अभ्यास –24 का दूसरा चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर, 2024 तक वायुसेना स्टेशन जोधपुर में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, जापान, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई और अमेरिका ने इस चरण में अपने सैन्य उपकरणों के साथ भाग लिया और 19 एफएफसी ने पर्यवेक्षकों के रूप में अभ्यास में भाग लिया।

तरंग शक्ति अभ्यास 2024

नए अधिग्रहण और परीक्षण

- **अरब सागर में कॉम्बैट एक्सपेंडेबल प्लेटफॉर्म (सीईपी) एवं कॉम्बैट फ्री फॉल (सीएफएफ) ड्रॉप्सः** 26 फरवरी, 2024 को अरब सागर में सीएफएफ के साथ मिलकर कॉम्बैट एक्सपेंडेबल प्लेटफॉर्म (सीईपी/सीआरआरसी) ड्रॉप के माध्यम से सी–130जे एयरक्राफ्ट द्वारा मार्कोस का ऑपरेशनल एयरबोर्न इंसर्शन किया गया। इस मिशन ने चल रहे एंटी–पायरेसी ऑपरेशन के समर्थन में तैनात मार्कोस का अतिरिक्त प्रहार के साथ संवर्धन किया।

- **परीक्षण आवश्यकताएँ – गौरव लांग रेंज गाइडेड बम (एलआरजीबी) के कैप्टिव और रिलीज़ फ्लाइट परीक्षणः** 11 मार्च से 20 मार्च, 2024 तक विंग 5, आईटीआर बालासोर में सीएफटी और आरएफटी के परीक्षणों के दौरान एएसएसआर कर्तव्यों के लिए हेलीकॉप्टर प्रदान किया गया था।

- **पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान (आरएलवी) के वहन और प्रक्षेपण के परीक्षण** : भारतीय वायु सेना, एकीकृत नौवहन परीक्षण (आईएनटी), इंजीनियरिंग मॉडल परीक्षण (ईएमटी) और लैंडिंग प्रयोग (एलईएक्स) मिशनों के संचालन हेतु एएसटीई के माध्यम से इसरो के सभी प्रयोगों में सहायता प्रदान कर रही है। भारतीय वायु सेना ने आरएलवी एलईएक्स2 परीक्षणों के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर प्रदान किया, ये परीक्षण मार्च 2024 में चित्रदुर्ग स्थित एटीआर से सफलतापूर्वक किए गए ।

- **आरोग्य मैत्री आपदा ब्रिकः** आरोग्य मैत्री आपदा ब्रिक (16 फीट प्लेटफ़ॉर्म वाला 6202 पाउंड वज़न वाला एचई एयरड्रॉप) के एयरड्रॉप को सी–130जे विमान द्वारा प्रमाणित किया गया। यह परीक्षण उन प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित आपदा राहत पहुँचाने में सहायक है जहाँ अन्य साधनों से पहुँच संभव नहीं है। यह परीक्षण आईए पैरा फील्ड रेजिमेंट और आरोग्य मैत्री टास्क फोर्स के समन्वय में किया गया।

- **प्रोजेक्ट भीस्मः** प्रोजेक्ट भीस्म के एक भाग के रूप में 10 अगस्त, 2024 को आरोग्य सेतु स्वास्थ्य मॉड्यूल को एयरड्रॉप किया गया, जो दुर्गम इलाकों में जमीनी बलों की सहायता करने के लिए भारतीय वायुसेना की बढ़ी हुई परिचालनात्मक क्षमता को प्रदर्शित करता है।

उद्योग आउटरीच कार्यक्रम

- **गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह–2024 में भागीदारीः** इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) ने भारतीय वायुसेना को 6 फरवरी से 9 फरवरी, 2024 तक गोवा में आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह–2024 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। आमंत्रण के आधार पर, आईएएफ ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) के संरक्षण में आयोजकों द्वारा व्यवस्थित जैव ईंधन मंडप में अपने सतत विमानन ईंधन (बायो जेट ईंधन) परियोजना स्टॉल की स्थापना की।

गोवा में आईईडब्ल्यू–2024 में बायोजेट ईंधन स्टॉल

- **पुणे में महाराष्ट्र रक्षा एक्सपो–2024 में भारतीय वायुसेना की भागीदारी:** यह आयोजन महाराष्ट्र सरकार के उद्योग विभाग द्वारा 24 फरवरी से 26 फरवरी, 2024 तक पुणे अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर, मोशी, पुणे में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की आंतरिक क्षमता का प्रदर्शन सफलता की कहानियों, नवाचारों, जैव–जेट ईंधन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परियोजनाओं के माध्यम से किया गया। एमएसएमई/उद्योग भागीदारों की रुचि जगाने के लिए स्वदेशीकरण की आवश्यकता वाली 100 से अधिक वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया।

महाराष्ट्र रक्षा एक्सपो–24

- **अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विमानन प्रदर्शनी (आईडीएएक्स–24):** अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विमानन प्रदर्शनी (आईडीएएक्स–24) का आयोजन एएफएस सुलूर (13 अगस्त से 15 अगस्त, 2024) और जोधपुर (12 सितंबर से 14 सितंबर, 2024) में तरंग शक्ति अभ्यास के अवसर पर किया गया था। इन आयोजनों का उद्घाटन तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल ने सुलूर में और माननीय रक्षा मंत्री ने जोधपुर में किया था। इस कार्यक्रम में विभिन्न मित्र विदेशी देशों (एफएफसी) के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों, डीआरडीओ, सीएसआईआर लैब–एनएएल जैसे प्रमुख संगठनों, एचएएल, बीईएल और बीडीएल जैसे डीपीएसयू, 48 प्रमुख निजी उद्योग भागीदारों, 13 स्टार्ट–अप फर्मों और पांच यूरोपीय उद्योग फर्मों ने पहले चरण में भाग लिया था और डीपीएसयू, पीएसयू, डीआरडीओ, टियर– I, टियर– II, एमएसएमई और स्टार्ट–अप सहित 68 भारतीय प्रदर्शकों ने क्रमशः कार्यक्रम के दूसरे चरण में भाग लिया। इस कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें संलग्न हैं।

अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विमानन एक्सपो (आईडीएएक्स–24) सुलूर की तस्वीरें

अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विमानन एक्सपो (आईडीएएक्स –24) जोधपुर की तस्वीरें

- **एविएमैट 2024:** सीएसडीओ द्वारा 17 सितंबर, 2024 को वायु सेना सभागार, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली में "विमानन रखरखाव में स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक नया प्रतिमानः एविएमैट 2024" विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। विमानन परिसंपत्तियों के एआई–सहायता प्राप्त रखरखाव और विमानन रखरखाव में भविष्य की तकनीकों पर चर्चा मुख्य विषय रही और रियल टाइम विश्लेषण, सटीक निदान और सुरक्षित संचालन के लिए तकनीकी बदलाव की संभावनाएँ प्रस्तुत की गईं ।

"विमानन रखरखाव में स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक नया प्रतिमान" विषय पर सेमिनार

समारोह और संबंधित गतिविधियाँ

- **वायु सेना दिवस परेड 2024:** राष्ट्र सेवा में 92 वर्षों के पराक्रम, उत्कृष्टता और अदम्य प्रयासों के उपलक्ष्य में, भारतीय वायु सेना ने 8 अक्टूबर, 2024 को वायु सेना स्टेशन तांबरम (चेन्नई) में अपनी 92वीं वर्षगांठ मनाई। इस वार्षिक समारोह का विषय 'प्रभावकारी, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर' भारतीय वायु सेना था। इस महत्वपूर्ण अवसर पर, वायु सेना स्टेशन तांबरम में एक सेरेमोनियल परेड के साथ–साथ हवाई करतब भी प्रदर्शित किए गए।

वायु सेना दिवस परेड 2024

- **गणतंत्र दिवस 2025 :** गणतंत्र दिवस 2025 पर, भारतीय वायु सेना ने अपने चार अधिकारियों और 144 कर्मियों के साथ एक श्रेष्ठ फॉर्मेशन में मार्च करते हुए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। भारतीय वायु सेना के विमानों ने आकाश में गर्जना की और दर्शक दंग रह गए। 22 अग्निवीरों सहित 72 संगीतकारों वाले भारतीय वायु सेना बैंड ने 'साउंड बैरियर' की धुन बजाई, जो हमारे राष्ट्र की शक्ति और समुत्थान–शक्ति को एक सशक्त श्रद्धांजलि थी।

गणतंत्र दिवस 2025

सम्मान और पुरस्कार

- वायु सेना दिवस परेड 2024 के दौरान कुल चार यूनिट प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।
- भारत की राष्ट्रपति ने वर्ष 2024–25 के दौरान भारतीय वायुसेना कर्मियों को 26 जनवरी 2024 को कुल 86 वीरता पुरस्कार, 15 अगस्त 2024 को 8 पुरस्कार और 26 जनवरी 2025 को 81 पुरस्कार प्रदान किए।

सतर्कता तंत्र और साइबर सुरक्षा

- **भारतीय वायुसेना में सतर्कता तंत्रः** कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय वायुसेना में एक सुपरिभाषित सतर्कता तंत्र है। भारतीय वायुसेना में, सतर्कता संगठन का गठन सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। सतर्कता गतिविधियों का उद्देश्य अवांछनीय गतिविधियों को रोकने, उनका पता लगाने और उन्हें न्यूनतम करने के लिए एक कुशल तंत्र सुनिश्चित करना है।
- **साइबर सुरक्षा और जागरूकता उपायः** संगठन के सभी कर्मियों को अनुपालन और जागरूकता के लिए समय–समय पर प्रासंगिक मामलों पर कई साइबर सुरक्षा सलाह और निर्देश जारी किए जाते हैं। गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) के विश्लेषण से पता चला है कि साइबर अपराध की 60% शिकायतें ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित हैं। इसलिए, गृह मंत्रालय ने कहा है कि साइबर अपराधों को रोकने के लिए मुख्य कदम जनता में निरंतर जागरूकता पैदा करना है।

अग्निवीरवायु को कुशल बनाना

- भारतीय वायुसेना में चार वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर अग्निवीर वायु को 'कौशल प्रमाण पत्र' प्रदान करने के लिए भारतीय वायुसेना को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा अवार्डिंग बॉडी और मूल्यांकन एजेंसी के रूप में दोहरी मान्यता दी गई है।

- भारतीय वायुसेना में प्राप्त इन कौशल योग्यताओं के आधार पर, एनईपी–2020 के क्रेडिट साझाकरण प्रावधानों के माध्यम से शैक्षणिक प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/यूजी डिग्री प्रदान करने के लिए क्रेडिट आवंटित किए जाएंगे, जिसमें 974209 एजीवी द्वारा 50% क्रेडिट भारतीय वायुसेना प्रशिक्षण और परीक्षण से प्राप्त किए जाएंगे और शेष 50% अग्निवीरवायु द्वारा चुने गए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के शैक्षणिक विषयों को पास करके प्राप्त किए जाएंगे। (स्नातक की डिग्री प्रदान करने के लिए कुल 120 क्रेडिट आवश्यक हैं)।

- भारतीय वायुसेना ने एनईपी–2020 और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के प्रावधानों को उपयुक्त रूप से अधिकतम करने में अग्रणी भूमिका निभाई है और अग्निवीरों (एजीवीएस) को कौशल आधारित स्नातक की डिग्री प्रदान करने की सुविधा के लिए स्तर 5.5 तक भारतीय वायुसेना योग्यता के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (एनएसक्यूसी) की मंजूरी प्राप्त की है।

- एनएसक्यूएफ स्तर के आधार पर और इग्नू की शैक्षणिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कौशल आधारित प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/यूजी डिग्री प्रदान करने की सुविधा के लिए भारतीय वायुसेना और इग्नू के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अग्निवीरवायु नॉन–कॉम्बैटेंट को नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) से कक्षा 12वीं का प्रमाणपत्र प्रदान करने में सुविधा प्रदान की जाएगी।

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप–समिति ने हिंदी के कार्यान्वयन की जाँच हेतु भारतीय वायु सेना के विभिन्न कमानों/स्टेशनों/इकाइयों का निरीक्षण किया। संसदीय राजभाषा समिति द्वारा 18 जनवरी, 2024 को वायु सेना स्टेशन पुणे का राजभाषा निरीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। निर्धारित समय–सीमा के भीतर समिति को आश्वासन रिपोर्ट भी भेज दी गई है। संसदीय राजभाषा समिति के माननीय सदस्यों ने हिंदी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में भारतीय वायु सेना द्वारा किए गए सभी प्रयासों की सराहना की है।

अभियान

- **एक पेड़ माँ के नामः** विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान शुरू किया गया। भारतीय वायुसेना को 26 जनवरी, 2025 तक 7.5 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य दिया गया था। यह लक्ष्य 31 दिसंबर, 2024 को प्राप्त कर लिया गया।

- **हर घर तिरंगाः** यह अभियान 13 अगस्त से 15 अगस्त, 2024 तक स्वतंत्रता दिवस समारोह के भाग के रूप में चलाया गया। वायु योद्धाओं और उनके परिवारों की उत्साही भागीदारी ने राष्ट्रवाद की भावना और भारत सरकार के निर्देशानुसार हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने की प्रतिबद्धता को दर्शाया।

- **विशेष अभियान 4.0:** भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटान हेतु क्रमशः 2021, 2022 और 2023 में आयोजित विशेष अभियान 1.0, 2.0 और 3.0 की तर्ज पर 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2024 तक विशेष अभियान 4.0 चलाया गया। भारतीय वायुसेना ने 12 मीट्रिक टन वाहनों और 1527 पुरानी बैटरियों सहित 8,23,403.95 किलोग्राम स्क्रैप का निपटान किया है। निपटाए गए स्क्रैप का कुल मूल्य 21,97,78,604.93 रु. है।

- **स्वच्छता ही सेवा:** 02 अक्टूबर, 2024 को स्वच्छ भारत दिवस की प्रस्तावना के रूप में 'स्वभाव स्वच्छता: संस्कार स्वच्छता' की थीम के साथ 14 सितंबर से 01 अक्टूबर, 2024 तक 'स्वच्छता ही सेवा' (एसएचएस) पखवाड़ा मनाया गया। एसएचएस 2024 के एक भाग के रूप में, स्वच्छता लक्षित इकाई और सफाई मित्र सुरक्षा शिविर सहित "स्वच्छता की भागीदारी, संपूर्ण स्वच्छता" नामक तीन गतिविधियां आयोजित की गईं।

खेल/टूर्नामेंट

- **21वीं एशियाई पुरुष हैंडबॉल चैम्पियनशिप:** यह चैम्पियनशिप 11 जनवरी से 25 जनवरी 2024 तक बहरीन में आयोजित की गई। इस चैम्पियनशिप में कुल नौ वायु योद्धाओं ने भाग लिया, जिनमें छह खिलाड़ी, दो कोच और एक प्रतिनिधिमंडल प्रमुख शामिल थे।

- **मॉस्को स्टार वुशु टूर्नामेंट 2024:** यह टूर्नामेंट 29 फरवरी से 3 मार्च, 2024 तक मॉस्को, रूस में आयोजित किया गया था। सार्जेंट कर्णजीत शर्मा ने रजत पदक और जेडब्ल्यूओ अंजुल नामदेव ने कांस्य पदक जीता ।

- **2024 आईएयू 24 घंटे एशिया और ओशिनिया चैम्पियनशिप :** यह चैम्पियनशिप 6 अप्रैल से 7 अप्रैल, 2024 तक कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई। अल्ट्रा मैराथन धावक कॉर्पोरल अमर सिंह देवंदा ने 24 घंटे में 272.537 किलोमीटर की दूरी तय करके स्वर्ण पदक जीता और 256.4 किलोमीटर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। अल्ट्रा मैराथन धावक कॉर्पोरल सौरव कुमार रंजन ने 24 घंटे में 240.13 किलोमीटर की दूरी तय करके चौथा स्थान हासिल किया ।

- **ब्रिक्स खेल 2024:** ये खेल 12 जून से 16 जून, 2024 तक रूस के कज़ान में आयोजित किए गए। एएफ वुशु टीम के सार्जेंट कर्णजीत शर्मा हंजबाम ने 9.820 अंकों के साथ ताओलू–ताइजीक्वान पुरुष स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।

- **पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में भागीदारी:** एएफ एथलेटिक्स टीम के सदस्य जेडब्ल्यूओ अब्दुल्ला अबूबकर एन और सार्जेंट मिजो चाको कुरियन ने क्रमशः ट्रिपल जंप और 4x400 मीटर पुरुष रिले में पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में भाग लिया है।

- **10वीं एशियाई वुशु चैम्पियनशिप 2024:** चैम्पियनशिप 9 सितंबर से 16 सितंबर, 2024 तक मकाऊ, चीन में आयोजित की गई थी। जेडब्ल्यूओ कुशल कुमार ने इस चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता।

- **अग्निवीरवायु संगीतकार:** कुल 23 अग्निवीरवायु संगीतकारों ने 11 सितंबर, 2024 को सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 के समापन समारोह के दौरान अंबेडकर स्टेडियम में एक आकर्षक बैंड और ड्रिल प्रस्तुति के रूप में अपनी प्रथम प्रस्तुति दी।

सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 के समापन समारोह के दौरान अग्निवीरवायु संगीतकार

"वायु वीर विजेता" – आईएएफ–उत्तराखंड युद्ध स्मारक (यूडब्ल्यूएम) थोइस से तवांग तक संयुक्त कार रैली

आईएएफ और यूडब्ल्यूएम ने संयुक्त रूप से 08 अक्टूबर, 2024 से 30 नवंबर, 2024 तक थोईस (लद्दाख) से तवांग (अरुणाचल प्रदेश) तक "वायु वीर विजेता कार रैली" नामक एक मेगा–कार रैली का आयोजन किया। रैली को माननीय रक्षा मंत्री द्वारा 01 अक्टूबर, 2024 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से थोईस के लिए विधिवत् रवाना किया गया और 08 अक्टूबर, 2024 को औपचारिक रूप से शुरुआत करते हुए तवांग के लिए 4300 किलोमीटर से अधिक की सड़क दूरी तय की गई। 12 मारुति जिम्नी में सेवारत कर्मियों, वायु सेना के भूतपूर्व सैनिकों और यूडब्ल्यूएम के सदस्यों सहित कुल 55 प्रतिभागी रास्ते में लगभग 16 स्थानों पर रुके, युद्ध स्मारकों का दौरा कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी तथा रास्ते के महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में युवाओं से बातचीत कर उन्हें सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। इस रैली का 30 अक्टूबर, 2024 को अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तवांग में विधिवत् स्वागत किया गया।

*****

मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ

मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ (एचक्यू आईडीएस) ने संयुक्त सिद्धांतों के निर्माण, एकीकृत प्रशिक्षण और अभ्यासों के संचालन और एकीकृत परिचालन रणनीतियों के विकास के माध्यम से भारतीय सशस्त्र बलों के बीच एकजुटता और एकीकरण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2024 में मुख्यालय आईडीएस की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख आगे के अनुच्छेदों में किया गया है।

विदेशी रक्षा सहयोग

अभ्यास कोबरा गोल्ड : 'अभ्यास कोबरा गोल्ड', संयुक्त राज्य अमेरिका, थाईलैंड और भारत–प्रशांत क्षेत्र में सहयोगी भागीदारों के बीच एक बड़े पैमाने का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 09 फरवरी से 09 मार्च, 2024 तक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। मुख्यालय आईडीएस और अंडमान और निकोबार कमान के 15 स्टाफ अधिकारियों ने इसमें भाग लिया।

अभ्यास कोबरा गोल्ड में भारतीय सशस्त्र बलों से प्रतिनिधि

अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ–24 (टीटी–24) : 'एक्स टाइगर ट्रायम्फ' भारत और अमेरिका के बीच एक द्वि पक्षीय, त्रि–सेना अभ्यास है जो मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) पर केंद्रित है। यह वार्षिक अभ्यास 18 मार्च से 31 मार्च, 2024 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। लगभग 1200 भारतीय सैनिकों और अमेरिका की ओर से भी इतनी ही संख्या में सैनिकों ने आईएनएस जलाश्व, आईएनएस ऐरावत, यूएसएस हेल्सी और यूएसएस समरसेट पर इस अभ्यास में भाग लिया।

विशाखापत्तनम में आईएनएस जलाश्व जहाज पर अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का उद्घाटन समारोह

इंडोनेशिया के साथ एचएडीआर पर आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (एडीएमएम–प्लस) विशेषज्ञ कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) : एडीएमएम–प्लस आसियान और उसके आठ संवाद साझेदारों अर्थात ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और अमेरिका (प्लस देशों) के लिए एक मंच है जो इस क्षेत्र में शांति और विकास के लिए सुरक्षा और रक्षा सहयोग को सशक्त बनाता है। सात क्षेत्रों में सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए ईडब्ल्यूजी की स्थापना की गई है। भारत से न्यूजीलैंड को एचएडीआर पर ईडब्ल्यूजी की अध्यक्षता सौंपने का समारोह 20 मार्च, 2024 को मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में इंडोनेशिया, सिंगापुर और न्यूजीलैंड के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया, जबकि शेष 14 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया।

रक्षा अताशे (नामोद्दिष्ट) का अभिविन्यास : रक्षा खुफिया एजेंसी द्वारा रक्षा अताशे (नामोद्दिष्ट) के लिए एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य समसामयिक राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों को व्यापक रूप से कवर करते हुए उपस्थित लोगों को बहुआयामी एवं बहु—एजेंसी अनुभव के माध्यम से सशक्त बनाना और तैयार करना था। यह कार्यक्रम 1 अप्रैल से 26 अप्रैल, 2024 तक नई दिल्ली में चार सप्ताह की अवधि तक आयोजित किया गया था।

रक्षा अताशे (नामोद्दिष्ट) का अभिविन्यास

संयुक्त स्टाफ वार्ता की योजना और संचालन : रक्षा सहयोग के लिए रोडमैप तैयार करने हेतु विभिन्न मित्र देशों के साथ संयुक्त स्टाफ वार्ता आयोजित की गई।

मार्च 2024 में नई दिल्ली में आयोजित 12वीं इटली—भारत सैन्य सहयोग समूह बैठक

जून 2024 में माले, मालदीव में आयोजित 7वीं भारत—मालदीव संयुक्त सेना वार्ता (जेएसटी)

आयोजित कार्यक्रम

संयुक्त कमांडर सम्मेलन (जेसीसी) —2024 : पहला जेसीसी 04 सितंबर से 05 सितंबर, 2024 तक लखनऊ में आयोजित किया गया था, जिसका विषय था **'सशक्त और सुरक्षित भारतः सशस्त्र बलों का रूपांतरण'** । यह आयोजन सशस्त्र बलों के भीतर आंतरिक 'प्रक्रिया सुधारों' के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। इस आयोजन में सीडीएस, सेना प्रमुखों, उप—प्रमुखों, सी—इन—सी और रक्षा मंत्रालय के सचिव ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान, सी—इन—सी, सेना प्रमुखों, सीडीएस और माननीय रक्षा मंत्री के बीच शत्रुओं के विरुद्ध विभिन्न रणनीतियों, बहु—क्षेत्रीय क्षमता विकास और बल आधुनिकीकरण पर विस्तृत विचार—विमर्श और चर्चा हुई। माननीय रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों को 'असफलता—रहित प्रतिवारण' सुनिश्चित करने के लिए भविष्य के लिए तैयार रहने का आह्वान किया।

माननीय रक्षा मंत्री संयुक्त कमांडर सम्मेलन– 2024 की अध्यक्षता करते हुए

संयुक्त प्रचालन समीक्षा एवं मूल्यांकन (कोर) कार्यक्रम 2024 : कोर कार्यक्रम – 2024, 9 सितंबर, 2024 से 13 सितंबर, 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें तीनों सेनाओं के 23 अधिकारियों और रक्षा मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। इसके ध्यान के प्रमुख क्षेत्र थेः उभरते खतरे और राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य बल एकीकरण एवं क्षमता विकास, समग्र सरकार के दृष्टिकोण के साथ तालमेल, रणनीतिक नेतृत्व और तकनीकी समावेशन।

कोर कार्यक्रम – 2024 के प्रतिभागी

संयुक्त सिद्धांत समीक्षा सम्मेलन–2024: संयुक्त सिद्धांत समीक्षा सम्मेलन (जेडीआरसी–24) का दूसरा संस्करण 11 सितंबर, 2024 को आयोजित किया गया। यह सम्मेलन संयुक्त सिद्धांतों के निर्माण में मुख्यालय आईडीएस और तीनों सेनाओं के बीच प्रयासों के सामंजस्य पर केंद्रित था। यह सम्मेलन सिद्धांत विकास में शामिल सभी प्रमुख हितधारकों को चर्चाओं में भाग लेने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और सैद्धांतिक मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए एक सहयोगी मंच प्रदान करता है। साइबरस्पेस संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत और जलस्थलीय संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत नामक दो सिद्धांत जारी किए गए।

साइबरस्पेस प्रचालनों पर संयुक्त सिद्धांत का विमोचन

परिवर्तन चिंतन – I और II : 'परिवर्तन चिंतन' एक अग्रणी त्रि–सेना सम्मेलन है जिसका उद्देश्य संयुक्तता और एकीकरण के प्रयासों को गति देने हेतु नवीन विचारों, पहलों और सुधारों को सृजित करना है। ये सम्मेलन अप्रैल और मई 2024 में आयोजित किए गए और इनकी अध्यक्षता सीडीएस ने की, जिसमें तीनों सेनाओं के संगठनों के प्रमुख और सशस्त्र बल प्रशिक्षण संस्थानों के कमांडेंट उपस्थित रहे। संयुक्त संरचनाओं के निर्माण और संचालन की दिशा में आवश्यक कदमों पर चर्चा की गई और तीनों सेनाओं के एकीकरण के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कार्य योजनाएँ तैयार की गईं।

जनरल अनिल चौहान, सीडीएस परिवर्तन चिंतन–। को संबोधित करते हुए

भावी युद्ध पाठ्यक्रमः पायलट भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम 23 सितंबर से 27 सितंबर, 2024 तक आयोजित किया गया था। पाठ्यक्रम का उद्देश्य उभरती और विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के निहितार्थों पर विशेष ध्यान देने के साथ–साथ भविष्य के युद्ध के सिद्धांतों के लिए एक सामान्य आधार प्रदान करना था, जिससे प्रतिभागियों की रणनीतिक समझ, अनुकूलनशीलता और संज्ञानात्मक कौशल में वृद्धि हो सके। मेजर से लेकर मेजर जनरल और समकक्ष रैंक तक के विविध अनुभव वाले तीनों सेनाओं के 30 अधिकारियों (सेना–14, नौसेना–08, भारतीय वायुसेना–08) ने पाठ्यक्रम में भाग लिया।

फ्यूचर वारफेयर कोर्स – 2024 के प्रतिभागी

संयुक्तता एवं एकीकरण : प्रक्रियाओं में समानता लाने, अंतर–संचालन को बढ़ाने और संसाधनों का अनुकूलन करने के लिए ठोस प्रयास किया जा रहा है। संचालन और आसूचना, क्षमता विकास, संचार और आईटी, ऑप लॉजिस्टिक्स, प्रशिक्षण, रखरखाव सहायता, मानव संसाधन और प्रशासन एवं विधिक के कार्यक्षेत्रों के तहत मुख्यालय आईडीएस की सभी शाखाओं में 196 एकीकरण पहलों की पहचान की गई है। प्रगति पूर्णता के विभिन्न चरणों में है।

नई दिल्ली स्थित स्मृति स्थलः नई दिल्ली में इंडिया गेट के निकट राष्ट्रीय समर स्मारक हमारे सशस्त्र बलों के उन सैनिकों के सम्मान में समर्पित है जिन्होंने स्वतंत्र भारत के सशस्त्र संघर्षों में वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दी। राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोहों के लिए आने वाले निकटतम परिजनों (एनओके) के लिए एक स्मृति स्थल का उद्घाटन रक्षाकर्मी पत्नी कल्याण संघ (डीडब्ल्यूडब्ल्यूए) की अध्यक्ष श्रीमती अनुपमा चौहान ने किया। 01 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक 314 एनओके समारोह आयोजित किए गए।

नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक, स्मृति स्थल

एकीकृत चिकित्सा केंद्र (आईएमएस), कैंपबेल खाड़ी : अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र के सुदूर द्वीपों पर स्थित सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके आश्रितों को उच्चतम स्तर की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, अंडमान और निकोबार के सुदूर दक्षिणी द्वीप में स्थित आईएनएस बाज़, कैंपबेल बे में एक एकीकृत चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र में तीन विशेषज्ञ अधिकारी (सर्जन, एनेस्थेटिस्ट और चिकित्सा विशेषज्ञ) और 20 अन्य रैंक के कर्मचारी कार्यरत हैं जो किसी भी आपात स्थिति में चौबीसों घंटे चिकित्सा सहायता प्रदान करते हैं।

प्रचालन और अभ्यास

मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) : कर्मियों के बचाव/निकासी, आपदा राहत सहायता की आपूर्ति, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान, हिमस्खलन बचाव मिशन और बाढ़ राहत कार्यों के लिए सशस्त्र बलों की एचएडीआर प्रतिक्रिया में तालमेल और समन्वय के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं।

वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास (एजेएचई)–2024 : 'संयुक्त विमोचन–2024', जो एक वार्षिक संयुक्त एचएडीआर अभ्यास है, भारतीय सेना द्वारा 18 नवंबर से 19 नवंबर, 2024 तक अहमदाबाद और पोरबंदर, गुजरात में आयोजित किया गया। इस बहु–एजेंसी क्षमता प्रदर्शन में विभिन्न एजेंसियों ने समन्वित लॉजिस्टिक्स, त्वरित प्रतिक्रिया और कृत्रिम चक्रवात परिदृश्य में प्रभावी आपदा प्रबंधन रणनीतियों का अभ्यास किया।

संचालित प्रचालनों का विवरण

क्र.सं.	तारीख	घटना	बचाव/राहत विवरण
राष्ट्रीय एचएडीआर प्रयास			
(क)	26–31 मई, 2024	तटीय बांग्लादेश और उससे सटे पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भीषण चक्रवाती तूफान 'रेमल'	• चक्रवाती तूफान 'रेमल' के बाद मिजोरम, मणिपुर और असम में सशस्त्र बल तैनात किए गए। • तैनात सैन्य दस्ते – 21 • इंजीनियर टास्क फोर्स (ईटीएफ) तैनात – 03 • चिकित्सा दल – 01 • बचाए गए कुल नागरिक / लोग – 6672 • राहत सामग्री का वितरण – 7480 व्यक्ति। • 50 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई।
(ख)	6 जून, 2024	बचाव अभियानः सहस्त्र ताल	• सहस्त्र ताल में फंसे ट्रेकर्स को बचाने के लिए 02 चीता हेलीकॉप्टर और 01 एमआई–17 तैनात किए गए। • 13 ट्रेकर्स को बचा लिया गया और 9 शव बरामद किए गए।
(ग)	30 जून, 2024	सियांग नदी अभियान	• लगातार बारिश के कारण असम के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ गई। 30 जून 2024 को बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने के दौरान धेमाजी जिले में सियांग नदी में नाव पलट जाने से 9 एसडीआरएफ कर्मी फंस गए। • उन्हें भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा बचाया गया।

<table>
<tr><td>(घ)</td><td>02–08 जुलाई, 2024</td><td>ऑपरेशन जल राहतः पूर्वी कमान (असम और अरुणाचल प्रदेश)।</td><td>• 02 जुलाई 2024 को कई पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण, राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को तैनात किया गया था। बचाव कार्यों का सारांश इस प्रकार हैः
<table>
<tr><th>एसएचक्यू</th><th>तैनात सैन्य दल</th><th>बचाए गए सिविलियन</th><th>लोड (एमटी)</th></tr>
<tr><td>आईए</td><td>11</td><td>3470</td><td>–</td></tr>
<tr><td>भारतीय वायु सेना</td><td>02x विमान</td><td>62</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल</td><td>3532</td><td>12</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(ड.)</td><td>08 जुलाई, 2024</td><td>बाढ़ राहतः टनकपुर और बनबसा</td><td>• 100 नागरिकों को निकाला/बचाया गया।</td></tr>
<tr><td>(च)</td><td>09 जुलाई, 2024</td><td>बाढ़ राहतः पीलीभीत</td><td>• पीलीभीत जिले में भारी बारिश और बाढ़ के कारण भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर तैनात किए गए और 7 नागरिकों को बचाया गया।</td></tr>
<tr><td>(छ)</td><td>16 जुलाई, 2024</td><td>एलपीजी टैंकर संकटः उत्तर कन्नड़ जिला</td><td>• लगातार मानसूनी बारिश के कारण कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में अंकोला–कुमता रोड पर श्रीउर में भूस्खलन हुआ।
• भारतीय नौसेना की दो डाइविंग टीमें और दो सोनार टीमें तैनात की गई।
• कुल 08 शव बरामद किये गये।
• भारतीय नौसेना का सोनार रडार नदी में दबे माल ट्रक का पता लगा सका।</td></tr>
<tr><td>(ज)</td><td>29 जुलाई, 2024</td><td>वायनाड लैंडस्लाइड</td><td>• निरंतर बारिश के कारण वायनाड में कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ।
• कन्नूर, कोझिकोड, एझिमाला, बेंगलुरु और त्रिवेंद्रम से इंजीनियर, मेडिकल और रिवर रेस्क्यू प्रशिक्षित विशेषज्ञों के 550 जवानों वाली सशस्त्र बलों की कई टुकड़ियों को सड़क और हवाई जहाज़ से ले जाया गया।
• प्रभावित ग्रामवासियों को भोजन और पानी पहुँचाने के साथ–साथ खोज और बचाव अभियान के लिए भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के छह हेलीकॉप्टर लगाए गए।
• तीन डॉग रेस्क्यू टीमें और 110 फ़ीट बेली ब्रिज स्टोर (लगभग 28 ट्रक लोड) सी–17 द्वारा हिंडन से कोझिकोड ले जाए गए।
• 110 फीट के दो सेट बेली ब्रिज स्टोर तीन जेसीबी के साथ 31 जुलाई 24 को बेंगलुरु से वायनाड सड़क मार्ग से ले जाए गए। पुल का निर्माण 02 अगस्त 24 को पूरा हुआ।
• खोज और बचाव अभियान के लिए 29 अगस्त 24 तक राज्य सरकार की सहायता के लिए दो हेलीकॉप्टर तैनात किए गए थे।</td></tr>
</table>

(झ)	01 अगस्त, 2024	बादल फटनाः हिमाचल प्रदेश	• **समेज गाँव (जाखरी) में बादल फटना** : बादल फटने से लगभग तीन लोगों की मौत हो गई और 40 लोग लापता हो गए। भारतीय सेना की तीन टुकड़ियाँ (05–10–110, एक इंजीनियर टास्क फोर्स (01–02–18) और एक मेडिकल टीम (01–02–11) तैनात की गई और तीन खोज एवं राहत कुत्तों के साथ खोजबीन एवं राहत अभियान चलाया गया।
(ञ)	5 अगस्त, 2024	गिरना नदी, नासिक	• गिरना नदी से 15 मछुआरों को निकालने के लिए नासिक एयरबेस से दो एएलएच ने उड़ान भरी।
(ट)	24 अगस्त, 2024	एचएडीआरः उत्तराखंड (केदारनाथ)	• भारतीय वायुसेना ने एक चिनूक और एक एमआई–17 वी5 तैनात किया। कुल 288 लोगों को बचाया गया और लगभग 13 टन भार गिराया गया । • भारतीय सेना की इंजीनियर टास्क फोर्स ने राहत कार्यों में सहायता करने और फंसे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए 500 फीट का एरियल केबल वे और दो कामचलाऊ पैदल पुल निर्मित किए।
(ठ)	21 अगस्त, 2024	ऑपरेशन जल राहत पर अपडेटः पूर्वी कमान (त्रिपुरा, मणिपुर और अगरतला)	• कई पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ आई। • भारतीय सेना ने चार टुकड़ियाँ और भारतीय वायुसेना ने आठ हेलीकॉप्टर तैनात किए। कुल 145 कर्मियों को बचाया गया और लगभग दो टन भार गिराया गया।
(ड)	02 सितंबर, 2024	एचएडीआर ऑपरेशन पर अपडेटः आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	• आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ आई। • गुंटूर और कृष्णापट्टनम क्षेत्र में 02 सितम्बर से 08 सितम्बर 2024 तक तीनों सेनाओं की परिसंपत्तियों को तैनात करके एचएडीआर ऑपरेशन चलाए गए।
(ढ)	12 सितंबर, 2024	एचएडीआर ऑपरेशन पर अपडेटः मध्य प्रदेश और राजस्थान	• मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ आई। • मध्य प्रदेश के ग्वालियर, लोधीपुर और दतिया तथा राजस्थान के धौलपुर में बचाव कार्यों के लिए राज्य सरकार के साथ एक हेलीकॉप्टर के साथ भारतीय सेना की तीन टुकड़ियाँ तैनात की गई।
(ण)	6 अक्टूबर, 2024	ट्रेकर्स को सुरक्षित निकालना	• उत्तराखंड के चमोली जिले के चौखंबा ॥॥ में दो ट्रेकर्स (एक अमेरिका से और एक यूके से) को निकालने के लिए 04 अक्टूबर 24 से 06 अक्टूबर 24 तक वायु सेना के दो चीता हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। ट्रेकर्स को 06 अक्टूबर 24 को बचा लिया गया।

(त)	02 दिसंबर, 2024	चक्रवात फेंगल, पुडुचेरी, तमिलनाडु	• सिविलियनों को राहत और बचाव सहायता प्रदान करने के लिए तीन आईए कॉलम और आईएएफ के एक एमआई–17 वी5 को तैनात किया गया। • आईए द्वारा 1000 नागरिकों को बचाया गया। • चार अतिरिक्त आईए कॉलम रिजर्व के रूप में रखे गए थे।
अंतर्राष्ट्रीय एचएडीआर प्रयास			
(क)	09–15 मई, 2024	केन्या को एचएडीआर सहायता	• भारतीय नौसेना जहाज सुमेधा ने 09 मई 2024 को मोम्बासा, केन्या में 1.5 टन एचएडीआर राहत सामग्री पहुंचाई। • एक एसी (सी–17) ने 14–15 मई 2024 को 40 टन दवाइयां और आवश्यक सामग्री पहुंचाई।
(ख)	12 जून, 2024	कुवैत से पार्थिव अवशेषों का परिवहन	• 12 जून 2024 को कुवैत में श्रमिक आवास सुविधा में आग लगने से 45 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। • 13 जून 2024 को एक आईएएफ सी–130जे विमान द्वारा उनके पार्थिव शरीर को कुवैत से भारत लाया गया।
(ग)	24 अगस्त, 2024	नेपाल में सड़क दुर्घटना के मृतकों को जलगांव ले जाया गया	• नेपाल के तनहु जिले के अम्बुखेरेनी क्षेत्र के मार्शयंडी में एक बस दुर्घटना हुई। • 25 मृतकों के पार्थिव शरीरों को ले जाने के लिए भारत से नेपाल के चितवन तक वायुसेना का एक विशेष विमान भेजा गया।
(घ)	15 सितंबर, 2024	हनोई, वियतनाम और लाओस तक एचएडीआर सहायता का परिवहन	• आईएएफ सी–17 विमान ने तूफान यागी के बाद हनोई, वियतनाम को 35 टन एचएडीआर सहायता तथा लाओस को 10 टन एचएडीआर सहायता पहुंचाई।
(ङ)	17 सितंबर, 2024	म्यांमार के लिए एचएडीआर	• म्यांमार को एचएडीआर सहायता पहुंचाने का कार्य भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना द्वारा किया गया। ऑपरेशन का सार निम्नानुसार है: **(क) भारतीय वायुसेना** : एक भारतीय वायुसेना आईएल–76 विमान ने हिंडन से म्यांमार तक लगभग 32 टन एचएडीआर सहायता पहुंचाई। **(ख) भारतीय नौसेना** : भारतीय नौसेना के एक जहाज (आईएनएस सतपुड़ा) ने 17 सितम्बर 2024 को म्यांमार को 21.5 टन एचएडीआर सहायता सामग्री पहुंचाई।

*****

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सत्यमेव जयते

रक्षा मंत्रालय
भारत सरकार

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

डीआरडीओ की स्थापना 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन और प्रौद्योगिकी विकास स्थापन के संयोजन से की गई थी। जैसे–जैसे यह विकसित हुआ, प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के स्वदेशी विकास को आगे बढ़ाने के लिए नई प्रयोगशालाएं बनाई गई। प्रयोगशालाओं को मोटे तौर पर प्रणाली डिज़ाइन, प्रौद्योगिकी विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और परीक्षण रेंज में बांटा गया है। डीआरडीओ ने सेनाओं के लिए कई हथियार प्रणालियां और वॉर फाइटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। डीआरडीओ ने लड़ाकू विमान, मिसाइल, रेडार, सोनार, टॉरपीडो, आर्टिलरी गन, मल्टी–बैरल रॉकेट लॉन्चर और टैंक के विकास में विशेषज्ञता हासिल की है।

भारतीय उद्योग द्वारा स्वदेशी प्रणाली के विकास को बढ़ावा देने वाली सरकार की नीति और दो डिफेंस कॉरिडोर बनाने से उद्योगों के लिए रक्षा क्षेत्र में आने के दरवाज़े खुल गए हैं। डीआरडीओ ने दो सूची प्रकाशित की है, जिनमें उन प्रणालियों अथवा प्रौद्योगिकी उत्पादों को उजागर किया गया है जिन्हें भारतीय उद्योग सीधे विकसित कर सकते हैं, और जिनके लिए डीआरडीओ नई परियोजनाएं नहीं लाएगा। इसलिए, डीआरडीओ के लिए यह सही समय और अवसर है कि वह ऐसी भावी प्रणालियों के निर्माण की प्रौद्योगिकी पर ध्यान दे जो युद्ध के मैदान में गेम चेंजर साबित हों।

डीआरडीओ के मिशन में मुख्य रूप से ये बड़ी गतिविधियां शामिल हैं:

- ज़मीन, हवा, समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर की रक्षा और सुरक्षा डोमेन में अत्याधुनिक सेंसर, हथियार प्रणाली, प्लेटफॉर्म और उससे जुड़े उपकरणों का डिजाइन और विकास करना
- विभाग के अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम के माध्यम से विकसित की गई प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों के उत्पादन और समावेशन को सुविधाजनक बनाना
- लड़ाई में क्षमता बढ़ाने के लिए सेनाओं को प्रौद्योगिकीय समाधान प्रदान करना
- भारतीय उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) संस्थान और शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर काम करके रक्षा अनुसंधान एवं विकास की क्षमता को बढ़ाना और मजबूत करना
- अवसंरचना और जांच एवं मूल्यांकन सुविधाओं का विकास; डिजाइन प्रमाणीकरण; कौशल विकास; और मानव संसाधन को मजबूत करना

बजट

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, रक्षा विभाग अनुसंधान एवं विकास (डीडीआरएंडडी) को 23,856 करोड़ रूपये दिए गए, जो भारत के कुल रक्षा सेवा आकलन बजट (4,54,773 करोड़ रूपये) का 5.25% है, पूंजी शीर्ष के तहत 13,208 करोड़ रूपये और राजस्व शीर्ष के तहत 10,648 करोड़ रूपये आबंटित किए गए।

कार्यक्रम एवं परियोजनाएं

इस दौरान (1 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2024) 44 नई परियोजनाएं मंजूर की गई, जिनकी कुल लागत 22,463.86 करोड़ रूपये थी। 31 मार्च, 2025 तक डीआरडीओ के पास 1,20,459 करोड़ रूपये के 360 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसमें सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) से मंजूर 11 बड़े प्रोग्राम शामिल हैं, जिनकी लागत 78,928 करोड़ रूपये है।

उत्पादन आदेश

डीआरडीओ द्वारा विकसित ऐसी प्रणालियां, जिन्हें भारतीय कंपनियों ने बनाया है और जिन्हें सशस्त्र सेनाओं के तीनों विंग्स और पैरामिलिट्री फोर्सेज़ में शामिल करने की मंजूरी मिली है, उनकी उत्पादन लागत आज लगभग 5.56 लाख करोड़ रूपये

है। साल 2024 के दौरान, रक्षा प्रापण बोर्ड (डीपीबी) और रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने 1.10 लाख करोड़ रूपये मूल्य के 16 डीआरडीओ विकसित प्रणालियों को शामिल करने के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) दी गई।

इंडक्शन अधीन/प्रयोक्ताओं को सौंपी गई प्रमुख प्रणालियां

आकाश हथियार प्रणाली

आकाश सतह से हवा में मार करने वाली पहली अत्याधुनिक स्वदेशी मिसाइल प्रणाली है जो लगभग एक दशक से सशस्त्र सेनाओं के पास है। यह डीआरडीओ की पहली सामरिक मिसाइल प्रणाली है जिसे सफलतापूर्वक विकसित और निर्मित कर भारतीय वायु सेना और भारतीय सेना को सौंपे गया है। अभी, आकाश को भारतीय वायु सेना और भारतीय थल सेना ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कॉम्बैट क्षेत्र में तैनात किया है। इस वर्ष, कई स्क्वाड्रन भारतीय वायु सेना को सौंपे गए हैं और ऑपरेशनल हैं। रक्षा निजी क्षेत्र उपक्रम (डीपीएसयू) ने मित्र विदेशी राष्ट्रों (एफएफसी) के प्रतिनिधियों को भी प्रशिक्षण दिया है और पहली बैटरी/फायरिंग यूनिट को बीईएल ने एफएफसी को निर्यात के लिए रवाना किया।

एमआरएसएएम (सेना और वायु सेना)

डीआरडीओ, भारतीय वायु सेना और भारतीय सेना वायु रक्षा (एएडी) के लिए मेसर्स इज़राइल एयरोस्पेस उद्योग (आईएआई), इज़राइल के साथ मिलकर मध्यम रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एमआरएसएएम) हथियार प्रणाली का विकास कर रहा है। एमआरएसएएम एडवांस्ड, ऑल वेदर, 360°, मोबाइल, भूमि आधारित, मध्यम रेंज वायु रक्षा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जो दुश्मन के विमान और निर्देशित हथियारों के हवाई हमलों से हमारे अपने इलाकों और ग्राउंड फोर्सेस की सुरक्षा करते हैं। दो भिन्न अंतिम प्रयोक्ताओं (सेना और वायु सेना) के लिए दो विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। डीआरडीओ एवं आईएआई के बीच यह संयुक्त विकास कार्यक्रम सिर्फ विकास के लिए ही नहीं है, बल्कि इससे जुड़े अंतिम प्रयोक्ताओं के लिए मध्यम रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एमआरएसएएम) के उत्पादन के लिए भी है। साल 2024 में एमआरएसएएम (भारतीय वायु सेना) और एमआरएसएएम (भारतीय सेना) की कई फायरिंग यूनिट प्रयोक्ता को सौंपी गई हैं।

नेत्रा

डीआरडीओ ने भारतीय वुया सेना के लिए सभी मिशन प्रणाली के साथ एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग एंड कंट्रोल (एईडब्ल्यूएंडसी) एयरक्राफ्ट प्रणाली की सुपुर्दगी हेतु एक परियोजना शुरू की है। एईडब्ल्यू एंड सी प्रणाली में एयरक्राफ्ट पर लगे सेंसर होते हैं, जो हवा में मौजूद और समुद्र की सतह पर मौजूद लक्ष्य तथा प्रतीकूल उत्सर्जनों का पता लगाने और पहले ही उनकी चेतावनी देने के लिए होते हैं। यह प्रणाली विमान में मौजूद नियंत्रकों के साथ–साथ ग्राउंड स्टेशन को भी पूरी जानकारी देती है। इसका उद्देश्य तीन एईडब्ल्यूएंडसी प्रणाली, एक इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप और दो ऑपरेशनल एईडब्ल्यूएंडसी प्रणाली विकसित करना था, जिसमें ईएमबी–145 एईडब्ल्यूएंडसी प्लेटफॉर्म पर मिशन एवियोनिक्स प्रणाली इंस्टॉल और एकीकृत किए हो। ऊपर दिए गए अधिदेश के अनुसार, तीनों विमानों में मिशन प्रणाली एकीकृत कर दी गई है और सिस्टम भारतीय वायु सेना (आईएएफ) को सौंप दिए गए हैं।

एनक्लोज्ड वातावरण में सर्च और रिपोर्ट ऑपरेशन के लिए स्वायत्त यूएवी

यह परियोजना स्वायत्त नेविगेशन स्टैक, ऑन बोर्ड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉड्यूल और फ्लाइट कंट्रोल फर्मवेयर के साथ

एकीकृत लोकलाइज्ड फॉल बैक मैकेनिज्म के साथ एकीकृत इनडोर यूएवी के विकास पर केंद्रित है। ऑटोनॉमस नेविगेशन स्टैक के साथ इंटीग्रेशन में 3 डी मैपिंग, एक्सप्लोरेशन एल्गोरिदम, एआई/एमएल इंजन और लोकलाइजेशन शामिल हैं। परियोजना की सफलता सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्विलांस, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन, एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग के साथ–साथ खतरनाक एनवायरनमेंट एक्सप्लोरेशन सहित कई एप्लीकेशन के लिए रास्ते खोलती है, जो मानवरहित एरियल सिस्टम की प्रौद्योगिकीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह परियोजना 18 अक्टूबर, 2024 को माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में सफलतापूर्वक पूरी हुई और प्रयोक्ता को सौंपी गयी।

मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम (एमसीपीएस)

एमसीपीएस, स्पेशल फोर्स के लिए कॉम्बैट लोड के साथ ऑपरेशन के निर्धारित क्षेत्र में घुसने का एक माध्यम है। एमसीपीएस पैराट्रूपर्स को एयरक्राफ्ट से कूदने और पहले से निर्धारित ऊंचाई पर अपने पैराशूट लगाने, नेविगेट करने और सुरक्षित रूप से लैंड करने देता है। इसे मानकीकरण निदेशालय द्वारा जारी जॉइंट स्टाफ़ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट (जेएसक्यूआर) के अनुसार डिज़ाइन और विकसित किया गया है। भारतीय सशस्त्र सेना को कॉम्बैट फ्री फ़ॉल ऑपरेशन्स के लिए मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम की ज़रूरत होती है। सेमिलाक से सफल क्वालिफ़िकेशन और सर्टिफ़िकेशन के बाद, एमसीपीएस को पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल (पीटीएस) आगरा को प्रस्तावित किया गया, जो कॉम्बैट फ्री फ़ॉल पैराशूट प्रणाली के मुख्य और सर्वाधिक सक्षम प्रयोक्ताओं में से एक है। पीटीएस, आगरा ने सभी तकनीकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए 110 से ज़्यादा जंप किए और अब सेना में शामिल करने के लिए इसकी सिफारिश की गयी है।

मल्टी–मोड हैंड ग्रेनेड (एमएमएचजी)

मल्टी–मोड हैंड ग्रेनेड (एएमएचजी) को पॉजिटिव सेफ्टी और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के साथ डिज़ाइन किया गया है। एमएमएचजी का प्रयोग ऑफेंसिव और डिफेंसिव मोड में किया जा सकता है। डिफेंस पीएसयू द्वारा उत्पादन के लिए कंट्रोलर ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस (आर्ममेंट), पुणे के साथ एमएमएचजी के दस्तावेजीकरण का काम पूरा हो गया है। एएमएचजी के उत्पादन के लिए उद्योग के साथ एलएटीओटी पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम (एटीएजीएस)

एटीएजीएस (155एमएम/52 कैलिबर) को इन–सर्विस एक्सटेंडेड रेंज फुल बोर–बेस्ड ब्लीड (ईआरएफबी–बीबी) शेल का इस्तेमाल करके ज़्यादा रेंज और ज़ोन–7 में बाई–मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम (बीएमसीएस) का प्रयोग करके कम रेंज के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ऑटो–फ्रेटेज्ड बैरल, डबल बैफल टाइप मज़ल ब्रेक और हाइड्रो–न्यूमैटिक टाइप रिकॉइल सिस्टम के साथ एकीकृत है। यह गन लेइंग के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ड्राइव और एम्युनिशन हैंडलिंग सिस्टम (एएचएस) से लैस है ताकि बहुत खराब मौसम में भी परिचालित हो सके और यह एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम (एफसीएस) से लैस है जिसमें आईएनएस आधारित ऑटोमैटिक गन अलाइनमेंट एंड पोजिशनिंग सिस्टम (एजीएपीएस), मज़ल वेलोसिटी रेडार (एमवीआर) और लेइंग के लिए ऑनलाइन कैलकुलेशन करने हेतु बैलिस्टिक्स कंप्यूटर शामिल हैं। गन ने सभी प्रयोक्ता परीक्षण सफलतापूर्वक पास कर लिए हैं जिसके लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) से एओएन मिल गया है।

मशीन पिस्टल

मशीन पिस्टल (9X19एमएम) एक सेल्फ–लोडिंग पिस्टल है जो सिंगल शॉट एवं पूर्णतः ऑटोमैटिक फायर कर सकती है।

भारत में बना यह पिस्टल इन–सर्विस 9एमएम पैराबेलम राउंड फायर करती है। यह हथियार कॉम्पैक्ट है और पिस्टल तथा सबमशीन गन (एसएमजी) दोनों का काम कर सकता है। यह हथियार कॉम्पैक्ट, मजबूत और विश्वसनीय है तथा लंबी बैरल और कोलैप्सिबल बट स्टॉक या आर्म ब्रेस होने की वजह से सामान्य पिस्टल की तुलना में ज़्यादा सटीक और असरदार रेंज देता है। इस हथियार के प्रयोक्ता परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। विस्तृत पूर्व प्रेषण जांच और संयुक्त प्राप्ति जांच के बाद मशीन पिस्टल को सफलतापूर्वक शामिल किया गया है। दो उद्योगों को विकास उत्पादन भागीदार (डीसीपीपी) घोषित किया गया है।

असॉल्ट राइफल

असॉल्ट राइफल (7.62x51एमएम) एक हल्का, कॉम्पैक्ट और प्रभावी हथियार है जिसका इस्तेमाल निकट कॉम्बैट काउंटर इंसर्जेंसी/काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में किया जाता है। असॉल्ट राइफल का एमएचए परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और विकास एवं उत्पादन भागीदार (डीसीपीपी) का चुनाव किया जा चुका है। भारतीय सेना के लिए फील्ड और उच्च तुंगता क्षेत्र में प्रयोक्ता परीक्षण किया गया। सेनाओं में असॉल्ट राइफल को शामिल करने और उद्योग के साथ टीओटी का काम चल रहा है।

गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम

पीएसक्यूआर के अनुसार अपग्रेडेड लॉन्चर सिस्टम के साथ गाइडेड पिनाका रॉकेट का डिजाइन और विकास सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। स्टेज–I, स्टेज–II एवं स्टेज III परीक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, सभी पीएसक्यूआर पैरामीटर (विस्तार, सटीकता, निरंतरता, मल्टीपल एंगेजमेंट, फायर दर) सफलतापूर्वक पूरे हो गए। तीन चरणों में पूर्व अधिप्रमाणन परीक्षण (पीवीटी) सफलतापूर्वक पूरे हो गए और परीक्षण टीम ने गाइडेड पिनाका रॉकेट को सेना में शामिल करने की सिफारिश की है। अपग्रेडेड इन–सर्विस लॉन्चर का एमईटी चल रहा है।

माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट मार्क–II (एमएफएमई मार्क–II)

डीआरडीओ ने न्यूनतम मानवीय दखल के साथ पिकेट को जमीन पर स्वचालित ड्राइविंग के लिए एडवांस्ड माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट मार्क–II बनाया है। यह एक बार में माइन फील्ड की एक बड़ी दूरी को मार्क कर सकता है। इस प्रणाली ने जीएसक्यूआर परीक्षण पूरे कर लिए हैं और रक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में उत्पादन एजेंसी के साथ संविदा अनुबंध किया है।

अनएक्सप्लोडेड ऑर्डनेंस हैंडलिंग रोबोट (यूएक्सओआर)

अनएक्सप्लोडेड ऑर्डनेंस हैंडलिंग रोबोट (यूएक्सओआर) रिमोट से चलने वाला एक प्लेटफॉर्म है जो दूर से अविस्फोटित गोले–बारूदों को हैंडल और डिफ्यूज कर सकता है। यूएक्सओआर सिस्टम के तीन प्रोटोटाइप बनाए गए हैं। हर प्रणाली में स्किड स्टीयर मोबाइल प्लेटफॉर्म और वाहन आधारित मास्टर कंट्रोल स्टेशन सह वाहक गाड़ी शामिल है। प्रणाली के तकनीकी परीक्षण और मूल्यांकन हो चुके हैं। उत्पादन का काम चल रहा है और 2024 में भारतीय वायु सेना को कुछ सेट सुपुर्द कर दिए गए हैं।

लेजर ऑर्डनेंस डिस्पोजल सिस्टम (एलओआरडीएस–एन)

डीआरडीओ ने अत्याधुनिक प्रणाली एलओआरडीएस–एन का विकास किया है जो भारत के स्वदेशी रक्षा तकनीकी विकास में एक बड़ा कदम है। एलओआरडीएस–एन प्रणाली का प्रयोग बिना फटे और लाइफ एक्सपायर हो चुके एम्यूनिशन को सुरक्षित, प्रभावी और जल्दी डिस्पोज करने के लिए किया जा सकता है। इसकी लेजर आधारित प्रौद्योगिकी, कार्मिकों के लिए जोखिम को कम करती है और संभावित हानिकारक पदार्थ को अधिक सटीकता से निष्क्रिय करने में सहायता करती है। डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना को वाहन पर लगा एलओआरडीएस–एन सुपुर्द किया है।

डिजिटल रेडार वार्निंग रिसीवर (डीआर118)

डीआर118 एक अत्याधुनिक डिजिटल रेडार वार्निंग रिसीवर (आरडब्ल्यूआर) है जो इन–हाउस और उद्योग साझेदार के साथ विकसित की गई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर (ईडब्ल्यू) तकनीक और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करेगा। यह प्रणाली एनालॉग आरडब्ल्यूआर की सीमाओं को दूर करने और प्रणाली की विशेषताओं को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन और विकसित किया गया है। यह प्रणाली अभी डीपीएसयू द्वारा उत्पादन में है और ये प्रणाली फाइटर स्क्वाड्रन के अपग्रेड को पूरा करने के लिए बनाए जा रहे हैं।

कॉम्पैक्ट ट्रांस–होराइजन कम्युनिकेशन सिस्टम (सीटीसीएस)

डीआरडीओ ने सी–बैंड मेन–पोर्टेबल ट्रोपोस्कैटर कम्युनिकेशन सिस्टम डिज़ाइन और विकसित किया है जो बियोंड लाइन ऑफ़ साइट (बीएलओएस) कम्युनिकेशन देता है। यह सिस्टम भारतीय सेना की ज़रूरत के आधार पर देश में ही विकसित किया गया है। यह कठिन पहाड़ी इलाकों में हाई डेटा रेट, लो लेटेंसी डिजिटल कम्युनिकेशन लिंक देता है। भारतीय सेना ने इंडक्शन के लिए क्यूआर तैयार किया है और उद्योग उत्पादन के लिए टीओटी हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में हैं।

शक्ति प्रणाली

शक्ति सिस्टम कैपिटल चिप्स पर इंस्टॉलेशन के लिए देश में बनी एक मॉडर्न एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (ईडब्ल्यू) प्रणाली है। इस प्रणाली में इंटरसेप्टेड एमिटर्स के इंटर और इंट्रा पल्स विश्लेषण और इलेक्ट्रॉनिक अटैक (ईए) सेगमेंट के लिए एक एकीकृत रेडार फिंगर प्रिंटिंग प्रणाली (आरएफपीएस) के साथ ईएसएम सेगमेंट है। भारतीय नौसेना ने मेसर्स बीईएल, हैदराबाद को उत्पादन आदेश दिए हैं और उनमें से कुछ वर्ष 2024 में सौंपे गए हैं।

नयन प्रणाली

नयन प्रणाली कैपिटल चिप्स पर इंस्टॉलेशन के लिए एक स्वदेशी सीओएमआईएनटी प्रणाली है। इसमें स्कैन डीएफ (एसडीएफ) सिस्टम और मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस रिसीवर (एमआरएक्स) शामिल हैं। यह नौसेना जहाजों के लिए डिज़ाइन और विकसित किया गया पहला स्वदेशी सीओएमआईएनटी प्रणाली है। भारतीय नौसेना ने डीपीएसयू को उत्पादन आदेश दिया है और उनमें से कुछ वर्ष 2024 में सौंपे गए हैं।

लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रेडार (एलएलटीआर) अश्विनी

लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रेडार (एलएलटीआर) अश्विनी एक भूमि आधारित, व्हीकल माउंटेड, 4डी एक्टिव फेज़्ड ऐरे रेडार है जो शत्रु इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (ईडब्ल्यू) ऑपरेशनल वातावरण में हवाई लक्ष्य का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने हेतु एयर स्पेस सर्विलांस के लिए है। रेडार को लोकल ऑपरेटर वर्क स्टेशन (ओडब्ल्यूएस) से एक कुशल मानव–मशीन इंटरफ़ेस के ज़रिए पूरी तरह से प्रोग्राम किया जा सकता है। इसका उत्पादन आदेश अंतिम चरण में है।

हल माउंटेड सोनार एडवांस्ड (एचयूएमएसए) अपग्रेड (यूजी) लिमिटेड सीरीज़ प्रोडक्शन (एलएसपी)

एचयूएमएसए अपग्रेड परियोजना, पहले से शामिल सोनार एचयूएमएसए के लिए एक अपग्रेड प्रोग्राम है। यह सोनार वर्ष 2000 से जहाजों पर लगाया जा रहा है और इसके तीन मुख्य घटक हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के पुराने हो जाने और रखरखाव तथा सपोर्ट की समस्याओं के कारण से भारतीय नौसेना को अपग्रेड की ज़रूरत पड़ी। हाई एवं लो फ्रीक्वेंसी दोनों संस्करणों के लिए सभी प्रणाली के सी एक्सेप्टेंस ट्रायलस (एसएटी) पूरे हो चुके हैं।

ड्रोन–डिटेक्ट, डिटर एंड डिस्ट्रॉय (डी4) प्रणाली

डी4 प्रणाली डीआरडीओ की चार प्रयोगशालाओं के संयुक्त प्रयासों से बनाई गई प्रणाली है। यह कॉम्प्लिमेंट्री प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके छोटे हाइब्रिड मानवरहित एरियल व्हीकल (यूएवी), माइक्रो और नैनो यूएवी समेत विभिन्न तरह के ड्रोन का पता लगा सकता है, उनकी पहचान कर सकता है और उन्हें बेअसर कर सकता है। यह रेडार कम दूरी पर माइक्रो और नैनो ड्रोन का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए एक सेमी–डिस्ट्रिब्यूटेड एक्टिव फेज़्ड ऐरे रेडार है। प्रयोक्ताओं को कई बार प्रदर्शन के बाद, डीपीएसयू को उत्पादन आदेश दिए गए हैं। इस प्रणाली को सुरक्षा व्यवस्था के तहत गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस 2024 के दौरान बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए तैनात किया गया था।

टॉरपीडो डिफेंस सिस्टम के लिए प्रौद्योगिकी (टीटीडीएस)

परियोजना टीटीडीएस को भारतीय नौसेना के लिए भविष्य के टॉरपीडो रक्षा प्रणाली के लिए ज़रूरी उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास के लिए शुरू किया गया था। टीटीडीएस के तहत विकास की गई कुछ तकनीकों का प्रयोग उन्नत टॉरपीडो रक्षा प्रणाली 'MAAREECH' में प्रदर्शन सुधारने और प्रौद्योगिकी के पुराने होने के प्रबंधन हेतु किया गया है। परियोजना कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न प्रौद्योगिकी का विकास और परीक्षण पूरा किया गया। डीपीएसयू द्वारा उत्पादन प्रणाली के फैक्ट्री एक्सेप्टेंस परीक्षण (एफएटी) पर काम किया जा रहा है।

माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेंट चैफ टेक्नोलॉजी

भारतीय नौसेना (आईएन) से मिले क्यूआर के आधार पर, मीडियम रेंज–माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेंट चैफ रॉकेट (एमआर–एमओ सीआर) का डिज़ाइन और प्रमाणन पूरा हो गया है। एमओसी क्लाउड के दृश्य विस्तार मापन के लिए फेज़–I परीक्षण डीआरडीओ टीम ने भारतीय नौसेना पोत (आईएनएस) प्लेटफॉर्म से भारतीय नौसेना (आईएन) के साथ मिलकर सफलतापूर्वक किए हैं। एमआर–एमओ सीआर के फेज़–I परीक्षण भारतीय नौसेना के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सफलतापूर्वक किए गए हैं। एमआर–एमओ सीआर को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है।

गामा रेडिएशन एरियल सर्विलांस प्रणाली (जीआरएएस)

यह प्रणाली विभिन्न तुंगता पर एरियल गामा रेडिएशन मॉनिटरिंग करने में सक्षम है और गामा रेडिएशन स्तर की एक बड़ी रेंज को माप सकता है। जीआरएएस प्रणाली को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है और उद्योगों के डीसीपीपी नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है।

7.62x54 आर एपीआई के विरुद्ध बुलेट प्रूफ जैकेट (बीपीजे)

डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है जो बीआईएस 17051–2018 के लेवल 6 के अनुसार 7.62x54 आर एपीआई एम्युनिशन से सुरक्षा देता है। यह जैकेट नए डिज़ाइन अप्रोच पर आधारित है जिसमें नए पदार्थ के साथ–साथ नई प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है। बीपीजे का फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल (एचएपी) आईसीडब्ल्यू (के संयोजन में) और स्टैंडअलोन डिज़ाइन दोनों में 7.62x54 आर एपीआई (स्नाइपर राउंड) के कई हिट को हरा देता है। यह एर्गोनॉमिक रूप से डिज़ाइन किया गया फ्रंट एचएपी पॉलीमर बैकिंग के साथ मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट से बना है जो प्रचालन के दौरान पहनने की सुविधा और आराम को बढ़ाता है। दो उद्योगों को टीओटी दिए गए हैं।

एडवांस्ड रायट प्रोटेक्शन सूट (एआरपीएस)

एडवांस्ड रायट प्रोटेक्शन सूट एक मॉड्यूलर और ज़बरदस्त प्रभाव प्रतिरोधी फुल बॉडी सूट है जो कम प्रभावी लड़ाइयों के दौरान फोर्स को पूर्ण सुरक्षा देता है। यह दंगे की स्थिति में पत्थर या किसी दूसरी सख्त चीज़ से लगने वाले प्रभाव/शॉक लोड को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल 9x19 mm गोलाबारूद से छाती, कंधे, पीठ, जांघ, कमर और कूल्हे को बचाने के लिए भी किया जाता है।

मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर (एमएएल)

भारतीय नौसेना ने मौजूदा एमएएल के नवीकरण और नए एमएएल तथा रिकवरी व्हीकल की आपूर्ति के लिए मेसर्स ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड (बीएपीएल) के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए है। एमएएल का नवीकरण पूरा हो गया है और एक नये एमएएल दस्तावेज के सेट के साथ सुपुर्द कर दिया गया है और भारतीय नौसेना (आईएन) क्रू को प्रशिक्षण दिया गया है।

एयर क्रू हेलमेट

डीआरडीओ ने भारतीय वायु सेना की आवश्यकताओं के अनुसार एकीकृत लाइट वेट एयरक्रू हेलमेट और प्रेशर ब्रीदिंग ऑक्सीजन मास्क की रूसी और यूरो श्रेणी विकसित की है। एसयू–30 हेलमेट पॉलिकार्बोनेट से बनी ट्विन वाइज़र युक्त है, आंतरिक रूप से सिकुड़ जाने योग्य है, जिसमें हेलमेट माउंटेड साइटिंग डिस्प्ले (एचएमएसडी) लगाने का इंतज़ाम है। यह टक्कर और छेद से बचाता है। हेलमेट–मास्क असेंबली ने छह विभिन्न प्रोफ़ाइल में डीजीए फ्रांस में विंडब्लास्ट परीक्षण स्थिति (600 KEAS) का सामना किया है। यह हेलमेट शोर की तीव्रता को कम करने की खासियतों को पूरा करता है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस/इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्पैटिबिलिटी (ईएमआई/ ईएमसी) वाला प्रीएम्प्लीफायर लगा है। इसका प्रयोग रूसी लड़ाकू विमान चलाने वाले एयरक्रू द्वारा किया जाएगा। एसयू–30 एयरक्रू हेलमेट और प्रेशर ब्रीदिंग ऑक्सीजन मास्क के लिए प्रचालन क्लीयरेंस प्राप्त हो गया है और भारतीय वायु सेना द्वारा फील्ड यूनिट्स में आइटम की पुनः पुष्टि हेतु इसकी सीमित मात्रा में खरीद की जा रही है।

ऑटोमैटिक केमिकल एजेंट डिटेक्टर एवं अलार्म (एसीएडीए)

ऑटोमैटिक केमिकल एजेंट डिटेक्टर एवं अलार्म सिस्टम को रासायनिक वॉरफेयर एजेंट्स (सीडब्ल्यू) और प्रोग्राम किए गए टॉक्सिक इंडस्ट्रियल केमिकल्स (टीआईसी) का पता लगाने के लिए बनाया गया है। यह आयन मोबिलिटी स्पेक्ट्रोमेट्री (आईएमएस) के सिद्धांत पर कार्य करता है। एसीएडीए में दो अति संवेदनशील सेल होते हैं जो बायोलॉजिकल एजेंट्स के साथ–साथ टीआईसी का लगातार पता लगाते है और एक साथ मॉनिटरिंग करते हैं तथा श्रव्य एवं दृश्य अलार्म देते हैं। एसीएडीए एक कॉम्पैक्ट, मज़बूत फिक्स्ड पॉइंट मैन पोर्टेबल सीडब्ल्यू डिटेक्टर है। इसे वाहन, जहाज़, इमारत और शेल्टर पर लगाया जा सकता है। इसे सीडब्ल्यूए के बड़े क्षेत्र में निगरानी के लिए नेटवर्क किया जा सकता है। डिटेक्टर में सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन पर डेटा पाने के लिए रिमोट अलार्म यूनिट है। आरएफपी दे दिया गया है और 2024 में लागत समझौता वार्ता पूर्ण हो गई है।

कदम

कदम एक पॉली–सेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी जॉइंट है जो ट्रांस–फेमोरल विच्छेदन वाले लोगों के लिए है और यह आईएसओ 10328 मापदंडों का पालन करने वाला एक स्वदेशी और सस्ता घुटने के ऊपर का कृत्रिम अंग है। इसे सोसाइटी ऑफ बायोमेडिकल जॉइंट (एसबीएमटी–डीआरडीओ द्वारा समन्वयित) ने आईआईटी मद्रास के साथ विकसित किया है। उद्योग के लिए टीओटी पूरा हो गया है और उत्पाद को 3 दिसंबर 2024 को भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था।

साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग टूल (PsySHOT)

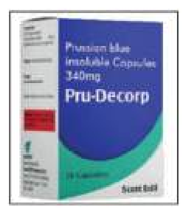

डीआरडीओ ने 3 अक्टूबर, 2024 को इन्फैंट्री स्कूल, महू को एक साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग टूल (PsySHOT) सौंपा है। PsySHOT इन्फैंट्री में खास भूमिका के लिए उचित फिट की पहचान करने में मदद करेगा। इसे विषय विशेषज्ञों, फील्ड परीक्षण और इन्फैंट्री स्कूल, महू और सेना ट्रेनिंग कमांड (एआरटीआरएएस) के सपोर्ट से ऑन–साइट मूल्यांकन प्रक्रियाओं की सहभागिता से तैयार किया गया है और इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया गया है।

प्रू–डेकॉर्प–टीएम और प्रू–डेकॉर्प–एमजी

प्रू–डेकॉर्प–टीएम एक 500 मि ग्रा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है जिसमें गहरे नीले रंग का पाउडर होता है जिसमें प्रशियन ब्लू अघुलनशील सहायक होते हैं। यह कैप्सूल परमाणु आपातकाल की स्थिति में रेडियोएक्टिव सीएस/टीआई के लिए एक एंटीडोट है। प्रू–डेकॉर्प–एमजी एक 1000 मिग्रा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है जिसमें प्रशियन ब्लू अघुलनशील और बाइंडिंग प्रभावकारिता बढ़ाने वाले एजेंट्स के साथ–साथ फार्मास्युटिकली स्वीकार्य सहायक भी होता है। प्रू–डेकॉर्प–एमजी एक कैप्सूल है जिसे रेस्क्यू रेस्पॉन्डर्स के लिए बनाया गया है। यह रेस्क्यू रेस्पॉन्डर्स या ऐसे ज़ोन में जाने वाले लोगों के लिए एक बार इस्तेमाल होने वाला कैप्सूल है, जिसके बारे में पता है या आशंका है कि वह सीज़ियम/ टाइटेनियम सीएस/टीआई के रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स से संदूषित हुआ है। इस दवा को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइज़ेशन (सीडीएससीओ) ने मंजूरी दे दी है और सर्विसेज़ ने जून 2024 में प्रू–डेकॉर्प–टीएम और प्रू–डेकॉर्प–एमजी को शामिल करना शुरू कर दिया है।

सेना वायु रक्षा (एडी) डिप्लॉयमेंट सिमुलेशन सिस्टम (ए2डी2एस2)

सेना एडी डिप्लॉयमेंट सिमुलेशन सिस्टम दुश्मन के हवाई खतरों के विरूद्ध ग्राउंड बेस्ड वायु रक्षा हथियार प्रणाली (जीबीएडीडब्ल्यूएस) की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। सिस्टम का 05वां संस्करण बेहतर कार्यक्षमताओं जैसे रेडार सिस्टम की प्रभावशाली तैनाती, ऑटो एडी लेआउट, जीबीएडीडब्ल्यूएस का प्रभावी कवरेज विश्लेषण और एकीकृत 3डी विज़ुअलाइज़ेशन के साथ विकसित किया गया है, इसे अक्टूबर 2024 के दौरान भारतीय सेना की संचालन इकाइयों को सौंप दिया गया है और इसे चालू कर दिया गया है।

एयरस्पेस मैनेजमेंट (एएसएम) सॉफ्टवेयर

एयरस्पेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टैक्टिकल बैटलफ़ील्ड एरिया (टीबीए) में कोर एयर स्पेस संघर्षों का पता लगाने, पहचान करने और समाधान करने में प्रयोक्ताओं की सहायता करता है। डीआरडीओ ने कोर एयरस्पेस कंट्रोल सेंटर (सीएसीसी) सॉफ्टवेयर को उनकी सक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन और विकसित किया है। एएसएम–सीएसीसी सॉफ्टवेयर को प्रयोक्ता साइट पर नवंबर 2024 में स्थापित किया गया है।

सिक्योर स्टोरेज मीडिया सॉल्यूशंस

सिक्योर स्टोरेज मीडिया डिवाइस विशेष हार्डवेयर हैं जिन्हें अनधिकृत पहुंच, छेड़छाड़ और डेटा उल्लंघनों के विरूद्ध मजबूत सुरक्षा के साथ संवेदनशील डेटा संग्रहीत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पर्यावरण, संबंधी अत्यधिक भिन्नताएं, विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप और भौतिक हमलों के प्रति इसकी मजबूती ने क्रिप्टोग्राफ़िक कुंजी, मिशन–क्रिटिकल सॉफ्टवेयर, परिचालन डेटा लॉग और वास्तविक समय सामरिक जानकारी के भंडारण सहित व्यापक अनुप्रयोग क्षेत्रों में उपयोगिता दर्शायी है। उत्पादन एजेंसी सह औद्योगिक भागीदार को नामित किया गया है और वर्ष 2024 में इसे प्रयोक्ता को सफलतापूर्वक वितरित कर दिया गया है।

प्रयोक्ता मूल्यांकन के तहत प्रमुख सिस्टम

ध्रुवास्त्र – एयर–टू–सरफेस मिसाइल

ध्रुवास्त्र इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर (आईआईआर) सीकर के साथ लॉक–ऑन–बिफोर–लॉन्च (एलओबीएल) क्षमता वाली तीसरी पीढ़ी की हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी–टैंक गाइडेड मिसाइल (एटीजीएम) है, जिसे एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (एएलएच) पर एकीकरण के लिए डिज़ाइन किया गया है। 2024 के दौरान, आईआईआर सीकर मूल्यांकन के लिए उड़ान परीक्षण और रेगिस्तान में और उच्च तुंगता परीक्षणों में एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (एएलएच) मार्क–IV हेलीकॉप्टर से सीमित ऐनवेलेप में ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया।

क्विक रिएक्शन सरफेस–टू–एयर मिसाइल (क्यूआरएसएएम)

क्विक रिएक्शन सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (क्यूआरएसएएम) सिस्टम एक एडवांस्ड वायु रक्षा सिस्टम है, जिसे भारतीय सेना के लिए डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह स्थिर और गतिमान संपत्तियों के लिए सामरिक भूमि आधारित वायु रक्षा कवरेज प्रदान करता है। हथियार प्रणाली कई दिशाओं से आने वाले कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। वर्ष 2024 के दौरान, एक मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) के विरूद्ध मिसाइल का सफल परीक्षण भी प्रदर्शित किया गया, जिसमें लक्ष्य को पीछे हटने और पार करने वाली संयुक्त प्रोफ़ाइल के साथ नष्ट कर दिया गया। सेना और वायु सेना संयुक्त एओएन पर कार्रवाई कर रहे हैं और जून 2024 में जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट (जीएसक्यूआर) जारी कर दी गई है।

आकाश–न्यू जेनरेशन (एनजी)

एकेएएसएच–एनजी सरफेस–टू–एयर मिसाइल हथियार प्रणाली को डीआरडीओ द्वारा आईएएफ के लिए डिज़ाइन और विकसित किया जा रहा है ताकि फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, अनमैन्ड एरियल व्हीकल (यूएवी), एंटी–रेडिएशन मिसाइल (एआरएम) और सब–सोनिक क्रूज़ मिसाइलों के विरूद्ध वायु रक्षा कवर दिया जा सके। हथियार प्रणाली को एक साथ कई टारगेट पर निशाना लगाने और 360° कवरेज की क्षमता के साथ डिज़ाइन किया गया है। साल 2024 के दौरान, आईटीआर बालासोर में एकेएएसएच–एनजी गाइडेड मिशन का फ्लाइट टेस्ट किया गया। मिशन का लक्ष्य कम ऊंचाई पर इंटरसेप्ट करना था और इस मिशन के दौरान टारगेट को वॉरहेड के धमाके से सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया था।

लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम (एलआरजीबी)

लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम (एलआरजीबी) को दो अलग–अलग क्लास में प्री–फ्रैगमेंटेड ब्लास्ट (पीएफ) और पेनेट्रेशन कम ब्लास्ट (पीसीबी) वॉरहेड्स नामक अलग–अलग वॉरहेड्स के साथ विकसित किया जा रहा है। इस स्टोर को एसयू–30 एमकेआई के अलग–अलग स्टेशनों पर एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एसयू–30 मार्क1 प्लेटफॉर्म से पीसीबी वॉरहेड के साथ एयर लॉन्च्ड लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम – गौरव का कैरिज फ़्लाइट ट्रायल मई 2024 में सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। सभी टेस्ट पॉइंट कवर किए गए और उसके बाद गौरव–पीसीबी का रिलीज़ फ़्लाइट ट्रायल (आरएफटी) अगस्त 2024 में सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफ़ेंस सिस्टम (वीएसएचओआरएडीएस)

वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफ़ेंस सिस्टम (वीएसएचओआरएडीएस) समकालीन मैन पोर्टेबल एयर डिफ़ेंस सिस्टम (एमएएनपीएडीएस) जो तीसरी पीढ़ी की तुलना में चौथी पीढ़ी का सिस्टम है। यह देश में बनाया गया वीएसएचओआरएडीएस हथियार तकनीकी रूप से एमएएनपीएडीएस से बेहतर है क्योंकि इसमें स्टेट ऑफ़ आर्ट अनकूल्ड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल होता है। साल 2024 के दौरान, अक्टूबर 2024 में इसका राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज (पीएफएफआर) में सफलतापूर्वक फ्लाइट ट्रायल किया गया।

इलेक्ट्रो–ऑप्टिकल–स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार (ईओ–एसएएडब्ल्यू)

इलेक्ट्रो–ऑप्टिकल–स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार एक लंबी दूरी का, स्टैंड–ऑफ ऑटोनॉमस एयर टू सरफेस गाइडेड बम है जिसमें टर्मिनल गाइडेंस के लिए आईआईआर सीकर होता है। साल 2024 के दौरान, कूल्ड सीकर मार्क1 के साथ तीन ईओ–एसएएडब्ल्यू का उड़ान परीक्षण किया गया है और सीकर गाइडेंस सफलतापूर्वक दिखाया गया है। नए ऑनबोर्ड कूलिंग सिस्टम और अनकूल्ड सीकर के साथ कूल्ड सीकर मार्क2 का डिज़ाइन पूरा हो गया है।

रुद्रम–II

रुद्रम–II एक एयर टू सरफेस हथियार प्रणाली है, जिसे क्विक रिएक्शन टैक्टिकल स्ट्राइक की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। मिसाइल में एंटी–रेडिएशन रोल में एक पैसिव होमिंग हेड और मिलीमीटर वेव एक्टिव रेडार सीकर है और जमीनी हमले के लिए, मिसाइल इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल करती है। एयर टू सरफेस मिसाइल रुद्रम–II का 29 मई, 2024 को ओडिशा के तट पर एसयू–30 मार्क–I फाइटर एयरक्राफ्ट से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया था। उड़ान परीक्षण ने सभी ट्रायल लक्ष्य पूरे किए, जिससे प्रोपल्शन सिस्टम के साथ–साथ कंट्रोल और गाइडेंस एल्गोरिदम को प्रमाणित किया गया।

गगनयान के लिए पैराशूट सिस्टम

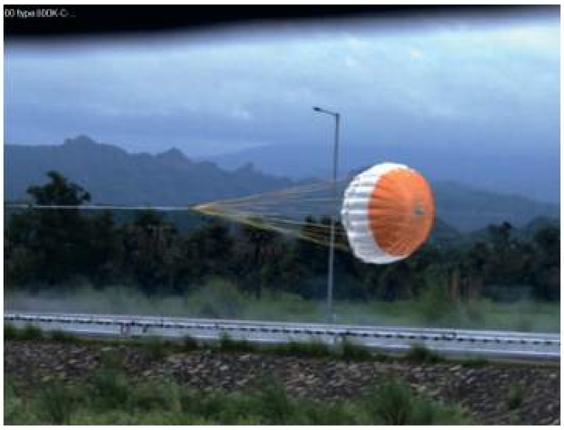

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) का गगनयान प्रोग्राम एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस एक्सपेरिमेंट करने के लिए लो अर्थ ऑर्बिट (एलईओ) में भेजने और मिशन पूरा होने के बाद उन्हें सुरक्षित रूप से धरती पर वापस लाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। री–एंट्री मॉड्यूल ले जाने वाले क्रू की धरती की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग एक पैराशूट सिस्टम से की जाएगी। 2024 के दौरान, ड्रोग पैराशूट के साथ रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज (आरटीआरएस) टेस्ट किए गए। ड्रोग और मेन पैराशूट के साथ एरियल ड्रॉप टेस्ट किए गए। टेक्सटाइल और पैराशूट के लिए एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बनाई गई।

सी–130 और सी–17 एयरक्राफ्ट के लिए हेवी ड्रॉप सिस्टम (एचडीएस)

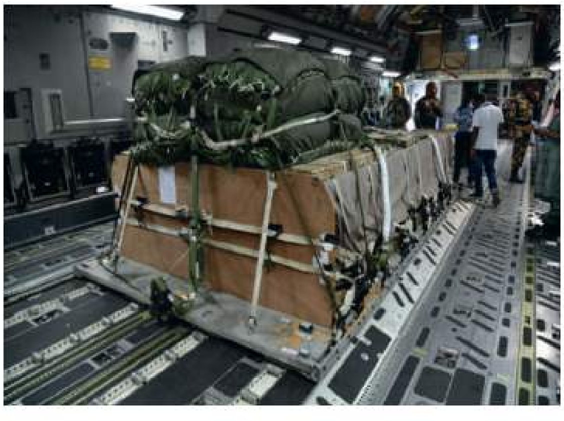

डीआरडीओ, सी–130 और सी–17 एयरक्राफ्ट के लिए एक एकीकृत हेवी ड्रॉप सिस्टम विकसित कर रहा है ताकि डिज़ाइन और सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण के हिसाब से इंडियन आर्म्ड फोर्सेज़ के पेलोड को पैराड्रॉप किया जा सके। इस सिस्टम में तीन हिस्से हैं, प्लेटफॉर्म सिस्टम, पैराशूट सिस्टम और हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लोडर। इसके विकास के दौरान अलग–अलग सब–सिस्टम डिज़ाइन किए गए, बनाए गए, टेस्ट किए गए, इंटीग्रेट किए गए और आखिर में उड़ान परीक्षण किए गए। 2024 के दौरान, तकनीकी परीक्षण पूरे हो गए हैं। सी17 एयरक्राफ्ट से यूज़र पेलोड पैराड्रॉप किया गया और प्रोजेक्ट के सभी उद्देश्य पूरे हो गए हैं।

आईएल–76 एयरक्राफ्ट के लिए हेवी ड्रॉप सिस्टम–16टी (एचडीएस–16टी)

आईएल–76 एयरक्राफ्ट से मिलिट्री स्टोर/इक्विपमेंट के पैरा ड्रॉप की स्वदेशी क्षमता बनाने के उद्देश्य से 16 टन हेवी ड्रॉप सिस्टम को विकसित किया गया है। प्रयोक्ताओं ने 29 अगस्त, 2024 को सफलतापूर्वक ट्रायल किए और प्रयोक्ता प्रमाणन परीक्षण भी सफलतापूर्वक पूरा किया गया। प्लेटफॉर्म और पैराशूट सिस्टम का मेंटेनेबिलिटी मूल्यांकन परीक्षण जनवरी 2024 में डीजीक्यूए ने पूरा किया। अनुमति के बाद बड़ी मात्रा में उत्पादन शुरू होगा।

विस्तारित रेंज पनडुब्बी रोधी रॉकेट (ईआरएएसआर)

डीआरडीओ ने ईआरएएसआर रॉकेट प्रणोदन प्रणाली के डिजाइन, विकास और निर्माण के उद्देश्य से 'ईआर–एएसआर' परियोजना शुरू की। ईआरएएसआर बैलिस्टिक–2 मोड (लंबी दूरी मोड) और बैलिस्टिक–1 मोड (छोटी दूरी मोड) में एक पनडुब्बी रोधी रॉकेट है। उच्च विस्फोटक, मोटर मिश्रित प्रणोदक और इग्नाइटर यौगिकों का टीओटी पूरा हो चुका है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए लाइसेंसिंग समझौते (एलएटीओटी) पर दोनों उत्पादन एजेंसियों (पीएएस) द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्ष 2024 के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक टाइम (ईटी) फ़्यूज़ कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए जहाज परीक्षण और गतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए। विभिन्न मोड में ईआरएएसआर रॉकेटों के रेंज प्रदर्शन, सटीकता और स्थिरता का आकलन करने के लिए बालासोर में रेंज टेबल वैलिडेशन परीक्षणों का सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया गया।

सीबीआरएन आरवी (टीआर) मार्क–II

डीआरडीओ सीबीआरएन टोही वाहन (ट्रैक्ड) मार्क–II विकसित कर रहा है, जो एक टोही प्लेटफार्म है जो सीबीआरएन एजेंटों से दूषित क्षेत्रों का पता लगाने, पहचान करने, निगरानी करने और चिह्नित करने में सक्षम है और इस जानकारी को तेजी से समर्थित संरचनाओं तक पहुंचाता है। वर्ष 2024 के दौरान डीपीएसयू के टीओटी पर हस्ताक्षर किये गये।

टी–72/टी–90 टैंकों के लिए ट्रॉल असेंबली

ट्रॉल असेंबली एक उपकरण है जिसे एक साथ चार ट्रॉल टैंकों का उपयोग करके बारूदी सुरंग से गुजर कर वाहन सुरक्षित लेन (वीएसएल) तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रणाली रोलर असेंबली, माइन प्लो और ईएमडी (इलेक्ट्रो मैग्नेटिक डिवाइस) का संयोजन है। माइनफील्ड में रोलर सेक्शन द्वारा माइन डेटोनेटर पर लगाए गए दबाव के परिणामस्वरूप पथ बनाया जाता है, जिसके बाद बिना विस्फोट वाले बारूदों को निकाला जाता है और फिर माइन प्लो द्वारा पथ से धकेल दिया जाता है। ईएमआई/ईएमसी परीक्षण फरवरी 2024 में और महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन (डीजीक्यूए) परीक्षण सितंबर 2024 में सफलतापूर्वक पूरे किए गए।

लेजर आयुध निपटान प्रणाली (एलओआरडीएस) मार्क–1

नौसेना स्टाफ गुणात्मक आवश्यकता (एनएसक्यूआर) के अनुसार गैर–विस्फोटित/अप्रचलित/अनुपयोगी नौसैनिक आयुध के अलग निपटान के लिए एलओआरडीएस का विकास किया जा रहा है। प्रारंभिक स्टाफ गुणात्मक आवश्यकता (पीएसक्यूआर) के अनुसार सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लेजर आयुध निपटान प्रणाली मार्क–1 (एलओआरडीएस मार्क–1) का विकास किया जा रहा है। सेना ने वर्ष 2021 में एलओआरडीएस मार्क–1 के अधिग्रहण के लिए सेवा प्रापण बोर्ड (एसपीबी) से एओएन प्रदान किया है। सिस्टम विकसित किया गया है और वर्ष 2024 में आंतरिक परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए। एक डीपीएसयू को उत्पादन एजेंसी (पीए) के रूप में नामित किया गया है।

ग्राउंड बेस्ड ईडब्ल्यू सिस्टम के जैमर एंटी यूएवी एंटिटी के लिए ईओ सेंसर सूट

जैमर एंटी यूएवी के लिए इलेक्ट्रो–ऑप्टिकल (ईओ) सूट में ईओ सेंसर होते हैं जिनमें माइक्रो वेव इंफ्रा रेड (एमडब्ल्यूआईआर) थर्मल इमेजर, कलर डे कैमरा, लेजर रेंज फाइंडर, डिजिटल इंटरफेस यूनिट और कंट्रोल यूनिट होते हैं। ईओ पेलोड को पहचाने गए टारगेट की ओर घुमाया जाता है ताकि उसे पहचाना जा सके और टारगेट को ट्रैक किया जा सके। ईओ ट्रैकर लगातार टारगेट को ट्रैक करता है और यह ट्रैक किए गए खतरे को सॉफ्ट–किल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेज़र्स (ईएसएम) / इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेज़र्स (ईसीएम) को ट्रैकिंग डेटा देता है। यूज़र्स द्वारा फील्ड मूल्यांकन परीक्षण अलग–अलग चरण में किए गए हैं और ईओ ने छोटे साइज़ के यूएवी के लिए ट्रैकिंग और रेंज की ज़रूरतों को पूरा किया है।

तटीय सर्विलांस रेडार (सीएसआर)

कोस्टल सर्विलांस रेडार (सीएसआर) एकीकृत तटीय सर्विलांस सिस्टम (आईसीएसएस) का एक हिस्सा है, जिसमें ज़मीन आधारित माइक्रोवेव रेडार, ईओ सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेज़र्स (ईएसएम) और ऑप्टिकल सेंसर की श्रृंखला होती है। तटीय सर्विलांस रेडार (सीएसआर) एक डुअल बैंड रेडार है जो समुद्र में छोटी नावों का पता लगा सकता है, जिनसे सुरक्षा को खतरा हो सकता है, और यह 24X7 निगरानी करता है। इसका इस्तेमाल इंडियन कोस्ट गार्ड/इंडियन नेवी छोटी नावों, डिंगी और दूसरे छोटे जहाजों की समुद्र के किनारे निगरानी के लिए करती है। सीएसआर के लिए टीओटी पर तीन उद्योग भागीदारों के साथ हस्ताक्षर किए गए थे। साल 2024 के दौरान, इंडियन नेवी के लिए एकीकृत अंडर–वाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्विलांस सिस्टम (आईयूएचडीएसएस) के लिए सीएसआर को प्रदर्शित किया गया है।

वायु रक्षा फायर कंट्रोल रेडार (एडीएफसीआर) अतुल्य

वायु रक्षा फायर कंट्रोल रेडार, एंटी–एयरक्राफ्ट गन के साथ मिलकर एक ग्राउंड बेस्ड वायु रक्षा सिस्टम बनाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य दिन और रात में और सभी मौसम में जैमिंग होने पर कम दूरी और बहुत कम दूरी पर सभी हवाई खतरों के विरूद्ध असरदार पॉइंट डिफेंस करना है। ओडीएफसीआर को सितंबर 2024 में एओएन दिया गया है।

सबमरीन फायर्ड डिकॉय (एसएफडी)

सबमरीन फायर्ड डिकॉय को किसी भी स्लीव वाली सबमरीन के सबमर्ज्ड सिग्नल इजेक्टर (एसएसई) से लॉन्च किया जा सकता है। यह किसी भी पैसिव टॉरपीडो के विरूद्ध अधिमान टारगेट के तौर पर काम करता है और एक्टिव टॉरपीडो के विरूद्ध रेंज गेट स्टीलर के तौर पर असरदार है। यह टॉरपीडो को ज्यादा गहराई तक ले जाने के लिए धीरे–धीरे डूबता भी है। अप्रैल 2024 में एसएफडी का चरण III परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया।

26 एमएम और 50 एमएम चैफ कार्ट्रिज

आईएएफ द्वारा दी गई गुणवत्ता आवश्यकताओं (क्यूआरएस) के आधार पर, डीआरडीओ ने एमआई–17 हेलीकॉप्टर और एसयू–30मार्क एयरक्राफ्ट के लिए क्रमशः 26 एमएम और 50 एमएम चैफ कार्ट्रिज के स्वदेशीकरण के लिए एक मिशन मोड प्रोजेक्ट शुरू किया। दो डीसीपीपी पार्टनर के साथ स्वदेशी 26 एमएम और 50 एमएम चैफ कार्ट्रिज का डिज़ाइन और विकास सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। डीआरडीओ ने आईएएफ को प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स के तौर पर स्वदेशी 50 एमएम चैफ कार्ट्रिज सफलतापूर्वक डिलीवर किए हैं। स्वदेशी 50 एमएम चैफ कार्ट्रिज के प्रयोक्ता परीक्षण आईएएफ द्वारा किए गए और संतोषजनक पाए गए।

इंडिविजुअल अंडर वॉटर ब्रीदिंग अपैरेटस (आईयूडब्ल्यूबीए)

आईयूडब्ल्यूबीए एक क्लोज्ड सर्किट बेस्ड इंडिविजुअल ब्रीदिंग अपैरेटस है, जो पानी के अंदर सांस लेने में मदद कर सकता है। यह सांस के साथ निकली कार्बन–डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रीजेनरेट करता है और दो तरह से सांस लेने में मदद करता है, यानी वातावरण से और उपकरण से। डीजीक्यूए ट्रायल और एमईटी मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं। साल 2024 के दौरान, तीन टीओटी धारक उद्योगों ने प्रयोक्ता मूल्यांकन योग्यता प्राप्त की है।

ऑग्मेंटेशन और रैपिड लॉजिस्टिक्स के लिए पैसिव एक्सो–स्केलेटन (पीईएआरएल)

डीआरडीओ ने पहनने लायक एक्सोस्केलेटन सिस्टम विकसित किए हैं जो सैनिक की वज़न उठाने की क्षमता को बढ़ाते हैं और सह्यता को बढ़ाते हैं। ये स्ट्रक्चर इंसान के साथ जुड़े होते हैं और सांमजस्य बनाकर चलते हैं और किसी व्यक्ति द्वारा उठाए गए वज़न को सीधे ज़मीन पर ट्रांसफर करते हैं। इसका उद्देश्य है कि तेज़ स्पीड से या ज़्यादा दूरी तक समतल और ऊबड़–खाबड़ ज़मीन पर चलते समय रीढ़ की हड्डी और लंबो–सैक्रल जोड़ों पर पड़ने वाले लोड को कम किया जा सके, जिससे मस्कुलोस्केलेटल चोट का खतरा कम हो सके। 2024 के दौरान, आईटीबीएफ, सीआरपीएफ और भारतीय सेना के साथ पैसिव एक्सो स्केलेटन के सफल परीक्षण अलग–अलग जगहों पर पूरे किए गए।

एनबीसी (न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल) रेस्पिरेटरी मास्क मार्क–II

डीआरडीओ ने सीबीआरएन दूषित एरिया में केमिकल वॉरफेयर एजेंट्स से सांस की सुरक्षा के लिए एनबीसी रेस्पिरेटरी मास्क मार्क II बनाया है। 10 साल की शेल्फ लाइफ के साथ, यह सही फिटिंग के लिए फाइव पॉइंट हार्नेस सिस्टम देता है जिसमें पीने के पानी की सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक वॉयस एन्हांसर, डुअल कैनिस्टर अटैचमेंट और 75% से ज़्यादा फील्ड विज़न के साथ ट्विन वाइज़र सिस्टम का प्रोविज़न है। इसे 750 ग्राम से कम वज़न के साथ तीन अलग–अलग साइज़ में बनाया गया है। 2024 के दौरान, प्रयोक्ता परीक्षण पूरे हो गए हैं और तीन फर्मों को टीओटी दिया गया है।

फिटमेंट/लीक टेस्टर (मार्क–II)

लीक टेस्टर एक उपकरण है जिसे सैनिकों को देने से पहले एनबीसी रेस्पिरेटरी मास्क के फिटमेंट को टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। टेस्टर में डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है जो 40 सेकंड के अंदर बताता है कि मास्क पास हुआ है या फेल। फेल होने पर, इसका कारण सक्शन फेल या फ्लो फेल भी सूचित करता है। प्रयोक्ता परीक्षण 2024 में पूरे हो गए हैं और तीन उद्योगों को टीओटी दिया गया है।

सीबीआरएन वॉटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम (डब्ल्यूपीएस) मार्क–II

डीआरडीओ ने सीबीआरएन (केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर) वॉटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम मार्क II बनाया है। इसका इस्तेमाल प्राकृतिक और मानवजनित आपदाओं, सीबीआरएन इमरजेंसी, युद्ध और आतंकवादी गतिविधियों के दौरान किया जाएगा। सीबीआरएन डब्ल्यूपीएस मार्क–II की एक इकाई के पीएसक्यूआर मूल्यांकन परीक्षण अक्टूबर 2024 में केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट के सिमुलेंट/सरोगेट के विरूद्ध किए गए और इसका परफॉर्मेंस संतोषजनक पाया गया और यह पीएसक्यूआर की सभी ज़रूरतों को पूरा करता है।

एक्स–बैंड जीएएन पावर एम्पलीफायर मोनोलिथिक माइक्रोवेव एकीकृत सर्किट (एमएमआईसी)

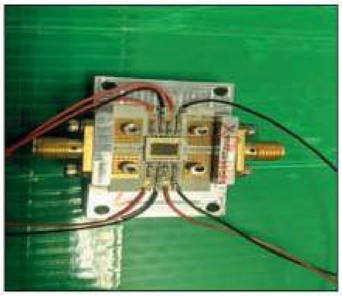

एक्स–बैंड पावर एम्पलीफायर को एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड ऐरे (एईएसए) रेडार के लिए डिज़ाइन और विकसित किया गया है, जिसकी पावर एडेड एफिशिएंसी पूरे बैंड पर 35% से बेहतर है। इन पावर एम्पलीफायरों को पैकेज किया गया है और अनुकूल परफॉर्मेंस दिखाने के लिए आरएफ को कैरेक्टराइज़ किया गया है। सिरेमिक क्वाड फ्लैट नो–लेड (क्यूएफएन) पैकेज में इस एम्पलीफायर को उत्पादन एजेंसी ने मार्च 2024 में परीक्षण के लिए सौंपा गया और इसका उत्पादन चल रहा है।

विकासात्मक परीक्षण चरण में मुख्य प्रणाली

प्रलय

प्रलय देश में बनी एक कम लागत वाली पारंपरिक सरफेस–टू–सरफेस क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है जो सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर और कई नई तकनीक से चलती है। इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है और इसमें अलग–अलग तरह के वॉरहेड से अलग–अलग तरह के टारगेट पर हमला करने की क्षमता है। भारतीय सेना और वायु सेना दोनों से एक्सेप्टेंस ऑफ़ नेसेसिटी (एओएन) मिल गई है। उत्पादन के लिए दो डीसीपीपीएस की पहचान की गई है और वायु सेना (आईएएफ) द्वारा संयुक्त प्रयोक्ता परीक्षण निर्देश जारी किए गए।

सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज़ मिसाइल (एसएलसीएम)

सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज़ मिसाइल (एसएलसीएम) एक एनकैप्सुलेटेड क्रूज़ मिसाइल है जिसे सबमरीन से लॉन्च किया जाता है। इसे ज़मीनी टारगेट और शिप टारगेट दोनों पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एनकैप्सुलेटेड मिसाइल को इतनी एग्जिट वेलोसिटी से धकेला जाता है कि आगे बढ़ने के दौरान, मिसाइल का एटीट्यूड उसकी बॉयन्सी के कारण बदल जाता है। अंडरवाटर बूस्टर को सही एंगल पर फायर किया जाता है ताकि एनकैप्सुलेटेड मिसाइल पानी से लगभग वर्टिकल बाहर आ जाए। इसके बाद मिसाइल क्रूज़ फेज़ सहित अपनी एयर ट्रैजेक्टरी लेती है, टारगेट पर लॉक हो जाती है और आखिर में कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर टारगेट को हिट करती है। साल 2024 के दौरान, इजेक्शन मैकेनिज्म, अंडरवाटर डायनामिक्स, पानी के ऊपर कैप्सूल सेपरेशन, एयर फेज़ बूस्टर ट्रैजेक्टरी, क्रूज़ फेज़ मैकेनिज्म और वेपॉइंट बेस्ड ट्रैजेक्टरी को साबित करने के लिए अंडरवाटर प्लेटफॉर्म से दो फुल रेंज मिशन किए गए।

वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (वीएल–एसआरएसएएम)

वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (वीएल–एसआरएसएएम) एक शिप बोर्न हथियार प्रणाली है जिसे इंडियन नेवी के लिए विकसित किया जा रहा है, यह फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, यूएवी वगैरह के विरूद्ध एक वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल को समुद्र में उड़ने वाले टारगेट सहित पास की रेंज से अलग–अलग हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए विकसित किया गया है। वीएल–एसआरएसएएम हथियार प्रणाली की पूरी चेन को सितंबर 2024 में बालासोर में किए गए उड़ान परीक्षण के दौरान प्रमाणित किया गया था, जिसमें सभी उद्देश्य संतोषजनक रूप से पूरे हुए।

वर्टिकल रूप से लॉन्च किए गए एसआरएसएएम के लिए मल्टी–फंक्शन रेडार

वीएल एसआरएसएएम के लिए मल्टी–फंक्शन रेडार (एमएफआर) एक शिप माउंटेड, एक्स बैंड एक्टिव ऐरे रेडार है जो वीएल एसआरएसएएम सिस्टम की निगरानी और फायर कंट्रोल के लिए है। यह एक चार दीवारों वाला एक्टिव फेज्ड ऐरे बेस्ड रेडार है जिसमें बिना रुकावट एजिमुथ कवरेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक बीम स्टेबिलाइजेशन है। साल 2024 के दौरान, मल्टी–फंक्शन रेडार ने विकासात्मक परीक्षण पूरे कर लिए हैं। ये रेडार इंडियन नेवी के नेक्स्ट जेनरेशन मिसाइल वेसल्स शिप के लिए एक डीपीएसयू द्वारा उत्पादन में हैं।

टीएपीएएस एमएएलई यूएवी (रुस्तम II)

टीएपीएएस–बीएच, एक मल्टी–मिशन यूएवी है जिसे आर्म्ड फोर्सेज़ के लिए इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रेकी रोल निभाने के लिए विकसित किया जा रहा है। टीएपीएएस यूएवी में मल्टी–चैनल/मल्टी–सेंसर डेटा लिंक सिस्टम है जिसमें बड़े एरिया, हाई एंड आईएसआर ऑपरेशन के लिए लाइन ऑफ़ साइट (एलओएस) और बियॉन्ड लाइन ऑफ़ साइट (बीएलओएस) क्षमता है। इंडियन एयर फ़ोर्स और इंडियन नेवी ने प्री–ऑपरेशनल रोल में इस्तेमाल के लिए आईयूएएस (इंडिजिनस अनमैन्ड एरियल सिस्टम) के लिए एक्सप्रेशन ऑफ़ इंटरेस्ट दिया है। साल 2024 के दौरान, टीएपीएएस वेरिएंट–एसईटीबी (सिंगल इंजन ट्विन बूम) और टीएपीएएस एएफ6ए और एएफ11/एएफ12 के उड़ान परीक्षण किए गए।

रुस्तम–II यूएवी के लिए ऑटोमोटिव इंजन के कन्वर्ज़न से डीज़ल इंजन

उच्च विशिष्ट शक्ति पावर वाला एयरवर्दी डीज़ल इंजन, टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एडवांस्ड सर्विलांस (टीएपीएएस) अनमैन्ड एरियल व्हीकल (यूएवी) के लिए डिज़ाइन और विकसित किया जा रहा है। देश में विकसित किया गया इंजन 180 एचपी की टेकऑफ़ पावर दे सकता है और उम्मीद है कि यह इम्पोर्टेड इंजन की जगह लेगा, जो अभी टीएपीएएस यूएवी के साथ एकीकृत है। 2024 के दौरान, 650 घंटे बीटा इंजन डिज़ाइन वैलिडेशन टेस्टिंग पूरी की गई और आर–II एएफ–9 एयरफ्रेम पर इंजन का एकीकरण और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन (जीसीएस) के ज़रिए इंजन ग्राउंड रन सफलतापूर्वक किया गया।

इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ क्रूज़ मिसाइल (आईटीसीएम)

इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज़ मिसाइल (आईटीसीएम) एक नई जेनरेशन की 'लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज़ मिसाइल' है, जिसे ज़मीन और समुद्र के प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप

किया जा रहा है। आईटीसीएम प्रोजेक्ट का उद्देश्य देश में बने इंजन को इंटीग्रेट करना है और **निर्भय** मिसाइल के साथ स्वदेशी टर्मिनल मार्गदर्शन प्रणाली और उड़ान परीक्षणों के जरिए मूल्यांकन, वर्ष 2024 के दौरान, स्वदेशी स्मॉल टर्बो फैन इंजन (एसटीएफई) के साथ आईटीआर, चांदीपुर से प्रक्षेपण किया गया।

स्मॉल टर्बो फैन इंजन (एसटीएफई)

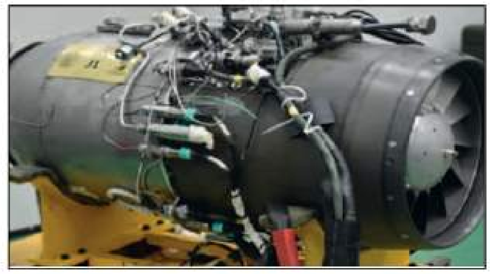

स्मॉल टर्बो–फैन इंजन (एसटीएफई) एक स्वदेशी प्रणोदन सिस्टम है। एसटीएफई ने अप्रैल 2024 में आईटीआर, बालासोर से स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज़ मिसाइल (आईटीसीएम) को सफलतापूर्वक पावर प्रदान की। इंजन ने पूरे मिशन में बेहतरीन प्रदर्शन और संचालन किया। इस कामयाबी के साथ भारत उन खास राष्ट्रों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास स्वदेशी गैस टर्बाइन इंजन से चलने वाली स्वदेशी क्रूज़ मिसाइल है।

लॉग रेंज– लैंड अटैक क्रूज मिसाइल (एलआर–एलएसीएम)

एलआर–एलएसीएम निर्भय कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें ज़मीन और जहाज़ पर आधारित लॉन्चर से कैनिस्टराइज़ेशन और डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता होती है। इस परियोजना के प्रयोक्ता भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना हैं और परियोजना एलआर–एलएसीएम के लिए दो विकास सह उत्पादन भागीदार (डीसीपीपी) मेसर्स बीडीएल, हैदराबाद और मेसर्स बीईएल बैंगलोर को चिह्नित किया गया। वर्ष 2024 के दौरान, एलआर–एलएसीएम–01 की पहली उड़ान का संचालन नवंबर 2024 में आईटीआर, चांदीपुर से किया गया था।

डॉर्मेंट टनल डिटेक्शन सिस्टम

डॉर्मेंट टनल डिटेक्शन सिस्टम एक वाहन पर लगे भूकंप स्ट्रीमर आधारित सिस्टम से संचालित होता है, जो निष्क्रिय सुरंग का पता लगा सकता है। यह सुरंगों की पहचान करने के लिए भूमिगत सेंसर, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रेडार और ध्वनि अवगमन जैसी कई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करता है। वर्ष 2024 के दौरान, गृह मंत्रालय (एमएचए), बोर्ड ऑफ़ ऑफिसर्स (बीओओ) के प्रयोक्ता परीक्षण पूरे हो चुके हैं और विशिष्टताओं के आधार पर प्रमाणन किया जा रहा है।

एमबीटी अर्जुन मार्क–I, के लिए एटीजीएम

डीआरडीओ एक लेज़र सीकर आधारित एंटी–टैंक गाइडेड मिसाइल बना रहा है जिसे एमबीटी अर्जुन की राइफल गन से लॉन्च किया जा सकता है। वर्ष 2024 के दौरान, भारतीय सेना ने विभिन्न रेंज के लिए दो चरणों में लेज़र टारगेट डेज़िग्नेटर (एलटीडी) के साथ एकीकृत इंस्ट्रूमेंटेड विकास फ़्लाइट परीक्षण (आईडीएफटी) किए। परियोजना के सभी उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया है।

लाइट टैंक (एलटी)

डीआरडीओ ने उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों, जल व जमीनी ऑपरेशन में तैनाती के लिए बेहतर सामरिक, सक्रियात्मकता, रणनीतिक गतिशीलता के साथ हल्के वजन वाले बहुमुखी हथियार प्लेटफॉर्म का डिजाइन और विकास कार्य शुरू

किया है। टैंक में पर्याप्त क्षमता के हथियार सिस्टम और सुरक्षा होगी, जो मौजूदा और भविष्य के जोखिमों में काम करने के लिए उपयुक्त होगी। वर्ष 2024 के दौरान, पहला प्रोटोटाइप बनाया गया और ऑटोमोटिव प्रदर्शन का मूल्यांकन पूरा किया गया। मरूस्थल और उच्च तुंगता क्षेत्र (एचएए) ऑटोमोटिव फायरिंग परीक्षण भी पूरे किए गए।

600 एचपी इंजन

डीआरडीओ ने भविष्य के लड़ाकू वाहनों को पावर देने के लिए स्वदेशी इंजन बनाने की पहल की है। इंजन को कॉम्पैक्ट, कुशल और हल्के वज़न का बनाया जा रहा है, जिससे यह भविष्य के लड़ाकू वाहनों के लिए उपयुक्त होगा। जेन 1 इंजन के 250 घंटे के विकास परीक्षण पूरे हो चुके हैं और टेस्ट बेड में लक्षित पावर और टॉर्क आउटपुट हासिल कर लिया गया है। वर्ष 2024 के दौरान, इंजन से 3200 आरपीएम पर 675 एचपी पावर आउटपुट प्राप्त किया गया है।

डब्ल्यूएचएपी–सीबीआरएन प्लेटफॉर्म

डीआरडीओ ने भारतीय पैरामिलिट्री फोर्स की संचालन आवश्यकता के आधार पर व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म (डब्ल्यूएचएपी) का पैरामिलिट्री संस्करण बनाया है। इसमें व्हील्ड 8x8 कॉन्फ़िगरेशन, 600 एचपी इंजन, पूरी तरह से ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वॉरफेयर एजेंट का पता लगाने के लिए इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं। वर्ष 2024 के दौरान, फ्लोटेशन परीक्षण, हथियार फायरिंग, सीबीआरएन गाड़ी और कमांड स्टेशन के बीच कम्युनिकेशन सहित विस्तार में परीक्षण और रनिंग की गई है। इस गाड़ी को महाराष्ट्र रक्षा एक्सपो–2024 में प्रदर्शित किया गया था।

एमबीटी अर्जुन मार्क–Iए के लिए 70टी टैंक ट्रांसपोर्टर

डीआरडीओ ने टैंक ट्रांसपोर्टर के तौर पर विशेषतः एमबीटी अर्जुन मार्क–Iए के सड़क मार्ग से ट्रांसपोर्टेशन के लिए 70टी के एक ट्रेलर का डिज़ाइन और विकास किया है। यह एमबीटी या अन्य बराबर के 70टी क्षमता तक के पेलोड को आवश्यकता/ऑपरेशन की जगहों पर सड़क से तेज़ी से ट्रांसपोर्ट करने के लिए काफी उपयोगी है। फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट (एफएटी) और डीआरडीओ के आंतरिक परीक्षण पूरे हो चुके हैं और ट्रांसपोर्टर ने इन परीक्षणों के दौरान 23,000 कि.मी की दूरी सफलतापूर्वक तय की है। 2024 के दौरान, टीओटी को उद्योगों को हस्तांतरित कर दिया गया है।

सेल्फ–प्रोपेल्ड माइन बरियर (एसपीएमबी)

डीआरडीओ ने स्व–प्रणोदित माइन बरियर बनाया है जो एक माइन बिछाने वाला उपस्कर है, जिसे कई तरह की टैंक–रोधी माइनों को बिछाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उपस्कर मैदानी इलाकों, रेगिस्तानों और अर्ध–रेगिस्तानों में काम कर सकता है। जीएसक्यूआर आधारित क्षेत्र मूल्यांकन परीक्षण सितंबर 2024 में पूरे हुए और ईएमआई/ईएमसी परीक्षण दिसंबर 2024 में पूरे हुए।

जगुआर डीएआरआईएन–III अपग्रेड (डीजेएजी) के लिए इंटरनल आरडब्ल्यूजे सिस्टम

एकीकृत रेडार चेतावनी और जैमर सिस्टम में रेडार वार्निंग रिसीवर (आरडब्ल्यूआर) इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेज़र (ईसीएम), इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेज़र (ईएसएम) शामिल हैं और यह जैमिंग के लिए माइक्रोवेव पॉवर मॉड्यूल (एमपीएम) आधारित ट्रांसमीटर का प्रयोग करता है। वर्ष 2024 के दौरान मल्टी–एमिटर ट्रायल्स, रिग टेस्टिंग, ग्राउंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और कन्फर्मेटरी सॉर्टी की आपत्तियों के विवरण के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट पूरा हो गया है। डीएआरआईएन–II अपग्रेड एयरक्राफ्ट के सक्रियात्मक उपयोग के लिए डीजेएजी सिस्टम को अनुशंसित किया गया है।

सहस्त्र शक्ति

डीआरडीओ ने जायरो स्टेबिलाइज्ड ईओ सिस्टम के साथ मल्टी चैनल बीम डायरेक्टर प्रौद्योगिकी सिस्टम पर आधारित एक सिस्टम बनाया है। इसके परीक्षण अगस्त 2024 में सफलतापूर्वक किए गए। छह चैनलों का प्रयोग करके मल्टी–चैनल बीम कॉम्बिनेशन का डीआरडीओ मूल्यांकन भी सफलतापूर्वक पूरा हो गया है।

एयरबोर्न प्लेटफॉर्म के लिए डेटा लिंक

डीआरडीओ एयरबोर्न प्लेटफॉर्म के लिए लाइन–ऑफ साइट (एलओएस) और सैटेलाइट कम्युनिकेशन (एसएटीसीओएम) डेटा लिंक के डिजाइन और विकास पर काम कर रहा है, जिसमें एईडब्ल्यूएंडसी मार्क–II के लिए डेटा लिंक में इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा। इस परियोजना के तहत कई प्रौद्योगिकी सब–सिस्टम बनाए गए हैं और गुणता परीक्षण पूरे हो गए हैं। सी–बैंड एलओएस लिंक के फ्लाइट परीक्षण दिसंबर 2024 में किए गए हैं।

लेजर बीम राइडर गाइडेंस (एलबीआरजी) सिस्टम

यह प्रणाली सटीक गाइडेड हथियारों को गाइड करने के लिए स्पेशल मॉड्यूलेटेड बीम बनाती है। इस प्रौद्योगिकी में प्रतिरोधी उपायों का खतरा बहुत कम होता है। इस प्रौद्योगिकी में प्रोजेक्टाइल लेज़र बीम के अंदर सवार होता है। वर्ष 2024 के दौरान, आई सेफ़ लेज़र रेंज फाइंडर (ईएलआरएफ) के साथ एलबीआरजी की दो यूनिट बनाई गई हैं और मिसाइल गाइडेंस के लिए आवश्यक विशेष मॉड्यूलेटेड पैटर्न हासिल किया गया।

एडवांस्ड गनर्स मेन साइट (एजीएमएस)

गनर का मेन साइट (जीएमएस) एमबीटी अर्जुन टैंक के लिए एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम का मुख्य सबसिस्टम है, जिससे ज़मीनी टारगेट पर निशाना लगाया जा सकता है। अर्जुन मुख्य बैटल टैंक के गनर के लिए एजीएमएस एक प्राथमिक एंगेजमेंट साइट है। यह गनर को दिन या रात में स्थिर और अवचलित मोड में टारगेट पर निशाना लगाने और फायर करने में मदद करता है। एजीएमएस में जायरो स्टेबिलाइज़्ड हेड असेंबली होती है जिसमें तीसरी पीढ़ी का थर्मल इमेजर, डे विज़न ऑप्टिक्स और आई सेफ लेज़र रेंज फाइंडर होते हैं। वर्ष 2024 के दौरान, एजीएमएस को चेन्नई में अर्जुन एमबीटी पर एकीकृत और सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया।

लॉंग रेंज रेडार (एलआरआर)

एलएलआर एक एल–बैंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड फेज़्ड ऐरे रेडार है जो लंबी दूरी पर छोटे क्रॉस सेक्शन और हाई स्पीड टारगेट का पता लगाता है। यह सिस्टम गैलियम नाइट्राइड पावर एम्पलीफायर वाले ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल का प्रयोग करता है। वर्ष 2024 के दौरान, रेडार के सबसिस्टम को देश में ही डिज़ाइन और विकसित किया गया है। टेस्ट साइट पर रेडार एकीकरण पूरा हो गया है।

सरफेस वेव ओवर–द–हॉरिजन रेडार (एसडब्ल्यूओटीएचआर)

एसडब्ल्यूओटीएच–रेडार बाई–स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन में, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का प्रयोग करके, समुद्र की सतह पर, क्षितिज के पार टारगेट का पता लगा सकता है और उन्हें ट्रैक कर सकता है। इसे बाई–स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन में संचालित किया जाता है, जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर एंटेना को काफ़ी दूरी पर अलग रखा जाता है। इसका प्रयोग स्टेल्थ टारगेट का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है। वर्ष 2024 के दौरान, परियोजना साइट पर सिस्टम एकीकरण और टेस्टिंग पूरी हो चुकी है।

हाई एंड्योरेंस ऑटोनॉमस अंडर वॉटर व्हीकल (एचईएयूवी)

हाई एंड्योरेंस रीकॉन्फिगरेबल ऑटोनॉमस अंडर वॉटर व्हीकल (एचईएयूवी) इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉन–नाइसेंस (आईएसआर), माइन काउंटर मेज़र (एमसीएम), बाथिमेट्री और ओशनोग्राफी (बी एंड ओ) और एंटी सबमरीन वारफेयर (एएसडब्ल्यू) से जुड़े मिशन में गाड़ियों को संचालित करने के लिए है। वर्ष 2024 के दौरान, एचईएयूवी का सरफेस फ्री रनिंग परीक्षण किया गया है और कंट्रोल लॉ बनाया गया है।

एयरोस्पेस अनुप्रयोग के लिए पर्सनल रेडिएशन डोसिमीटर (पीईआरडीएए)

यह गतिविधि आईएसआरओ के गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल के अंदर गामा रेडिएशन को मापने के लिए पीईआरडीएए (पर्सनल रेडिएशन डोसिमीटर फॉर एयरोस्पेस एप्लीकेशन) नाम के रेडिएशन डोसिमीटर को विकसित करने के लिए है। पीईआरडीएए प्रोटोटाइप को सफलतापूर्वक विकसित किया गया है और आईएसआरओ टीम को प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 2024 के दौरान, मॉडल पर योग्यता परीक्षण किए गए हैं। फ्लाइट मॉडल की एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी सफलतापूर्वक पूरी हो गई है।

पोर्टेबल डोज़ रेट मीटर (पीडीआरएम) मार्क–II

पीडीआरएम मार्क–II एक कॉम्पैक्ट, हाथ में पकड़ने वाला, बैटरी चलित इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग शुरुआती न्यूक्लियर रेडिएशन (आईएनआर), गामा और न्यूट्रॉन रेडिएशन डोज़ और रेसिडुअल न्यूक्लियर रेडिएशन (आरएनआर) गामा डोज़ और डोज़ रेट को मापने के लिए किया जाता है। यह पैनल डिस्प्ले पर मापी गई डोज़ और डोज़ रेट दिखाता है। वर्ष 2024 के दौरान, पीडीआरएम मार्क–II के योग्यता परीक्षण भी पूरे हो गए हैं।

नॉन–लीथल रबर बॉल आधारित हैंड ग्रेनेड (एनएलएचजी)

डीआरडीओ ने 28 मई, 2024 को मल्टीमोड फ्यूज को एकीकृत करके रबर बॉल्स से भरे नॉन–लीथल हैंड ग्रेनेड शेल का परीक्षण किया। परीक्षण रबर बॉल्स धमाके की जगह से 10–12 मीटर की दूरी तक जाती हैं और सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। रिकॉर्ड किया गया डिले टाइम लगभग 3.94 सेकंड है।

इंडिविजुअल केमिकल एजेंट डिटेक्टर (आईसीएडी)

डीआरडीओ इंडिविजुअल केमिकल एजेंट डिटेक्टर विकसित कर रहा है, जो एक हल्का, बेल्ट/हार्नेस पर पहनने वाला केमिकल वॉरफेयर एजेंट डिटेक्टर है जिसका वज़न बिना बैटरी के एक कि.ग्रा. से कम है। वर्ष 2024 के दौरान, प्रोटोटाइप को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया गया है और इसकी फंक्शनल टेस्टिंग चल रही है।

बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट्स (बीडब्ल्यूए) के लिए एंजाइम–रहित इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर

एंजाइम रहित इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर प्रौद्योगिकी को संवेदनशील और तेज़ी से बीडब्ल्यूए का पता लगाने के लिए विकसित किया गया है। इस प्रौद्योगिकी में इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल बनाने और एम्प्लीफिकेशन के लिए फंक्शनल नॉन–मटीरियल का प्रयोग आवश्यक है। लेबल के तौर पर नैनोमटीरियल, सेंसर चिप्स, बायो रिएजेंट और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर के मुख्य पार्ट्स हैं। वर्ष 2024 के दौरान, बायोसेंसर लैब प्रोटोटाइप का विकास और मूल्यांकन किया गया है।

भारतीय वायु सेना में एयरमैन के चयन के लिए न्यू जेनरेशन साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट

डीआरडीओ भारतीय वायु सेना में एयरमैन के सिलेक्शन के लिए न्यू जेनरेशन एयरमैन सिलेक्शन सिस्टम विकसित कर रहा है। इस टेस्ट में भारतीय वायु सेना में एयरमैन के तौर पर शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स की काबिलियत का पता लगाया जाएगा। यह टेस्ट प्रयोक्ताओं द्वारा तय किए गए कुछ साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स पर कैंडिडेट्स का मूल्यांकन करेगा। टेस्ट के शुरुआती ट्रायल्स अक्टूबर 2024 में एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल, बेलगांव में किए गए हैं।

डिजाइन और विकास के अधीन प्रमुख प्रणालियाँ

लंबी अवधि की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों (ईटी–एलडीएचसीएम) को सक्षम बनाने वाली तकनीकें

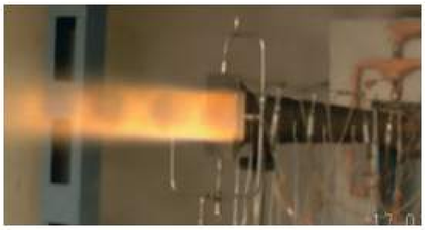

ईटी–एलडीएचसीएम(लंबी अवधि की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए प्रौद्योगिकी को सक्षम बनाना) को लंबी अवधि की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के डिजाइन और विकास के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी के विकास हेतु मंजूरी दी गई है। वर्ष 2024 के दौरान एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट इंजन का डिजाइन पूरा हो गया; सब–स्केल कम्बस्टर बनाया गया और 60 सेकंड के लिए सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया।

उन्नत टर्बो गैस जनरेटर (एटीजीजी)

एटीजीजी इंजन को अनमैन्ड एरियल व्हीकल की प्रणोदन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग और इंजन असेंबली के लिए उद्योग भागीदार की पहचान कर ली गई है। प्रूफ़ ऑफ़ कॉन्सेप्ट (पीओसी) इंजन को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (एएम) प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बनाया जा रहा है। वर्ष 2024 के दौरान, इंजन के हाई स्पीड स्थायी मैग्नेट अल्टरनेटर का एक प्रोटोटाइप विकसित किया गया है और पूरी स्पीड पर टेस्ट किया गया।

एडवांस्ड फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल (ए–एफएडीईसी)

ए–एफएडीईसी एक एडवांस्ड डिजिटल इंजन कंट्रोल यूनिट है। यह यूनिट योग्य है और इसे कावेरी ड्राई इंजन प्रोग्राम में शामिल किया गया है। इसने कावेरी ड्राई इंजन के साथ करीब 300 घंटे की टेस्टिंग और कुल 1300 घंटे से ज़्यादा की रिग टेस्टिंग पूरी की है। यूनिट के साथ कावेरी ड्राई इंजन की 75 घंटे की एल्टीट्यूड टेस्टिंग पूरी की गई है। वर्ष 2024 में, बैंगलोर में फ्लेम–आउट और ऑटो–रीलाइट लॉजिक विकसित और टेस्ट किए गए।

हाई प्रेशर टर्बाइन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड और रेडी–टू–फिट कंडीशन में वेन्स

इसका उद्देश्य सिंगल क्रिस्टल हाई प्रेशर टर्बाइन ब्लेड और वेन्स, जो सिंगल क्रिस्टल कास्टिंग से बने हों और जिसमें हाई टेम्परेचर ब्रेज़िंग, क्रीप फ़ीड ग्राइंडिंग, फ़िल्म कूलिंग होल्स की ड्रिलिंग और थर्मल बैरियर कोटिंग शामिल हैं, के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना है। 2024 में, सिंगल क्रिस्टल एचपी टर्बाइन ब्लेड कास्टिंग की डिलीवरी पूरी हो गई है। सिंगल क्रिस्टल एचपी टर्बाइन वेन्स की कास्टिंग का काम प्रगति पर है।

यूएलपीजीएम मिसाइल पेनेट्रेशन–कम–ब्लास्ट वारहेड

डीआरडीओ, यूएवी लॉन्च्ड प्रिसिजन ग्रेडेड मिसाइल (यूएलपीजीएम) के परीक्षण करने की प्रक्रिया में है, जिससे मानवरहित हवाई युद्ध क्षमता में एक बड़ी छलांग लगेगी। वर्ष 2024 के दौरान, मॉड्यूलर वॉरहेड्स कॉन्फ़िगरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। पूरे वॉरहेड सिस्टम को टेस्ट किया गया है और मिसाइलों में सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है।

1000 किलोग्राम सामान्य उद्देश्य के बम

भारतीय वायु सेना ने सही शुरूआती मैकेनिज्म के साथ 1000 कि.ग्रा. श्रेणी (मार्क–84) सामान्य उद्देश्य के बम बनाने की आवश्यकता दर्शाई है। वर्ष 2024 तक, एलयूजी–1000 का स्ट्रक्चरल एनालिसिस पूरा हो चुका है।

इलेक्ट्रो मैग्नेटिक (ईएम) रेलगन

इस परियोजना का उद्देश्य एक पैक्ड ईएम रेलगन सिस्टम का विकास करना है जिसे सड़क मार्ग से ले जाया जा सके और कैपेसिटर बैंक का प्रयोग करके हाइपरवेलोसिटी पर प्रोजेक्टाइल फायर कर सके। इस परियोजना के तहत कई आवश्यक प्रौद्योगिकी विकसित की जा रही हैं, जिसमें बैटरी आधारित कॉम्पैक्ट पावर सोर्स, कॉम्पैक्ट कैपेसिटर बैंक और रेलगन बैरल शामिल हैं। हाई एनर्जी डेंसिटी कैपेसिटर और सेमीकंडक्टर स्विच के प्रोटोटाइप का विकास और सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए हैं। इस वर्ष, रेलगन लॉन्चर को अपग्रेड किया गया है और कई बार सफलतापूर्वक टेस्ट फायर किया गया।

1500 एचपी इंजन

डीआरडीओ आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स (एएफवी) के लिए 1500 एचपी इंजन का विकास कर रहा है। 2024 के दौरान, पहले इंजन प्रोटोटाइप के पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और फायरिंग पूरी हो चुकी है। एक प्रोटोटाइप इंजन को क्रैंक किया जा चुका है और इंजन पार्ट्स की फटीग/एंड्योरेंस टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। कूलिंग सिस्टम के पार्ट्स विकसित हो चुके हैं और दो प्रोटोटाइप की असेंबली का काम चल रहा है।

एडवांस्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म (व्हील्ड और ट्रैक्ड) – विक्रम–21

डीआरडीओ ने ट्रैक्ड और व्हील्ड एडवांस्ड आर्मर्ड व्हीकल्स के डिज़ाइन और विकास की परियोजना शुरू की है। इसमें हल, पावर पैक, रनिंग गियर ड्राइव लाइन, टरेट, एम्युनिशन और साइटिंग सिस्टम, एम्फीबियन कैपेबिलिटी, प्रोटेक्शन और एर्गोनॉमिक्स के एरिया में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है। वर्ष 2024 के दौरान, एएपी–व्हील्ड, ट्रैक्ड प्लेटफॉर्म और क्रूलेस टरेट का डिटेल्ड डिज़ाइन पूरा कर लिया गया है। क्रूलेस टरेट देश में पहली बार विकसित किया जा रहा है और इसका कॉन्फ़िगरेशन और डिज़ाइन फाइनल हो गया है।

उन्नत रोबोटिक्स के लिए प्रणाली और प्रौद्योगिकियां (एसटीएआर)

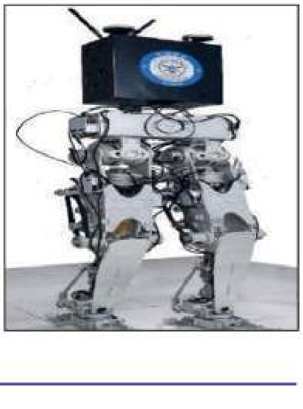

डीआरडीओ मिलिट्री रोबोटिक्स एप्लीकेशन के लिए सर्विलांस, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, कॉम्बैट इंजीनियरिंग और कॉम्बैट सपोर्ट के क्षेत्र में एडवांस्ड रोबोटिक्स के लिए प्रौद्योगिकी विकसित कर रहा है। एडवांस्ड रोबोटिक्स एक ऐसी मशीन होगी जो ऐसे काम कर सकती है जिनके लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस, अडैप्टेबिलिटी और प्रिसिजन की ज़रूरत होती है। क्वाड्रुपेड रोबोटिक सिस्टम और बाइपेड रोबोटिक सिस्टम का रियलाइजेशन मार्च 2024 और अक्टूबर 2024 में पूरा हुआ।

ग्राउंड आधारित ईडब्ल्यू सिस्टम (धराशक्ति)

डीआरडीओ सेना के लिए मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में ग्राउंड आधारित एकीकृत ईडब्ल्यू सिस्टम के लिए इंट्राकॉम रेडियो पर काम कर रहा है। सीमित इकाइयों के सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण किए जा चुके हैं। इंट्राकॉम का फर्स्ट ऑफ प्रोडक्शन मॉडल (एफओपीएम) वर्जन बन चुका है और इंटरऑपरेबिलिटी, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट और रिपीटर फंक्शन के लिए बेंच लेवल टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। वर्ष 2024 के दौरान, डीआरडीओ आंतरिक मूल्यांकन समिति द्वारा इंट्राकॉम सिस्टम का सफल मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है।

श्येन परियोजना के लिए क्षितिज रेडार

डीआरडीओ, भारतीय नौसेना के डोर्नियर मिड लाइफ अपग्रेड प्रोग्राम के लिए सेंसर सूट के विकास के लिए नोडल संगठन है। रेडार के टाइल कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांसमिट रिसीवर (टीआर) मॉड्यूल के साथ एक एक्स–बैंड एक्टिव ऐरे एंटीना का प्रयोग करता है। रेडार के लिए विकास फ़्लाइट सॉर्टीज़ की गई और प्लान किए गए टेस्ट पॉइंट्स के लिए सिंथेटिक अपर्चर रेडार (एसएआर) इमेजरी हासिल की गई। वर्ष 2024 के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेज़र्स (ईएसएम) सिस्टम के लिए प्रयोक्ता प्रयोगशाला मूल्यांकन दो चरणों में पूरा हो गया है। ईएसएम सिस्टम को एक डीपीएसयू में विमान में इंस्टॉल किया जा रहा है।

डिजिटल एक्टिव फेज्ड ऐरे रेडार (डीएपीएआर)

डीएपीएआर एक एस–बैंड एक्टिव फेज़्ड ऐरे रेडार है जिसमें डिजिटल टीआर मॉड्यूल हैं जो ट्रांसमिट और रिसीव करने के दैरान बनने वाली डिजिटल बीम में मदद करते हैं। यह मल्टी–फंक्शन 4डी रेडार है जो स्वचालित रूप से लड़ाकू विमान से लेकर धीरे चलने वाले हवाई लक्ष्यों तक का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने में सक्षम है। वर्ष 2024 के दौरान, एलिमेंट लेवल वेवफॉर्म डिजिटल सिंथेसिस और ऐरे कैलिब्रेशन ट्रांसमिट और रिसीव मोड में पूरा हो गया।

फोटोनिक्स रेडार

डीआरडीओ ने रेडार अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित फोटोनिक्स प्रौद्योगिकी को बनाने, शामिल करने और प्रदर्शित करने का काम शुरू किया है: जैसे फोटोनिक्स सिग्नल जेनरेशन (पीएसजी), वेवलेंथ डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग (डब्ल्यूडीएम) पर आधारित आरएफ का डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा और कंट्रोल सिग्नल और मल्टी–चैनल फोटोनिक्स रिसीवर। फोटोनिक्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और अल्ट्रा नैरो बैंड आरएफ फिल्टर का काम पूरा हो गया है। फोटोनिक पर आधारित मल्टीबैंड रेडार ट्रांसमिट सिग्नल जेनरेशन के लिए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया गया है। वर्ष 2024 के दौरान, मोड लॉक्ड लेजर (एमएलएल) का प्रयोग करके फोटोनिक्स ट्रांसमीटर और रिसीवर की शुरुआती टेस्टिंग पूरी हो गई है।

सबमरीन के लिए इन्टीग्रेटेड कॉम्बैट सूट हेतु नेविगेशन रेडार (एनआरआईसीएएस)

यह एक पारंपरिक एक्स–बैंड रेडार है जो समुद्र में नावों, बोया और जहाजों का पता लगाता है और उन्हें ट्रैक करता है, ताकि सबमरीन के नेविगेशन में मदद मिल सके। वर्ष 2024 के दौरान, बेंगलुरु में रेडार टेस्ट प्लेटफॉर्म पर एक रेडार बनाया गया, एकीकृत किया गया और टेस्ट किया गया।

एईडब्ल्यूएंडसी मार्क–II सिस्टम के लिए प्राइमरी रेडार

इस परियोजना का उद्देश्य एयरबस एयरक्राफ्ट पर लंबी दूरी के एयरबोर्न पूर्व चेतावनी अनुप्रयोगों के लिए एक डोर्सल माउंटेड S–बैंड एक्टिव ऐरे एंटीना आधारित रेडार और एक नोजकोन माउंटेड X–बैंड एक्टिव ऐरे एंटीना आधारित रेडार विकसित करना है। वर्ष 2024 तक, सिस्टम का पीडीआर और विकास पूरा हो गया है।

एईडब्ल्यूएंडसी मार्क–II के लिए मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम (एईडब्ल्यूएंडसी)

डीआरडीओ, एईडब्ल्यूएंडसी मार्क–II के लिए मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम (एईडब्ल्यूएंडसी) विकसित कर रहा है। इस उत्पाद के रियलाइजेशन के लिए मेसर्स बीईएल (मछलीपट्टनम) डीसीपीपी है। वर्ष 2024 के दौरान, एईडब्ल्यूएंडसी के लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स (एलआरयूएस) का डिज़ाइन फाइनल हो गया है और ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए डिज़ाइन का स्ट्रक्चरल/थर्मल एनालिसिस चल रहा है।

ग्राउंड आधारित हाई पावर माइक्रोवेव (एचपीएम) डायरेक्टेड एनर्जी हथियार (डीईडब्ल्यू) प्रणाली

ग्राउंड आधारित एचपीएम डीईडब्ल्यू प्रणाली को रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) पावर देने के लिए विकसित किया जा रहा है, ताकि यूएवी के इलेक्ट्रॉनिक्स को लंबी दूरी तक निष्क्रिय किया जा सके। प्रणाली के फील्ड परीक्षण जुलाई 2024 में किए गए हैं।

सबमरीन के लिए एकीकृत लड़ाकू सूट (आईसीएएस) कार्यक्रम

आईसीएएस प्रोग्राम सबमरीन के लिए एक स्वदेशी एकीकृत कॉम्बैट सूट के डिज़ाइन, विकास और एकीकरण के लिए है। फेज–1 शोर इंटीग्रेशन फेसिलिटी, एनपीओएल में प्रोटोटाइप के प्रमाणन का है, फेज–2 सब सरफेस किलर (एसएसके) सबमरीन में प्रोडक्शन ग्रेड का है और फेज–3 में सबमरीन की पी–76 क्लास पर आईसीएस का फिटमेंट किया जाएगा। डिफेंस एक्विजिशन ने ऑन–बोर्ड पी–75 सबमरीन पर आईसीएएस लगाने की मंजूरी दे दी है। परीक्षण और एकीकरण से जुड़ी गतिविधियां चल रही हैं। फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट (एफएटी) और प्रयोक्ता मूल्यांकन का कार्य प्रगति पर है।

एयर इंडेपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) प्रणाली

पी–75 क्लास सबमरीन के लिए एआईपी के एनर्जी मॉड्यूल बनाने एवं एआईपी प्लग का विस्तृत डिज़ाइन का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2024 में, एनर्जी मॉड्यूल और उसकी उप प्रणालियां डिज़ाइन की जा चुकी है। मैकेनिकल प्रणाली का डिटेल्ड डिज़ाइन रिव्यू (डीडीआर) और एनर्जी मॉड्यूल/लिक्विड ऑक्सीजन मॉड्यूल समेत एआईपी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स की जांच सबमरीन डिज़ाइनर के साथ चल रही है।

थिएटर लेवल सोनार के लिए टेक्नोलॉजी (टीटीएलएस)

टीटीएलएस का उद्देश्य थिएटर लेवल सोनार को बनाने के लिए आवश्यक प्रणाली और प्रौद्योगिकी को विकसित करना और प्रदर्शित करना है। प्रमुख सबसिस्टम जिनको विकसित करना है, उनमें लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर ऐरे, ट्रांसमीटर और रिसीवर ऐरे के लिए फेयर्ड टो केबल, ट्रांसमीटर ऐरे के डिप्लॉयमेंट और रिट्रीवल के लिए हैंडलिंग प्रणाली, पावर एम्पलीफायर और ट्रांसमीटर प्रणाली, ट्विन–लाइन टोड रिसीवर ऐरे, टो किए जाने वाले ऐरे के लिए विंच और हैंडलिंग प्रणाली और थिएटर लेवल सोनार के लिए सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीक शामिल है। लो फ्रीक्वेंसी प्रोजेक्टर एलिमेंट के प्रथम प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया और अंडरवाटर अकूस्टिक रिसर्च फैसिलिटी (यूएआरएफ) में बने नए सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकूस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड मूल्यांकन (एसपीएसीई) प्लेटफॉर्म पर एलिमेंट लेवल और ऐरे लेवल, दोनों पर टेस्ट किया गया। वर्ष 2024 के दौरान, ट्विन–लाइन टोड ऐरे को बनाने के लिए सभी सबसिस्टम प्रौद्योगिकी को लैब में विकसित और प्रमाणित किया गया। बॉटम–रिफ्लेक्शन लॉस मेज़रमेंट एक्सपेरिमेंट किए गए और विभिन्न फ्रीक्वेंसी पर क्षय का अनुमान लगाया गया।

वाइड एरिया सी सरफेस एंड सब–सरफेस सर्विलांस नेटवर्क (डब्ल्यूएएस4 एनईटी)

डब्ल्यूएएस4एनईटी सेंसर नोड्स के एक लीनियर बैरियर को पार करने वाली सबमरीन का पता लगाने के लिए है। 2–रिंग प्रोटोटाइप ऐरे स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन, ट्रांसड्यूसर की असेंबली और इलेक्ट्रॉनिक्स का एकीकरण पूरा हो गया है। शुरुआती प्रर्दशन मूल्यांकन परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए हैं और लीड सिस्टम इंटीग्रेटर की पहचान कर ली गई है। वर्ष 2024 के दौरान, सिस्टम सॉफ्टवेयर विकास पूरा हो गया है और प्रोटोटाइप परीक्षण के हिस्से के तौर पर प्रदर्शन को भी टेस्ट किया गया है।

पी–75 के लिए विद्युतीय भारी वजन टारपीडो (ईएचडब्ल्यूटी)

इस परियोजना का उद्देश्य, पी–75 प्लेटफार्मों पर तैनाती के लिए ईएचडब्ल्यूटी का विकास, नौसेना स्टाफ गुणात्मक आवश्यकताओं (एनएसक्यूआर) के अनुसार उत्पादन संस्करण टारपीडो का परीक्षण और डीसीपीपी की पहचान करना है। वर्ष 2024 के दौरान, युद्धक विन्यास को साकार किया गया है और गतिशील परीक्षणों में टारपीडो की नियंत्रणीयता और स्थिरता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है। थर्मल बैटरी की फायरिंग और लड़ाकू संस्करण टारपीडो की पुनर्प्राप्ति का भी प्रदर्शन किया गया है।

दृश्य छलावरण के लिए अनुकूली ऐड–ऑन प्रणाली (एवीआईएस)

दृश्य अनुकूली छलावरण की तकनीक विकसित की गई है ताकि तैनाती के स्थान पृष्ठभूमि की विशेषताओं से मेल खाने के लिए वाहन पर गतिशील रूप से दृश्य रंग पैटर्न उत्पन्न करके गतिशील पृष्ठभूमि में सैन्य वस्तुओं को छलावरण किया जा सके। छलावरण वाला वाहन पृष्ठभूमि में विलीन हो जाता है और उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। दृश्य अनुकूली प्रणाली के कार्यात्मक प्रोटोटाइप का विकास, परीक्षण और प्रयोगशाला वातावरण में खड़े वाहन के साथ–साथ फील्ड एरिया में भी इसकी कार्यात्माकता का प्रदर्शन किया गया।

टीटीएस के विभिन्न प्रकारों का फिल्ड मूल्यांकन

थर्मल टारगेट सिस्टम (टीटीएस) के विभिन्न प्रकार, जैसे 3 आयामी (3डी–टीटीएस), उच्च विश्वसनीयता वाली (एचएफ–टीटीएस) और कम लागत के (एलसी–टीटीएस), विकसित किए गए हैं और उनका फील्ड में मूल्यांकन किया गया है। 3डी थर्मल टारगेट सिस्टम (टीटीएस) एक सैन्य वाहन के आगे, चौड़े, पिछले और ऊपरी दृश्यों के थर्मल संकेतों को एक इकाई के रूप में दर्शाता है। 3डी–टीटीएस का क्षेत्रीय मूल्यांकन पोखरण में किया गया। टार्गेट के थर्मल संकेतों को नियंत्रित करने के लिए, दूर से नियंत्रित आरएफ आधारित मल्टी–चैनल तापमान नियंत्रक (एमसीटीसी) विकसित किया गया है। वर्ष 2024 के दौरान, एमसीटीसी का फील्ड आधारित दूरस्थ संचालन, तापमान नियंत्रण, परीक्षण और मूल्यांकन सफलतापूर्वक किया गया है।

मिट्टी में दबी हुई बारूदी सुरंगों का दूरस्थ पता लगाने वाली ड्रोन आधारित तकनीक

मिट्टी में दबी हुई बारूदी सुरंगें सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे काफिले की गति को धीमा कर देती हैं। गतिशील सतह प्रकृति के कारण रेगिस्तानी परिस्थितियों में यह विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है। डेजर्ट वारफेयर एंड ऑपरेशन सपोर्ट टेक्नोलॉजीज (डीओएसटी) परियोजना के अंतर्गत, एंटी–पर्सनल (एपी) माइंस और एंटी–टैंक (एटी) माइंस का पता लगाने के लिए, सुरक्षित ऊँचाई एवं त्वरित गति से हवाई रिमोट माइन डिटेक्शन तकनीक विकसित की जा रही है। वर्ष 2024 के दौरान, सिस्टम डिज़ाइन रिव्यू (एसडीआर) आयोजित किया गया।

डैमेज टॉलरेंट डिज़ाइन मेथडोलॉजी (डीटीडीएम)

डीआरडीओ ने वर्तमान सुरक्षित जीवन डिज़ाइन दृष्टिकोण को और अधिक विश्वसनीय और लागत प्रभावी बनाने के लिए एक परियोजना शुरू की है। यह विधि, सुरक्षित जीवन दृष्टिकोण की सीमाओं को दूर करने के अलावा, सुरक्षित निरीक्षण अंतरालों को शामिल करके महत्वपूर्ण घटकों की संरचनात्मक अखंडता को भी सुनिश्चित करेगी। यह विधि फ्रैक्चर मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर और फटीग क्रैक प्रोपगेशन लाइफ का आकलन महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। वर्ष 2024 में, दरार वाले प्रतिनिधि एयरो इंजन डिस्क का पूर्ण पैमाने पर फटीग परीक्षण किया गया और दरार वृद्धि पूर्वानुमान पद्धति को मान्य किया गया। चयनित सामग्रियों के विभंजन मापदंड विभिन्न तापमानों और प्रतिबल अनुपातों पर तैयार किए गए। दो और प्रतिनिधि डिस्कों का परीक्षण किया जा रहा है।

ऑटोमेटिक फिल्ड डिटक्सन किट (एएफडीके)

उभरे हुए कोलोरीमेट्रीक सेंसर सारणी चिप आधारित एएफडीके का विकास वाष्प अवस्था में रासायनिक युद्ध कारकों का पता लगाने और उनकी पहचान के लिए किया जा रहा है। रासायनिक युद्ध कारकों (सीडब्ल्यूए) और संभावित हस्तक्षेप उपकरण का डेटा जनरेशन पहले एकीकृत उपकरण के साथ पूरा किया गया। पहले एकीकृत उपकरण का आंतरिक कार्यात्मक परीक्षण पूरा हो गया है। इसके बाद, एटीपी के अनुसार कार्यात्मक परीक्षण के उद्देश्य से औद्योगिक साझेदार ने एएफडीके का पहला औद्योगिक प्रोटोटाइप प्रस्तुत किया है। वर्ष 2024 के दौरान, एएफडीके का पहला औद्योगिक प्रोटोटाइप डिज़ाइन और निर्मित किया गया।

नौसेना अनुप्रयोगों के लिए पीएमएन–पीटी (लेड मैग्नीशियम नियोबेट–लेड टाइटेनेट) एकल क्रिस्टल ट्रांसड्यूसर तत्व

विभिन्न नौसेना अनुप्रयोगों के लिए अगली पीढ़ी की अति कार्यक्षमता ट्रांसड्यूसर के लिए पीएमएन–पीटी एकल क्रिस्टल की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक रूप से विकसित पीएमएन–पीटी एकल क्रिस्टल से क्रिस्टलोग्राफिक रूप से उन्मुख और ध्रुवित पीएमएन–पीटी एकल क्रिस्टल ट्रांसड्यूसर तत्वों का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया है। इन क्रिस्टलों ने विशिष्ट पीजोइलेक्ट्रिक आवेश गुणांक दर्शाते हुए अत्यधिक उत्साहजनक पीजोइलेक्ट्रिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित की है। ये ट्रांसड्यूसर तत्व नौसेना सोनार उपकरणों की संवेदनशीलता और परास में दो गुना से भी अधिक वृद्धि प्रदान करेंगे।

प्रमुख अवसंरचना और अद्वितीय परीक्षण सुविधाओं का निर्माण

सुपरसोनिक पवन सुरंग (एचडीपीएसडब्ल्यूटी) का उन्नयन

डीआरडीओ ने उड़ान की स्थिति में नियंत्रण सतह वाले एक्चुएटर का परीक्षण करने और पूर्ण उड़ान आवरण में मिसाइल मॉडलों पर पवन सुरंग परीक्षण करने के लिए हैदराबाद में एक उच्च गतिशील दाब सुपरसोनिक पवन सुरंग सुविधा स्थापित की है। आज तक भारत में इस प्रकार के परीक्षण, विशेष रूप से उड़ान की स्थिति का अनुकरण करने के लिए कोई पवन सुरंग सुविधा नहीं थी। परीक्षण सुविधा में पारंपरिक और उच्च गतिशील दाब आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो सुरंग सर्किट हैं, इसके अलावा तीन प्रवाह व्यवस्थाएँ – सबसोनिक, ट्रांसोनिक और सुपरसोनिक भी हैं। वर्ष 2024 तक, सभी सुरंग उप–प्रणालियों का निर्माण पूरा हो चुका है और सुविधा में प्रमुख उप–प्रणालियाँ स्थापित की जा चुकी हैं।

स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप परीक्षण सुविधा (एससीपीटी) की स्थापना

1000 सेकंड तक की अवधि वाले स्क्रैमजेट परीक्षण के लिए हैदराबाद में स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप परीक्षण (एससीपीटी) सुविधा स्थापित की जा रही है। कई फीड सिस्टम, बड़ी भंडारण सुविधाओं और विशिएटड एयर हीटरों की स्थापना और कमीशनिंग इसकी प्रमुख आवश्यकता है। विभिन्न सुविधा उप–प्रणालियों की सफल स्थापना और कमीशनिंग के लिए क्रमिक विकास गतिविधियाँ संचालित की गईं। परीक्षण स्थल और नियंत्रण कक्ष सफलतापूर्वक स्थापित कर दिए गए हैं और आगे के परीक्षण चल रहे हैं।

विद्युतचुंबकीय प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी केंद्र (सीमाल्ट)

रेल गन प्रौद्योगिकी के भविष्योन्मुखी विकास को सुगम बनाने के लिए पुणे में नागरिक अवसंरचना और परीक्षण सुविधा के निर्माण हेतु सीमाल्ट की स्थापना की गई थी। यह केंद्र हथियार–ग्रेड रेल गन विकसित करने हेतु कैपेसिटर बैंक और बड़े कैलिबर रेल गन की स्थापना कर सकेगा। इसमें एक डिज़ाइन केंद्र, इंस्ट्रूमेंटेशन केंद्र और एक रेंज भी है।

छोटे हथियारों के लिए बैरल निर्माण सुविधा

पुणे में 5.56, 7.62 और 9 मिमी कैलिबर के छोटे हथियारों के लिए बैरल निर्माण सुविधाएँ स्थापित की गई हैं। विशिष्ट कच्चे माल, गन ड्रिलिंग और होनिंग मशीनें, कोल्ड फोजिंग मशीन, क्रोम प्लेटिंग सुविधा, बोर और चैम्बर गेज, बैरल के लिए गैर–विनाशकारी और प्रूफ परीक्षण सुविधाएँ स्थापित की गई हैं। विकसित बुनियादी ढाँचागत सुविधाओं, जैसे गन बैरल तकनीक और 5.56 मिमी तथा 7.62 मिमी के 100 प्रोटोटाइप बैरल, क्रमशः क्लोज–क्वार्टर बैटल (सीक्यूबी) कार्बाइन और लाइट मशीन गन (एलएमजी) के लिए निर्मित किए गए।

इन्फ्रारेड थर्मोग्राफी सिस्टम

यह सुविधा हैदराबाद में स्थापित की जा रही है और इसमें अनकूल्ड माइक्रो बोलोमीटर थर्मल कैमरा, एक्टिवेशन सोर्स, कंट्रोलर और इमेजिंग सॉफ्टवेयर शामिल हैं। यह प्रणाली कंपोजिट केस में डिलेमिनेशन, डिसबॉन्ड, पोरोसिटी, मैट्रिक्स क्रैकिंग, पोरोसिटी और इंसुलेटर में डिलेमिनेशन और डिसबॉन्ड के निरीक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है। यह कई इंटरफेस पर डिसबॉन्ड और डिलेमिनेशन का पता लगाने के साथ–साथ स्टील केसिंग वाले रॉकेट मोटर्स के निरीक्षण के लिए भी उपयोगी है।

हवाई रडार एकीकरण एवं परीक्षण सुविधाएँ (एआरआईटीएफ)

हवाई रडार एकीकरण एवं परीक्षण सुविधाएँ (एआरआईटीएफ) का उद्देश्य रडारों का एकीकरण, परीक्षण और मूल्यांकन करना है जिससे इच्छित प्लेटफार्मों पर रडार के प्रदर्शन को प्रमाणित करने में लगने वाले समय, प्रयास और लागत की बचत हो सकती है। इस परियोजना का उद्देश्य हवाई रडार एकीकरण एवं परीक्षण सुविधा का निर्माण करना है जिसमें परीक्षण रिग, सिमुलेटर, रेडियो आवृत्ति (आरएफ) स्तर के परीक्षण जिग और लाइन रिप्लेसेबल यूनिट (एलआरयू) स्तर के स्वचालित परीक्षण उपकरण (एटीई), 6 डिग्री स्वतंत्रता (डीओएफ) गति सिम्युलेटर और एनेकोइक कक्ष शामिल हैं। लड़ाकू विमानों सिमुलेटर, आरएफ स्तर के परीक्षण जिग्स और एलआरयू स्तर के एटीई में अग्नि नियंत्रण हेतु सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड ऐरे (एईएसए) रडार, के परीक्षण हेतु परीक्षण रिग की स्थापना के लिए बुनियादी ढाँचे की स्थापना का कार्य बेंगलुरु में प्रगति पर है।

ध्वनिक अभिलक्षणन एवं मूल्यांकन हेतु जलमग्न प्लेटफ़ॉर्म (स्पेस)

ध्वनिक अभिलक्षणन एवं मूल्यांकन हेतु जलमग्न प्लेटफ़ॉर्म, यूएआरएफ, कुलमावु (केरल) की एक परीक्षण सुविधा है, जिसका उपयोग नियंत्रित वातावरण में जलमग्न परिस्थितियों में सोनार प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों के एकीकृत परीक्षण, अभिलक्षणन और मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इसका उद्घाटन अप्रैल 2024 में डीडीआरएंडडी सचिव और डीआरडीओ अध्यक्ष द्वारा किया गया था।

तटीय एकीकरण सुविधा (एसआईएफ)

तटीय एकीकरण सुविधा (एसआईएफ) का उद्‌घाटन सितंबर 2024 में कोच्चि में किया गया। इसके बाद, पनडुब्बी के पतवार, पख और बाहरी पतवार व डेक सहित कम्पार्टमेंट का निर्माण पूरा हो चुका है। पनडुब्बी के कम्पार्टमेंट उपकरणों की स्थापना के लिए तैयार किए जा रहे हैं। सभी उपकरणों की स्थापना पूरी होने के बाद, आईसीएस प्रणाली की कार्यक्षमता को सिद्ध करने के लिए 2025 की शुरुआत में एकीकृत तटीय निगरानी (आईसीएस) सेंसरों का पूर्ण पैमाने पर एकीकरण और परीक्षण किया जाएगा।

भूमि आधारित परीक्षण सुविधा (एलबीटीएफ)

भारतीय नौसेना को ली–आयन बैटरी मॉड्‌यूल के कार्य का प्रदर्शन करने के लिए विशाखापत्तनम में एक भूमि आधारित परीक्षण सुविधा (एलबीटीएफ) स्थापित की गई है। पनडुब्बी बैटरी कम्पार्टमेंट, बैटरी मॉड्‌यूल के लिए चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सुविधाएँ स्थापित की गई हैं। इस सुविधा का उद्‌घाटन अक्टूबर 2024 में किया गया।

ल्यूब ऑयल पंप और स्केवेंज यूनिट (एलओपीएसयू) के स्थायित्व परीक्षण हेतु परीक्षण सुविधा

स्मॉल टर्बो फैन इंजन (एसटीएफई) में प्रयुक्त ल्यूब्रिकेशन ऑयल पंप (एलओपी) इकाई, बियरिंग्स और गियरबॉक्स को तेल की आपूर्ति करने और बियरिंग सम्पों से तेल निकालने के लिए महत्वपूर्ण एलआरयू में से एक है। इन इकाइयों को सभी पर्यावरणीय परिस्थितियों में संचालन क्षमता सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय योग्यता परीक्षण से गुजरना आवश्यक है। विनिर्देशों के अनुसार निर्मित और बेंगलुरु में स्थापित एवं इस परीक्षण सुविधा का उद्देश्य–40°C पर कोल्ड स्टार्ट, 300°C पर उच्च तापमान में स्थायित्व, कमरे के तापमान में स्थायित्व और ऊँचाई प्रदर्शन परीक्षण जैसे कार्यात्मक और योग्यता परीक्षण करना है। यह सुविधा 10 किमी तक की ऊँचाई की स्थितियों का अनुकरण करने के लिए वैक्यूम पंप और एक ऑयल हीटर और कूलर से सुसज्जित है, जो परीक्षण के दौरान तेल का तापमान (300°C तक) बनाए रखता है।

तवांग (अरुणाचल प्रदेश) में अनुसंधान एवं विकास केंद्र

तवांग (अरुणाचल प्रदेश) में अनुसंधान एवं विकास केंद्र (आरडीसी) का निर्माण पूरा हो गया और इसका उद्‌घाटन 24 मई 2024 को डॉ. समिर वी. कामत, सचिव, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग एवं अध्यक्ष डीआरडीओ ने किया। तवांग में निर्मित यह सुविधा डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को उत्तर–पूर्व क्षेत्र में सीमावर्ती एवं अग्रिम क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं के साथ निकटता बनाए रखते हुए उच्च तुंगता और निम्न तापमान वाले क्षेत्रों में समस्याग्रस्त क्षेत्रों से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों के संचालन के लिए प्रोत्साहित करेगी।

ब्रह्मोस

उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा (यूपीडीआईसी) परियोजना के तहत लखनऊ, उत्तर प्रदेश में एक नया अत्याधुनिक ब्रह्मोस निर्माण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इस हथियार प्रणाली की परिचालन क्षमताओं जैसे कि रेंज, मारक क्षमता और सटीकता में सुधार के लिए इसे निरंतर उन्नत किया जा रहा है। उपयोगकर्ता को प्रदान किए जा रहे ''संपूर्ण समाधान'' में विशेष मिसाइल संचालन और परीक्षण उपकरण, अत्याधुनिक अवसंरचना सुविधाएँ, ऑन–साइट रखरखाव, प्रशिक्षण, निरंतर क्षमता वृद्धि, उन्नयन, अप्रचलन प्रबंधन, मिसाइलों का जीवनकाल विस्तार, भू–प्रणालियों और सीकर सहित मिसाइलों के लिए विशेष और समर्पित मरम्मत सुविधाओं का निर्माण शामिल है।

शॉक ट्यूब परीक्षण सुविधा

डीआरडीओ ने विस्फोट रोधी सामग्रियों और संरचनाओं के मूल्यांकन के लिए डीआरडीओ कौशल विकास केंद्र, पिलखुवा (उत्तर प्रदेश) में 500 मिमी व्यास की शॉक ट्यूब परीक्षण सुविधा स्थापित की है। इस सुविधा का उद्घाटन अगस्त 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सचिव और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के अध्यक्ष द्वारा किया गया।

एमईएमएस उपकरणों के लिए अद्वितीय परीक्षण सुविधा

सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त अनुसंधान केंद्र (एसटीएआरसी) ने बेंगलुरु में माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम (एमईएमएस) उपकरणों के प्रदर्शन और विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने के लिए एक अत्याधुनिक और एनएबीएल–मान्यता प्राप्त परीक्षण सुविधा स्थापित की है। यह उच्च तापमान, आघात, कंपन जैसी चरम पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनुकरण और परीक्षण करने में सक्षम है, और रक्षा एवं एयरोस्पेस में इसके अनुप्रयोगों के लिए चुनौतीपूर्ण परिदृश्यों की प्रतिकृति तैयार करता है। यहां हार्डवेयर के सुरक्षा परीक्षण के लिए और एंड्रॉइड आधारित स्मार्ट उपकरणों के सुरक्षा परीक्षण के लिए भी सुविधा स्थापित की गई है।

कॉर्पोरेट पहल

प्रशिक्षण एवं विकास

डीआरडीओ मुख्यालय स्थित मानव संसाधन विकास निदेशालय ने वर्ष 2024 में आयोजित व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से डीआरडीओ जनशक्ति के ज्ञान एवं कौशल विकास के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।

- **डीआरडीएस के लिए अनिवार्य त्रि–चरणीय प्रशिक्षण**: लगभग 550 वैज्ञानिकों ने डीआरडीएस संवर्ग के कर्मचारियों के लिए चलाए जा रहे त्रि–चरणीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 'पोस्ट इंडक्शन ट्रेनिंग स्कूल (पीओआईएनटीएस), 'मिड–कैरियर ट्रेनिंग ऑग्मेंटेशन (एमआईटीआरए) और 'आवश्यक प्रबंधन कौशल पर विशेष प्रशिक्षण' इस वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

- **सतत शिक्षा कार्यक्रम (सीईपी)** – विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में **78** पाठ्यक्रम संचालित किए गए।

- **प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)**: वरिष्ठ स्तर के वैज्ञानिक अधिकारियों के लिए आईआईएम, एएससीआई, ईएससीआई और एमडीआई द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए।

- नवनियुक्त निदेशकों के लिए **डब्ल्यूवाईएएस (आपके प्रशासनिक कौशल का विस्तार)**।

शिकायत निवारण

डीआरडीओ ने पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा और निवारण हेतु केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) 7.0 का संशोधित संस्करण लागू किया है। 2024 के दौरान डीआरडीओ को कुल 876 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 830 का समाधान कर दिया गया है। शिकायत निवारण सूचकांक के अनुसार डीआरडीओ को 27वाँ स्थान प्राप्त है।

उद्योग इंटरफ़ेस

वर्ष 2024 के दौरान, डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण हेतु भारतीय उद्योगों के साथ 256 एलएटीओटी समझौतों (एलएटीओटीएस) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हालाँकि, मार्च 2025 तक, उद्योग के साथ 1950 एलएटीओटी समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। भारतीय उद्योगों द्वारा डीआरडीओ परीक्षण सुविधाओं का उपयोग करके 5,000 से अधिक परीक्षण किए गए हैं। डीआरडीओ ने रक्षा परीक्षण पोर्टल पर प्रयोगशालाओं को जोड़ने की सुविधा भी प्रदान की है, जो रक्षा मंत्रालय का एक ऐसा मंच है जो रक्षा उद्योगों को मंत्रालय के परीक्षण ढाँचे को अधिक पारदर्शी तरीके से प्रदान करता है।

इसके अलावा, रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, मित्र देशों (एफएफएन) को रक्षा उत्पादों के निर्यात हेतु 91 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' और 15 'सैद्धांतिक अनुमोदन' जारी किए गए। उद्योग मंडलों के सहयोग से उद्योग तक पहुँचने के एक विशेष प्रयास के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास तथा विनिर्माण में उद्योगों की भागीदारी को समर्थन देने हेतु संगठन की नीति को लागू करने के उद्देश्य से डीआरडीओ ने देश भर में 25 से अधिक उद्योग सम्मेलनों का आयोजन किया। ''प्रयोगशालाओं के साथ उद्योग संपर्क समूहों (आईआईजी) के निर्माण हेतु दिशानिर्देश'' जारी किए गए। यह समूह टीओटी, हैंडहोल्डिंग सहायता, परीक्षण सुविधाओं के उपयोग, डीसीपीपी/पीए और टीडीएफ से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे उद्योगों के लिए एकल–खिड़की समाधान सुनिश्चित करता है।

2024 के दौरान, डीआरडीओ की मिशन मोड परियोजनाओं के लिए 19 से अधिक विकास सह–उत्पादन साझेदारों (डीसीपीपी)/उत्पादन एजेंसियों (पीएएस) का चयन किया गया।

राजभाषा

2024 के दौरान, चेन्नई में पहला अखिल भारतीय राजभाषा तकनीकी सम्मेलन (यूएनएमईएसएच–2024) आयोजित किया गया। 'रक्षा अनुसंधान भारती' नामक हिंदी पत्रिका का प्रकाशन किया गया जिसे 15 सितंबर 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर **माननीय गृह मंत्री** द्वारा **'कीर्ति पुरस्कार'** से सम्मानित किया गया।

संसदीय कार्य

वर्ष 2024 के दौरान 'प्राक्कलन समिति', 'रक्षा स्थायी समिति' और 'अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति' ने 'डीआरडीओ के प्रदर्शन', 'डीआरडीओ के विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं के उन्नयन की स्थिति', 'प्रमुख अनुसंधान पहलों सहित सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा स्वदेशी रक्षा उत्पादन का मूल्यांकन', 'संगठन में अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण और प्रतिनिधित्व' और 'अनुदान मांगों (2024–25)' पर विस्तृत परीक्षण के लिए डीआरडीओ का चयन किया है।

स्वच्छता अभियान

भारत सरकार की पहल के अंतर्गत, **स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024** का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता अभियान से संबंधित कई गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिनमें डीआरडीओ के सभी कर्मियों ने योगदान दिया और भाग लिया। डीआरडीओ में ''एक पेड़ माँ के नाम'' पर केंद्रित स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) मनाया गया, स्वास्थ्य जाँच का आयोजन किया गया और सफाई मित्रों को सुरक्षा उपकरण/किट वितरित किए गए।

डीआरडीओ प्रदर्शनियाँ और गणतंत्र दिवस परेड 2024

आउटरीच गतिविधियों के एक भाग के रूप में, डीआरडीओ ने अखिल भारतीय स्तर पर 35 प्रदर्शनियों और पेरिस, विक्टोरिया, त्शवाने, मनीला और हनोई में 5 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया। इन प्रदर्शनियों ने डीआरडीओ को अपने प्रमुख उत्पादों और तकनीकों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान किया। डीआरडीओ ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 में भाग लिया और अपनी झांकी प्रदर्शित की। इस झांकी का विषय था ''सभी पाँच आयामों (भूमि, वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष) में रक्षा प्रौद्योगिकियाँ प्रदान करके राष्ट्र की रक्षा में नारी शक्ति''।

बौद्धिक संपदा अधिकार

कुल 132 बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) दायर किए गए और पूर्व में दायर बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के आधार पर 238 बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) प्राप्त किए गए। इसके साथ ही, डीआरडीओ को अब कुल 1277 पेटेंट और 2779 बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआरएस) प्राप्त हैं।

शैक्षणिक संपर्क

वर्ष 2024 के दौरान, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को 36.90 करोड़ रुपये की लागत वाली 23 परियोजनाएँ स्वीकृत की गईं और वर्तमान में 107.99 करोड़ रुपये की लागत वाली 75 परियोजनाएँ चल रही हैं। अब तक डीआरडीओ ने बाह्य अनुसंधान के लिए कुल 1151.22 करोड़ रुपये की लागत वाली 1292 परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है और वर्ष 2024 के दौरान देश भर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में 45 से अधिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित 213 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2024 के दौरान, आयुध, नौसेना, जीवन विज्ञान और वैमानिकी के क्षेत्र में 4 अनुसंधान बोर्डों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास केंद्रों में उनके तकनीकी क्षेत्रों से संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु अनुसंधान गतिविधियों को समर्थन देने के लिए 108.35 करोड़ रुपये की लागत से 116 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में 249.97 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 319 परियोजनाएँ चल रही हैं।

वर्तमान में, देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में 15 डीआईए–सीओई स्थित हैं, जो लगभग 82 चिन्हित अनुसंधान क्षेत्रों में स्थानांतरीय अनुसंधान गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। अब तक, 1022.38 करोड़ रुपये की लागत से 279 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 120 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। इन डीआईए–सीओई में कुल 49 शैक्षणिक संस्थान, 532 संकाय, 930 शोधकर्ता और डीआरडीओ के 354 वैज्ञानिक कार्यरत हैं।

थिंक टैंकों के साथ जुड़ाव

डीआरडीओ अपने मज़बूत तकनीकी आधार और प्रतिष्ठित थिंक टैंक संस्थानों, जैसे सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज़ (सीएपीएस), मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस (एमपी–आईडीएसए), विवेकानंद इंटरनेशनल फ़ाउंडेशन (वीआईएफ), सेंटर फॉर जॉइंट वारफेयर स्टडीज़ (सीईएनजेओडब्ल्यूएस), इंडियन स्पेस एसोसिएशन (आईएसपीए) और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ़ इंडिया (यूएसआई) की भू–राजनीतिक विशेषज्ञता के बीच सहयोग को सक्रिय बढ़ावा दे रहा है।

प्रौद्योगिकी विकास निधि

वर्ष के दौरान, विभिन्न उद्योगों/एमएसएमईएस/स्टार्टअप्स को कुल 42.84 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 09 परियोजनाएँ प्रदान की गई हैं और वर्तमान में प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत कुल 334.10 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 79 परियोजनाएँ विकासाधीन हैं। इन परियोजनाओं को भी काफ़ी सफलता मिली है, जिनमें 26 तकनीकों का सफलतापूर्वक विकास किया गया है और दो परियोजनाओं को पीएसएलवी मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजा गया है। 2024–25 की बजट घोषणा के अनुरूप, डीपटेक और अत्याधुनिक तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए टीडीएफ योजना के लिए 500 करोड़ रुपये अतिरिक्त स्वीकृत किए गए हैं।

सपने देखने का साहस

राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता डी2डी 4.0 वर्ष 2023 में शुरू की गई थी। डीआरडीओ के विभिन्न प्रौद्योगिकी समूहों द्वारा पहचाने गए रक्षा और एयरोस्पेस प्रौद्योगिकियों के 10 चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों के लिए भारतीय व्यक्तियों और स्टार्टअप्स से लगभग 4000 विचार और समाधान प्राप्त हुए। 18 अक्टूबर 2024 को डीआरडीओ भवन में माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आंतरिक मूल्यांकन समिति द्वारा कुल 31 विजेताओं का चयन किया गया, जिनमें से 13 स्टार्टअप श्रेणी से और 18 व्यक्तिगत श्रेणी से थे। इन व्यक्तियों और स्टार्टअप्स को कुल 146 लाख रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई।

माननीय रक्षा मंत्री ने प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) के अंतर्गत रक्षा अनुप्रयोगों के लिए परिवर्तनकारी विचारों के साथ आगे आने वाले नवप्रवर्तकों के लिए डेयर टू ड्रीम 5.0 का शुभारंभ किया। माननीय रक्षा मंत्री द्वारा रक्षा एवं एयरोस्पेस प्रौद्योगिकियों के परिभाषित चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में नवप्रवर्तकों/स्टार्ट–अप्स/एमएसई को प्रोत्साहन/समर्थन प्रदान करने हेतु एक नवाचार प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया गया। रक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रमुख प्रगति को गति देने के लिए डीप–टेक चुनौतियों का अनावरण किया गया और इस कार्यक्रम में टीडीएफ योजना के तहत विकसित प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया और उन्हें उपयोगकर्ताओं को सौंपा गया।

100 दिवसीय प्रमुख कार्य योजना

विकसित भारत @2047 – एक विकसित भारत को दृष्टिकोण को आधार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित 100 दिवसीय लक्ष्य में, डीआरडीओ के निम्नलिखित प्रमुख एजेंडा थे जिन्हें 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल किया गया।

क्र.स.	कार्यसूची बिंदु	स्थिति
1	मल्टी–पेटाफ्लॉप कंप्यूटिंग सुविधा का कमीशनिंग और संचालन।	सुविधा चालू हो गई है और 24X7 चालू है तथा इसके उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिए गए हैं।
2	बाह्य अनुसंधान निदेशालयों और 04 अनुसंधान बोर्डों का एक इकाई में विलय।	बाह्य अनुसंधान निदेशालय (ईआर) और चार अनुसंधान बोर्डों का अब विलय हो गया है और वे जुलाई 2024 से एक एकल इकाई के रूप में संचालित हो रहे हैं।
3	प्रौद्योगिकी दिशानिर्देशों का सरल हस्तांतरण	डीआरडीओ की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नीति 2025 को फरवरी 2025 में अनुमोदित किया गया था।
4	मध्यम ऊंचाई में उड़ान भरने वाले लंबी क्षमता के मानवरहित स्वदेशी हवाई वाहन (टीएपीएएस और इसके विभिन्न प्रकार) की पूर्व–संचालन भूमिका में उड़ान।	अब तक एटीआर, चित्रदुर्ग में एएफ6, की 11 उड़ानें भरी जा चुकी हैं, जिनमें विन्यास स्वतंत्र पेलोड (एसएआर, एमआरईओ, आईएफएफ, यूसीआर, एसएटीसीओएम) का मूल्यांकन किया जा रहा है। एएफ–11 ने 46 नॉट तक की गति पर टैक्सी परीक्षण पूरे कर लिए हैं और यह सीईएमआईएलएसी एवं डीजीएक्यूए की मंजूरी पर आधारित है।
5	विकास सह उत्पादन भागीदार (डीसीपीपी), डीआरडीओ उद्योग शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र (डीआईए–सीओई) और प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) के माध्यम से उद्योग की भागीदारी बढ़ाने की प्रक्रियाएँ।	प्रक्रियाओं को मंजूरी दे दी गई है।
6	डीआरडीओ में भर्ती प्रक्रिया का नया चैनल शुरू करना	नई भर्ती विधियों, जैसे कि कैंपस भर्ती, परियोजना आधारित जनशक्ति (गैर–सीसीएस) और विज्ञान वीर, के कार्यान्वयन हेतु नीतियों को अंतिम रूप दे दिया गया है और विचार एवं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है।

*****

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

सत्यमेव जयते

रक्षा मंत्रालय
भारत सरकार

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (डीईएसडब्ल्यू) देश में भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के कल्याण और पुनर्वास के लिए विभिन्न नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करता है। इस विभाग के दो प्रभाग हैं: पुनर्वास और पेंशन, और इसके तीन संबद्ध कार्यालय हैं: केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी), पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) और केंद्रीय संगठन, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (सीओ, ईसीएचएस)।

पेंशन सुधार

भारत सरकार ने रक्षा सेनाओं के कर्मियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया जिसकी प्रारंभिक नीति 7 नवंबर, 2015 को जारी की गई थी और यह 1 जुलाई, 2014 से प्रभावी हुई। ओआरओपी के तहत, संबंधित कैलेंडर वर्ष में समान रैंक और सेवा अवधि में सेवानिवृत्त हुए कर्मियों की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर हर पाँच साल में पेंशन का पुनर्निर्धारण किया जाता है। इस औसत से अधिक पेंशन को संरक्षित किया जाता है ताकि पेंशनभोगियों को कोई नुकसान न हो।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 दिसंबर, 2022 को ओआरओपी के तहत पेंशन संशोधनों को मंजूरी दे दी, जो 1 जुलाई, 2019 से प्रभावी हुए। इसके बाद 3 जुलाई, 2024 को एक और संशोधन को मंजूरी दी गई, जो 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी हुआ। इसके लिए विस्तृत निर्देश और संशोधित पेंशन तालिकाएँ 4 सितंबर, 2024 को जारी की गई। इस संशोधन से लगभग 24.36 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा, जिनमें 3.54 लाख नए लाभार्थी शामिल हैं। पिछले एक दशक में, ओआरओपी के कारण पेंशन में लगभग 1.24 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त वितरण हुआ है।

शिकायत निवारण प्रणाली

डीईएसडब्ल्यू शिकायतों को कम करने, निपटान समय को कम करने और हमारे पूर्व सैनिकों के साथ संवाद और बातचीत को बढ़ावा देने के साथ–साथ पूर्व सैनिकों की शिकायतों के समाधान के लिए राज्य सैनिक बोर्ड (आरएसबी)/जिला सैनिक बोर्ड (जेडएसबी) को संवेदनशील बनाने के लिए ठोस प्रयास करता है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (डीईएसडब्ल्यू) का रक्षा (पेंशन/शिकायत) अनुभाग पूर्व सैनिकों/पेंशनभोगियों से संबंधित ऑनलाइन/ऑफलाइन शिकायतें प्राप्त करता है। पूरे कैलेंडर वर्ष अर्थात् 1 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 तक कुल 57,583 (सत्तावन हजार पांच सौ तिरासी) शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 54,539 (95%) (चौवन हजार पांच सौ उनतालीस) शिकायतों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया और औसत निपटान समय 27 दिन था।

कल्याण

राज्यों को वित्तीय सहायता– केएसबी सचिवालय भारत सरकार का शीर्ष निकाय है जो युद्ध–विधवाओं/निःशक्त सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए उत्तरदायी है। राज्य सैनिक बोर्ड/जिला सैनिक बोर्ड (आरएसबी/जेडएसबी) के स्थापना व्यय के लिए केएसबी के माध्यम से विभाग द्वारा केंद्रीय हिस्से के रूप में राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है। विशेष श्रेणी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के संबंध में निधीयन पैटर्न 75:25 है, और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 60:40 है। भारत सरकार रक्षा सेवा अनुमान (डीएसई) बजट से सैनिक विश्राम गृहों (एसआरएच) के निर्माण की 50% लागत भी साझा करती है। सैनिक विश्राम गृहों का रखरखाव राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा अपने संसाधनों/निधियों से किया जाना अपेक्षित है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान केंद्रीय हिस्से के रूप में केएसबी के माध्यम से राज्यों को 179.84 करोड़ रुपये (31 मार्च 2025 तक) वितरित किए गए हैं।

सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष – सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) का उद्देश्य पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण हेतु योजनाएँ चलाना है। इस कोष का प्रबंधन केएसबी द्वारा किया जाता है और इसमें दिए गए दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के अंतर्गत छूट के पात्र हैं। इस कोष को तीनों सेनाओं, कॉर्पोरेट्स, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी दानदाताओं से योगदान प्राप्त होता है। इस कोष की कुल राशि 360.02 करोड़ रुपये है और एएफएफडीएफ की कुल राशि से प्राप्त होने वाली उपयोग योग्य आय का एक हिस्सा रक्षा मंत्री पूर्व सैनिक कल्याण कोष (आरएमईडब्ल्यूएफ) योजनाओं के लिए निर्धारित किया जाता है।

रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष (आरएमईडब्ल्यूएफ) योजनाएँ– आरएमईडब्ल्यूएफ के अंतर्गत पूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों की चिन्हित व्यक्तिगत आवश्यकताओं, जैसे गरीबी अनुदान, बाल शिक्षा एवं विवाह अनुदान, चिकित्सा अनुदान आदि के लिए एएफएफडीएफ से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024–25 (31 मार्च 2025 तक) के दौरान, भूतपूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों के नामे 178091 लाभार्थियों को 370.15 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। इसके अलावा, किरकी और मोहाली स्थित युद्ध स्मारक छात्रावासों और पैराप्लेजिक पुनर्वास केंद्रों को 2.13 करोड़ रुपये का वित्तीय अनुदान भी दिया गया है। सभी कल्याणकारी योजनाओं की समय–समय पर समीक्षा की जा रही है।

गौरव माह – सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर साल 7 दिसंबर को देश भर में सशस्त्र सेनाओं द्वारा दिए गए बलिदानों की स्मृति में मनाया जाता है। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, 2024 तक **"गौरव माह"** के रूप में मनाए जाने वाले एक महीने के अभियान के दौरान, झंडा दिवस के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गई, जैसे प्रिंट/सोशल मीडिया का उपयोग और पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के रेडियो साक्षात्कार ताकि झंडा दिवस के महत्व के बारे में जागरूकता लाई जा सके।

7 दिसंबर 2024 को केएसबी के सचिव माननीय प्रधानमंत्री को एएफएफडी ध्वज लगाते हुए

13 दिसंबर 2024 को भारत की महामहिम राष्ट्रपति को एएफएफडी ध्वज पहनाने के दौरान केएसबी के अधिकरियों के साथ सचिव (ईएसडब्ल्यू) और संयुक्त सचिव (ईएसडब्ल्यू)

सीएसआर कॉन्क्लेव– 03 मार्च 2025 को मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली में एक सीएसआर कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। कॉन्क्लेव के दौरान, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में उनके उदार योगदान के लिए माननीय रक्षा मंत्री द्वारा एएफएफडी के प्रमुख योगदानकर्ताओं को सम्मानित किया गया। पिछले तीन वर्षों में सीएसआर योगदान में हुई वृद्धि इस प्रकार है:–

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	सीएसआर योगदान (रुपये में)
(क)	2022–23	23.64 करोड़
(ख)	2023–24	41.68 करोड़
(ग)	2024–25	56.29 करोड़

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएस)– इस योजना के अंतर्गत पूर्व सैनिकों के बच्चों और विधवाओं को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा प्रशासित राष्ट्रीय रक्षा कोष से प्रतिवर्ष कुल 5500 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान 16,380 लाभार्थियों को 55.06 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की जा चुकी है।

पूर्व सैनिक दिवस– नौवाँ सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी, 2025 को मनाया गया। इस वर्ष, समारोह का विस्तार किया गया और नौ स्थानों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अखनूर में मुख्य समारोह की अध्यक्षता की। मुंबई में पूर्व सैनिक दिवस समारोह की अध्यक्षता रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने की। इन कार्यक्रमों में सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों, उनके परिजनों, पूर्व सैनिकों और विभिन्न पूर्व सैनिक संगठनों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया।

केएसबी सचिव ने वेटरन दिवस 2025 पर पूर्व–सैनिकों के साथ बातचीत की

मानेकशॉ सेंटर में केएसबी अधिकारी

अतिरिक्त आरएसबी/जेडएसबी की स्थापना– पांच नए जेडएसबी–गुजरात में पोरबंदर जिले और सुरेन्द्र नगर जिले में, पश्चिम बंगाल में कलिम्पोंग, राजस्थान में राजसमंद (भीम) और उत्तराखंड के देहरादून में हरबर्टपुर में, स्थापित किए गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव– 21 जून, 2024 को **"स्वयं और समाज के लिए योग"** थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सामान्य योग प्रोटोकॉल के अभ्यास के अलावा, योग संबंधी गतिविधियाँ भी आयोजित की गईं और इनमें डीईएसडब्ल्यू और इसके संबद्ध कार्यालयों अर्थात् केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी), पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) और केंद्रीय संगठन, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (सीओ, ईसीएचएस) सहित उनके क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों द्वारा भाग लिया गया।

केएसबी सचिवालय सीएसआरएच नारायणा, दिल्ली में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हुए

सरकारी उपलब्धियां और योजनाएं एक्सपो 2024— केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 20.07.2024 से 22.07.2024 तक 10वें सरकारी उपलब्धियों और योजनाओं के एक्सपो 2024 में एक स्टॉल लगाया गया था, जिसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों के मुद्दों/प्रश्नों को संबोधित/उनका समाधान करना और वीर नारियों/विधवाओं/पूर्व सैनिकों (ईएसएम) आदि के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित करना था।

प्रगति मैदान में आयोजित 10वां सरकारी उपलब्धियां और योजनाएं एक्सपो 2024

स्वच्छता अभियान— "स्वच्छता ही सेवा 2024" के लिए 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2024 तक विशेष अभियान चलाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों में कमी लाना, कार्यालय परिसर की समग्र स्वच्छता और कार्यालय स्थान का कुशल प्रबंधन करना था। शिकायतों की निगरानी और निपटान, संदर्भ मामलों की समीक्षा और आरएसबी/जेडएसबी स्तर पर विशेष आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा, दिसंबर 2024 के दौरान स्वच्छता पखवाड़ा अभियान भी चलाया गया।

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड और आरएसबी/जेडएसबी में स्वच्छता अभियान

पुनर्वास

पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर)– डीजीआर को पूर्व सैनिकों (ईएसएम), दिव्यांग सैनिकों, विधवाओं और उनके आश्रितों के पुनःस्थापना और पुनर्वास के लिए अधिदेशित किया गया है। परिचालन और प्रशासनिक कारणों से, लगभग 60,000 से 70,000 सशस्त्र सेना कार्मिक हर वर्ष सक्रिय सेवा से सेवानिवृत्त/मुक्त होते हैं, जिनमें से अधिकांश 35 से 45 वर्ष की अपेक्षाकृत कम आयु वर्ग के होते हैं और उन्हें अपने परिवारों का भरण–पोषण करने के लिए 'दूसरे करियर' की आवश्यकता होती है। इस दिशा में, डीजीआर इन पूर्व सैनिकों/आश्रितों के लिए पुनर्वास योजनाएँ संचालित कर रहा है।

सेवामुक्ति–पूर्व/कौशल विकास पाठ्यक्र– डीजीआर को तीनों सेनाओं के सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त सशस्त्र सेना कार्मिकों के लिए पुनर्वास प्रशिक्षण/कौशल विकास पाठ्यक्रम आयोजित करने और संचालित करने का दायित्व सौंपा गया है। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य सिविल/कॉर्पोरेट क्षेत्र में उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है।

अधिकारियों के लिए प्री–रिलीज़ पाठ्यक्रम– अधिकारियों के लिए, आईआईएम/समान प्रमुख प्रबंधन संस्थानों में पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इन पाठ्यक्रमों की अवधि 2 सप्ताह से 24 सप्ताह तक होती है। अधिकारियों के पाठ्यक्रमों की फीस सरकार और प्रत्येक अधिकारी द्वारा 60:40 के अनुपात में वहन की जाती है। नए संस्थानों को शामिल करके और उद्योग की आवश्यकताओं और पूर्व सैनिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले पाठ्यक्रम विकसित करके इन पाठ्यक्रमों के दायरे और पहुँच को व्यापक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना में जेसीओ/ओआर और उनके समकक्षों के लिए कौशल विकास पाठ्यक्रम– कौशल विकास और उद्यमिता विकास पाठ्यक्रम जेसीओ /ओआर अथवा उनके समकक्ष के लिए भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में अखिल भारत में विभिन्न सरकारी संस्थानों में अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए आयोजित किये जाते हैं। उक्त पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क का पूरा खर्च भारत सरकार/रक्षा मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान प्रशिक्षण– चालू वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान कुल 277 पाठ्यक्रम (20 अधिकारी पाठ्यक्रम सहित) आयोजित किए गए हैं। इन प्रशिक्षण पहलों से कुल 804 अधिकारी और 10,783 जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी एवं अन्य रैंक (जेसीओ/ओआर) लाभान्वित हुए। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष जेसीओ/ओआर की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ईएसएम के लिए केंद्र सरकार में रोजगार के अवसर– केंद्र सरकार ने पूर्व–सैनिकों के पुनर्वास के लिए सरकारी नौकरियों में निम्नलिखित आरक्षण कोटा प्रदान किया है :–

(क) सभी अर्धसैनिक बलों (सीएपीएफ) में सहायक कमांडेंट स्तर तक के पदों में 10% रिक्तियां।

(ख) केन्द्रीय सरकार के विभागों में ग्रुप 'सी' सीधी भर्ती के पदों में 10% रिक्तियां तथा ग्रुप 'डी' सीधी भर्ती के पदों में 20% रिक्तियां।

(ग) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ग्रुप 'सी' पदों में 14.5% रिक्तियां तथा ग्रुप 'डी' पदों में 24.5% रिक्तियां (जिनमें विकलांग ईएसएम/युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए 4.5% रिक्तियां शामिल हैं) आरक्षित हैं।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ग्रुप 'सी' पदों में 14.5% रिक्तियां तथा ग्रुप 'डी' पदों में 24.5% रिक्तियां (जिनमें विकलांग ईएसएम/युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए 4.5% रिक्तियां शामिल हैं) आरक्षित हैं।

(ड़) रक्षा सुरक्षा कोर (डीएससी) में 100%।

रोजगार के लिए प्रायोजित ईएसएम – कुल 3104 (01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक) पूर्व सैनिकों को डीजीआर और आरएसबी/जेडएसबी के माध्यम से स्थायी/संविदागत नौकरियों (स्व–रोजगार योजनाओं को छोड़कर) के लिए विभिन्न संगठनों (सरकारी/निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) में प्रायोजित किया गया।

डीजीआर सुरक्षा एजेंसी योजना – यह डीजीआर की एक 'प्रमुख' परियोजना है जो पूर्व सैनिकों (ईएसएम) को अधिकतम रोजगार प्रदान करती है। पूर्व सैनिक (अधिकारी) इस योजना के स्वामी हैं, जिनमें जेसीओ/ओआर और भारतीय नौसेना/भारतीय वायु सेना में उनके समकक्ष सुरक्षा पर्यवेक्षक/गार्ड के रूप में कार्यरत हैं। वर्ष 2024–25 के दौरान कुल 855 सुरक्षा एजेंसियों को पैनलबद्ध किया गया है और इस योजना के अंतर्गत 33,858 पूर्व सैनिकों (ईएसएम) को रोजगार प्रदान किया गया।

डीजीआर तकनीकी सेवा योजना – डीजीआर, पैनलबद्ध राज्य ईएसएम निगमों के माध्यम से सरकारी प्रतिष्ठानों/परिसरों को 'तकनीकी सेवाओं' के लिए पूर्व सैनिकों के रूप में जनशक्ति प्रदान करता है। यह योजना हाल ही में शुरू की गई है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान इस योजना के तहत कुल 316 तकनीकी जनशक्ति और 8883 ईएसएम को रोजगार प्रदान किया गया है।

स्वरोजगार के लिए योजनाएँ

डीजीआर के माध्यम से रोजगार के अवसर – डीजीआर सेवानिवृत्त अधिकारियों, जेसीओ/ओआर और भारतीय सेना/भारतीय वायुसेना में उनके समकक्षों, विकलांग सैनिकों, विधवाओं और उनके आश्रितों के रोजगार और कल्याण हेतु पुनर्वास योजनाएँ संचालित करता है। वर्ष 2024–25 में प्रमुख योजनाएँ और उनके माध्यम से लाभार्थियों की संख्या नीचे दी गई है:–

क्रम सं.	योजना	लाभार्थियों की संख्या
(क)	मदर डेयरी दूध बूथ और फल एवं सब्जी (सफल) की दुकान	647
(ख)	दिल्ली/एनसीआर और पुणे में ईएसएम (अधिकारी) द्वारा सीएनजी स्टेशन का प्रबंधन	16
(ग)	8% आरक्षण कोटा के तहत एलपीजी/खुदरा आउटलेट (पेट्रोल/डीजल) के आवंटन के लिए डीजीआर पात्रता प्रमाण पत्र जारी करना	03
(घ)	कंपनी के स्वामित्व वाली व कंपनी द्वारा संचालित (सीओसीओ) खुदरा दुकानों का प्रबंधन	205
(ङ)	प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का प्रबंधन	14

पूर्व सैनिक सेमिनार/रोजगार मेले – वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान अखिल भारत में बारह पूर्व सैनिक रोजगार सेमिनार/नौकरी मेले आयोजित किए गए। सेमिनार/नौकरी मेले में 520 कंपनियों ने भाग लिया और 15927 पूर्व सैनिकों ने रोजगार हेतु पंजीकरण कराया।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) – पूर्व सैनिकों के लिए विशेष प्रोत्साहन (सामान्य प्रोत्साहन के अलावा 2 लाख रुपये का एकमुश्त अनुदान) के साथ पीएमबीजेपी को फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) के सहयोग से जून 2023 से लागू किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान इस योजना के तहत कुल 14 पूर्व सैनिक लाभान्वित हुए।

स्वास्थ्य देखभाल

पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) 1 अप्रैल, 2003 से शुरू की गई थी। ईसीएचएस का उद्देश्य देश भर में फैले ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स, सैन्य चिकित्सा सुविधाओं और सिविल पैनलबद्ध/सरकारी अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। यह योजना केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की तर्ज पर बनाई गई है और भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए पैनलबद्ध अस्पतालों का उपयोग करके, जहाँ तक संभव हो, नकद रहित उपचार सुनिश्चित करने का प्रयास किया

जाता है। इस योजना के कुल लाभार्थी लगभग 59 लाख हैं। इस योजना का विस्तार नेपाल में छह पॉलीक्लिनिक्स के साथ गोरखा अधिवासियों तक भी किया गया है।

सेवाओं का विस्तार : जनशक्ति को बढ़ाने सहित 23 नए पॉलीक्लिनिकों के निर्माण और 50 मौजूदा पॉलीक्लिनिकों के उन्नयन को मंजूरी दी गई है और यह कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।

अस्पतालों का पैनलीकरण : वर्तमान में लगभग 3000 अस्पताल ईसीएचएस के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। गुणवत्तापूर्ण अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के उद्देश्य से, मुंबई, विशाखापत्तनम, वाराणसी, गुवाहाटी और संगरूर में टाटा मेमोरियल अस्पताल (टीएमएच) का पैनलीकरण पूरा हो चुका है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों/सरकारी आयुष अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के लिए समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दे दी गई है। विगत पाँच महीनों के दौरान, भोपाल, रायपुर, हैदराबाद, गोरखपुर, इलाहाबाद, रायबरेली, ऋषिकेश और जोधपुर स्थित एम्स का पैनलीकरण किया गया है।

ईसीएचएस के लिए आईटी अवसंरचना का विकास : ईसीएचएस के स्वास्थ्य सेवा वितरण तंत्र को डिजिटल रूप से रूपांतरित करने और एक व्यापक, एकीकृत और स्वचालित प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करके योजना संचालन के निर्बाध और संपूर्ण प्रबंधन हेतु एक एकीकृत आईटी प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से, जो इनपुट, प्रक्रियाओं और योजना परिणामों को कुशलतापूर्वक संचालित कर सके, सूक्ष्म सेवा वास्तुकला पर आधारित एक एकीकृत प्रणाली की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना को 'आंतरिक क्षमता विकास कार्यक्रम' के माध्यम से विकसित किया जाना है। डिजिटलीकरण प्रक्रिया ईसीएचएस तंत्र को अधिक कुशलता से संचालित करने, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रित परिवारों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच और गुणवत्ता में सुधार करने और मैनुअल प्रणाली पर बोझ कम करने में सक्षम बनाएगी।

उन्नत ईसीएचएस मोबाइल ऐप की शुरूआत : 13 दिसंबर, 2024 को दिल्ली कैंट स्थित ईसीएचएस भवन में डीईएसडब्ल्यू के सचिव डॉ. नितेन चंद्रा द्वारा एक उन्नत ईसीएचएस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ऐप का नया संस्करण अधिक उपयोगकर्ता–अनुकूल इंटरफ़ेस के साथ तैयार किया गया है और एक सुगम पंजीकरण प्रक्रिया प्रदान करता है। यह लाभार्थियों को पॉलीक्लिनिक में डॉक्टरों के साथ अपॉइंटमेंट पहले से बुक करने की सुविधा देता है और रेफरल इतिहास और स्मार्ट कार्ड उपयोग जैसी आवश्यक जानकारी तक पहुँच प्रदान करता है। ऐप के माध्यम से, उपयोगकर्ता अपने मोबाइल फोन से ही वार्षिक सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं, कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं, कार्ड खो जाने की सूचना दे सकते हैं, या अपने मूल पॉलीक्लिनिक को बदल सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, यह ऐप उपयोगकर्ताओं को अपने कार्ड आवेदनों की स्थिति, पात्रता और प्रतिपूर्ति दावों की जांच करने में सक्षम बनाता है। यह अस्पतालों और पॉलीक्लिनिक्स में प्राप्त सेवाओं के बारे में फीडबैक जमा करने की सुविधा भी प्रदान करता है और उपयोगकर्ताओं को सूचीबद्ध अस्पतालों की खोज करने में मदद करता है। एक अभिनव विशेषता में ईसीएचएस एसपीएआरसीएच स्वयंसेवी सेवाओं के लिए आवेदन करने का विकल्प शामिल है, जो ईसीएचएस और गैर–ईसीएचएस लाभार्थियों दोनों के लिए और साथ ही एनसीसी स्वयंसेवकों के लिए खुला है। यह ऐप संबंधित प्राधिकारियों, जैसे कि मूल पॉलीक्लिनिक के प्रभारी अधिकारी और ईसीएचएस के सीओ, से पुश सूचनाएँ भी भेजता है। उपयोगकर्ता की सुविधा के लिए, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के एक खंड और एक सहायता बूथ को एकीकृत किया गया है। अपग्रेडेड ऐप अब एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफार्मों पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है, जो ईसीएचएस सदस्यों के लिए बेहतर सेवा और बढ़ी हुई पहुँच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ई–सेहत ओपीडी प्लेटफार्म का समावेश : ई–सेहत प्लेटफॉर्म को शामिल करने के लिए केंद्रीय संगठन ईसीएचएस और सीडैक, मोहाली के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और ई–सेहत मॉड्यूल का प्रमाणन किया जा चुका है। सभी चिकित्सा अधिकारियों (एमओ) को निदेशक क्षेत्रीय समन्वयकों द्वारा ई–सहेत टेली–कंसल्टेंसी ओपीडी पोर्टल पर जोड़ा गया है और ई–सेहत मॉड्यूल को लागू करने के लिए पॉलीक्लिनिक्स के चिकित्सा अधिकारियों (एमओ) का टेली–कंसल्टेंसी हेतु प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। क्षेत्रीय केंद्र दिल्ली–I और क्षेत्रीय केंद्र दिल्ली–II में पीसी के लिए 27 फरवरी 2025 को ई–सेहत का एक परीक्षण पायलट प्रोजेक्ट आयोजित किया गया था। इससे ईसीएचएस लाभार्थी घर बैठे टेली–कंसल्टेंसी प्राप्त कर सकेंगे।

*****

महिला सशक्तिकरण और कल्याण

सत्यमेव जयते

रक्षा मंत्रालय

भारत सरकार

महिला सशक्तिकरण और कल्याण

हाल ही के वर्षों में, रक्षा क्षेत्र में एक रूपांतरकारी बदलाव देखा गया है क्योंकि महिलाएँ लगातार बाधाओं को तोड़ रही हैं और सेना, कानून प्रवर्तन और सुरक्षा बलों में अपनी भूमिकाओं को नए सिरे से परिभाषित कर रही हैं। जो क्षेत्र कभी पुरुष–प्रधान था, अब महिलाओं के योगदान से पहचाना जाने लगा है, जो न केवल गैर–युद्धक पदों पर कार्यरत हैं, बल्कि युद्ध, नेतृत्व और विशिष्ट भूमिकाओं में भी उत्कृष्टता प्राप्त कर रही हैं। यह उभरता हुआ रुझान दुनिया भर के सबसे चुनौतीपूर्ण और प्रतिष्ठित क्षेत्रों में से एक में लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

रक्षा क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने और समर्थन देने के उद्देश्य से की गई प्रमुख पहलों और उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है:–

भारतीय सेना

महिलाओं को करियर पाठ्यक्रम, विदेशी अनुभव और दुर्गम क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण नियुक्तियों सहित समान अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। 1992–2008 बैच की महिला अधिकारियों (डब्ल्यूओ) के लिए विशेष चयन बोर्ड का गठन किया गया है और उन्हें चुनौतीपूर्ण कमान नियुक्तियाँ दी गई हैं। विशेष चयन बोर्ड के माध्यम से 507 डब्ल्यूओ को स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है। आर्टिलरी कोर में महिला अधिकारियों की कमीशनिंग से लड़ाकू शाखाओं को छोड़कर, सभी शाखाओं और सेवाओं में उनकी उपस्थिति में वृद्धि हुई है। महिला अधिकारियों को गैर–विभागीय प्रादेशिक सेना अधिकारियों के रूप में भी कमीशन दिया जा रहा है और अब तक ऐसी नौ अधिकारियों को शामिल किया जा चुका है।

महिला अधिकारियों का प्रशिक्षण : काउंटर इंसर्जेंसी जंगल वॉरफेयर स्कूल में चुनौतीपूर्ण कम तीव्रता वाले संघर्ष संचालन पाठ्यक्रम और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में माउंटेन वॉरफेयर (बेसिक) पाठ्यक्रम में महिला अधिकारियों की भागीदारी, भारतीय सेना में एक परिवर्तनकारी क्षण का प्रतीक है। पहली बार, महिला अधिकारियों को पारंपरिक रूप से पुरुषों के वर्चस्व वाले शारीरिक रूप से कठिन पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है, जो उनके साहस और समुत्थानशीलता को दर्शाता है। यह कदम भारतीय सेना द्वारा लैंगिक तटस्थता को बढ़ाने के निरंतर प्रयासों के अनुरूप है। दोनों पाठ्यक्रम, जो अपने कठोर प्रशिक्षण और मानसिक एवं शारीरिक सहनशक्ति की परीक्षा के लिए जाने जाते हैं, भारतीय सेना के प्रगतिशील, विविध और समावेशी दृष्टिकोण के प्रमाण हैं।

'नारी योद्धा' स्काईडाइविंग टीम : भारतीय सेना महिला स्काईडाइविंग टीम का गठन शुरू हो गया है। चरण–I प्रशिक्षण के अंतर्गत, सितंबर–अक्टूबर 2024 में 21 महिला अधिकारियों/महिला सैन्य पुलिस कर्मियों के लिए बुनियादी स्काईडाइविंग टीम पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

नारी योद्धा स्काईडाइविंग टीम

संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक मिशन : वर्तमान में विभिन्न मिशनों में 23% स्टाफ अधिकारी/सैन्य पर्यवेक्षक महिलाएं हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों के अनुरूप है। विभिन्न मिशनों में पहले से तैनात तीन महिला एंगेजमेंट टीमों (एफईटी) के अतिरिक्त, जुलाई 2024 में यूएनएमआईएसएस में एक महिला एंगेजमेंट टीम (एफईटी) को शामिल किया गया है। 2025 के मध्य तक दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (यूएनएमआईएसएस) और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (यूएनआईएफआईएल) में ऐसी और टीमों को तैनात करने की योजना है, जिससे प्रत्येक संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ महिला एंगेजमेंट टीम (एफईटी) सुनिश्चित हो सके। महिला शांति रक्षकों के बढ़ते प्रतिनिधित्व से स्थानीय लोगों तक पहुँच बढ़ी है।

संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार: संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय ने वर्ष 2016 में 'सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार' की स्थापना की। यह पुरस्कार उस सैन्य शांति रक्षक को दिया जाता है जिसने शांति स्थापना गतिविधियों में जेंडर दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से समाहित किया हो। मोनुस्को में एफईटी कमांडर मेजर राधिका सेन को वर्ष 2023 के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया, जो लैंगिक समानता और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के अधिकार को बढ़ावा देने के प्रति हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

खेलों में महिला सैन्य पुलिस (डब्ल्यूएमपी) का प्रदर्शन

- **पेरिस ओलंपिक**: मिलिट्री पुलिस कोर (सीएमपी) की हवलदार (अब नायब सूबेदार) (डब्ल्यूएमपी) जैस्मीन लम्बोरिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में मुक्केबाजी (57 किलोग्राम वर्ग) में भाग लिया। उन्हें अक्टूबर 2024 में नायब सूबेदार के पद पर पदोन्नत किया गया है।

- **अंडर–23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता :**

हवलदार साक्षी ने काज़ा में हुए ब्रिक्स खेल 2024 में मुक्केबाजी (57 किलो ग्राम वर्ग) में रजत पदक जीता

हवलदार (डब्ल्यूएमपी) प्रियंका ने जॉर्डन के अम्मान में हुई अंडर–23 एशियन कुश्ती प्रतियोगिता में कुश्ती में रजत पदक जीता

भारतीय नौसेना

भारतीय नौसेना ने एक सच्ची लैंगिक रूप से तटस्थ और समावेशी सेना बनने की दिशा में, कथनी और करनी, दोनों ही नज़रियों से महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारतीय नौसेना ने सभी शाखाओं में महिलाओं को शामिल करना शुरू कर दिया है, और अब भारतीय नौसेना में महिलाओं के लिए करियर में प्रगति के सभी अवसर उपलब्ध हैं ।

महिला अग्निवीर : भारतीय नौसेना देश के कार्यबल की जीवंत 'नारी शक्ति' का सदुपयोग करने के लिए अग्निपथ का लाभ उठाने वाली पहली सेवा बन गई है। महिला अग्निवीरों को नियमित नाविकों के रूप में चयन हेतु उनके पुरुष समकक्षों के समान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और नामांकन संबंधी मानदंडों का पालन करना होगा। महिला नाविकों को नाविकों के सभी व्यवसायों में, जहाज़ों पर अग्रिम पंक्ति की परिचालन इकाइयों में भी, नियुक्त किया जाएगा। दिसंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार, भारतीय नौसेना में 1321 महिला अग्निवीर शामिल हैं।

महिला खिलाड़ियों का नामांकन : भारत सरकार ने 17 अगस्त, 2023 को सशस्त्र सेनाओं में मेधावी खिलाड़ियों के सीधे नामांकन की घोषणा की थी। इस योजना के अंतर्गत, चयनित उम्मीदवार (पुरुष और महिला दोनों) हवलदार/नायब सूबेदार और समकक्ष पदों पर मेधावी खिलाड़ियों के रूप में नामांकन के पात्र हैं। तदनुसार, पहली बार, 12 महिला खिलाड़ियों को भारतीय नौसेना में नाविकों के रूप में शामिल किया गया है।

महिला अधिकारी को विंग्स से सम्मानित किया जाना : भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट को 07 जून, 2024 को 'विंग्स' से सम्मानित किया गया है और साथ ही पहली महिला अधिकारी ने जुलाई 2024 में 'पी8आई' विमान पायलट के रूप में योग्यता प्राप्त की है।

विंग्स से सम्मानित होती महिला अधिकारी

भारतीय नौसेना में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए)** : एनडीए के संबंध में, महिला कैडेटों का प्रवेश जून 2022 बैच से शुरू हुआ और भारतीय नौसेना को तीन रिक्तियां आवंटित की गई। वर्तमान में, एनडीए में महिला नौसेना कैडेटों के लिए रिक्तियों की संख्या तीन से बढ़ाकर छह कर दी गई है।

- **भारतीय नौसेना अकादमी (आईएनए)** : आईएनए में, महिला कैडेट अब '10+2 बी–टेक' प्रवेश योजना के माध्यम से शामिल होने के लिए पात्र हैं। महिला कैडेटों का पहला ऐसा बैच जनवरी 2024 से प्रशिक्षण शुरू कर चुका है। इसके अलावा, आईएनए में 'यूपीएससी प्रवेश' के माध्यम से महिलाओं का प्रवेश जून 2024 बैच से शुरू हो गया है।

- **भारतीय नौसेना के जहाजों पर महिला कर्मियों के लिए आवास** : अग्निवीरों और कैडेटों के रूप में महिलाओं की भर्ती के साथ, इन रैंकों में आवास के संबंध में लैंगिक समावेशिता की आवश्यकता एक महत्वपूर्ण पहलू बन गई है। भारतीय नौसेना सरकार की एकमात्र शाखा है जहाँ आवास स्थानों में वृद्धि/रूपांतरण एक चुनौती है, क्योंकि जहाज के भीतर उपलब्ध स्थान स्थिर रहता है। एक नीति के रूप में, भारतीय नौसेना जहाजों पर अधिकारियों के लिए 30% आवास तथा नाविकों के लिए 20% आवास महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया है।

भारतीय वायु सेना

महिला अग्निवीरवायु की भर्ती : अग्निपथ योजना की शुरुआत से लेकर अब तक भारतीय वायुसेना ने तीन बैचों में 655 महिला अग्निवीरवायु को शामिल किया है। महिला अग्निवीरों के पहले दो बैचों को प्रशिक्षण के बाद विभिन्न भारतीय वायुसेना अड्डों पर तैनात किया गया है। महिला अग्निवीरों को विमान उप–प्रणाली में भी तैनात किया जा रहा है। भर्ती संख्या में वृद्धि के साथ, चरणबद्ध तरीके से महिला अग्निवीरों के लिए और अधिक उप–प्रणालियाँ और इकाइयाँ/स्थान खोले जा रहे हैं।

अग्निवीरवायु महिला ड्रिल टीम (एडब्ल्यूडीटी) : फरवरी 2024 में वायुसेना स्टेशन, नई दिल्ली में अग्निवीरवायु महिला ड्रिल टीम बनाने के लिए कुल 30 अग्निवीरवायु महिलाओं का विशेष रूप से चयन किया गया था। अपने प्राथमिक कर्तव्यों के निर्वहन के अलावा, इन अग्निवीरवायु महिलाओं को संगीत के साथ समन्वय में ड्रिल करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया था। पाँच महीने के प्रशिक्षण के बाद, 26 जुलाई, 2024 को कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति आयोजित की गई।

कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के दौरान अग्निवीरवायु महिला ड्रिल टीम

गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार महिला मार्चिंग दस्ता : स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार 'कर्तव्य पथ' पर मार्च करके 'तीनों सेनाओं की पूर्ण महिला मार्चिंग टुकड़ी' ने इतिहास रच दिया। इसके अलावा, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं की एक पूर्ण महिला मार्चिंग टुकड़ी ने भी गौरवपूर्ण मार्च किया, जो इतिहास में अपनी तरह की पहली टुकड़ी थी। उनके अद्‌भुत प्रदर्शन ने महिला अधिकारियों की शक्ति, अनुशासन, क्षमता और समर्पण को दर्शाया।

गणतंत्र दिवस परेड में पूर्णतया महिला मार्चिंग दस्ता

त्रि–सेवा महिला जलयात्रा नौकायन अभियान : विश्व मंच पर भारत की नारी शक्ति का प्रदर्शन और चुनौतीपूर्ण वातावरण में उनकी बढ़ती भागीदारी की उपस्थिति दर्शाने के लिए, भारतीय सेना ने 23 मार्च से 17 अप्रैल 2024 तक मुंबई–कारवार–लक्षद्वीप से मुख्य भूमि से द्वीप और वापसी तक नौकायन अभियान चलाया। तीनों सेनाओं की 12 महिला अधिकारियों ने इस अभियान में भाग लिया।

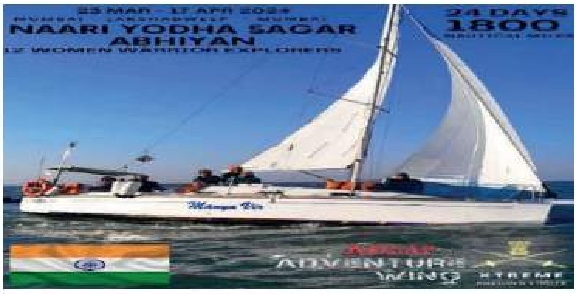

भारतीय तटरक्षक बल

भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) दशकों से महिलाओं को सशस्त्र बलों में सेवा के अनेक अवसर प्रदान करता रहा है। वर्तमान में, कुल **82** महिला अधिकारी आईसीजी की प्रशासनिक, लॉजिस्टिक्स और युद्धक भूमिका में प्रत्येक मोर्चे पर ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए सक्रिय रूप से तैनात हैं। आईसीजी ने महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण की दिशा में सक्रिय कदम उठाए हैं। वर्ष 2024–25 में तटरक्षक चार्टर ऑफ़ ड्यूटीज़ से संबंधित विभिन्न विशेषज्ञताओं में कुल **17** महिला अधिकारियों ने कोर्स पूरे किए हैं। उनके अनुभव और कौशल का सामान्य प्रशासन और संभारिकी, सूचना प्रौद्‌योगिकी (आईटी) सेवाओं और तटरक्षक विमानन (पायलट, पर्यवेक्षक और सहायक सेवाओं के रूप में) के क्षेत्र में प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है।

आईसीजी में महिला ईपी की नियुक्ति : भारत सरकार की लैंगिक समावेशिता और सशक्तिकरण नीति के अनुरूप, भारतीय तटरक्षक बल वर्ष 2027 से महिला नामांकित कार्मिकों की नियुक्ति की तैयारी कर रहा है। यह पहल आईसीजी की अपने रैंकों में विविधता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस परिवर्तन को सुगम बनाने के लिए, आईसीजी महिलाओं के लिए एक निर्बाध और सहायक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने हेतु नीतियों में संशोधन कर रहा है और तटवर्ती और समुद्री दोनों स्तरों पर अपने बुनियादी ढाँचे में सुधार कर रहा है।

रक्षा उत्पादन विभाग

डीडीपी के अंतर्गत आने वाले संगठनों ने 2024–25 के दौरान महिला सशक्तिकरण और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कीं। इन उपायों में कौशल विकास, कार्यस्थल कल्याण, वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन, स्वास्थ्य और बाल देखभाल सुविधाएँ, और जागरूकता कार्यक्रम शामिल थे , जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि कर्मचारियों और आसपास के समुदायों की महिलाओं, दोनों को लाभ मिले।

कौशल विकास और आजीविका के अवसर

- **एचएएल** ने बेंगलुरु के आसपास के ग्रामीण इलाकों में एक सूक्ष्म कौशल उद्यमिता विकास कार्यक्रम में सहयोग किया, जिसके तहत 1200 से ज़्यादा महिलाओं को फ़ैशन तकनीक, जूट निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण जैसे व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया गया। लाभार्थियों को वित्तीय साक्षरता, बैंक लिंकेज के लिए सहायता, और उद्यम तथा एफएसएसएआई पंजीकरण में सहायता भी प्रदान की गई। 250 से ज़्यादा महिलाओं ने पंजीकरण कराया और नए उद्यमों के लिए ₹50 लाख से ज्यादा के ऋण स्वीकृत किए गए।
- **बीईएमएल और जीआरएसई** ने तकनीकी, सॉफ्ट–स्किल, व्यवहारिक, नेतृत्व और परियोजना प्रबंधन प्रशिक्षण के माध्यम से महिला कर्मचारियों के कौशल को उन्नत किया।
- **जीआईएल** ने अपनी महिला कल्याण एसोसिएशन (डब्ल्यूडब्ल्यूए) के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए व्यावसायिक कोर्स आयोजित किए।

कार्यस्थल कल्याण और संस्थागत समर्थन

- **बीईएमएल, जीएसएल, एमडीएल, मिधानी, एमआईएल, टीसीएल, वाईआईएल, जीआईएल और डीजीएक्यूए** ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अधीन **आंतरिक शिकायत समितियों** का गठन किया है। कई संगठन कर्मचारियों के लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं।
- **बीईएमएल** की सभी इकाइयों में महिला प्रकोष्ठ हैं तथा पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाले कर्मचारियों को मासिक शिशुगृह भत्ता भी प्रदान किया जाता है।
- **मिधानी** अपने परिसर में एक पूर्णतः सुसज्जित शिशुगृह चलाती है तथा संगत अधिनियमों के अंतर्गत मातृत्व लाभ प्रदान करती है।
- **एमआईएल** छह कारखानों में शिशु–गृह सुविधाएं प्रदान करता है, अन्य में पहल चल रही है, तथा मासिक धर्म स्वच्छता के लिए महिलाओं और लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड वितरण सुनिश्चित करता है।
- **वाईआईएल** मातृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश और शिशुगृह सुविधाएं प्रदान करता है, साथ ही वेतन, प्रशिक्षण, पदोन्नति और कार्य आवंटन में समान अवसर सुनिश्चित करता है।
- **जीएसएल और एमडीएल** आंतरिक शिकायत समितियाँ बनाए रखते हैं और नियमित रूप से जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। **एमडीएल** की महिला कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र की महिलाओं के मंच (डब्ल्यूआईपीएस) में सक्रिय भागीदार हैं ।

स्वास्थ्य और कल्याण उपाय

- **एमआईएल** ने महिलाओं के अधिकारों और संरक्षण पर जागरूकता प्रशिक्षण आयोजित किया, जिसमें पॉश अधिनियम पर सत्र भी शामिल थे।

- **जी.आई.एल.** ने अपनी ओ.पी.एफ. इकाई में एक महिला डॉक्टर के नियमित दौरे सुनिश्चित किए।
- **एडब्ल्यूईआईएल** उदिता महिला कल्याण एसोसिएशन का संचालन करता है, जो एक नर्सरी स्कूल चलाने सहित एस्टेट और आसपास के क्षेत्रों में कल्याणकारी गतिविधियों का प्रबंधन करती है।

समारोह और मान्यता

- **जीआरएसई** ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर वनिताः ए डे–आउट प्रोग्राम का आयोजन किया।
- **एडब्ल्यूईआईएल** ने अपनी सभी इकाइयों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 मनाया।
- **एमडीएल** ने डब्ल्यूआईपीएस के नेतृत्व में गतिविधियों और क्षेत्रीय बैठकों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया।

सैनिक स्कूल

सैनिक स्कूल लैंगिक समानता और महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देने वाले समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसमें महिला कैडेटों को सशक्त बनाने और उनके विकास के समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलों और नीतियों को लागू करना शामिल है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013) पर नियमित रूप से तिमाही बैठकें आयोजित की जाती हैं। बालिकाओं और महिलाओं की जागरूकता और सुरक्षा के लिए शिकायत तंत्र प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। काउंसलर नियुक्त किए गए हैं और काउंसलर द्वारा पीओसीएसओ अधिनियम पर नियमित सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानाचार्य, उप–प्रधानाचार्य और हाउस मास्टर्स असेंबली के दौरान पीओसीएसओ अधिनियम के संगत प्रावधानों के बारे में कैडेटों को जागरूक करने के लिए नियमित सत्र आयोजित किए जा रहे हैं और महिला स्टाफ सदस्यों को मातृत्व अवकाश और सीसीएल दिया जा रहा है।

सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएँ

सशस्त्र सेनाओं के इतिहास में प्रथम महिला डीजीएएफएमएस : सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन, एवीएसएम, वीएसएम को 01 अक्टूबर 2024 को डीजीएएफएमएस के रूप में नियुक्त किया गया, और वह इस सर्वोच्च नियुक्ति तक पहुंचने वाली सशस्त्र सेनाओं की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं।

सेना की प्रथम महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवाएं : लेफ्टिनेंट जनरल साधना एस नायर, एवीएसएम, वीएसएम 01 अगस्त 2024 को नियुक्ति ग्रहण करने के साथ ही प्रथम महिला डीजीएमएस (सेना) बन गई।

एएमसी सेंटर एवं कॉलेज, लखनऊ की प्रथम महिला कमांडेंट : लेफ्टिनेंट जनरल कविता सहाय, एसएम, वीएसएम (अब सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय) एएमसी सेंटर एंड कॉलेज, लखनऊ की प्रथम महिला कमांडेंट थीं, जब उन्होंने 01 फरवरी 2024 को नियुक्ति ग्रहण की थी।

सियाचिन ग्लेशियर पर महिलाएँ : कैप्टन गीतिका कौल, कठिन प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनीं, और कैप्टन फ़ातिमा वसीम ने ग्लेशियर पर एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया। ये उपलब्धियाँ भारतीय सशस्त्र सेनाओं, विशेष रूप से सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में, महिलाओं द्वारा की जा रही महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती हैं और सैन्य चिकित्सा सेवाओं में उनके बढ़ते प्रभाव और अमूल्य योगदान को रेखांकित करती हैं।

पूर्णतया महिला एएफएमएस मार्चिंग टुकड़ी: 'सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं' की पूर्णतया महिला मार्चिंग टुकड़ी ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार कर्तव्य पथ पर मार्च करके इतिहास रच दिया। इस टुकड़ी में टुकड़ी के कमांडर के तौर पर सेना चिकित्सा कोर की मेजर सृष्टि खुल्लर, सेना दंत चिकित्सा कोर की कैप्टन अंबा सामंत, भारतीय नौसेना की सर्जन लेफ्टिनेंट कंचना और अतिरिक्त अधिकारी के रूप में भारतीय वायु सेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिव्या प्रिया के साथ साथ, सैन्य नर्सिंग सेवा के 144 अधिकारी भी शामिल थे।

आगे बढ़ने का रास्ता

रक्षा क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण केवल समानता तक सीमित नहीं है; यह दुनिया भर के रक्षा बलों की प्रभावशीलता, अनुकूलनशीलता और समुत्थानशीलता को बढ़ाने के बारे में है। पुरुषों और महिलाओं, दोनों की पूरी क्षमता का दोहन करके, इस क्षेत्र को व्यापक दृष्टिकोणों, विचारों और प्रतिभाओं का लाभ मिलता है। हालाँकि चुनौतियाँ बनी हुई हैं, फिर भी रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इस बात का एक सशक्त संकेत है कि शक्ति, नेतृत्व और साहस ऐसे गुण हैं जो लिंग–भेद से परे हैं। जैसे–जैसे दुनिया विकसित होती जाएगी, रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका भी विकसित होती जाएगी, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक समावेशी, गतिशील और प्रभावी रक्षा क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त होगा।

*****

नोट

नोट

BEACH CLEANING
PROGRAMME
PUNEET SAGAR ABHIYAN